संपादकीय

“ देशभक्ति दान की तरह है, जो घर से शुरू होती है।
-हेनरी जेम्स

पंजाब में 2023 में आई बाढ़ के बाद इसकी वजहों पर हुए अध्ययनों के बावजूद जिस तरह से यहां के सभी जिले बाढ़ के प्रकोप से जूझ रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व तैयारियों पर तमाम विमर्श के बाद भी हम इनसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं।

आफत का सैलाब

रावी, ब्यास व सतलुज जैसी बारहमासी नदियों के अलावा मौसमी नदी घग्गर और कई छोटी सहायक नदियां और उनमें प्रवाहित जलोढ़ मिट्टी जिस पंजाब को धरती के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक बनाती है, उसे इस उर्वरता की कीमत भी चुकानी पड़ रही है। दरअसल, पंजाब में बाढ़ जैसी स्थितियों के लिए हिमालयी राज्यों से आ रही नदियों और वहां हो रही भारी बारिश को दोषी माना जा रहा है। भारतीय पंजाब में अगस्त महीने में पिछले 26 वर्षों में सबसे अधिक बारिश हुई और सितंबर के पहले हफ्ते में भी सामान्य से 187 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे मौजूदा बाढ़ की स्थिति और भयावह हो गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, एक से सात सितंबर के बीच पंजाब में 66.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से लगभग तीन गुना ज्यादा है। इसकी गंभीरता का पता इस बात से चलता है कि पंजाब का कोई भी जिला बाढ़ के प्रकोप से बच नहीं सका है, और इससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के लिए करीब 1,600 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच कर बचाव कार्य कर रही हैं, लेकिन अभी कुल नुकसान का अंदाज लगाना मुश्किल है। अगर पंजाब इस वक्त हाल की सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है, तो इसकी वजहें सिर्फ प्राकृतिक नहीं हैं। समझना चाहिए कि पंजाब की स्थिति हिमाचल और जम्मू से अलग है। दोनों हिमालयी राज्यों में तबाही की वजह अचानक आई बाढ़ को समझा जा सकता है, लेकिन इन राज्यों की नदियों का उफान पंजाब तक पहुंचने में कुछ दिन का समय लगा, इसके बावजूद, इस समय का फायदा नहीं उठाया जा सका, जो वाकई हैरत की बात है। इसके अलावा एक अध्ययन के अनुसार, जुलाई से सितंबर के बीच भारी बारिश से पंजाब में बाढ़ जैसी स्थितियां हर वर्ष पैदा होती ही हैं। लेकिन, नदियों की उचित ढंग से सफाई न किए जाने पर उनमें गाद भर जाने से वे उथली हो जाती हैं और पानी किनारों को तोड़कर नजदीकी क्षेत्रों को डुबा देता है। इसके अतिरिक्त, बांधों से पानी छोड़ने की प्रक्रिया के प्रबंधन पर उठ रहे सवालों पर भी ध्यान देना चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए तो सरकारी एजेंसियां जुटी ही हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन को लेकर एक दूरगामी योजना के निर्माण की दिशा में तत्काल कदम उठाना भी जरूरी है।

परंपरा की मजबूत धुरी

भागवत जी की खासियत है कि उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। संघ की 100 साल की यात्रा में उनका कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा।

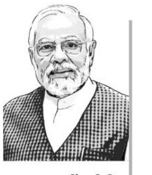

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

आज 11 सितंबर है। यह दिन अलग-अलग स्मृतियों से जुड़ा है। एक स्मृति 1893 की है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व बंधुत्व का संदेश दिया और दूसरी स्मृति है 9/11 का आतंकी हमला, जब विश्व बंधुत्व को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। आज के दिन की एक और विशेष बात है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्मदिवस है, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। संघ परिवार में जिन्हें परम पूजनीय सरसंघचालक के रूप में श्रद्धाभाव से संबोधित किया जाता है, ऐसे आदरणीय मोहन भागवत जी का आज जन्मदिन है।

मेरा मोहन भागवत जी के परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। मुझे उनके पिता, स्वर्गीय मधुकरराव भागवत जी के साथ निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। मैंने अपनी पुस्तक *ज्योतिपुंज* में मधुकरराव जी के बारे में विस्तार से लिखा भी है। अपनी युवावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ कार्य की मजबूत नींव रखी। मधुकरराव जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि अपने पुत्र मोहनराव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे। एक पारसमणि मधुकरराव ने मोहनराव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी।

भागवत जी 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। जो संघ को जानते हैं, उन्हें पता है कि प्रचारक परंपरा संघ कार्य की विशेषता है। भागवत जी भी उस महान परंपरा की मजबूत धुरी हैं। भागवत जी ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उन्होंने कई वर्षों तक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों, विशेषकर विदर्भ में काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में उनके कार्यों को आज भी कई स्वयंसेवक स्नेहपूर्वक याद करते हैं। इसी कालखंड में मोहन भागवत जी ने बिहार के गांवों में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने के कार्य में समर्पित रहे।

वर्ष 2000 में वे सरकार्यवाह और 2009 में सरसंघचालक बने। उन्होंने राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को हमेशा सर्वोपरि रखा। सरसंघचालक होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है। यह एक पवित्र विश्वास है, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी दूरदर्शी व्यक्तित्वों ने आगे बढ़ाया है और इस राष्ट्र के नैतिक और सांस्कृतिक पथ को दिशा दी है। यह गर्व की बात है कि मोहन भागवत जी ने न केवल इस विशाल जिम्मेदारी के साथ पूर्ण न्याय किया है, बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति, बौद्धिक गहराई और सहृदय नेतृत्व भी जोड़ा है।

उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ कार्य के लिए प्रेरित किया है। श्रेष्ठ कार्य पद्धति अपनाने की इच्छा और बदलते समय के प्रति खुला मन रखना, मोहन जी की बहुत बड़ी विशेषता रही है। संघ की 100 साल की यात्रा में भागवत जी का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। चाहे गणवेश परिवर्तन हो या संघ शिक्षा वर्गों में बदलाव हो, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके निर्देशन में संपन्न हुए।

कोरोना काल में उन्होंने स्वयंसेवकों को सुरक्षित रहते हुए समाजसेवा करने की दिशा दी और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने पर बल दिया। हमें कई स्वयंसेवकों को खोना भी पड़ा, लेकिन भागवत जी की प्रेरणा ऐसी थी कि अन्य स्वयंसेवकों की दृढ़ इच्छाशक्ति कमजोर नहीं पड़ी।

इस वर्ष की शुरुआत में, मैंने नागपुर में उनके साथ माधव नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के दौरान कहा था कि संघ अक्षयवट की तरह है, जो राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है। इसकी जड़ें इसके मूल्यों की वजह से बहुत गहरी और मजबूत हैं। इन मूल्यों को आगे बढ़ाने में जिस समर्पण से मोहन भागवत जी जुटे हुए हैं, वह हर किसी को प्रेरणा देता है। समाज कल्याण के लिए संघ की शक्ति के निरंतर उपयोग पर उनका विशेष बल रहा है। इसके लिए उन्होंने पंच परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें स्व-बोध, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण के सूत्रों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। हर भारतवासी को पंच परिवर्तन के इन सूत्रों से अवश्य प्रेरणा मिलेगी।

संघ का हर कार्यकर्ता वैभव संपन्न भारत माता का सपना साकार होते देखना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए जिस स्पष्ट विजन और ठोस एक्शन की जरूरत होती है, मोहन जी इन दोनों गुणों से परिपूर्ण हैं। उनके स्वभाव की एक और बड़ी विशेषता है कि वे मृदुभाषी हैं। उनमें सुनने की भी अद्भुत क्षमता है। यह विशेषता न केवल उनके दृष्टिकोण को गहराई देती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व में संवेदनशीलता और गरिमा भी लाती है। मोहन जी हमेशा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के प्रबल पक्षधर रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि वे अपनी व्यस्तता के बीच संगीत और गायन में भी रुचि रखते हैं। वे विभिन्न भारतीय वाद्ययंत्रों में भी निपुण हैं। पठन-पाठन में उनकी रुचि, उनके अनेक भाषणों और संवादों में साफ दिखाई देती है। पिछले दिनों देश में जितने सफल जन-आंदोलन हुए, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोहन भागवत जी ने पूरे संघ परिवार को इन आंदोलनों में ऊर्जा भरने के लिए प्रेरित किया। मैं पर्यावरण से जुड़े प्रयासों और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को जानता हूं। मोहन जी का आत्मनिर्भर भारत पर भी बहुत जोर है।

कुछ ही दिनों में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो जाएगा। यह भी सुखद संयोग है कि विजयादशमी का पर्व, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और संघ का शताब्दी वर्ष एक ही दिन आ रहे हैं। यह भारत और विश्व भर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघचालक हैं, जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। एक युवा स्वयंसेवक से लेकर सरसंघचालक तक की उनकी जीवन यात्रा उनकी निष्ठा और वैचारिक दृढ़ता को दर्शाती है।

मैं मां भारती की सेवा में समर्पित मोहन भागवत जी के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की पुनः कामना करता हूं। उन्हें जन्मदिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं!

जीवन धारा

एलिजाबेथ गिल्बर्ट

हिम्मत और जिज्ञासा एकसाथ मिलकर हमारे साधारण जीवन को असाधारण और जादुई बना सकती हैं, क्योंकि ये हमें चुनौतियों का सामना करने, नए रास्तों पर चलने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं।

रचनात्मक जीवन जीने का मार्ग है जिज्ञासा

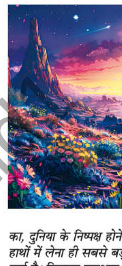

__ब्रह्मांड__ हम सभी के अंदर अनोखे रत्न छिपाता है और फिर पीछे हटकर देखता है कि क्या हम उन्हें ढूंढ पाते हैं। उन रत्नों को खोजने की कोशिश ही 'रचनात्मक जीवन' है। उस खोज को शुरू करने के लिए हिम्मत और जिज्ञासा चाहिए, जो एकसाथ मिलकर हमारे साधारण जीवन को असाधारण और जादुई बना सकती हैं, क्योंकि ये हमें चुनौतियों का सामना करने, नए रास्तों पर चलने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। उस खोज के अक्सर आश्चर्यजनक परिणाम होते हैं, जिन्हें मैं 'बड़ा जादू' कहती हूं। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है, जो सक्रिय रूप से अर्थ की तलाश करते हैं। आपको अपनी खुशियों को पाने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। और एक बार जब आप खुशी हासिल कर लें, तो उसे बनाए रखने में कभी ढील नहीं देनी चाहिए। आपको हमेशा उस खुशी की ओर बढ़ने के लिए कड़ा प्रयास करना होगा, ताकि आप उसमें डूबे रहें। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपका सहज संतोष खत्म हो जाएगा। संकट में प्रार्थना करना आसान है, लेकिन संकट के बीत जाने के बाद भी प्रार्थना करते रहना मायने रखता है, जो आपकी आत्मा को उसकी अच्छी उपलब्धियों को मजबूती से थामे रखने में मदद करती है। मुझे लगता है कि सबसे क्रांतिकारी काम यह है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। किसी के बचाने का, किसी की इजाजत का, दुनिया के निष्पक्ष होने का इंतजार नहीं करना और अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेना ही सबसे बड़ा बदलाव है। जिज्ञासा रचनात्मक जीवन जीने का मार्ग है। जिज्ञासा शुरुआत भी है और अंत भी। सबसे खास बात, जिज्ञासा सबके लिए उपलब्ध है। जुनून कभी-कभी बहुत दूर और मुश्किल लगता है। लेकिन जिज्ञासा नरम, शांत, स्वागत करने वाली और सबके लिए खुली है। जिज्ञासा का जोखिम जुनून से बहुत कम है। जिज्ञासा बस एक साधारण सवाल पूछती है, 'क्या कुछ है, जो तुम्हें रुचिकर लगता है? जिज्ञासा हमारी वह मित्र है, जो हमें स्वयं बनना सिखाती है। यह बहुत नरम, बहुत क्षमाशील और हमेशा साथ देने वाला दोस्त है। जुनून इतना स्थिर, इतना नरम, इतना क्षमाशील नहीं है और कभी-कभी उपलब्ध भी नहीं होता। जब हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, जो कहती है कि हमें हर वक्त जुनूनी होना चाहिए। अगर हमारे अंदर वह तीव्र इच्छाशक्ति नहीं है, तो हम निराशा महसूस कर सकते हैं। लेकिन जिज्ञासा हमेशा हमारे भीतर होती है। यह कम जोखिम वाला आगे बढ़ने और जीने का तरीका है। कामयाबी का रहस्य है कि हम खोजते रहें और हार न मानें, भले ही हमें पता चले कि कुछ वैसा नहीं है, जैसा हमने सोचा था। यही जिज्ञासा हमसे मांग करती है कि हम जागते रहें, सवाल पूछते रहें, पत्थर पलटते रहें, चाहे हम थक जाएं, डर जाएं, या सोचें कि हमने सब देख लिया। दुनिया इतनी बड़ी और खूबसूरत है कि इसे पूरी तरह कभी जाना नहीं जा सकता, और यही इसकी खूबी है।

अपनी जिम्मेदारी खुद लें

सूत्र

जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाबी के लिए जिज्ञासु होना जरूरी है। अपने भीतर के जानने की इच्छा को दिशा देनी होगी, तभी आप हर क्षेत्र में बेहतर हो पाएंगे। अपनी जिम्मेदारी खुद लेने से आपका जीवन निखर कर सुंदर हो जाएगा। दुनिया की विशालता को जानना मुश्किल है, और इसे जानने से ही जिंदगी खूबसूरत हो सकती है।

दूसरा पहलू

आखिर इंजीनियर पुलों पर पड़ने वाले भार की सीमा कैसे तय करते हैं और पानी के नीचे चीजें कैसे बनाते हैं?

पानी के नीचे पुल कैसे बनते हैं

एरी पेरेज

पानी के अंदर निर्माण जटिल और चुनौतीपूर्ण है। बिल्डरों ने 'ब्रुकलिन ब्रिज' के खंभों का निर्माण कैसॉन का उपयोग करके किया था।

इन्सान, सामग्री और मशीनें पानी में ठीक से काम नहीं कर पातीं। लोगों को निरंतर वायु की जरूरत पड़ती है, पानी में कंक्रीट डालना मुश्किल है और कई सामग्रियां केवल सूखी जगह पर ही काम करती हैं।

जब मैं बच्चा था, मैंने एक कॉमिक (चित्रकथा) पढ़ी थी, जिसने मेरे सामने एक ज्वलंत प्रश्न खड़ा कर दिया था। पुलों पर पड़ने वाले भार की सीमा कैसे तय करते हैं? कॉमिक में केल्विन के पिता गलत जवाब देते हुए कहते हैं कि वे बड़े-बड़े ट्रक चलाते हैं, जब तक कि पुल टूट न जाए, फिर आखिरी ट्रक का वजन नापकर पुल बनाते हैं। अब मैं एक भू-तकनीकी इंजीनियर हूं और मुझे बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रश्नों के सही उत्तर मालूम हैं। लोग अक्सर केल्विन के पिता की तरह गलत दिशा में सोचते हैं। इंजीनियर एक अनुमानित भार वहन करने के लिए पुलों की डिजाइन बनाते हैं, न कि वजन सीमा का परीक्षण करते हैं। इसी तरह, लोग यह भी पूछते हैं कि इंजीनियर पानी के नीचे चीजें कैसे बनाते हैं? इंजीनियर आम तौर पर पानी के नीचे चीजें नहीं बनाते, बल्कि वे ऐसी चीजें बनाते हैं, जो बाद में पानी के नीचे चली जाती हैं। आप जो निर्माण कर रहे हैं और उसके चारों ओर चट्टान या मिट्टी है, तो उसे भूमिगत निर्माण माना जाता है, भले ही उसके ऊपर पानी की एक परत हो। जमीन के नीचे निर्माण में आम तौर पर शक्तिशाली सुरंग खोदने वाली मशीन का उपयोग होता है। यह मशीन मिट्टी या चट्टान को खोदकर सुरंग बनाती है। इंजीनियर इसका उपयोग चैनल टनल (एक रेलवे सुरंग) के जरिये करते हैं। हालांकि आधुनिक मशीनें काफी उन्नत हैं, फिर भी निर्माण की यह पद्धति करीब 200 साल पुरानी है। इन्सान, सामग्री और मशीनें पानी में ठीक से काम नहीं कर पातीं। लोगों को निरंतर वायु की जरूरत पड़ती है, पानी में कंक्रीट डालना मुश्किल है और कई सामग्रियां केवल सूखी जगह पर ही काम करती हैं। छोटे-मोटे काम, जैसे पहले से बनी सुरंग के हिस्सों को जोड़ना या जांच करना, पानी के नीचे हो सकता है। इसलिए निर्माण का अधिकांश कार्य बाहर ही होता है। एक बार ढांचा स्थापित हो जाने पर पानी के भीतर उसकी निरंतर निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। लोग आम तौर पर बाहर निर्माण करके ढांचे को पानी में ले जाते हैं। यदि पानी उथला है, तो श्रमिक धातु की दीवारें बनाकर सीधे सतह से निर्माण कर सकते हैं। आजकल, कॉफरडैम का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक अस्थायी, जलरोधी घेरा है, जिसके भीतर की जगह का पानी सुखाया जाता है। बिल्डरों ने 'ब्रुकलिन ब्रिज' के खंभों का निर्माण कैसॉन का उपयोग करके किया था। कैसॉन एक खाली ढांचा है जिसका उपयोग पानी के भीतर निर्माण कार्य करने के लिए किया जाता है। पानी के अंदर निर्माण के लिए इंजीनियरों ने कई तरीके विकसित किए हैं। अधिकांशतः वे पानी के अंदर निर्माण नहीं करते।

आंकड़े

भारत में खनन

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में खनन क्षेत्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें छत्तीसगढ़ सबसे आगे है।

छत्तीसगढ़	9.38%
ओडिशा	9.0%
झारखंड	5.32%
गुजरात	3.39%
मध्य प्रदेश	2.68%

आंकड़े प्रतिशत में हैं। | स्रोत : MoSPI

राजा ने क्रोध में साधु-संतों को देश से बाहर कर दिया। इसके एक-दो दिन बाद ही राज्य की व्यवस्था चरमरा गई और अंत में राजा क्षमा याचना करने लगा।

काया-माया झूठी है, सर्वत्र राम हैं

अंतर्यात्रा
संकलित

श्रीजीमहाराज के प्रमुख शिष्यों में एक श्रीरामदास जी थे। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की। इसके बाद श्रीरामदास जी गुरु की इच्छानुसार भगवान की कथा लोगों तक पहुंचाते थे। संतों से वैर रखने वाले कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने राज्य में भ्रम फैलाया कि यहां के संत धर्म की अवहेलना कर रहे हैं। वहां के राजा ने बिना विचार-विमर्श किए, क्रोध में आदेश दिया कि जो भी साधु-संत सनातन वर्णाश्रम धर्म की अवहेलना कर सभी वर्णों को हरि भक्ति का समान अधिकारी बताकर राम नाम जाप की ही प्रधानता से प्रचार कर मर्यादा को मिटा रहा है, उसे शीघ्र ही देश से बाहर कर दो।

सैनिकों ने सबको बाहर जाने को कहा। इस पर श्रीरामदास जी बोले, 'हम अनादि राम के साधु हैं। राजा की इच्छा है, तो हम देश छोड़ देंगे। देश किसका है? काया-माया झूठी है, सर्वत्र राम का ही राज्य है। जिस मुरारी की इच्छा को पुरारी महादेव मस्तक पर धारण करते हैं, वही हमारे साथ हैं। तुम अपनी सीमा रखो। ऐसा कहकर श्रीरामदास जी राज्य की सीमा से बाहर चले गए। संतों का अनादर व भगवान के नाम पर बिना सोचे-समझे निर्णय लेना राजा को महंगा पड़ा। एक-दो दिन में ही राज्य की व्यवस्था चरमरा गई। तब राजा घबराकर श्रीरामदास जी के पास जाकर क्षमा याचना करने लगा। श्रीरामदास जी बोले, 'भगवान से क्षमा मांगो।' इसके बाद राज्य व्यवस्था सही हो गई।

आज का इतिहास

आतंकवादी हमले से अमेरिका का सीना छलनी

इतिहास में 11 सितंबर का दिन एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के सीने पर इस दिन हुए घातक आतंकवादी हमले ने एक ऐसा घाव दिया, जिसकी टीस दुनिया रहने तक कायम रहेगी। साल 2001 में 11 सितंबर के दिन आतंकवादियों ने यात्री विमानों का अपहरण कर अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन मुख्यालय को निशाना बनाया। इसे अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादी हमले के तौर पर देखा जाता है। 1893 : अमेरिका के शिकागो क्षेत्र में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता और हिंसा पर ऐतिहासिक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने सभी धर्मों की अच्छाइयों का भी जिक्र किया। 1895 : महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता विनोबा भावे का जन्म। 1906 : महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया।

नेपाली आंदोलन के पीछे कौन

जितना स्वतःस्फूर्त यह आंदोलन दिख रहा है, क्या वाकई में ऐसा है या इसके पीछे विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं?

सुबीर भौमिक | मुद्दा

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जिस तरह से इस्तीफा देने के बाद नेपाली सेना के हेलिकॉप्टर में बैठकर भागे, उससे हमें पिछले साल पांच अगस्त को सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपने देश से भागने की याद आ गई। हसीना के मामले में, यह जल्द ही स्पष्ट हो गया था कि वह भारत जा रही हैं। लेकिन ओली को कौन आश्रय देता है, यह जानने के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन दोनों घटनाओं के बीच की भयावह समानताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पिछले साल बांग्लादेश में और अब नेपाल में, हसीना और ओली को सत्ता से हटाने वाले आंदोलन का नेतृत्व ज्ञात राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा नहीं किया गया था। बांग्लादेश में बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी ने छात्र आंदोलन को समर्थन दिया था, जो एक बड़े आंदोलन में बदल गया, लेकिन उसका प्रत्यक्ष नेतृत्व ऐसे युवा नेताओं द्वारा किया गया था, जिनका किसी भी राजनीतिक दल से सीधा संबंध नहीं था। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसी राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि एक गुमनाम गैर-सरकारी संगठन 'हामी नेपाल' ने किया था। पेशेवर इवेंट मैनेजर सुदन गुरुंग द्वारा 2015 में स्थापित, 'हामी नेपाल' आपदा राहत पर केंद्रित है। नेपाल के कई लोगों का कहना है कि उनके कार्यक्रमों को पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से दान में अच्छी-खासी धनराशि मिलती थी। जागरूकता शिविरों में उन युवा कार्यकर्ताओं की अच्छी-खासी भीड़ उमड़ी, जो नेपाल की राजनीतिक पार्टियों से निराश थे और सोशल मीडिया को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार से लड़ने की गुरुंग की प्रतिबद्धता में विश्वास रखते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी के दौरान, गुरुंग के सहयोगी, बांग्लादेश भेदभाव विरोधी छात्र मंच के 'समन्वयकों' की तरह, बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों को जुटाने के लिए संदेश भेज रहे थे, और जोर दे रहे थे कि वे स्कूल बैग के साथ स्कूल यूनिफॉर्म में आएं। संभवतः उनका विचार रहा होगा कि यदि आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो वर्दी में स्कूली बच्चे पुलिस को गोली चलाने जैसी कठोर कार्रवाई करने से रोक सकते हैं, लेकिन यदि पुलिस की गोलीबारी में कुछ स्कूली बच्चे मारे जाते, तो भावनात्मक प्रतिक्रिया आंदोलन को उस बिंदु तक पहुंचा देती, जहां से वापस लौटना असंभव होता।

बांग्लादेश और अब नेपाल, दोनों जगहों पर पुलिस ने शासन को बचाने के लिए सख्ती बरती और बड़ी संख्या में युवाओं की मौत ने आंदोलन को इतना उग्र बना दिया कि कोई रास्ता नहीं बचा। दोनों ही देशों में, आंदोलन और भी उग्र हो गया, जबकि सरकार ने आंदोलनकारियों की मुख्य मांगें मान ली थीं। बांग्लादेश और नेपाल, दोनों में आंदोलन अपेक्षाकृत अज्ञात संगठनों द्वारा चलाए गए, जिनकी गतिविधियां अक्सर खुफिया रडार से दूर रहती हैं। दोनों देशों में, आंदोलनकारियों ने लामबंदी के लिए नई पीढ़ी की तकनीकों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। भ्रष्टाचार और दमन के कारण राजनीतिक परिवेश में व्याप्त जनाक्रोश को कम करके नहीं आंका जा सकता और निश्चित रूप से 'हामी नेपाल' या बांग्लादेश छात्र मंच जैसे संगठन इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यह उम्मीद करना बहुत ज्यादा होगा कि वे अकेले नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। यहीं पर सत्ता परिवर्तन में रुचि रखने वाली महत्वपूर्ण शक्तियों के लिए काम करने वाली बाहरी एजेंसियों की भूमिका होती है।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 108 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

बाढ़ और भूस्खलन प्रमुख कारण पेड़ों की अवैध कटाई

देश के चार उत्तरी राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने लगता है उस मर्म पर हाथ रख दिया है जिसकी ओर पर्यावरणविद, भूगर्भशास्त्री और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अर्से से ध्यान दिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार और नीति-निर्धारकों, राजनीतिक नेताओं और प्रशासनिक अमले के कानों पर कोई जूं नहीं रेंगती। स्थानीय सरकारों, मंत्रियों और अफसरों से मिल कर भू माफिया ने इन राज्यों का जो हाल कर दिया है, वह तो अब कभी सुधर नहीं सकता। अदालत ने बाढ़ और भूस्खलन पर गंभीर चिंता जताते हुए इसके लिए पेड़ों की अवैध कटाई को प्रमुख कारण माना है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर सरकारों को नोटिस जारी कर उनसे दो हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ कटाई की गई है, और यही हालिया आपदा का बड़ा कारण हो सकता है। अदालत ने मीडिया रिपोटरे पर संज्ञान लेते हुए कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश के दृश्य देखे, जहां बड़ी संख्या में लकड़ी के कुंदे के कुंदे बाढ़ में बहते हुए नजर आए। यह अनियंत्रित पेड़ कटाई का संकेत है। विकास जरूरी है, लेकिन वह संतुलित होना चाहिए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या कहते, उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि हमने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की है कि अब प्रकृति हमें उसका जवाब दे रही है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर वे पर्यावरण मंत्रालय के सचिव से बात करेंगे और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से भी संवाद स्थापित करेंगे। लेकिन क्या ये बातें कहने से पहले मेहता को सोचना नहीं चाहिए था कि जब-जब पर्यावरणविद, भूगर्भ शास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता सवाल उठाते हैं, या स्थानीय लोग आंदोलन करते हैं, तब सरकारों की गलत नीतियों की पैरवी करने राज्य ओर केंद्र के अटॉर्नी और सालिसिटर जनरल जैसे बड़े अधिकारी क्यों आ जाते हैं। उस समय क्या उन्हें दुष्परिणामों का भान नहीं होता। केदारनाथ त्रासदी, जोशीमठ की दरारें, हिमाचल और उत्तराखंड के भूस्खलन और बाढ़, वैष्णो देवी तथा अमरनाथ यात्रा मागरे पर हुए हादसों और पंजाब की बर्बादी से हम कभी सबक भी लेंगे या नोटिसों का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा।

प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा : नीतिगत और कूटनीतिक मायने

आरती कुमारी

बीते मई के महीने में जब भारत-पाक संघर्ष के समय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की उनके समर्थकों ने प्रशंसा की थी तो देश के विपक्ष को और विशेष रूप से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की वह प्रशंसा अच्छी नहीं लगी थी ।तब उन्होंने यह विमर्श गढ़ने का प्रयास किया था कि यह प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता की जीत नहीं है बल्कि सेना के शौर्य की जीत है। यद्यपि 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुई जीत को कांग्रेस आज तक उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जीत के रूप में स्थापित करती रही है । कांग्रेस बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने की श्रीमती गांधी की रणनीति को भी सेना की जीत ने मानकर श्रीमती गांधी की जीत मानती रही है। प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता को श्रीमती गांधी की नेतृत्व क्षमता से कम आंकने के लिए राहुल गांधी ने पाकिस्तान के विरुद्ध की गई सफल कार्यवाही में प्रधानमंत्री की भूमिका को गौण करते हुए उपरोक्त विमर्श गढ़ने का प्रयास किया। ऐसा करके उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व को प्रभावशून्य करने का प्रयास किया था, परंतु अब जबकि प्रधानमंत्री श्री मोदी चीन की यात्रा के समय चीन और रूस के साथ मिलकर भारत की सफल कूटनीतिक विदेश नीति का परिचय देने और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सारी धमकियों की हवा निकालने में सफल होकर एक विजेता सेनानायक की भांति स्वदेश लौटे हैं तो इसे निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की राजनीतिक नेतृत्व की सूझबूझ ही कहा जाना चाहिए। उनकी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण माना जाना चाहिए , क्योंकि उन्होंने इस समय अकेले एक बड़ी जंग जीतने में सफलता प्राप्त की है । उनके समर्थक जहां उनकी इस विजय का उत्सव मना रहे हैं वहीं उनकी इस विजय ने विपक्ष के मुंह पर ताले जड़ दिए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी की इस रणनीतिक यात्रा के पश्चात तेजी से वैश्विक राजनीति की गति में परिवर्तन अनुभव हुआ है । चीन और भारत का इस प्रकार निकट आना और रूस का एक अच्छे साथी के रूप में भारत के साथ खड़े होकर अमेरिका को ललकारना इस राजनीति का दूरगामी परिणाम निश्चित करता है। इसी समय इसराइल ने भी भारत के साथ एक अच्छे और सच्चे मित्र की भूमिका को निभाने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है। कल परसों अमेरिका की यात्रा पर गए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी चीन में हुई एससीओ की बैठक में अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ उपस्थित रहे। उन्होंने भी अपनी आंखों से देख लिया है कि बदलते हुए भारत की वैश्विक क्षमता और शक्ति कितनी है ? कितना उसका सम्मान है ? और यह भी कि आज का भारत अमेरिका की भी परवाह नहीं करता है। हमारा मानना है कि इस सबके उपरांत भी हमें चीन से सावधान रहने की आवश्यकता है। एक समय था, जब देश के प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन के तत्कालीन नेतृत्व के द्वारा दिए गए "हिंदी चीनी – भाई-भाई " के नारे में भूल कर दी थी। उस भूल का इतिहास न दोहरा दिया जाए , इसके लिए भारत के राजनीतिक नेतृत्व को अत्यंत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। फिर भी प्रधानमंत्री श्री मोदी की इस यात्रा के दौरान जिस प्रकार उन्होंने चीन के लोगों और नेतृत्व को आकर्षित किया है, वह बदलते हुए भारत का सही चित्रण करने में महत्वपूर्ण कारक हो सकता है । हम सभी को इस बात पर गर्व करने का पूरा अधिकार है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के वर्चस्व को चीन ने स्वीकार किया है। उसने अपने आचरण और व्यवहार से यह भी स्वीकार कर लिया है कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। इसके उपरांत भी चीन और भारत की इस प्रकार की निकटता को "तात्कालिक आधार पर स्थापित किया गया सामंजस्य " ही माना जाना चाहिए। अच्छी बात यह होगी कि चीन स्थाई रूप में भारत के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए । वह भारत को अपने लिए सांस्कृतिक रूप से प्रेरणा का स्रोत स्वीकार करे। उसे धार्मिक दृष्टि देने वाला भारत उसके लिए आज भी कई क्षेत्रों में सहयोगी हो सकता है । भारत की सदिच्छा और वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता को चीन यदि स्वीकार कर ले और इस दिशा में भारत का सहयोगी बनकर चलने का निर्णय ले ले तो दोनों देश विश्व राजनीति के लिए नई दिशा स्थापित करते हुए कई प्रकार के कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। दोनों देशों को इस प्रकार की अनेक संभावनाओं को खोजना चाहिए और उन पर मिलकर काम करना चाहिए। इसके लिए चीन को अपने राजनीतिक चिंतन और कार्यशैली में परिवर्तन लाना होगा। इसे परिवर्तन न कह कर यह कहना उचित होगा कि ऐसा करने के लिए चीन को अपनी नीतियों की बलि देनी पड़ेगी अर्थात उसे विस्तारवादी दृष्टिकोण त्यागना पड़ेगा। क्या भारत के साथ चलने के लिए चीन इस प्रकार की सोच को अपना सकता है या इस प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार हो सकता है ? यदि नहीं तो यही वह पेंच है जिसे समझकर भारत को चीन के प्रति अपनी नीतियों का निर्धारण करना पड़ेगा। "तात्कालिक आधार पर सामंजस्य स्थापित करना "और किसी बड़ी ताकत को सुर में सुर मिलाकर चुनौती दे देना "राजनीतिक सूझबूझ " तो हो सकती है , परन्तु राजनीति की दिशा निर्धारित करने वाला एक "निश्चायक बिंदु " नहीं हो सकता। हमारे प्रधानमंत्री की सोच स्पष्ट है कि वह मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर और अपने देश के हितों को सर्वोपरि रखकर चीन की भूमि पर गए थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चीन साफ नीयत से आगे चलने का निर्णय लेता है तो भारत को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब यह चीन के ऊपर निर्भर करता है कि वह प्रधानमंत्री श्री मोदी की हाल ही में संपन्न हुई यात्रा के समय जिस हाथ को उनसे मिलाने के लिए आगे बढ़ा रहा था, उससे दूसरे वाला हाथ सचमुच खाली था या उस हाथ में आज भी वही खंजर था जो 1962 में उसने भारत की पीठ में भौंका था। यदि आज की वैश्विक राजनीति की परिस्थितियों पर विचार करें तो चीन, भारत और रूस- तीनों का निकट आना समय की आवश्यकता है । यह मानवता के हित में भी है। अमेरिका जिस प्रकार से अपनी दादागिरी चलाता रहा है अब उसके पतन का समय आ गया है। दूसरे विश्व युद्ध के समय उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर मानवता के विरुद्ध जो महापाप किया था, उसका परिणाम उसे अपने कर्मों से ही भुगतना है ? यदि चीन, रूस और भारत की यह तिकड़ी दूर तक साथ चलती रही तो शीघ्र ही सारे विश्व की राजनीति का केंद्र एशिया बनेगा। यदि ऐसा होता है तो यह मानवता के हित में ही होगा। क्योंकि तब भारत का मानवतावाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एकात्ममानववाद की जिस विचारधारा को संसार के लिए परोसने का प्रयास करेगा, वह विचारधारा सारे वैश्विक समाज को शांति का अनुभव करायेगी। 17,125 ,200 वर्ग किलोमीटर में फैला विशालकाय रूस , 95 लाख 97 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ चीन और 32 लाख 87000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भारत अमेरिका सहित किसी भी वैश्विक शक्ति को धराशाई करने में सफल हो सकते हैं। इन तीनों देशों के पास विशाल जनशक्ति भी है। इसके अतिरिक्त तीनों ही एक सैन्य शक्ति के रूप में भी अपना सम्मान पूर्ण स्थान भी रखते हैं। यह बात तो और भी महत्वपूर्ण है कि भारत के चिंतन में यह बात नहीं है कि वह किसी शक्ति को धराशाई करेगा ? यद्यपि आज का भारत अपने राष्ट्रीय हितों के दृष्टिगत सैन्य शक्ति को आधुनिकतम बनाने के लिए कृत संकल्प है, परंतु इसके उपरांत भी वह विस्तारवादी नीतियों को मानवता के विरुद्ध मानता है। वास्तव में यह भारत का प्राचीन राजनीतिक मूल्य है। वेदों सहित ' मनुस्मृति' और उसके बाद की सभी नीतियों या स्मृतियों में भारत के राजनीतिक नेतृत्व के लिए ऋषियों द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक शिक्षा के अंतर्गत यह उपदेश दिया गया है कि कोई भी राजा किसी दूसरे राजा के राज्य को हड़पने का प्रयास नहीं करेगा। यदि कहीं कोई दुष्ट राजा शासन करता हुआ पाया जाता है , जिसके कारण उसकी प्रजा दुखी है तो भी केवल राजा को ही उसके पद से हटाया जाएगा और उसके हटाने के उपरांत उसी के परिवार के किसी योग्य व्यक्ति अर्थात प्रजाहितचिंतक को शासन सौंप दिया जाएगा। इसी के चलते रामचंद्र जी ने रावण को हटाकर उसके भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। यह परंपरा महाभारत काल तक भी यथावत जारी रही, जब श्री कृष्ण जी ने कंस को सत्ता से हटाकर उसके स्थान पर उसी के परिवार के लोगों को राजनीतिक सत्ता सौंप दी थी। राज्य विस्तार का लोभ हमारे चिंतन में नहीं है ,जबकि इस्लाम और ईसाइयत इस प्रकार के लोभ के लिए कुख्यात रहे हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि भारत रूस और चीन के साथ मिलकर अपनी नीतियों को लागू करने में सफल होता है तो विश्व राजनीति से उपनिवेशवाद ,आर्थिक आतंकवाद, बौद्धिक आतंकवाद और जिहादी आतंकवाद जैसी मनोवृतियों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं होगा। जब भारत इस प्रकार की नीतियों को लागू करने में सफल होगा और विश्व इस प्रकार के स्वच्छ सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को अनुभव कर रहा होगा, वास्तव में भारत तभी विश्व गुरु कहलाने योग्य होगा । इसमें रूस और चीन हमारे लिए कितने उपयोगी या सहयोगी हो सकते हैं ? इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी. क्योंकि यह प्रश्न अभी उत्तर की खोज में है।

बिहार में सियासी पारा – NDA बनाम INDI, PK बनेंगे किंगमेकर या वोटकटवा?

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

बिहार की राजनीति में चुनावी माहौल ऐसा है मानो गर्मी के दिनों में अचानक लू चलने लगे। आधिकारिक चुनावी बिगुल अभी नहीं बजा है, लेकिन गाँव से लेकर शहर तक हर गली-मोहल्ले में चर्चा चुनावी समीकरणों की हो रही है। चाय की दुकान से लेकर पंचायत चौपाल तक एक ही बहस "कौन बनेगा बिहार का सरताज?" दिलचस्प स्थिति यह है कि मुकाबला सीधे तौर पर NDA (भारतीय जनता पार्टी + जदयू + सहयोगी दल) और INDI गठबंधन (राजद + कांग्रेस + वाम दल) के बीच है। वहीं, प्रशांत किशोर (PK) और उनकी "जनसुराज पार्टी" का शोर-शराबा भले चुनावी सीन को सजाता दिख रहा है, लेकिन जमीन पर उनकी भूमिका फिलहाल "वोटकटवा" से आगे नहीं बढ़ती नजर आ रही है। बिहार की सियासत में लंबे समय से भाजपा और जदयू गठबंधन का वर्चस्व रहा है। मगर इस बार का समीकरण थोड़ा अलग है। NDA की स्थिति- भाजपा का पारंपरिक कैडर वोट धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है। स्थानीय नेताओं की आपसी खींचतान और गुटबाज़ी ने पार्टी के वोटरों को भ्रमित किया है। जदयू (नीतीश कुमार) की लोकप्रियता अभी भी ग्रामीण इलाकों में "काम करने वाले मुख्यमंत्री" की छवि के कारण बनी हुई है। INDI की स्थिति- राजद का कैडर वोट आज भी लोहे की तरह मजबूत है। लालू प्रसाद की परंपरागत राजनीति और तेजस्वी की नई छवि का मिश्रण, खासकर युवाओं और अल्पसंख्यकों में, भारी समर्थन जुटा रहा है। कांग्रेस जमीन तलाशने में जुटी है, और इस प्रक्रिया में वह राजद को और भी मजबूत कर रही है। प्रशांत किशोर, जो राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी रणनीतिकार के तौर पर नाम कमा चुके हैं, बिहार की सियासत में "जन सुराज" के नाम पर अपनी पार्टी खड़ा करने में लगे हैं। गाँव-गाँव जाकर उन्होंने लंबी यात्राएँ की हैं। वोटर अधिकार यात्रा जैसे अभियानों ने चर्चा तो खूब बटोरी है। मगर सच यही है कि फिलहाल उनका वोट NDA या INDI के खिलाफ निर्णायक ताकत नहीं बन रहा। असल में, PK के समर्थक वही तबके हैं जहाँ पहले से ही गठबंधन की पकड़ मजबूत है। ऐसे में उनके मैदान में उतरने से वोटों का बिखराव जरूर होगा, लेकिन यह सीधे तौर पर NDA के खिलाफ नुकसानदायक साबित हो सकता है। चुनावी समीकरण का असली हाल गाँव ही बताता है।गाँवों में आज जदयू के पक्ष में स्पष्ट लहर दिखाई दे रहा है। भाजपा को लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह उतना नहीं है, जितना पिछले चुनावों में था। राजद की पकड़ मजबूत है, मगर कांग्रेस को लेकर संदेह है कि क्या वह गठबंधन के लिए "मददगार" साबित होगा या "बोझ"। PK की वोटर अधिकार यात्रा ने मीडिया में सुर्खियाँ खूब बटोरीं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जिन रूटों पर यह यात्रा गई, वहाँ पहले से ही उनका संगठन मजबूत था। नए वोटरों को जोड़ने या राजनीतिक जमीन बदलने में यह यात्रा कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाई। नतीजा NDA और INDI दोनों ही अपनी-अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। अगर आज बिहार में चुनाव हो जाए तो स्थिति इस प्रकार दिखती है कि NDA – 128 सीटें, INDI – 109 सीटें और अन्य – 6 सीटें। लेकिन, ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग 113 सीटों पर लड़ाई 3% वोट के अंतर से तय होगी। यहाँ PK की उपस्थिति निर्णायक हो सकती है। भाजपा का सबसे बड़ा संकट यह है कि उसके पास बिहार में कोई बड़ा स्थानीय चेहरा नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा तो है, मगर स्थानीय स्तर पर नेताओं के बीच आपसी टकराव और गुटबाजी ने संगठन को कमजोर किया है। यही कारण है कि भाजपा का कैडर वोट टूटता दिख रहा है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनकी गाँव-गाँव में बनी "काम करने वाले मुख्यमंत्री" की छवि है। सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी नीतियों का असर अब भी ग्रामीण इलाकों में देखा जा सकता है। यही कारण है कि जदयू NDA में सबसे बड़ा फायदा उठाने वाली पार्टी बनती दिख रही है। राजद की सबसे बड़ी ताकत उसका अटूट कैडर वोट बैंक है। यादव + मुस्लिम समीकरण अब भी मजबूत है। कांग्रेस के कमजोर होने का फायदा सीधा राजद को मिल रहा है। तेजस्वी की "रोजगार" वाली राजनीति युवाओं को आकर्षित कर रही है। कांग्रेस फिलहाल "गायब होती ताकत" की तरह दिख रही है। उसके पास अपने दम पर जीतने लायक सीटें नहीं हैं। लेकिन गठबंधन में रहने से राजद को उसका राजनीतिक और सामाजिक समर्थन जरूर बढ़ता है। भले ही आज PK वोटकटवा लग रहे हैं, मगर उनके अभियान और संगठनात्मक ढाँचे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर वे लगातार मेहनत करते रहे तो भविष्य में वे तीसरे मोर्चे के रूप में उभर सकता है। लेकिन 2025 का चुनाव उनके लिए नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक सफर की "परीक्षा" होगा। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। NDA का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन भाजपा का कैडर वोट टूटने से जदयू ही सबसे बड़ा विजेता बनकर उभर सकता है। INDI गठबंधन में राजद अपने मजबूत कैडर और युवाओं को लेकर चुनावी जंग में मजबूती से खड़ा है। PK का असर फिलहाल सीमित है, लेकिन उनके वोट काटने से कई सीटों पर समीकरण पलट सकते हैं। अगर चुनाव आज हो, तो परिणाम होगा NDA- 128, INDI- 109 और अन्य- 6 और असली लड़ाई उन 113 सीटों पर होगी जहाँ मामूली वोटों का अंतर भविष्य का फैसला करेगा।

मेष राशि- आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज लंबे समय से चल रही किसी समस्या से आज आपको निजात मिलेगी और आपकी चतुराई और योग्यता की सराहना होगी। आज आपको कोई शुभ सूचना मिलने वाली है, साथ ही लाभ प्राप्ति के साथ-साथ उत्साह और ऊर्जा भी महसूस होगी।

वृष राशि- आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्तिथि रखने के लिए शेड्यूल बनाएंगे और उसी के अनुरूप कार्य करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। वर्तमान परिवेश में आपने जो नई नीतियां बनाई है, इस वजह से आपकी काफी समस्याएं हल होंगी।

मिथुन राशि- आज का दिन आपके लिए ख़ास होने वाला है। आज आपकी कारोबारी गतविधियां सुचारु रूप से चलती रहेंगी। आज आपको किसी कार्य को लेकर की गई मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। आज आप किसी भी नए निवेश के बारे में प्लान करेंगे आपको अच्छा लाभ हो सकता है। आज घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन संबंधी शुभ समाचार मिलने से उत्सव का माहौल रहेगा।

कर्क राशि- आज का दिन आपके लिए ठीक – ठाक रहने वाला है। आज आप किसी नए काम की शुरुआत को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे। आज आपको किसी समस्या से छुटकारा मिलेगा और आप दोबारा आत्मविश्वास और ऊर्जा से अपने काम में लग जाएंगे। आज आप अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे। आज आपको प्रयास करने पर कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

सिंह राशि- आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज व्यवसाय में बहुत अधिक जिम्मेदारियां और काम का बोझ रहेगा, लेकिन सहकर्मियों की मदद से सब निपट जायेगा। आज आपके घर पर किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, घर में चहल – पहल बनी रहेगी। आज आप कार्यस्थल पर गंभीरता और ईमानदारी से अपने प्रोजेक्ट को पूरा करें, इस समय आपकी तरक्की के भी योग बन रहे हैं। आज किसी भी अनजान व्यक्ति पर ज्यादा विश्वास न करें, अपनी योजनाओं को गुप्त ही रखें।

कन्या राशि- आज का दिन आपके लिए फेवरेबल बना रहेगा। आज आपको किसी कानूनी समस्या का समाधान मिलेगा, जिससे आपके मन का बोझ हल्का होगा। आज आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति अथवा राजनीतिज्ञ के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा। इस राशि के छात्रो को किसी प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम अनुकूल मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

तुला राशि- आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज आप बिजनेस में अच्छा धन लाभ कमायेंगे और आपके व्यवसायिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। आज आपका व्यावहारिक दृष्टिकोण हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करेगा। अगर आपका सरकारी अथवा कोर्ट से संबंधी कोई मामला अटका हुआ है तो आज उसमें सफलता मिलने की उचित संभावना है।

वृश्चिक राशि- आज का दिन आपके लिए मिला – जुला रहने वाला है। आज किसी आयोजन की वजह से खर्च की अधिकता थोड़ी ज्यादा रहेगी। आज आप नए वाहन को खरीदने का मन बना सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी सोच में और अधिक सकारात्मकता लाने की जरूरत है। आज आपका कोई रुका काम पूरा होने से मानसिक शांति मिलेगी और आप काम करने के नए तरीकों पर विचार करेंगे।

धनु राशि- आज का दिन आपके लिए ख़ुशी से भरा रहने वाला है। आज आपको रोजगार में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आज का दिन पारिवारिक सुख-शांति में वृद्धि लेकर आएगा। आज आप किसी समस्या को सुलझाने में सफल रहेंगे और आपकी कार्यकुशलता तथा योग्यता की सराहना होगी। आज आप अपने करियर और पढ़ाई को लेकर सजग रहेंगे।

मकर राशि- आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए परिवार का सहयोग ले सकते हैं, इससे आपको साहस मिलेगा। आज का दिन पारिवारिक सुखों में वृद्धि लेकर आएगा। यदि किसी वजह से कोई उलझन बनी हुई थी, तो आज उसका भी निवारण हो जाएगा।

कुम्भ राशि- आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आपको कारोबार में दुगुना धन लाभ कमाने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा और बिजनेस की रुकावटें दूर होंगी। आज आपको इंश्योरेंस और कमीशन के बिजनेस में विशेष सफलता मिलेगी। आज आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज आपके बेटे का अच्छी जगह चयन होने से परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा।

मीन राशि- आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज किसी पॉलिसी में निवेश करने की योजना बन रही है, तो दिन शुभ है। ये निवेश आने वाले दिनों में बेहतर फायदा देने वाला रहेगा। आज आप सभी जरूरी काम आसानी से पूरा कर लेंगे। इस राशि के जो लोग किसी बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। आपको किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने का अवसर मिलेगा।

युवाओं के दबे आक्रोश का विस्फोट है नेपाल में बगावत ?

मनोज कुमार अग्रवाल

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में एकाएक जो युवा विद्रोह का तूफान आया है उसने बेहद चिंता जनक स्थिति भी पैदा कर दी है कि दुनिया का युवा वर्ग सोशल मीडिया से कितना प्रभावित है? वहां कुछ दिन पहले बात सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाए जाने से शुरू हुई थी। इसके विरोध में भारी संख्या में युवक राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने राजनीतिक नेताओं के घरों पर हमले शुरू कर दिए। ताज़ा जानकारी के अनुसार आन्दोलनकारियों द्वारा एक पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खानाल की पत्नी राजिल-लक्ष्मी चित्रकार को आग लगाकर जला दिया गया। एक और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर दिओबा के घर में दाखिल होकर आन्दोलनकारियों ने उनकी और उनकी पत्नी से मारपीट की। संसद भवन और कई अन्य इमारतों को आग लगा दी गई। सरकार को सेना बुलानी पड़ी। पुलिस और सेना की गोली से लगभग 22 व्यक्ति मारे गए और 400 से भी अधिक घायल हो गए। इन घटनाओं ने लगी आग को लपटों में बदल दिया, जिस कारण वहां राजनीति अस्थिरता चरम सीमा पर पहुंच गई है। आखिर प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली को त्याग-पत्र देने के लिए विवश होना पड़ा और वह देश छोड़ कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। ओली ने भी त्याग-पत्र देते हुए सेना को स्थिति सम्भालने के लिए कहा था। आपको बता दें कि नेपाल का मौजूदा घटनाक्रम बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है। एक तरफ वहां की भीड़ का गुस्सा लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली को लेकर है उधर दूसरी ओर मीडिया का एक धड़ा नेपाल में राजशाही की वापसी या हिन्दू राष्ट्र की वापसी का राग अलापने में लगा है। जरूरत इस समय मौजूदा घटनाक्रम पर सतर्क निगाह रखने की है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई बड़ी ताकत इस घटनाक्रम का फायदा उठाकर नेपाल को अपने नियंत्रण में ले ले। भारत के प्रधानमंत्री की चिंता इसी ओर इशारा करती है। जिसे मीडिया नजरअंदाज कर रहा है। नेपाल में जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे की वजह तलाशना बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, भाई-भतीजावाद और सोशल मीडिया पर पाबंदियों के ख़िलाफ़ तथाकथित जेन-ज़ी द्वारा संचालित नेतृत्वहीन विरोध प्रदर्शनों ने अब अराजकता का रूप ले लिया है। नेपाल अनुपातन एक छोटा-सा देश है। इसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है, परन्तु आश्चर्यजनक बात यह है कि गरीब कहे जाते इस देश के 90 प्रतिशत लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसी साधन द्वारा विरोधियों की ओर से सरकारी भ्रष्टाचार को उजागर किया जाता रहा है और यह भी कि वहां रिश्वत का बोलबाला है। लगभग 17 वर्ष पहले वर्ष 2008 में नेपालियों ने हिम्मत दिखाते हुए सैकड़ों वर्ष से चली आ रही राजाशाही का अंत कर दिया था। इसमें वामपंथी पार्टियों का बड़ा योगदान था। के.पी. शर्मा ओली भी लड़े गए इस संघर्ष में शामिल थे। उनके साथ-साथ नेपाल में मार्सी नेता पुष्प कमल दहल (प्रचंड) का भी उभार हुआ था। लगभग 10 वर्ष के लम्बे संघर्ष के बाद राजाशाही का अंत हो गया था। उसके बाद चाहे वामपंथी पार्टियों का प्रभाव बढ़ गया था परन्तु वहां की राजाशाही के समय से ही नेपाली कांग्रेस ने अपनी पूरी पैठ बनाए रखी थी। इस पूरी कशमकश में नया संविधान बनाने के लिए लम्बा समय लगा था। मार्सी नेता पुष्प कमल दहल भी प्रधानमंत्री बने। के.सी. शर्मा ओली (जो कि हमेशा से ही चीन पक्षीय रहे थे और अब भी वह चीन का ही दम भरते रहे हैं) भी प्रधानमंत्री बनते रहे, परन्तु वहां समय-समय पर होते रहे चुनावों में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत लेकर सरकार बनाने में असमर्थ रही। इसीलिए अब तक भी वहां मिलीजुली सरकार ही चलती रही है। निःसंदेह ओली इसके प्रधानमंत्री रहे हैं परन्तु इसके बावजूद बहुसंख्या में सदस्य नेपाल कांग्रेस के ही रहे हैं, परन्तु इस समय में ही ओली पर तानाशाही ढंग से सरकार चलाने का आरोप भी लगता रहा। पिछले कुछ समय में जनरेशन जैड के बैनर तले हामी नेपाल नामक एक संगठन सामने आया जिसने देश में फैली ग़रीबी और भ्रष्टाचार को अपना मुख्य लक्ष्य बनाकर लोगों को अपने साथ जोड़ने का यत्न किया। लम्बी अवधि से बन रहे संकटमय हालात के दृष्टिगत इस संगठन को भारी समर्थन मिला, परन्तु अब इस संगठन का आन्दोलन हिंसक रूप धारण कर गया है। आज हुई इस बड़ी उथल-पुथल के बाद नेपाल में अनिश्चितता बनी दिखाई देती है। सेना की ओर से कमान सम्भाले जाने की आशंका है परन्तु इसके साथ ही जनरेशन जैड काठमांडू के मेयर बलेन शाह जो कलाकार और इंजीनियर भी हैं और लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं, को यह नया संगठन अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहा है। ऐसे अनिश्चित और गड़बड़ वाले हालात में नेपाल के निकट भविष्य के हालात किस तरह के होंगे यह कहना मौजूदा समय में कठिन है परन्तु भारत के लिए नज़दीकी पड़ोसी होने के कारण ये हालात चिन्ताजनक ज़रूर हैं। पिछले कुछ वर्षों से इसके नज़दीकी पड़ोसी ऐसे हालात में से ही गुज़रते दिखाई दे रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान के अतिरिक्त बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका भी शामिल हैं। भारत को इस कारण भी अधिक सचेत रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसी की भांति चीन भी नेपाल का पड़ोसी है और आज शक्तिशाली बन चुके चीन के दशकों से नेपाल के प्रति इरादे क्या हैं, उन्हें भी दुनिया जानती है। निःसंदेह इस समय नेपाल एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। आपको बता दें कि आंदोलन के हिंसक होने के बाद नेपाल जिस तरह से अराजकता की ओर बढ़ा है। वह चिंता का विषय है। युवाओं के नेतृत्व में काठमांडू में भड़के विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली का इस्तीफा हो जाने के बाद जो आंदोलन शांत होना था वह और भड़क गया जिसका मतलब है उद्देश्य कुछ और है। उप-प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को प्रदर्शनकारियों द्वारा पीटा जाना, पूर्व प्रधानमंत्री खनल की पत्नी को आग के हवाले कर देना जैसी घटनाएं खतरनाक हालात के संकेत देने को काफी हैं और अब नेपाल के सेना प्रमुख का बांग्लादेशी विद्रोह की याद दिलाते हुए एक राजनीतिक शून्य के बीच सत्ता संभालने के लिए तैयार हो जाना उनके साथ नेपाल के पहले राजा की तस्वीर कुछ और संकेत दे रही है। खास बात यह है कि ओली हाल ही में चीन से लौटे हैं और सितंबर के अंत में भारत यात्रा पर आने वाले थे.इस समय यह नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी कि इसके पीछे कोई बाहरी ताकत है. लेकिन नेपाल लंबे समय से अस्थिर चल रहा है जिसका फायदा उठाने के लिए अब बाहरी और घरेलू ताकतें सक्रिय हो सकती हैं नेपाल की मौजूदा अशांति को लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि ओली चीन समर्थक हैं, इसलिए इसमें अमेरिका की भूमिका हो सकती है, जैसे बांग्लादेश में हुआ था. दूसरी ओर, कुछ का मानना है कि चीन विरोध को भड़का रहा है, ताकि अमेरिका के एमसीसी निवेश को कमजोर किया जा सके. फिलहाल इस विषय पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। भारत को नेपाल के घटनाक्रम पर सतर्क निगाह रखनी होगी। और कठोर कदम उठाने को तैयार रहना होगा

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

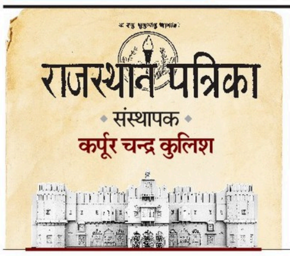

संसदीय गरिमा को और मजबूती मिलने की उम्मीद

देश के नए उपराष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन चुन लिए गए हैं। राजग ने जब उनकी उम्मीदवारी घोषित की थी तो कई दिग्गजों की चर्चा के बीच राधाकृष्णन का नाम कई लोगों के लिए अप्रत्याशित था लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ चुनाव ऐसे होते हैं, जो सिर्फ पदों की पूर्ति भर के लिए नहीं होते, बल्कि व्यापक संकेतों और भविष्य की रणनीति के प्रतीक होते हैं। सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति चुना जाना भी कुछ ऐसा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व ने उनका इस पद के लिए चयन कर राजनीति में सरप्राइज फैक्टर वाली रणनीति से सभी को एक बार फिर परिचित कराया।

आंकड़ों के गणित के हिसाब से राजग प्रत्याशी राधाकृष्णन का चुनाव निश्चित ही था। सिर्फ बीजद और शिरोमणि अकाली दल जैसे राजनीतिक दलों की ओर से वोटिंग से अलग रहने के फैसले के कारण उनकी जीत का अंतर ही महत्त्वपूर्ण रह गया था। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े रहे राधाकृष्णन तमिलनाडु में पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं। इस संवैधानिक पद पर उनका चुना जाना पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी संदेश देने वाला है कि कर्तव्यनिष्ठा, सादगी और ईमानदार छवि के बूते कोई भी कार्यकर्ता उच्च संवैधानिक पदों पर पहुंच सकता है। सियासी तौर पर देखें तो राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति चुना जाना भाजपा की दक्षिण की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय तक द्रमुक और अन्नाद्रमुक के इर्द-गिर्द घूमती रही। राधाकृष्णन के चुने जाने के बाद भाजपा यह दिखाने की कोशिश करेगी कि तमिलनाडु की आवाज देश के सर्वोच्च मंचों पर सुनी जा रही है। ऐसे में यह निर्वाचन भाजपा के दक्षिण के अभियान को बल दे सकता है। राधाकृष्णन के राज्यपाल रहते हुए भी छवि विवादरहित रही है। उनके बारे में माना जाता है कि वे आपसी सहमति और सबको साथ लेकर चलने वाले लोगों में है। राज्यसभा के नए सभापति के रूप में राधाकृष्णन के सामने चुनौतियां कम नहीं रहने वाली। असली चुनौती राज्यसभा का बाधारहित संचालन करने की होगी। वह भी ऐसे दौर में जब पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार के चलते संसद में कामकाज ठप होने के मौके आए दिन सामने आते रहे हैं। उन्हें विपक्ष को भी यह विश्वास दिलाना होगा कि सदन में उनकी बात सुनी जाएगी। साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही को अधिक समावेशी और उत्पादक बनाना होगा। उपराष्ट्रपति केवल संसद के ऊपरी सदन के सभापति ही नहीं होते, बल्कि वह देश के दूसरे सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर आसीन होते हैं।

उम्मीद की जानी चाहिए कि नए उपराष्ट्रपति की शालीनता और उनका संगठनात्मक अनुभव संसदीय शुचिता बनाए रखने में मददगार साबित होगा। राज्यसभा के माध्यम से उनके नेतृत्व में संसदीय गरिमा को न केवल और मजबूती मिलेगी, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्य भी सशक्त होंगे।

कर्पूर चन्द्र कुलिश
जन्म शताब्दी वर्ष
भाग -25

आज भी लाखों कन्नड़ भाषी लोग संस्कृत का प्रयोग करते हैं। संस्कृत की इस भाव भूमि में हिन्दी के प्रसार में वहां विशेष बाधा नहीं होनी चाहिए।

राजकाज और सामान्य व्यवहार की भाषा हिन्दी

अंग्रेजी को कानूनी रूप से बनाए रखना बेमानी

अपनी अमरीका यात्रा के दौरान हिन्दी की पैरवी हो या पत्रिका का कर्नाटक की राजधानी बंगलौर (अब बेंगलूरु) से प्रकाशन, कुलिश जी ने सदैव हिन्दी की गरिमा बढ़ाने के प्रयास किए। उनके ये प्रयास आजादी के तत्काल बाद उस वक्त ही शुरू हो गए थे जब पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए सिंधी भाषी लोगों को उन्होंने हिन्दी सिखाने का बीड़ा उठाया। हिन्दी दिवस (14 सितंबर) के मौके पर कुलिश जी के इन प्रयासों की झलकः

मुझसे अमरीका में पत्रकारों ने पूछा कि भाषायी समस्या का भारत में क्या रूप है? मैंने पहले तो यही कहा कि इस समस्या को दो टूक नहीं समझाया जा सकता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारत की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। सवाल यह भी था कि आप किस भाषा के पक्ष में हैं। भारतीय भाषा के पक्ष में अथवा हिन्दी भाषा के पक्ष में। मैंने समझाने का प्रयत्न किया कि भारतीय भाषाओं में हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो राजकाज एवं सामान्य व्यवहार की भाषा बन सकती है। मैं स्वयं सभी भारतीय भाषाओं के विकास की कामना करता हूं। हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं का प्रश्न अन्तर्विरोधी नहीं है। विभिन्न भाषायी राष्ट्रों को इसी रूप में समस्या का निदान खोजना होगा।

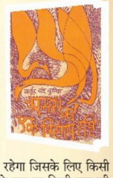

एक सवाल यह भी था कि क्या आपकी राय है कि अंग्रेजी को भारत में समाप्त कर दिया जाए। मैंने कहा- नहीं। अंग्रेजी समाप्त किए जाने की संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन भारतीयों को आपसी व्यवहार में अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। उच्च शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यवहार, और व्यापार में उसका प्रयोग होता रहेगा जिसके लिए किसी कानूनी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी के ज्ञान पर किसी तरह की रोकथाम नहीं हो किन्तु उसको कानूनी रूप से बनाए रखना बेमानी है। इस बीच एक साहब ने पूछा - आप इस समस्या का हल क्या सोचते हैं। मैंने कहा- हल करने का संकल्प चाहिए जो हमारी सरकार में नहीं है। दृढ़ संकल्प के अभाव में कोई विकल्प भी नहीं है।

*16 मई 1968 को अमरीका में पत्रकारों से संवाद के दौरान (**'अमरीका एक विहंगम दृष्टि'** पुस्तक से)*

उत्तर-दक्षिण के बीच सेतु है पत्रिका

राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन कर्नाटक राज्य में दक्षिण भारत के प्रमुख नगर बंगलौर से भी प्रारम्भ होना सचमुच ही एक बड़ी घटना है। बंगलौर का यह प्रकाशन सीमोल्लंघन की परिभाषा में आता है। पत्रिका का यह भूमाभाव है जो उसे अधिकाधिक विस्तार दे रहा है। मेरे लिए इसका महत्व इसलिए भी है कि यह मेरे योगदान के बिना हो रहा है। इससे अधिक प्रसन्नता क्या हो सकती है? पाठकों के लिए यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण कि उनका प्रिय समाचार पत्र राष्ट्रीय ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहा है। राजस्थान पत्रिका अपने नाम में निहित भौगोलिक सीमाओं को लांघ रही है, यही राष्ट्रीय बनने की पहल है। राजस्थान पत्रिका का बंगलौर से प्रकाशन हिन्दी माध्यम से उत्तर- दक्षिण की भौगोलिक, राजनीतिक एवं मानसिक दूरी को पाटने में एक सेतु का काम करेगा और भारत के दोनों छोरों के बीच आदान प्रदान का हेतु बनेगा। राजस्थान पत्रिका हिन्दी की मुख्य धारा के प्रवाह को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाने का साधन बनेगी। वैसे कर्नाटक को तो अहिन्दी भाषी कहना भी पूर्णतः उचित नहीं होगा। एक पीढ़ी पहले तो कर्नाटक की मुख्य भाषा ही संस्कृत थी और आज भी लाखों कन्नड़ भाषी लोग संस्कृत का प्रयोग करते हैं। संस्कृत की इस भाव भूमि में हिन्दी के प्रसार में वहां विशेष बाधा नहीं होनी चाहिए। कन्नड़ भाषा में भी संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं और पड़ोस की दूसरी भाषाओं में भी तद्‌भव रूप में संस्कृत के शब्द हैं। कर्नाटक के साथ दक्षिण के अन्य राज्यों में हिन्दी भाषी भी दिन दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वहां लाखों की संख्या में स्थानीय लोग भी हिन्दी पढ़ते जा रहे हैं। उत्तर से सम्पर्क रखने में हिन्दी ही एकमात्र माध्यम है।

(3 मई 1995 को ***'पत्रिका के बंगलौर संस्करण की शुरुआत पर अग्रलेख के अंश***

..और शुरू हुआ हिन्दी पढ़ाने का क्रम

विभाजन के बाद बहुत सारे पंजाबी और सिंधी परिवार जयपुर में आकर बस गए थे। पंजाबी तो हिन्दी और उर्दू जानते थे इसलिए वे तो समाज में घुल-मिल गए। सिंधियों को भाषा संबंधी परेशानियां हो रही थी। मेरे एक सिंधी शरणार्थी मित्र की भावना थी कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के माध्यम से यदि सिंधियों को हिन्दी पढ़ाने का काम शुरू किया जाए तो इस समस्या का काफी हद तक निदान हो सकता है। साहित्य सदावर्त में पढ़ा चुकने का मेरा अनुभव भीतर ही भीतर हिलोरें मार रहा था। मैंने उन्हें स्वीकृति दे दी। राज्य सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के बाद खाली समय में पढ़ाने का क्रम शुरू हो गया। दरबार स्कूल, महाराजा स्कूल में सिंधी लोगों को हिन्दी पढ़ाने का कार्य मैं करने लगा। भाषा और व्याकरण की शुद्धता तो शुरू से ही थी। कुछ धीरे-धीरे पढ़ाने के अनुभव ने ज्ञान बढ़ाया। यह सन 1948-49 की बात होगी। मुझे 21-22 की उम्र में ही बड़े-बड़े कवियों से मिलने का-सुनने का अवसर भी मिला।

*(कुलिश जी के आत्मकथ्य आधारित पुस्तक **'धाराप्रवाह'** से)*

(जारी... कुलिश जी का सृजन संसार पढ़ें आगामी गुरुवार को भी)

जन्मदिवस विशेष : मोहन भागवत जी हर कठिन परिस्थिति को सहजता और सटीकता से संभालते हैं

एक प्रचारक से सरसंघचालक तक: निष्ठा और नेतृत्व की अद्‌भुत यात्रा

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री
@patrika.com

आज 11 सितंबर है। यह दिन अलग-अलग स्मृतियों से जुड़ा है। एक स्मृति 1893 की है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व बंधुत्व का संदेश दिया और दूसरी स्मृति है 9/11 का आतंकी हमला, जब विश्व बंधुत्व को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। आज के दिन की एक और विशेष बात है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्मदिवस है, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है।

संघ परिवार में, जिन्हें परम पूजनीय सरसंघचालक के रूप में श्रद्धाभाव से संबोधित किया जाता है, ऐसे आदरणीय मोहन भागवत जी का आज जन्मदिन है। यह एक सुखद संयोग है कि इसी साल संघ भी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। मैं भागवत जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। मेरा मोहन भागवत जी के परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है।

मुझे उनके पिता, स्वर्गीय मधुकरराव भागवत जी के साथ निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। मैंने अपनी पुस्तक ज्योतिपुंज में मधुकरराव जी के बारे में विस्तार से लिखा भी है। वकालत के साथ-साथ मधुकरराव जी जीवनभर राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित रहे। अपनी युवावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ कार्य की मजबूत नींव रखी। मधुकरराव जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि अपने पुत्र मोहनराव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे। एक पारसमणि मधुकरराव ने मोहनराव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी।

भागवत जी का पूरा जीवन सतत प्रेरणा देने वाला रहा है। वे 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। सामान्य जीवन में प्रचारक शब्द सुनकर ये भ्रम हो जाता है कि कोई प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन जो संघ को जानते हैं उनको पता है कि प्रचारक परंपरा संघ कार्य की विशेषता है। गत 100 वर्षों में देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक-युवतियों ने अपना घर-परिवार त्याग कर पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। भागवत जी भी उस महान परंपरा की मजबूत धुरी हैं।

भागवत जी ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उस दौर में प्रचारक के रूप में भागवत जी ने आपातकाल-विरोधी आंदोलन को निरंतर मजबूती दी। उन्होंने कई वर्षों तक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों, विशेषकर विदर्भ में काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में मोहन भागवत जी के कार्यों को आज भी कई स्वयंसेवक स्नेहपूर्वक याद करते हैं। इसी कालखंड में मोहन भागवत जी ने बिहार के गांवों में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने के कार्य में समर्पित रहे।

वर्ष 2000 में वे सरकार्यवाह बने और यहां भी भागवत जी ने अपनी अनोखी कार्यशैली से हर कठिन परिस्थिति को सहजता और सटीकता से संभाला। 2009 में वे सरसंघचालक बने और आज भी अत्यंत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। भागवत जी ने राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को हमेशा सर्वोपरि रखा। सरसंघचालक होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है। यह एक पवित्र विश्वास है, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी दूरदर्शी व्यक्तित्वों ने आगे बढ़ाया है और इस राष्ट्र के नैतिक और सांस्कृतिक पथ को दिशा दी है। असाधारण व्यक्तियों ने इस भूमिका को व्यक्तिगत त्याग, उद्देश्य की स्पष्टता और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण के साथ निभाया है। यह गर्व की बात है कि मोहन भागवत जी ने न केवल इस विशाल जिम्मेदारी के साथ पूर्ण न्याय किया है, बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति, बौद्धिक गहराई व सहृदय नेतृत्व भी जोड़ा है।

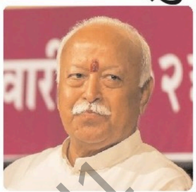

भागवत जी का युवाओं से सहज जुड़ाव है और इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ कार्य के लिए प्रेरित किया है। वे लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं और संवाद करते रहते हैं। श्रेष्ठ कार्य पद्धति को अपनाने की इच्छा और बदलते समय के प्रति खुला मन रखना, ये मोहनजी की बहुत बड़ी विशेषता रही है। अगर हम व्यापक संदर्भ में देखते हैं तो संघ की 100 साल की यात्रा में भागवत जी का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। चाहे वो गणवेश परिवर्तन हो, संघ शिक्षा वर्गों में बदलाव हो, ऐसे अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन उनके निर्देशन में संपन्न हुए। इस वर्ष की शुरुआत में, नागपुर में उनके साथ माधव नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के दौरान मैंने कहा था कि संघ अक्षयवट की तरह है, जो राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है।

इस अक्षयवट वृक्ष की जड़ें इसके मूल्यों की वजह से बहुत गहरी और मजबूत हैं। इन मूल्यों को आगे बढ़ाने में जिस समर्पण से मोहन भागवत जी जुटे हुए हैं, वो हर किसी को प्रेरणा देता है। पिछले दिनों देश में जितने सफल जन-आंदोलन हुए चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मोहन भागवत जी ने पूरे संघ परिवार को इन आंदोलनों में ऊर्जा भरने के लिए प्रेरित किया।

मैं पर्यावरण से जुड़े प्रयासों और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को जानता हूं। मोहन जी का बहुत जोर आत्मनिर्भर भारत पर भी है। कुछ ही दिनों में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो जाएगा।

यह भी सुखद संयोग है कि विजयादशमी का पर्व, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और संघ का शताब्दी वर्ष एक ही दिन आ रहे हैं। यह भारत और विश्वभर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघचालक हैं, जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। एक युवा स्वयंसेवक से लेकर सरसंघचालक तक की उनकी जीवन यात्रा उनकी निष्ठा और वैचारिक दृढ़ता को दर्शाती है। विचार के प्रति पूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन करते हुए उनके नेतृत्व में संघ कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है।

मैं मां भारती की सेवा में समर्पित मोहन भागवत जी के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की पुनः कामना करता हूं। उन्हें जन्मदिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं।

मिशिगन में खेत की खुदाई में निकला प्राचीन मैमथ

साल 2015 में मिशिगन के लीमा टाउनशिप में किसान जेम्स ब्रिस्टल अपने खेत में नाली पाइप बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी उनकी मशीन आठ फीट गहराई पर किसी कठोर वस्तु से टकराई। एक तीन फुट लंबा विशालकाय जीवाश्म निकला, जो किसी गाय की हड्डी से कहीं बड़ा था। यह अवशेष निकला एक प्रागैतिहासिक मैमथ का, जो लगभग 12 से 15 हजार साल पहले इस धरती पर विचरण करता था। विशेष बात यह थी कि यह खोज इतनी अच्छी स्थिति में मिली कि वैज्ञानिकों के लिए बेहद मूल्यवान साबित हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के पैलियॉन्टोलॉजिस्ट्स ने केवल एक दिन में सावधानी से खुदाई पूरी कर मैमथ की खोपड़ी, दांत, रीढ़, पसलियां और अन्य हड्डियां निकालीं।

प्रसंगवश

प्रदेश के सरकारी स्कूलों की इमारतें बदहाल क्यों?

पहले घोर लापरवाही और बाद में लीपापोती के प्रयास करना सिस्टम का अंग हो चला है। राजस्थान में भारी बरसात के दौरान स्कूल की जर्जर इमारतों के क्षतिग्रस्त होने व बच्चों की जान तक लाने के बाद ऐसी ही लीपापोती को हाईकोर्ट ने आईना दिखाया है। सरकार की ओर से सफाई दी गई कि ऐसे स्कूल भवनों में पढ़ रहे बच्चों के लिए अब टेंट अथवा टीन-शेड का इंतजाम किया गया है। हैरत की बात यह है कि सरकार खुद अपनी जांच में यह पता लगा चुकी है कि प्रदेश में लगभग 86 हजार कक्षा-कक्ष जर्जर स्थिति में हैं। यह हमारे उस शिक्षा तंत्र की तस्वीर है, जिस पर सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 15-18 सितंबर के बीच स्कूलों का औचक निरीक्षण कर 19 सितंबर को रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, कोर्ट ने इन वैकल्पिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक व बच्चों के अनुकूल बनाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं।

बड़ा सवाल यही है कि हमारे यहां स्कूल खुलने के साथ ही यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया जाता कि वहां के कक्षा-कक्ष पढ़ाई-लिखाई कराने योग्य हैं या नहीं। इससे बड़ी विडम्बना यह है कि शिक्षा जैसी बुनियादी व्यवस्था को दुरुस्त करने में भी न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। यह न केवल प्रशासनिक चूक है, बल्कि सामाजिक अपराध भी है। सुरक्षित और गरिमामय शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। स्कूल भवन निर्माण व इनकी मरम्मत के लिए केवल बजट पास करना ही काफी नहीं, बल्कि निगरानी जरूरी है। जर्जर भवनों की मरम्मत प्राथमिकता में होनी चाहिए। **- शरद शर्मा**

sharad.sharma@in.patrika.com

नेपाल में जेन-जी आंदोलन | दीर्घकालीन समाधान तो केवल राजनीतिक संवाद से ही निकलेगा

यह आंदोलन क्षणिक गुस्सा नहीं, गहरे बदलाव की मांग है

के.एस. तोमर
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक एवं स्तंभकार
@patrika.com

यदि काठमांडू ने आंतरिक घावों को जल्द नहीं भरा, तो नेपाल बांग्लादेश जैसी अस्थिरता की राह पर फिसल सकता है। बहुलतावादी राजनीति और सशक्त नागरिक समाज की वजह से उसके पास अब भी हालात को सुधारने का अवसर है।

नेपाल इस समय बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। जनाक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा है और लोकतंत्र की नींव हिलती नजर आ रही है। यह संकट केवल बल प्रयोग से नहीं सुलझेगा। इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक संवाद को प्राथमिकता दी जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएं, अर्थव्यवस्था में सुधार किए जाएं और डिजिटल स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए।

हालांकि 'गुप्त ताकतों' के षड्यंत्रों की चर्चाएं जरूर हो रही हैं, लेकिन आंदोलन की जड़ें घरेलू असंतोष में ही नजर आती हैं। विदेशी शक्तियां इसका लाभ उठाने की कोशिश कर सकती हैं, पर इसकी बुनियादी वजह जनता की लंबे समय से उपेक्षित मांगें हैं। नए शासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह हिंसक और नेता-विहीन भीड़ के बीच से ऐसे प्रतिनिधियों की पहचान करे, जिनसे बातचीत शुरू कर स्थिति को सामान्य किया जा सके। सेना की तैनाती ने राज्य व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त होने से बचाया, लेकिन दीर्घकालीन समाधान तो केवल राजनीतिक संवाद से ही निकलेगा। भारत और चीन दोनों इस संकट को गहरी नजर से देख रहे हैं। उनकी प्राथमिकता केवल स्थिरता बनाए रखना है, परिणाम को प्रभावित करना नहीं। यदि काठमांडू ने आंतरिक घावों को जल्द नहीं भरा, तो नेपाल बांग्लादेश जैसी अस्थिरता की राह पर फिसल सकता है। फिर भी, अपनी बहुलतावादी राजनीति और सशक्त नागरिक समाज की वजह से नेपाल के पास अब भी हालात को सुधारने का अवसर है, बशर्ते सुधारों को गंभीरता से लागू किया जाए। नेपाल में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित रणनीति की जरूरत है- संवाद, भ्रष्टाचार पर प्रहार, आर्थिक नवीनीकरण और डिजिटल स्वतंत्रता का संरक्षण।

सरकार, विपक्ष और आंदोलनकारियों के बीच संरचित बातचीत तुरंत शुरू होनी चाहिए। यह संवाद किसी तटस्थ मंच, जैसे नागरिक समाज की मध्यस्थता से संभव है। बातचीत को औपचारिकता तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसमें ठोस समयसीमा और लागू किए जा सकने वाले परिणाम तय हों। भ्रष्टाचार नेपाल की राजनीति की सबसे घातक बीमारी है। जनता अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं होगी। स्वतंत्र भ्रष्टाचार-निरोधक संस्थाओं को मजबूत करना, न्यायपालिका को निष्पक्ष बनाना और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना जरूरी है। सभी दलों के भ्रष्ट नेताओं पर सख्त कार्रवाई जनता को संदेश देगी कि सुधार केवल नारा नहीं, बल्कि हकीकत है। लगभग हर वरिष्ठ नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कुप्रशासन से असंतोष चरम पर है। असमानता, जलवायु संकट और आपदाओं ने युवाओं को बड़े पैमाने पर पलायन को मजबूर कर दिया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल की 82 प्रतिशत कार्यशक्ति असंगठित क्षेत्र में है, जो वैश्विक और क्षेत्रीय औसत से कहीं अधिक है। रोजगार सृजन, खासकर युवाओं के लिए सबसे अहम है। बुनियादी ढांचे, पर्यटन और जलविद्युत में निवेश से संभावनाएं खुल सकती हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने और नौकरशाही की जटिलताओं को कम करने के लिए सुधार आवश्यक हैं। महंगाई पर नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा भी प्राथमिकता में शामिल हो।

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ने युवाओं और सत्ता के बीच गहरी खाई उजागर की है। डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं, बल्कि छोटे कारोबार और नवाचार के लिए जीवनरेखा हैं। इन्हें बहाल करना और भविष्य में सुरक्षा देना जनता का विश्वास वापस पाने के लिए अनिवार्य है। दमन के बजाय सरकार को साइबर साक्षरता कार्यक्रम और ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जो अफवाहों को रोकें लेकिन स्वतंत्रता को न कुचलें। नेपाल का यह संकट केवल एक फैसले से पैदा नहीं हुआ, भले ही सोशल मीडिया पर प्रतिबंध इसका तात्कालिक कारण था। 1990 में लोकतंत्र की बहाली और 2006 में राजशाही की समाप्ति ने जनता में उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन रोजगार, पारदर्शिता और जवाबदेही में सरकारें नाकाम रहीं। भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और ठहरी हुई अर्थव्यवस्था ने लोगों को निराश कर दिया। युवाओं के लिए यह प्रतिबंध केवल डिजिटल स्वतंत्रता पर हमला नहीं था, बल्कि शासकों द्वारा विफलताओं को छिपाने की कोशिश भी प्रतीत हुआ।

आंदोलन मुख्यतः घरेलू शिकायतों से उपजा है। इसमें विश्वविद्यालय के छात्र, बेरोजगार स्नातक और शहरी युवा आगे रहे। यह किसी स्थापित राजनीतिक दल के नियंत्रण में नहीं, जिससे यह तेज और अप्रत्याशित बन गया। फिर भी, नेपाल की भौगोलिक स्थिति उसे बाहरी प्रभावों के लिए संवेदनशील बनाती है। भारत और चीन दोनों सतर्क हैं ताकि अस्थिरता उनकी सीमाओं या परियोजनाओं को प्रभावित न करे। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा आंदोलन की एक विशेषता यह है कि इसमें भारत विरोधी नारों की पूरी तरह अनुपस्थिति है। नेपाल की सेना को हमेशा स्थिरता का प्रतीक माना गया है। उसकी तैनाती ने हालात काबू में किए, पर लंबे समय तक सुरक्षा बलों पर निर्भरता सेना की साख को भी खतरे में डाल सकती है। हिंसा को सीमित करना सेना कर सकती है, पर मूल समस्याओं का हल केवल राजनीतिक नेतृत्व के पास है। विश्लेषकों ने नेपाल की स्थिति की तुलना बांग्लादेश से की है, लेकिन फर्क यह है कि नेपाल की राजनीति अधिक बहुलतावादी है और नागरिक संगठन सक्रिय हैं। यही विविधता सुधारों के लिए अवसर देती है।

यह आंदोलन केवल क्षणिक गुस्सा नहीं, बल्कि गहरे बदलाव की मांग है। सवाल यह है कि क्या नेपाल का नेतृत्व इस चुनौती को अवसर में बदल पाएगा या इतिहास में उस पीढ़ी के रूप में दर्ज होगा जिसने लोकतंत्र के वादे को व्यर्थ कर दिया।

आपकी बात

इच्छाशक्ति और संकल्प जरूरी

बजरी और खनन माफिया पर अंकुश के लिए सबसे पहले अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत व गठजोड़ को तोड़ने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्ट आचरण का सहारा लेने वाले अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए सख्त नीतियां बनानी होंगी और अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस व प्रशासन की जवाबदेही तय करनी होगी। इसके लिए सरकार की इच्छाशक्ति और संकल्प जरूरी है। **- शिवजी लाल मीना,** जयपुर

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'बजरी और खनन माफिया पर अंकुश के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?' अन्य प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/MFF6Z

आज का सवाल

देशभर में आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर अंकुश के लिए किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 11 सितम्बर • 2025
www.rashtriyasahara.com

भगवा भाव न हो

एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। उनके पक्ष में 452 वोट पड़े। कुल 767 सांसद इस वोटिंग में शामिल हुए। 15 वोट अमान्य कर दिए गए। विपक्ष के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी थे, जिन्हें तीन सौ फर्स्ट प्रिफरेंस वोट मिले। राधाकृष्णन की जीत पहले से ही तय थी क्योंकि संख्या बल एनडीए के पक्ष में था। हालांकि क्रॉस वोटिंग का संदेह व्यक्त किया जा रहा था। उपचुनाव के लिए कुल 98.2% वोटिंग हुई। तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। 1974 में जनसंघ की कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। 1996 में तमिलनाडु भाजपा के सचिव बने। उसके बाद दो बार सांसद चुने गए पर कोयंबटूर से तीन बार हार का सामना भी किया। 2020-22 तक भाजपा

केरल के चुनाव प्रभारी रहे। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बनाए गए। फिर 2024 में उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। जुलाई में तब के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था। साठ दिन के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। इसके लिए चुनाव आयोग निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है, जो किसी सदन का महासचिव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होता है, जिसमें राज्य सभा और लोक सभा के सांसद शामिल होते हैं। मनोनीत सांसद भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। राधाकृष्णन को दक्षिण भारत में भाजपा के विस्तार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। विनम्र, मेधावी, मिलनसार और समाज सेवा को समर्पित राधाकृष्णन की तारीफ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कह चुके हैं कि उन्हें खेलों में गहरी रुचि है पर वे राजनीति में खेल नहीं खेलते। कपड़ा उद्योग के माहिर व्यवसायी राधाकृष्णन तमिलनाडु में हिन्दुत्व की विचारधारा का नेतृत्व करते रहे हैं। इसलिए विपक्ष में सुगबुगाहट होना लाजिमी है कि उनका झुकाव धर्म विशेष की तरफ हो सकता है। दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने को बेताब भाजपा के लिए यह दूर की कौड़ी भी साबित हो सकती है। हालांकि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के दामन पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या पक्षपात जैसे आरोपों के छींटें नहीं हैं मगर कोयंबटूर में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता। संवैधानिक पदों पर रह चुके सीपी राधाकृष्णन अपने पूर्ववर्ती से अधिक माहिर और पारदर्शी हो सकते हैं।

कनाडा में टेरर फंडिंग

आतंकवाद के वित्त पोषण पर कनाडा में जारी एक रपट में खुलासा हुआ है कि कम से कम दो खालिस्तानी चरमपंथी गुटों को कनाडा से वित्तीय सहायता मिल रही है। '2025 असेसमेंट ऑफ मनीलॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क इन कनाडा' नाम से जारी इस रपट में जिन चरमपंथी समूहों के नाम दिए गए हैं, उनमें दो संगठन-बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन-भी शामिल हैं। चिंता की बात यह है कि ये संगठन गैर-लाभकारी और धर्मार्थ गतिविधियों के लिए धन बता कर उसका अपने मंसूबे पूरे करने में इस्तेमाल करते हैं। इस रपट के सनसनीखेज खुलासे से नई दिल्ली के इन दावों की पुष्टि होती दिख रही है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्व बिना रोक-टोक के भारत विरोधी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। यह कोई पहली रपट नहीं है जिसने आंख खोल देने वाले खुलासे किए हैं। इससे पहले ओटावा की खुफिया एजेंसी ने भी 1980 के दशक में जारी अपनी एक रपट में खुलासा

किया था कि कनाडा में राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसक चरमपंथ का खतरा खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा भारत के पंजाब में खालिस्तान नाम से स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश के तहत उत्पन्न हुआ था। इसके बाद कनाडा सरकार ने भी एक रपट जारी की जिसमें शंका जताई गई थी कि चरमपंथियों ने धार्मिकता का चोला ओढ़ लिया है। दरअसल, चरमपंथी संगठन, जिनमें हमास, हिज्बुल्ला जैसे मुस्लिम संगठन भी शामिल हैं, अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं। बैंकिंग तंत्र के दुरुपयोग, क्रिप्टोकरंसी के इस्तेमाल के अलावा ये संगठन सरकारी वित्त-पोषित नीतियों और कार्यक्रमों में भी सेंध लगा कर धन जुगाड़ने में पीछे नहीं रहते। धर्मार्थ और गैर-लाभकारी संगठनों का दुरुपयोग तो करते ही हैं, यहां तक कि आपराधिक गतिविधियों से भी धन जुटाते हैं। परेशानकुन यह कि ये संगठन कनाडा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ब्रिटेन समेत कई देशों तक फैले हुए हैं। अलबत्ता, कनाडा में उग्रपंथी खालिस्तानी संगठनों के लिए मुफीद स्थिति इसलिए है कि वहां आबादी में काफी बड़ा हिस्सा सिखों का है, जो सरकार बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए सरकार भी नरम रवैया अपनाती है। इतना कि भारत जैसे देशों से अपने संबंधों के बिगाड़ तक की हद तक जा पहुंचती है।

कटाक्ष/ सहीराम

एक और सिंहासन खाली हुआ

अपने अड़ोस-पड़ोस में धड़ाधड़ सिंहासन खाली हुए जा रहे हैं जी। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। अपने यहां तो दावा पचास साल सत्ता में रहने का है। लेकिन क्या पता जी, जो सिंहासन खाली हुए, उन पर बैठने वालों का भी दावा तो कुछ-कुछ ऐसा ही था। वो किसी शायर ने कहा है न कि जो तुमसे पहले यहां तख्तनशीं था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीं था। खैर जी, पहले लड़ाइयां लंबी लड़ी जाती थीं। चाहे आजादी की लड़ाइयां हों, तानाशाही के खिलाफ या क्रांति के लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाइयां हों। बरसों चलती थीं। लेकिन अब तो चुटकियों में सिंहासन खाली होते हैं जी। अरब स्प्रिंग से सिलसिला शुरू हुआ था और नेपाल तक आ पंहुचा है। कहते हैं कि यह सोशल मीडिया का कमाल है। चुटकियों में क्रांति हो जाती है। लेकिन फिर उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। जैसे लीबिया अस्थिर हो जाता है, वहां गृह युद्ध छिड़ जाता है, सीरिया में कोई आतंकवादी आकर सत्तासीन हो जाता है, मिस्र में फिर तानाशाही जमने लगती है और बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी हो जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि नेपाल में भी राजशाही फिर लौट आए। जैसी क्रांति, वैसा फल।

अच्छी बात यही है कि इन देशों की जनता का तो चाहे कुछ बनता न हो और बनने की बजाय बिगड़ता ही ज्यादा हो, पर पश्चिम की पूंजी का, उसके प्रभुत्व का कुछ न बिगड़ता बल्कि बनता ही ज्यादा है। वो क्या कहते हैं पंजाबी में बल्ले-बल्ले हो जाती है। लेकिन चलो अच्छी बात है कि जेन जी के नाम भी एक क्रांति दर्ज हो गयी। वरना तो अभी तक उस पर यही आरोप था कि रील देखने-बनाने के अलावा उसे तीसरा काम नहीं आता। चिंता की बात यही है कि अपने यहां का वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा वहां पंहुच गया। बस, थोड़ा बदल कर पंहुचा-ओली चोर गद्दी छोड़। इससे साबित होता है कि यह आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ भी था। फिर अपने यहां बॉलीवुड वाला नेपो किड का नारा भी वहां पंहुच गया। इससे साबित होता है कि भाई-भतीजावाद भी वहां खूब है। अब बालेन शाह, रवि लामिछाने और सुदुन गुरूंग नये नेता हैं, जिनमें कोई रैपर है, टीवी स्टार है, और एनजीओ चलाने वाला है। अगर राजशाही नहीं लौटी तो इन्हीं में से कोई नेपाल का नया जेलेंस्की होगा। मुबारक हो!

अनमोल वचन

जहां सम्मान है वहां डर है, पर ऐसी हर जगह सम्मान नहीं है, जहां डर है, क्योंकि संभवतः डर सम्मान से ज्यादा व्यापक है।

-सुकरात

समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व

आज 11 सितंबर है। यह दिन अलग-अलग स्मृतियों से जुड़ा है। एक स्मृति 1893 की है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्वबंधुत्व का संदेश दिया और दूसरी स्मृति है 9/11 का आतंकी हमला, जब विश्व बंधुत्व को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। आज के दिन की एक और विशेष बात है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्मदिवस है जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। संघ परिवार में जिन्हें परम पूजनीय सरसंघचालक के रूप में श्रद्धाभाव से संबोधित किया जाता है, ऐसे आदरणीय मोहन भागवत जी का आज जन्मदिन है। यह एक सुखद संयोग है कि इसी साल संघ भी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। मैं भागवत जी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें।

मेरा मोहन भागवत जी के परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। मुझे उनके पिता, स्वर्गीय मधुकरराव भागवत जी के साथ निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। मैंने अपनी पुस्तक ज्योतिपुंज में मधुकरराव जी के बारे में विस्तार से लिखा भी है। वकालत के साथ-साथ मधुकरराव जी जीवनभर राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित रहे। अपनी युवावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ कार्य की मजबूत नींव रखी। मधुकरराव जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि अपने पुत्र मोहनराव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे। एक पारसमणि मधुकरराव ने मोहनराव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी। भागवत जी का पूरा जीवन सतत प्रेरणा देने वाला रहा है। वे 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। सामान्य जीवन में प्रचारक शब्द सुनकर ये भ्रम हो जाता है कि कोई प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन जो संघ को जानते है उनको पता है कि प्रचारक परंपरा संघ कार्य की विशेषता है। गत 100 वर्षों में देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक-युवतियों ने अपना घर-परिवार त्याग करके पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। भागवत जी भी उस महान परंपरा की मजबूत धुरी है।

नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री, भारत

भागवत जी ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उस दौर में प्रचारक के रूप में भागवत जी ने आपातकाल-विरोधी आंदोलन को निरंतर मजबूती दी। उन्होंने कई वर्षों तक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों, विशेषकर विदर्भ में काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में मोहन भागवत जी के कार्यों को आज भी कई स्वयंसेवक स्नेहपूर्वक याद करते हैं। इसी

कालखंड में मोहन भागवत जी ने बिहार के गांवों में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने के कार्य में समर्पित रहे। 20वीं सदी के आखिरी पड़ाव पर वे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख बने। वर्ष 2000 में वे सरकार्यवाह बने और यहाँ भी भागवत जी ने अपनी अनोखी कार्यशैली से हर कठिन परिस्थिति को सहजता और सटीकता से संभाला। 2009 में वे सरसंघचालक बने और आज भी अत्यंत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे है। भागवत जी ने राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को हमेशा सर्वोपरि रखा।

सरसंघचालक होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है। यह एक पवित्र विश्वास है, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी दूरदर्शी व्यक्तित्वों ने आगे बढ़ाया है और इस राष्ट्र के नैतिक और सांस्कृतिक पथ को दिशा दी है। असाधारण व्यक्तियों ने इस भूमिका को व्यक्तिगत त्याग, उद्देश्य की स्पष्टता और माँ भारती के प्रति अटूट समर्पण के साथ निभाया है। यह गर्व की बात है कि मोहन भागवत जी ने न केवल इस विशाल जिम्मेदारी के साथ पूर्ण न्याय किया है, बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति, बौद्धिक गहराई और सहृदय नेतृत्व भी जोड़ा है।

भागवत जी का युवाओं से सहज जुड़ाव है और इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ कार्य के लिए प्रेरित किया है। वे लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क में रहते है, और संवाद करते रहते है। श्रेष्ठ कार्य पद्धति को अपनाने की इच्छा और बदलते समय के प्रति खुला मन रखना, ये मोहनजी की बहुत बड़ी विशेषता रही है। अगर हम व्यापक संदर्भ में देखते है तो संघ की 100 साल की यात्रा में भागवत जी का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। चाहे वो गणवेश परिवर्तन हो, संघ शिक्षा वर्गों में बदलाव हो, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके निर्देशन में संपन्न हुए। कोरोना काल में मोहन भागवत जी के प्रयास विशेष रूप से याद आते है। उस कठिन समय में उन्होंने स्वयंसेवकों को सुरक्षित रहते हुए समाजसेवा करने की दिशा दी और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने पर बल दिया। उनके मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने जरूरतमंदों तक हरसंभव सहायता पहुँचाई, जगह-जगह मेडिकल कैंप लगाए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों और वैश्विक विचार को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्थाओं को विकसित किया। हमें कई स्वयंसेवकों को खोना भी पड़ा, लेकिन भागवत जी की प्रेरणा ऐसी थी कि अन्य स्वयंसेवकों की दृढ़ इच्छाशक्ति कमजोर नहीं पड़ी। इस वर्ष की शुरुआत में, मैंने नागपुर में उनके साथ माधव नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के दौरान मैंने कहा था कि संघ अक्षयवट की तरह है, जो राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है। इस अक्षयवट वृक्ष की जड़ें इसके मूल्यों की वजह से बहुत गहरी और मजबूत है। इन मूल्यों को आगे बढ़ाने में जिस समर्पण से मोहन भागवत जी जुटे हुए है, वो हर किसी को प्रेरणा देता है।

समाज कल्याण के लिए संघ की शक्ति के निरंतर उपयोग पर मोहन भागवत जी का विशेष बल रहा है। इसके लिए उन्होंने पंच परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें स्व बोध, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुम्ब प्रबोधन और पर्यावरण के सूत्रों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। संघ का हर कार्यकर्ता वैभव संपन्न भारत माता का सपना साकार होते देखना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए जिस स्पष्ट विज़न और ठोस एक्शन की जरूरत होती है, मोहन जी इन दोनों गुणों से परिपूर्ण है। मोहन जी के स्वभाव की एक और बड़ी विशेषता ये है कि वो मृदुभाषी हैं। उनमें सुनने की भी अद्भुत क्षमता है। यह विशेषता न केवल उनके दृष्टिकोण को गहराई देती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व में संवेदनशीलता और गरिमा भी लाती है। मोहन जी, हमेशा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के प्रबल पक्षधर रहे है। भारत की विविधता और भारत भूमि की शोभा बढ़ा रही अनेक संस्कृतियों और परंपराओं के उत्सव में भागवत जी पूरे उत्साह से शामिल होते है। वैसे बहुत कम लोगों को ये पता है कि मोहन भागवत जी अपनी व्यस्तता के बीच संगीत और गायन में भी रुचि रखते है। वे विभिन्न भारतीय वाद्ययंत्रों में भी निपुण है। पठन-पाठन में उनकी रुचि, उनके अनेक भाषणों और संवादों में साफ दिखाई देती है।

संघ का हर कार्यकर्ता वैभव संपन्न भारत माता का सपना साकार होते देखना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए जिस स्पष्ट विज़न और ठोस एक्शन की जरूरत होती है, मोहन जी इन दोनों गुणों से परिपूर्ण हैं। मोहन जी के स्वभाव की एक और बड़ी विशेषता ये है कि वो मृदुभाषी हैं। उनमें सुनने की भी अद्भुत क्षमता है। यह विशेषता न केवल उनके दृष्टिकोण को गहराई देती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व में संवेदनशीलता और गरिमा भी लाती है। मोहन जी, हमेशा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के प्रबल पक्षधर रहे हैं।

मुनक्का के नियमित सेवन से सौंदर्य में निखार

- मुनक्का को काली किशमिश भी कहा जाता है, जो एक तरह का सूखा हुआ अंगूर है। यह विटामिन, फाइबर, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जिसका सेवन करने से बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है
- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, अमेरिका की फरवरी, 2022 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, किशमिश (मुनक्का) में लिपिड (वसा) कम करने के और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं, जो स्किन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, त्वचा की रंगत में सुधार लाने और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं

(मीडिया इनपुट्स)

दिनोंदिन राजनीतिक उथल-पुथल, नेपाल में अराजकता इस कड़ी में हालिया घटना है, से घिरा भारत लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। अमेरिका की शह पर हसीना के देशनिकाले के बाद बांग्लादेश मुस्लिम कट्टरपंथियों की गिरफ्त में है। म्यांमार में अमेरिकी मदद से जुंटा-विरोधी विद्रोही पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता का खतरा मंडराए हुए हैं। पाकिस्तान नाकाम देश है, जहां सेना राजनीति पर हावी है।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

एक तीर से कई निशाने साधे एनडीए ने

उपराष्ट्रपति चुनाव | **ललित गर्ग**

सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार एवं तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को परास्त कर 17वें उपराष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की। यह ऐतिहासिक घटना भारतीय राजनीति में बदलते समीकरणों और भविष्य की दिशा का भी संकेत है। राधाकृष्णन का चुना जाना न केवल एनडीए और भाजपा की रणनीतिक सूझबूझ का परिणाम है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि व्यक्ति चयन की प्रक्रिया को उन्होंने केवल राजनीतिक समीकरण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसमें व्यापक सामाजिक-राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी जोड़े। उपराष्ट्रपति पद संवैधानिक गरिमा का प्रतीक होता है, जहां राजनीति से ऊपर उठ कर राष्ट्रहित सर्वोपरि हो जाता है।

इस जीत के कई निहितार्थ हैं। पहला, यह भाजपा और एनडीए की राजनीतिक पकड़ और संगठनात्मक शक्ति को और मजबूत करती है। दूसरा, यह विपक्षी इंडिया गठबंधन की कमजोरियों और आंतरिक मतभेदों को उजागर करती है। तीसरा, यह भविष्य की राजनीति की उस दिशा को दर्शाती है, जहां व्यक्तिगत ईमानदारी, सामाजिक स्वीकार्यता और राष्ट्रीय दृष्टि को अधिक महत्त्व मिलेगा। यह कदम भाजपा की उस राजनीति की भी झलक देता है, जहां वह केवल चुनावी जीत की ओर नहीं, बल्कि दीर्घकालीन सांस्कृतिक-वैचारिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। कहा जा सकता है कि चुनाव में एक तीर से अनेक निशाने साधे गए हैं, एनडीए की शक्ति का प्रदर्शन, विपक्ष को स्पष्ट संदेश, संवैधानिक गरिमा की रक्षा और भविष्य की राजनीति में व्यक्ति चयन की एक नई परंपरा का सूत्रपात।

भाजपा ने एक और तीर साधा है। जैसाकि तमिलनाडु की राजनीति परंपरागत रूप से द्रविड़ आंदोलनों और क्षेत्रीय पहचान से प्रभावित रही है, जहां कई दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा रहा है। भाजपा के लिए इस राज्य में राजनीतिक जमीन तैयार करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को महज 4 सीटें मिलीं जबकि एनडीए गठबंधन को 66 सीटों पर सफलता मिली। स्पष्ट है कि तमिलनाडु में भाजपा की पकड़ कमजोर है, और उसे क्षेत्रीय भावनाओं, भाषा और संस्कृति से जुड़े

सवालों पर गहरी पैठ बनाने की जरूरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बना कर रणनीतिक दांव खेला है। राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, और उनकी पहचान को आगे रखकर भाजपा राज्य की राजनीति में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना चाहती है। संदेश देना चाहती है कि वह तमिल अस्मिता, संस्कृति और क्षेत्रीय नेतृत्व को सम्मान देती है। राधाकृष्णन के चुने जाने से भाजपा को उम्मीद है कि विधानसभा चुनावों में वह अपनी उपस्थिति और प्रभाव को विस्तार दे सकेगी और द्रविड़ राजनीति के प्रभुत्व को चुनौती देने का आधार बना सकेगी। भारत का उपराष्ट्रपति पद एवं उनका कार्यालय भारतीय लोकतंत्र की गरिमा और संतुलन का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन का अध्यक्ष होने के कारण संवाद, विचार और लोकतांत्रिक विमर्श की आत्मा को दिशा देते हैं। इस पद को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे दार्शनिक, विचारक और शिक्षाविद ने अपने व्यक्तित्व और कार्य से ऊंचाई दी तब यह पद राष्ट्र के सांस्कृतिक, नैतिक और बौद्धिक आदर्शों का संवाहक बन गया। उनके माध्यम से संदेश गया कि उपराष्ट्रपति का पद केवल राजनीतिक महत्त्व का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मूल्यों के संरक्षण और विकास का भी दायित्व वहन करता है।

रचनात्मक व्यक्तित्व को उपराष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित करना भारतीय राजनीति की उज्ज्वल परंपरा को बढ़ाने का संकेत है। यह बताता है कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती केवल सत्ता-संघर्ष में नहीं, बल्कि उच्च पदों पर ऐसे व्यक्तित्वों के चयन में निहित है, जो नैतिकता, विद्वत्ता और संवेदनशीलता से लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाएं। डॉ. राधाकृष्णन की परंपरा को स्मरण करते हुए आवश्यक है कि उपराष्ट्रपति पद निरंतर आदर्शवाद, विमर्श की गहराई और राष्ट्रीय मूल्यों की ऊर्जा का केंद्र बना रहे। राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने से राज्य सभा की कार्यवाही में संयम और संवाद की संस्कृति मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति पद का दायित्व केवल औपचारिक नहीं होता, बल्कि संसद की गरिमा और संविधान की मर्यादा का संरक्षक भी होता है। दक्षिण भारत से आना और ओबीसी समुदाय से होना उन्हें सामाजिक-राजनीतिक संतुलन का प्रतिनिधि बनाता है। उनका जीवन कर्मयोगी की तरह रहा है। उन्होंने किसी भी पद को शक्ति के रूप में नहीं देखा, बल्कि सेवा और कर्त्तव्य निभाने का अवसर माना। अब वे सत्रहवें उपराष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ रहे हैं, तो आशा की जा सकती है कि संसद में शांति, लोकतांत्रिक परंपराओं और संवाद के स्तर को ऊंचाई देंगे। उनका अनुभव, धैर्य और समर्पण देश की लोकतांत्रिक संरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

अपरिग्रह | **डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी**

अपग्रिह भारतीय दर्शन का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'आवश्यकता से अधिक ग्रहण न करना' या 'संपत्ति

अथवा वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग'। यह केवल भौतिक वस्तुओं के संग्रह से दूरी बनाए रखना नहीं है, बल्कि मन-वचन-कर्म से आसक्ति के भावों से भी ऊपर उठना है। पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार, जब योगी अपरिग्रह का अभ्यास करता है, तो उसके भीतर बोध जाग्रत होता है कि जो कुछ भी है, वह क्षण भंगुर है, और किसी के भी स्थायी स्वामित्व में नहीं है। गीता में इसी योगी के लिए 'त्यक्तसर्वपरिग्रह' कहा गया है। अपरिग्रह का अभ्यास केवल साधु-संतों या योगियों के लिए नहीं है। यह गृहस्थ जीवन में भी उतना ही आवश्यक और उपयोगी है। जब हम वस्त्र, भोजन, धन या अन्य संसाधनों का अति संग्रह करते हैं, तो हम दूसरों के हिस्से की चीजें ले लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति सैकड़ों जोड़ी जूते रखता है, जबकि किसी के पास एक जोड़ी भी नहीं। यह सामाजिक विषमता का कारण बनता है। अगर हर व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकता भर की चीजें रखे तो समाज अधिक संतुलित और न्यायपूर्ण बन सकता है। गांधी जी मानते थे, 'धरती सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है, लेकिन किसी एक के लालच को नहीं।' आज के समय में जब जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट और उपभोग की संस्कृति बढ़ रही है, अपरिग्रह का मूल्य और भी बढ़ गया है। उपभोक्तावाद ने मनुष्य को लोभी, असंतुष्ट और तनावग्रस्त बना दिया है। हम जितना अधिक संग्रह करते हैं, उतना ही भय भी हमें सताता है चोरी का, नष्ट होने का, खो जाने का। अधिक वस्तुएं हमें सुख नहीं देतीं, बल्कि हमारी चिंता का कारण बनती हैं। ऐसे में, अपरिग्रह न केवल आध्यात्मिक समाधान है, बल्कि मानसिक शांति, सामाजिक समरसता और पारिस्थितिक संतुलन का भी आधार है। महंत स्वामी महाराज यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख संग्रह में नहीं, बल्कि त्याग में है। जो जितना कम चाहता है, वह उतना ही अधिक स्वतंत्र होता है। अपराध, संघर्ष और विषमता से ग्रस्त इस संसार को यदि किसी मूल्य की सबसे अधिक आवश्यकता है, तो वह है-अपरिग्रह!

रीडर्स मेल

ऑनलाइन गेमिंग बाजार ध्वस्त

सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 को लागू कर लगभग 3.8 अरब डॉलर के ऑनलाइन गेमिंग बाजार को ध्वस्त कर दिया है। हुकूमत ने अपने राजस्व को दरकिनार कर जनहित में निर्णय लिया है, जो निःसंदेह सराहनीय है। कम समय में अधिक पैसा कमाने के लालच में हर रोज न जाने कितने लोग अपनी जमापूंजी बर्बाद कर बैठते थे। न जाने कितने कर्ज के दलदल में फंस कर आत्महत्या को मजबूर हो गए। ऑनलाइन जुए की लत कितनी खतरनाक है, इसका एक मामला सुल्तानपुर में देखने को मिला जहां एक शिक्षक ने महज नौ महीने में सवा करोड़ रुपये गंवा दिए। दिल दहला देने वाली एक खबर इंदौर में भी देखने को मिली जहां तेरह साल के एक बच्चे ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि ऑनलाइन मनी गेम में तीन हजार रुपये हार गया था। ऑनलाइन गेम्स प्रतिबंधित होने से भले ही इनसे जुड़े दो लाख लोगों का रोजगार छिन गया है पर यह निर्णय उन करोड़ों परिवारों के लिए संजीवनी साबित होगा जिन्हें ये गेम्स धीरे-धीरे निगल रहे थे।

शिवेन्द्र यादव, कुशीनगर, उप्र

नेपाल में शांति बहाली जरूरी

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में युवाओं के आक्रोश ने पूरे नेपाल को अराजकता में धकेल दिया है। विरोध कर रहे युवाओं पर सेना द्वारा गोली चलाने से उनका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास और संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। नेतागण जान बचा कर भाग रहे हैं। आज वहां आम जनता की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा है। पड़ोसी देश में अराजकता बनी रही तो उससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। भारत सरकार को तत्काल नेपाल में शांति बहाली के प्रयास करने चाहिए। आखिर, भारत और नेपाल के बीच सदियों से गहरे संबंध रहे हैं।

हिमांशु शेखर, गयाजी

सोशल मीडिया और अराजकता

आज की तारीख में सोशल मीडिया के यूजर की संख्या हर सेकंड बढ़ रही है। लोग अपनी अभिव्यक्ति का सशक्त मंच सोशल मीडिया को मान रहे हैं। इस पर प्रतिबंध स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का पर्याय होगा। इस बात का ज्वलंत उदाहरण नेपाल है। दूसरी ओर, सोशल साइट्स के दुरुपयोग एवं सरकार के लिए डिजिटल संप्रभुता वाली बात भी आती है, जिसमें आम लोगों के व्यवहार प्रभावित होने के साथ-साथ सरकार द्वारा नियंत्रित परिवेश की बात भी शामिल हो जाती है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के पश्चात देश में त्राहिमाम जैसी स्थिति उत्पन्न होना नई बात नहीं रह गई है। किसी भी साइट पर विद्वेष जैसी बातें विस्तृत रूप में प्रचारित-प्रसारित नहीं हो पाएं, इसके लिए नियंत्रण तो सरकार के पास ही होना चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद नेपाल में जो हालात हो गए हैं, यह अपने आप में सही नहीं है। शांति, सहिष्णुता के वातावरण में लोगों की आजादी के साथ-साथ किसी प्रकार की तल्खी न आवे, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। आम जनता को भी अपनी सरकार पर विश्वास बना कर अराजक परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए।

मिथिलेश कुमार, भागलपुर

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-35, अंक 28

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रेरणा

मैं अपनी जिंदगी में बार-बार असफल हुआ हूं और इसीलिए मैं सफल होता हूं। - माइकल जॉर्डन

संपादकीय

बाहरी लोगों को बिना वजह नहीं अपनाता है समाज

सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला को दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट उपक्रमों ने सीईओ बनाकर कोई अहसान नहीं किया। यह उनके टैलेंट का कमाल था। भारतीय इंजीनियरों, शोधकर्ताओं और डॉक्टरों की सफलता उनकी क्षमता को बताती है। संपन्न और खुले समाजों में जीने की आसान शर्तों के कारण युवा संघर्षशील नहीं रहते, लिहाजा कमजोर समाजों से लोग प्रवासी के तौर पर वहां पहुंचते हैं। बेहतरी की ललक में वे ज्यादा शारीरिक-मानसिक श्रम करते हैं। अमेरिका में भारतीय इंजीनियरों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों से लेकर रसोइए व ड्राइवर तक बेहतर काम कर रहे हैं और स्थानीय अमेरिकियों से सस्ते और कर्मठ भी हैं। आज चीन की प्रति-व्यक्ति आय भी भारत से 5.5 गुना ज्यादा है और युवाओं के लिए अपने देश में ही आन्त्रप्रेन्योर (नव-उद्यमी) या नौकरीपेशा के रूप में ज्ञान आजमाने की गुंजाइश बढ़ी है। एच1बी वीसा पर अमेरिका जाने वाले 70% युवा भारत के थे। ट्रम्प अगर मागा के तहत अपने युवाओं को इस प्रवाह में लाना चाहते हैं तो भारतीय युवाओं वाली क्षमता भी देनी होगी। भारत ने ब्रेन ड्रेन को पहचाना और ब्रेन गेन की अवधारणा के तहत स्टार्ट-अप्स को मौका देना शुरू किया। अमेरिकी समाज को बाहरी-भीतरी विवाद में पड़ने के बजाय यह समझना होगा कि बाहरी का क्यों किसी सिस्टम में स्वागत किया जाता है। ट्रम्प को अगर अमेरिका को फिर से महान बनाना है तो अमरीकी युवाओं की मानसिक क्षमता बढ़ानी होगी। भारत भी इसी मार्ग पर चल रहा है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

योग ऐसा उपाय है, जो एआई की बुराइयों से हमें बचाएगा

हमारे स्वभाव की डीप लर्निंग यदि हमारे अलावा कोई दूसरा करने लगे, तो हमें बहुत नुकसान होगा। हमारा नियंत्रण उस शक्ति के हाथ में चला जाएगा। फिर वो हमें बहकाएगा, फुसलाएगा, उकसाएगा, भटका देगा और काफी हद तक भड़का देगा। इन दिनों इस शक्ति का नाम है- एआई। ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप करने लगी है। और सुना जा रहा है कि इसमें एक बड़ा खतरा है कि वो हमारी चारित्रिक कमजोरियों को पकड़ लेगी। कुछ ऐसी कमजोरियां जो हमारे अलावा दूसरे नहीं जानते, पर एआई जान जाएगा। और फिर आप इसके लिए एक आज्ञाकारी, लाभकारी व्यक्तित्व होंगे, उपभोक्ता होंगे। इसलिए हमें इसका उतना ही सदुपयोग करना चाहिए कि ये हमारा दुरुपयोग न करने लगे। जो लोग परम-सत्ता के हाथ अपना जीवन सौंप देंगे, तो एक अज्ञात शक्ति इस ज्ञात शक्ति से उनकी रक्षा करेगी। और परम सत्ता तक जाने के लिए नियमित योग करिए। योग ही ऐसा माध्यम है, जो एआई की खूबियों का स्वागत करेगा, पर उसकी बुराइयों से हमें बचाएगा।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

पाठकों के पत्र

बच्चों की स्कूलों से बेरुखी क्यों?

मध्यप्रदेश के 223 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। 7217 स्कूलों में एक ही शिक्षक है। शिक्षकों की योग्यता भी एक अहम विषय है। बच्चों को स्कूल ना भेजने वाले अभिभावकों को समझाना शिक्षकों का ही काम है। ड्रॉप आउट बच्चों के लिए अभियान चलाने के बावजूद बच्चों की बेरुखी बड़ा प्रश्न है। इसे पूरी संवेदनशीलता के साथ सुलझाया जाना चाहिए। यह मध्य प्रदेश के भविष्य का भी सवाल है। -सुभाष चंद्र व्यास, इंदौर, मध्यप्रदेश

भारत-चीन को करीब लाया टैरिफ वॉर

शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में ड्रैगन और हाथी ने अप्रत्याशित रूप से हाथ मिला कर दुनिया में दादागिरी करने वालों को दो टूक जवाब दिया है। चीन और भारत की दोस्ती इतनी सहजता और सरलता से इतनी जल्दी हो जाएगी, यह असंभव लगता था। लेकिन ट्रम्प के टैरिफ वार के परिप्रेक्ष्य में दोनों देश नजदीक आ गए। भारत और चीन की नजदीकी के लिए दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने कदम बढ़ाए हैं।
-मिथिलेश कुमार, भागलपुर, बिहार

देशभर में शुरू हो ई-मतदान

हमारे देश में मोबाइल से ऑनलाइन मतदान की सुविधा शुरू हुई है। बिहार निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका चुनाव में ई-वोटिंग शुरू की। इस प्रक्रिया में उन मतदाताओं ने भाग लिया, जो राज्य से बाहर थे या मतदान केन्द्र जाने में अक्षम थे। उम्मीद है कि इस प्रक्रिया का विस्तार सारे देश में होगा। इससे ईवीएम पर जो सवाल खड़े किए जाते हैं, उन पर पूर्ण विराम लग सकता है।
-राजेश कुमार चौहान, जालंधर, पंजाब

बीमारियों के समाधान खोजने होंगे

आज के दौर में कई नई-नई बीमारियां सामने आ रही हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के तरीकों पर शोध होना जरूरी है। सभी लोगों को गलत खान-पान, व्यायाम की कमी, बढ़ते तनाव, जरूरत से ज्यादा सोचने और बदलती जीवनशैली जैसी समस्याओं पर विचार करना होगा। इन समस्याओं के समाधान ढूंढकर उन्हें व्यवहार में लाना होगा। तभी बीमारियों की संख्या में कमी लाई जा सकेगी।
-पीएम काले, नासिक, महाराष्ट्र

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

महासागरों में बनती है पृथ्वी की 70% ऑक्सीजन

पृथ्वी की 50 से 70 प्रतिशत तक ऑक्सीजन का उत्पादन महासागरों में होता है। महासागरों में फाइटोप्लांकटन, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण के जरिए ऑक्सीजन बनाते हैं। फाइटोप्लांकटन बेहद सूक्ष्म जीव होते हैं, जो समुद्र की सतह पर काफी बड़े समूहों में तैरते हुए दुनिया को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हालांकि, समुद्रों में दिनोंदिन बढ़ रहे प्रदूषण से इन जीवों के अस्तित्व पर बड़ा खतरा भी सामने आया है।

24 घंटे में ही फाइटोप्लांकटन अपनी आबादी दोगुनी कर सकते हैं। ये पृथ्वी के सबसे तेज बढ़ने वाले जीवों में से एक हैं।

विशेष • विविधताओं से भरे 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के प्रबल पक्षधर रहे हैं मोहन भागवत

एक युवा स्वयंसेवक से संघ प्रमुख तक की यात्रा

जयंती-प्रसंग

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्मदिवस है, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना जीवन समर्पित किया है। संघ परिवार में जिन्हें सरसंघचालक के रूप में संबोधित किया जाता है, ऐसे आदरणीय मोहन भागवत जी का आज जन्मदिन है। सुखद संयोग है कि इसी साल संघ भी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है।

मेरा भागवत जी के परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। मुझे उनके पिता स्व. मधुकर राव भागवत जी के साथ निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। मैंने अपनी पुस्तक ज्योतिपुंज में मधुकर राव जी के बारे में विस्तार से लिखा भी है। वकालत के साथ-साथ मधुकर राव जी जीवनभर राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित रहे। अपनी युवावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ कार्य की मजबूत नींव रखी। उनका राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि अपने पुत्र मोहन राव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे। उन्होंने मोहन राव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी।

भागवत जी 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। सामान्य जीवन में प्रचारक शब्द सुनकर ये भ्रम हो जाता है कि कोई प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन जो संघ को जानते हैं उनको पता है कि प्रचारक परंपरा संघ कार्य की विशेषता है। देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक-युवतियों ने घर-परिवार त्यागकर पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। भागवत जी भी उस महान परंपरा की मजबूत धुरी हैं।

भागवत जी ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला, जब कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उस दौर में प्रचारक के रूप में भागवत जी ने आपातकाल-विरोधी आंदोलन को मजबूती दी। उन्होंने कई वर्षों तक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों, विशेषकर विदर्भ में काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में मोहन भागवत जी के कार्यों को आज भी कई स्वयंसेवक स्नेहपूर्वक याद करते हैं। इसी कालखंड में भागवत जी ने बिहार के गांवों में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने के कार्य में समर्पित रहे।

20वीं सदी के आखिरी पड़ाव पर वे संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख बने। 2000 में वे सरकार्यवाह बने। 2009 में वे सरसंघचालक बने और आज भी अत्यंत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। सरसंघचालक होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है। यह एक पवित्र विश्वास है, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी दूरदर्शी व्यक्तित्वों ने आगे बढ़ाया है और राष्ट्र के नैतिक और सांस्कृतिक पथ को दिशा दी है।

भागवत जी का युवाओं से सहज जुड़ाव है और इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ कार्य के लिए प्रेरित किया है। वे लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं और संवाद करते रहते हैं। श्रेष्ठ कार्य पद्धति को अपनाने की इच्छा और बदलते समय के प्रति खुला मन रखना, ये मोहन जी की बहुत बड़ी विशेषता रही है। अगर हम व्यापक संदर्भ में देखते हैं तो संघ की 100 साल की यात्रा में भागवत जी का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। चाहे वो गणवेश परिवर्तन हो, संघ शिक्षा वर्गों में बदलाव हो, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके निर्देशन में संपन्न हुए।

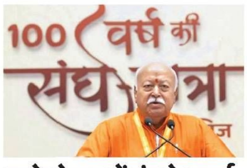

उनके नेतृत्व में संघ के कार्य का विस्तार हो रहा है...

एक युवा स्वयंसेवक से सरसंघचालक तक की उनकी जीवन-यात्रा उनकी निष्ठा और वैचारिक दृढ़ता को दर्शाती है। विचार के प्रति पूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन करते हुए उनके नेतृत्व में संघ कार्य का विस्तार हो रहा है।

इस वर्ष की शुरुआत में, नागपुर में उनके साथ माधव नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के दौरान मैंने कहा था कि संघ अक्षयवट की तरह है, जो राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है। इस अक्षयवट की जड़ें इसके मूल्यों की वजह से बहुत गहरी और मजबूत हैं। इन मूल्यों को आगे बढ़ाने में जिस समर्पण से मोहन भागवत जी जुटे हुए हैं, वो हर किसी को प्रेरणा देता है।

समाज कल्याण के लिए संघ की शक्ति के निरंतर उपयोग पर मोहन भागवत जी का विशेष बल रहा है। इसके लिए उन्होंने पंच परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें स्व बोध, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुम्ब प्रबोधन और पर्यावरण के सूत्रों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। देश और समाज के लिए सोचने वाले हर भारतवासी को पंच परिवर्तन के इन सूत्रों से अवश्य प्रेरणा मिलेगी।

मोहन जी के स्वभाव की एक और बड़ी विशेषता ये है कि वो मृदुभाषी हैं। उनमें सुनने की भी अद्भुत क्षमता है। यह विशेषता न केवल उनके दृष्टिकोण को गहराई देती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व में संवेदनशीलता और गरिमा भी लाती है। वे हमेशा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के प्रबल पक्षधर रहे हैं। भारत की विविधता और भारत भूमि की शोभा बढ़ा रही अनेक संस्कृतियों और परंपराओं के उत्सव में भागवत जी पूरे उत्साह से शामिल होते हैं। वैसे बहुत कम लोगों को ये पता है कि मोहन भागवत जी अपनी व्यस्तता के बीच संगीत और गायन में भी रुचि रखते हैं। वे विभिन्न भारतीय वाद्ययंत्रों में भी निपुण हैं। पठन-पाठन में उनकी रुचि, उनके अनेक भाषणों और संवादों में साफ दिखाई देती है।

कुछ ही दिनों में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो जाएगा। यह भारत और विश्वभर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघचालक हैं, जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं।

सुर्खियों से आगे • जनता के गुस्से से सावधान

मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो!

देश-दुनिया

नवनीत गुर्जर
navneet@dbcorp.in

'तूफानों से आंख मिलाओ / सैलाबों पर वार करो / मल्लाहों का चक्कर छोड़ो / तैर के दरिया पार करो।'

राहत इंदौरी साहब के इस शेर को ही शायद ध्येय मानकर नेपाल के युवाओं ने मात्र चौबीस घंटों में सत्ता पलट दी। पहले श्रीलंका और बांग्लादेश। अब नेपाल। गुस्सा हर जगह एक जैसा था। देश कोई भी हो, सत्ताधीशों को यह समझ लेना चाहिए कि जनता का गुस्सा पल भर में कुछ भी कर सकता है।

बांग्लादेश में जब विद्रोह हुआ तो नेपाल खुश था कि उसके यहां ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल, जिनके अपने घर पर छत नहीं होती, वे दूसरों के पांव की जमीन नापते फिरते हैं। उनका यही भ्रम एक दिन उनकी दीवारें भी गिरा देता है। जिस तरह सोने में सुगंध नहीं होती, गन्ने में फूल नहीं होते और चंदन में फल नहीं होते- उसी तरह जनता-जनार्दन की लाठी में भी आवाज नहीं होती। वास्तविकता यह है कि आजादी के बाद भारत में जितना विकास हुआ है, पड़ोसी-छोटे देश वह कर नहीं पाए। इन पड़ोसी देशों में विकास के नाम पर केवल सत्ताधीशों के घर भरते गए। सत्ता का स्थायित्व भी इन देशों में या तो न के बराबर रहा या एक ही सत्ताधीश ने इतने लम्बे समय तक राज किया कि एक समय पर लोगों का गुस्सा तूफान बनकर टूट पड़ा।

ये बात अलहदा है कि भारत में भी गांवों की हालत आज तक उस तरह नहीं सुधर पाई, जिस तरह की अपेक्षा रही होगी। वर्षों से चुनाव पर चुनाव होते जा रहे हैं। कोई जीत रहा है। कोई हार रहा है। लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल से श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी तक गांव की हालत अभी भी वैसी ही है। शहरों में जरूर विकास की आंधी चली और निश्चित तौर पर भरपूर विकास हुआ भी है, लेकिन इस विकास और नई अर्थव्यवस्था ने शहरों के बाजारों को चुम्बक और आदमी को लोहा बनाकर रख दिया है। बाजार लहलहा रहे हैं। लोगों को आकर्षित भी कर रहे हैं लेकिन लोग भावनाशून्य हो गए हैं। मोबाइल की इस दुनिया ने ई-सम्पर्क का दायरा तो बढ़ाया, लेकिन मेल-जोल, रूठना-मनाना, गप-शप करना, सब इतना सीमित हो गया कि आदमी से आदमी का मिलना दूभर हो गया है।

किसी के पास वक्त नहीं है। सच यह है कि आप मोबाइल खरीद सकते हैं लेकिन रिश्ते नहीं। दोस्त भी नहीं। समय तो खरीदा ही नहीं जा सकता, जो मोबाइल और रील्स देखने में बुरी तरह खर्च होता जा रहा है।

बहरहाल, देश कोई भी हो, सत्ताधीशों को ठहरकर ये सोचना ही होगा कि वे लोगों के गुस्से को किस तरह शांत करके रखें। किस तरह की सुविधाएं उन्हें दे सकते हैं? किस तरह का विकास उनके क्षेत्र में कर सकते हैं, जिससे उनका जीवन आसान हो सके। यह बात समग्र विकास की है। मुफ्त की रेवड़ियों से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये मुफ्त की रेवड़ियां एक तरह से चुनाव जीतने का उपक्रम भर हैं... और कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। दरअसल, भारत में सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रहे चुनाव-खर्च ने पूरी व्यवस्था को, पूरे ढांचे को ही तहस-नहस कर दिया है। इसे कम करने का कोई मैकेनिज्म नेताओं को बनाना चाहिए। गढ़ना चाहिए।

एक जमाना था, जब पं. द्वारका प्रसाद मिश्र का निर्वाचन इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने चुनाव में सीमा से एक रुपया ज्यादा खर्च कर दिया था! अब ऐसा नहीं होता। प्रत्याशी कोई भी हो, अनाप-शनाप खर्च किया जाता है। पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन चुनाव आयोग को सीमा के भीतर का हिसाब थमा दिया जाता है। आयोग भी उससे संतुष्ट होकर बैठ जाता है। धरातल पर जांचने-परखने की कोई विधि नहीं है। है भी तो कोई यह जेहमत उठाना नहीं चाहता। आज-कल में बिहार में भी यही होने वाला है। एक तरफ गंगा मैया में पानी बहेगा और दूसरी तरफ बिहार की धरती पर पैसों की बाढ़ आएगी। इस बाढ़ में कई लोग नहाएंगे और कहीं ज्यादा लोग बह जाएंगे। बिहार के आमजन की हालत तो गुलजार साहब द्वारा संग्रहित किताब की यह कविता बखूबी बयां करती है :

'गंगा मैया आई थीं / मेहमान बनकर / कुटिया में रहकर गईं / मायके आई लड़की की तरह / चारों दीवारों पर नाचीं / खाली हाथ अब जातीं कैसे? खैर से, पत्नी बची है / दीवार चूरा हो गई / चूल्हा बुझ गया / जो था, नहीं था, सब गया! / परसाद में पलकों के नीचे / चार कतरे रख गई है पानी के!'

जिनके अपने घर पर छत नहीं होती, वे दूसरों के पांव की जमीन नापते फिरते हैं। उनका यही भ्रम एक दिन उनकी दीवारें भी गिरा देता है। जैसे सोने में सुगंध नहीं होती, गन्ने में फूल नहीं होते और चंदन में फल नहीं होते- उसी तरह जनता-जनार्दन की लाठी में भी आवाज नहीं होती।

दूरदृष्टि • नेपाल की घटनाओं में सबके लिए सबक

सोशल मीडिया के दौर में आप युवाओं को दबा नहीं सकते

नेपाल

लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन
कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर

हमने पहले भी यह देखा है। हाल ही में बांग्लादेश में, कुछ साल पहले श्रीलंका और अब नेपाल में। प्रत्येक घटना के अपने अलग कारण हैं, लेकिन एक चिंताजनक पैटर्न समान है। युवा आक्रोश, एकाएक उकसावा (जैसे इंटरनेट शटडाउन, कोटा निर्णय या बुनियादी सेवाओं की समाप्ति) और शासन की विफलताओं का एक ज्वलनशील मिश्रण। बढ़ती युवा आबादी जनसांख्यिकीय लाभ जरूर है, लेकिन यदि उसे उपेक्षित- बेरोजगार, अकुशल और हाशिए पर- छोड़ दिया जाए तो वो विस्फोटक भी हो सकती है। इन तमाम बदलावों में जेन-जी और युवा मिलेनियल्स केंद्र में क्यों हैं? जनसांख्यिकी इसमें मायने रखती है। दक्षिण एशिया की युवा आबादी विशाल है। संभवत: यह एक आर्थिक इंजन है, लेकिन शोध एक चिंताजनक पैटर्न भी बताते हैं। जहां बड़ी युवा आबादी बेरोजगारी, कमजोर शासन और हाशिए पर धकेलने वाली राजनीति झेलती है, वहां राजनीतिक अशांति की आशंका बढ़ जाती है। साफ शब्दों में कहें तो बेचैन, डिजिटली कनेक्टेड युवा, भीड़ जुटाने वालों के लिए वरदान और कमजोर राजनेताओं के लिए सिरदर्द हैं।

इस घटना को समझने के लिए आपको तीन दृष्टिकोण से विचार करना होगा। नेपाल के टूटे-फूटे लोकतांत्रिक प्रयोगों और हिंसक विद्रोह का इतिहास। मोबाइल, मीडिया-सैवी युवा आबादी की संगठन शक्ति। और अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक जीन शार्प द्वारा गढ़ी गई सैद्धांतिक रणनीति- जो बताती है कि आंदोलन सत्ता को कैसे उखाड़ फेंकते हैं। नेपाल में 2008 तक राजशाही थी। देश की राजनीति बेहद अस्थिर थी। 1996-2006 तक चले लंबे माओवादी विद्रोह ने हजारों लोगों की जान ली और शासन और जनता के रिश्ते खराब हुए। इस इतिहास ने तय किया कि सेना और पुलिस किसी अव्यवस्था का जवाब कैसे देते हैं और राजनीतिक कुलीन कैसे राष्ट्रवादी ढांचों का उपयोग करते हैं। ताकतें अतीत से कुछ नहीं सीखती हैं।

किसी भी राजनीतिक विज्ञानी ने नेतृत्व विहीन, त्वरित और अहिंसक संघर्ष की यांत्रिकी को जीन शार्प से बेहतर नहीं समझाया है। अपनी महान कृति फ्रॉम डिक्टेटरशिप टु डेमोक्रेसी में शार्प ने बताया है कि कैसे विकेंद्रीकृत आंदोलन सांकेतिक अवज्ञा, हड़ताल, असहयोग और कम्युनिकेशन नेटवर्क के रणनीतिक उपयोग के जरिए सत्ता की जड़ों को कमजोर कर सकते हैं। जहां सोशल मीडिया है, वहां ये प्रक्रिया तेजी से चलती है। जब सोशल मीडिया को रोका जाता है तो विकेंद्रीकरण के चलते आंदोलन अकसर डार्क नेट जैसे एनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए बढ़ निकलता है।

2024 में बांग्लादेश के आंदोलन से इसकी चेतावनी मिली थी। उस घटना ने दिखाया कि एक छात्र आंदोलन कितनी जल्दी राष्ट्रीय संकट में बदल सकता है और सख्ती से इसका दमन करने पर समस्या और विकराल होती जाती है। नेपाल की वर्तमान अशांति को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। नेपाल ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित कर दिए थे। विद्रोह के जख्म झेल चुके किसी देश में शहरी भीड़ को काबू करने के लिए सेना का इस्तेमाल भी अविवेकपूर्ण था। इसमें सुरक्षा बलों के अलग-थलग पड़ने, प्रदर्शनकारियों का हौसला और बुलंद होने और कभी ना भरने वाले घाव छोड़ने का जोखिम है। बल प्रयोग के बजाय भरोसा बनाने, रोजगार-शिक्षा के विश्वसनीय वादे और सुधारों की स्पष्ट योजना स्थिरता लाने के कारगर उपाय होंगे।

ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? जवाब के दो पहलू हैं- बुद्धिमानी और तैयारी। कोई सैन्य या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा सभी पक्ष उठाएंगे। ऐसा करना नेपाली राजनीति को ऐसे दौर में धकेल देगा, जिसे काबू करना मुश्किल होगा। हम नेपाल में अपने नागरिकों के लिए दूतावास संबंधी त्वरित सेवाएं सुनिश्चित कर सकते हैं। सीमावर्ती राज्यों में आकस्मिक तैयारियां चाकचौबंद कर सकते हैं। नेपाली नागरिक और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए संचार लाइनें खुली रख सकते हैं। नेपाली संप्रभुता का सम्मान करने वाली भाषा में संयम का सार्वजनिक आग्रह कर सकते हैं। सूचना संबंधी तैयारियों के तहत गलत सूचनाओं की निगरानी और उनका जवाब देना और मीडिया के किसी भी पक्षपात से बचना सही उपाय है। अभी संयम ही सबसे अच्छा नैरेटिव होगा। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

दमन एक अल्पकालिक समाधान और दीर्घकालिक गलती है। इंटरनेट प्रतिबंध या बलप्रयोग एक-दो दिन के लिए विरोध शांत कर सकता है, लेकिन सत्ता की ताकत अच्छी नौकरियों, विश्वसनीय पुलिसिंग, स्वतंत्र न्याय और शांतिपूर्ण शिकायत निवारण पर टिकी होती है।

सरोकार • देश के 40% क्षेत्र सूखा-प्रभावित हो चुके हैं, जबकि बाढ़-प्रभावित क्षेत्र 60% अधिक बढ़े हैं

आपदाएं पहले भी आया करती थीं लेकिन आजकल के जैसी नहीं

क्लाइमेट

संजय सिंह
जल जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक

हाल ही में दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर तक ऊंचा हो गया, इससे कई निचले इलाकों में पानी भर गया। पंजाब में 1,900 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए, जिससे 400,000 एकड़ फसल की भूमि जलमग्न हुई और 3.84 लाख लोग प्रभावित हुए- यह 1988 के बाद सबसे भयंकर बाढ़ मानी जा रही है। धराली और वैष्णोदेवी की घटनाएं भी इसी कड़ी में हैं।

पिछले साल भी केरल के वायनाड जिले में 30 जुलाई की रात हुए भीषण भूस्खलन ने चूरालमाला और मुंडक्काई क्षेत्रों (मेप्पाड़ी ग्राम पंचायत) को पूरी तरह तबाह कर दिया था। आपदा से एक दिन पहले हुई अभूतपूर्व बारिश- जो जिले की सालाना औसत का 6% थी- ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। इस घटना में लगभग 400 लोगों की जानें गईं और 200 से अधिक शव चालीयार नदी में 40 किमी दूर तक मिले। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केरल का लगभग 40% हिस्सा भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र में आता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जलवायु जल विज्ञानी डॉ. लिसा कॉर्टेज के अनुसार, पहले जिस बारिश को 'सदी में एक बार' होने वाली घटना माना जाता था, अब कुछ इलाकों में हर कुछ वर्षों में हो रही है।

2023 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि 1950 के दशक के बाद से भारत के अधिकांश हिस्सों में अत्यधिक बारिश की घटनाएं 20% से 50% तक बढ़ी हैं। भारत मौसम विभाग के आंकड़े भी बताते हैं कि बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, खासकर हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों में।

दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति, तीव्रता और विनाशकारी क्षमता लगातार बढ़ रही है। बढ़ते वैश्विक तापमान के चलते समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, मौसम के पैटर्न असामान्य हो रहे हैं और अतिवृष्टि, सूखा, चक्रवात, बाढ़ तथा भूस्खलन जैसी घटनाएं अधिक बार और पहले से अधिक भीषण रूप में घटित हो रही हैं। यह न केवल मानव जीवन और आजीविका के लिए खतरा है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर भी गहरा असर डाल रहा है।

आजादी के समय भारत में जो आपदाएं आती थीं, उनकी तुलना में आज स्थिति कहीं अधिक गंभीर हो चुकी है। वर्तमान में देश के 40% क्षेत्र सूखा-प्रभावित हो चुके हैं, जबकि बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों में 60% से अधिक की वृद्धि हुई है। नए बाढ़-प्रवण क्षेत्र बन रहे हैं और जहां पहले सूखा पड़ता था, अब वहां बाढ़ आने लगी है।

इस वर्ष गुजरात से महाराष्ट्र, राजस्थान और बुंदेलखंड से लेकर महाकौशल तक के इलाकों में अत्यधिक वर्षा हुई। इसके परिणामस्वरूप बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में भी बाढ़ आ गई। जालौन, हमीरपुर और बांदा जिलों के बड़े हिस्से प्रभावित हुए। यमुना का जलस्तर 1994 में पार किए गए खतरे के निशान से तीन मीटर अधिक हो गया।

प्राकृतिक आपदाओं की यह बढ़ती रफ्तार आने वाले समय के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके कारण बड़े पैमाने पर भूमि का कटाव हुआ, फसलों का नुकसान हुआ और यह सब एक-दो दिनों में नहीं बल्कि वर्षों से हो रहे जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों का नतीजा है।

अब सरकारों की भारी-भरकम धनराशि आपदाओं से निपटने में खर्च हो रही है, जबकि किसान आर्थिक संकट में हैं और पर्यावरण लगातार क्षतिग्रस्त हो रहा है। भविष्य की आपदाओं से बचाव के लिए हमें जलवायु-उपयुक्त कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा। वर्षा जल संचयन, तालाब और जलाशयों के संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली और स्थानीय आपदा प्रबंधन योजनाओं को मजबूत करना होगा। शहरी-ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हरित क्षेत्र (ग्रीन कवरेज) बढ़ाकर भूमि के कटाव और तापमान वृद्धि को कम करना होगा। यह समय है कि हम अनियोजित विकास के मॉडल को छोड़कर, स्थायी और सतत विकास की ओर बढ़ें, ताकि भविष्य में आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। अनियोजित विकास- जैसे नदियों के किनारे अतिक्रमण, जलनिकासी मार्गों का अवरोध और हरित क्षेत्र का लगातार कम होना- आपदाओं के असर को और गंभीर बना रहा है। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 176

रोजगार की गुणवत्ता

वर्ष 2023-24 का वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एक चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है और वह है अनुबंध आधारित रोजगार में वृद्धि। इस समय संगठित विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत कुल कामगारों में से 42 फीसदी अनुबंध कार्यबल हैं। यह अनुपात 1997-98 के बाद सबसे अधिक है, जब अनुबंध कामगारों की हिस्सेदारी मात्र 16 फीसदी थी। वास्तव में, पिछले 10 वर्षों में अनुबंध आधारित रोजगार में लगभग 8 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि फैक्टरियों द्वारा सीधे नियोजित कामगारों की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट देखी गई है। भारत जैसे देश के लिए, जिसे श्रम-प्रधान विनिर्माण पर निर्भर रहना पड़ता है, अनुबंध आधारित रोजगार में वृद्धि इस बात का संकेत है कि नए रोजगार की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है।

अनुबंधित कामगारों को आमतौर पर फैक्टरियों द्वारा सीधे काम पर नहीं रखा जाता है बल्कि उन्हें तीसरे पक्ष की एजेंसियों के माध्यम से अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है। प्रमाण बताते हैं कि भारतीय कंपनियों को पारंपरिक रूप से कठोर श्रम कानूनों और मजबूत रोजगार सुरक्षा प्रावधानों का सामना करना पड़ा है, जिससे मांग की स्थिति के अनुसार कार्यबल को समायोजित करना कठिन हो जाता है। इन प्रतिबंधों से बचने के लिए कंपनियां अब तेजी से अनुबंध आधारित व्यवस्थाओं पर निर्भर हो रही हैं, जो उन्हें कामगारों के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करती हैं और लाभ व नौकरी सुरक्षा से जुड़े खर्चों को कम करती हैं। इस प्रवृत्ति का एक उल्लेखनीय पहलू राज्यों के बीच व्यापक अंतर है। वर्ष 2022-23 में यह देखा गया कि बिहार में औद्योगिक कर्मियों का 68.6 फीसदी हिस्सा अनुबंध श्रमिकों का है, जबकि केरल में यह आंकड़ा मात्र 23.8 फीसदी है।

इस प्रकार, राज्यों में असमान नियामक प्रवर्तन और विभिन्न औद्योगिक प्रथाएं इस चुनौती को और अधिक जटिल बना देती हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अनुबंधित कामगारों की हिस्सेदारी में स्पष्ट अंतर देखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित फैक्टरियों में अनुबंधित कामगारों की हिस्सेदारी शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक होने की संभावना है। अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन और अन्य विशेषज्ञों ने यह दर्शाया है कि कंपनियां अनेक संयंत्रों वाली रणनीतियां अपनाती हैं ताकि लचीलापन बना रहे और श्रम कानूनों सहित विभिन्न नियामकीय जोखिमों से बच सकें। यह विभाजन कामगारों को प्रभावी रूप से संगठित होने से रोकता है, जिससे सामूहिक सौदेबाजी कमजोर पड़ती है और वेतन की मांगें भी कम बनी रहती हैं। हालांकि, इसके परिणामस्वरूप भारतीय कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर पातीं, जिससे उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यही कारण है कि भारत अपने यहां श्रम की बहुलता का लाभ उठाने में असफल रहा है और श्रम-प्रधान वस्तुओं के निर्यात के मामले में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाया है। यहां तक कि पूंजी-प्रधान उद्योग, जिन्हें सामान्यतः कुशल कामगारों की आवश्यकता होती है, वे भी श्रम-प्रधान क्षेत्रों की तुलना में अधिक अनुबंध कामगारों को नियुक्त कर रहे हैं। इससे यह तर्क कमजोर पड़ता है कि अनुबंध आधारित रोजगार केवल अल्पकालिक या कम-कुशल कार्यों के लिए होता है। इसके बजाय, यह एक प्रणालीगत बदलाव की ओर संकेत करता है। ऐसा बदलाव जो लागत में कटौती और शक्ति के असंतुलन को ध्यान में रखते हुए अस्थिर रोजगार प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

ये रुझान चिंताजनक हैं क्योंकि अनुबंधित कामगारों को रोजगार से जुड़े वे लाभ नहीं मिलते जो अन्य नियमित कामगारों को मिलते हैं। इसमें रोजगार की सुरक्षा न होना, सीमित बीमा या बीमा न मिलना और सवैतनिक अवकाश नहीं मिलना शामिल है। इसका परिणाम कमजोर श्रम शक्ति के रूप में सामने आ रहा है जो आर्थिक झटके नहीं झेल पाती। उसके पास संसाधन बहुत सीमित रहते हैं। इस संदर्भ में चार श्रम संहिताओं को बिना देरी किए लागू करना अहम है। वे अनुबंधित और गिग श्रमिकों के लिए सुव्यवस्थित नियमन, बेहतर कार्य परिस्थितियां और अधिक स्थिरता का वादा करती हैं। श्रम बाजार को अधिक समावेशी और सुरक्षित बनाकर, ये उपाय औपचारिक क्षेत्र में भी रोजगार की गिरती गुणवत्ता को रोकने में मदद कर सकते हैं। व्यापक आर्थिक परिणामों के संदर्भ में, श्रम बाजार की स्थितियों में गिरावट फिर चाहे वह औपचारिक क्षेत्र में ही क्यों न हो, समग्र मांग पर प्रभाव डाल सकती हैं। भारत को श्रम बाजार में लचीलापन और रोजगार की शर्तों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

जीएसटी में सुधार की अब आगे की राह

जीएसटी के स्लैब और दरों में कमी के बाद जीएसटी परिषद को अब अगले सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बता रहे हैं एके भट्टाचार्य

गत सप्ताह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में सुधार का निर्णय जुलाई 2017 में इसकी शुरुआत के बाद आठ साल में तीसरा ऐसा प्रयास था। यह प्रयास पहले से कितना अलग है और इसे कितना अलग होना चाहिए था?

पहले बात करते हैं फर्क की। जीएसटी परिषद द्वारा 3 सितंबर को लिया गया निर्णय अपनी तरह का सबसे बड़ा निर्णय है। करीब 450 से अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं की जीएसटी दरें 22 सितंबर से बदल जाएंगी। कराधान के नजरिये से यह अब तक का सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है और इसे जीएसटी पूर्व के दिनों के केंद्र सरकार के सालाना बजट से भी अधिक प्रभावी माना जा सकता है। इस बार दरों को युक्तिसंगत बनाने का असर 420 से अधिक वस्तुओं पर पड़ेगा जो खाद्य, तंबाकू, कृषि, उर्वरक, कोयला, नवीकरणीय ऊर्जा, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज, परिवहन, खेल के सामान, खिलौने, चमड़ा, लकड़ी, रक्षा, फुटवियर, निर्माण, हस्तकला और मशीनरी तक विस्तारित हैं। इसके अलावा 34 सेवाएं जिनमें परिवहन, जॉब वर्क, निर्माण, स्थानीय आपूर्ति और बीमा आदि शामिल हैं, उनकी दरों में भी बदलाव आएगा।

तुलनात्मक रूप से देखें तो पहली दो कवायदों का दायरा और प्रभाव बहुत कम था। जीएसटी की शुरुआत के महज चार महीने बाद नवंबर 2017 में परिषद ने 94 वस्तुओं के लिए दरें बदल दी थीं। दूसरी कवायद पहली से भी छोटी रही जब इसके 13 महीने बाद यानी दिसंबर 2018 में 17 तरह की वस्तुओं की दरें बदल दी गईं। इन निर्णयों के लिए चुना गया समय कमोबेश एक जैसा रहा। तीसरी बार किए गए सुधार इस वर्ष के अंत में होने वाले बिहार विधान सभा चुनावों से कुछ पहले किए गए हैं। उसके बाद 2026 की पहली छमाही में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में महत्त्वपूर्ण विधान सभा चुनाव होने हैं। दरों को युक्तिसंगत बनाने की पहली कवायद दिसंबर 2017 में गुजरात विधान सभा चुनावों के कुछ सप्ताह पहले की गई थी। इसके ठीक बाद यानी 2018 की पहली छमाही में त्रिपुरा और कर्नाटक विधान सभा के चुनाव होने थे। दरों को दूसरी बार उस समय परिवर्तित किया गया जब कुछ ही महीने बाद 2019 के लोक सभा चुनाव होने वाले थे।

परंतु इसमें अहम अंतर यह है कि पहली और दूसरी बार किए गए सुधार जीएसटी व्यवस्था के लागू होने के बाद बहुत जल्दी कर दिए गए थे जबकि नई कर व्यवस्था के तहत कर संग्रह भी वांछित स्तर पर नहीं पहुंच सका था। आश्चर्य की बात नहीं है कि कर संग्रह की गति पर शुरुआती दो सुधारों ने विपरीत प्रभाव डाला।

इसके विपरीत तीसरी कवायद आठ साल बाद की गई और इस पर पिछले एक साल से चर्चा चल रही थी कि किन बदलावों को लागू किया जाए। इस बीच संग्रह दर में स्थिरता आ गई थी भले ही वह वांछित स्तर पर नहीं पहुंच सकी। गत वर्ष सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विशुद्ध जीएसटी संग्रह अभी भी जीएसटी पूर्व के वर्षों की तुलना में कम था। इस बार ज्यादा बड़ा अंतर था दरों को युक्तिसंगत बनाने की प्रकृति। वर्ष 2017 और 2018 में दरों में किए गए बदलाव एक ही दिशा में थे। कई वस्तुओं को बिना स्लैब की संख्या बदले निचले स्लैब में कर दिया गया था। 2025 में केवल दरों में कमी नहीं की गई है बल्कि कुछ मामलों में उनमें इजाफा भी किया गया है ताकि मुख्य स्लैब की संख्या कम की जा सके।

एक दर्जन से अधिक वस्तुओं को छोड़कर लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं को 5 फीसदी और 18 फीसदी की दो दरों में शामिल कर दिया गया। ऐसा करने के लिए 380 वस्तुओं और 24 सेवाओं की दरों में कमी की गई। इसके अलावा 40 वस्तुओं और 10 सेवाओं के लिए कर दर बढ़ाई जानी है। लगभग 50 वस्तुओं की दरें बढ़ाने का सरकार का अपेक्षाकृत कम चर्चित निर्णय ही सरकार को यह भरोसा दिला रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर दरों में कटौती के बावजूद राजस्व पर पड़ने वाला प्रभाव सीमित रहेगा। वर्ष2023-24 में हुई वसूली के आधार पर, सरकार ने दरों में कटौती से चालू वित्त वर्ष में राजस्व पर लगभग 93,000 करोड़ रुपये का असर पड़ने का अनुमान लगाया है।

हालांकि, दरों में वृद्धि के निर्णय ने इस प्रभाव को लगभग 45,000 करोड़ रुपये तक कम कर दिया और चालू वित्त वर्ष के लिए कुल प्रभाव को घटाकर लगभग 48,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि यह प्रभाव समय के साथ समाहित किया जा सकेगा, जो दरों में कटौती और अनुपालन में सुधार से की वजह से राजस्व में बढ़त पर निर्भर करेगा। सरकार इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या नहीं, यह तो समय बताएगा लेकिन यह तथ्य स्पष्ट है कि 50 से अधिक वस्तुओं पर दरें बढ़ाने से सरकार का राजकोषीय कार्य थोड़ा कम चुनौतीपूर्ण हो गया है।

दर संरचना को तर्कसंगत बनाने की तीसरी प्रक्रिया में एक और बड़ा अंतर यह है कि मानव निर्मित वस्त्रों और उर्वरकों जैसे कई क्षेत्रों में उलटी शुल्क संरचना की समस्या को जिस तरीके से संबोधित किया गया है, वह उल्लेखनीय है। इसके साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और करदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए देशभर में अपीलीय निकायों की स्थापना की गई है।

दरों को तर्कसंगत बनाने की इस तीसरी प्रक्रिया को पहले की दो प्रक्रियाओं की तुलना में विशिष्ट बनाने वाले अन्य अंतर क्या हो सकते थे? एक प्रमुख अंतर यह हो सकता था कि जिस प्रकार जीएसटी परिषद ने 12 फीसदी और 28 फीसदी की दो दरों को समाप्त करने का साहसिक निर्णय लिया, उसी तरह यदि वह मौजूदा 5 फीसदी की दर को समाप्त कर एक नई दर मसलन 8 फीसदी को अपनाती, तो पिछले आठ वर्षों से गिरती हुई औसत भारित प्रभावी कर दर में सुधार किया जा सकता था। जीएसटी परिषद की अगली बैठक में वह वास्तव में एक स्पष्ट खाका प्रस्तुत कर सकती है, जिसके तहत अगले दो वर्षों की अवधि में 5 फीसदी की दर को चरणबद्ध तरीके से 8 फीसदी तक बढ़ाया जाए। औसत प्रभावी कर दर को जीएसटी पूर्व स्तर के लगभग 15 फीसदी पर बहाल करना जीएसटी परिषद का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। यह कदम राजस्व संग्रह को बढ़ाकर राजकोषीय मजबूती लाने में भी मदद करेगा।

दूसरा, पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी व्यवस्था में शामिल करने की तैयारी करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि इसके समावेश का मतलब यह है कि मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों को जो लगभग 57 से 70 फीसदी के बीच हैं, उन्हें घटाकर 40 फीसदी तक लाया जाए। इन दरों को अतिरिक्त शुल्कों की मदद से वर्तमान स्तर पर बनाए रखा जा सकता है। लेकिन एक बार जब पेट्रोल और डीज़ल को जीएसटी प्रणाली में शामिल कर लिया जाएगा, तो इनका उपयोग करने वाली प्रत्येक कंपनी को लाभ होगा, क्योंकि वे इन उत्पादों पर दिए गए कर को अपने अंतिम कर भुगतान के विरुद्ध समायोजित कर सकेंगी। यह कंपनियों, खासतौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक बड़ा लाभ होगा, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। जीएसटी कर मूल्यांकन प्रणाली को व्यवस्थित करना आवश्यक है। जिस प्रकार प्रत्यक्ष कर मूल्यांकन प्रणाली अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुकी है, इसमें आम तौर पर किसी मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, वैसा ही जीएसटी में भी किया जाना चाहिए। जीएसटी मूल्यांकन प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन और फेसलेस बनाने के लिए एक समयसीमा निर्धारित करना एक अच्छी शुरुआत होगी।

सरकार के पास इन लंबित जीएसटी सुधारों को लागू करने के लिए एक सीमित अवसर है। यदि वह नहीं चाहती कि यह पूरा प्रयास अनावश्यक राजनीतिक मजबूरियों के कारण बाधित हो जाए, तो इन सुधारों को अगले आम चुनावों से पहले ही लागू कर देना चाहिए। याद रखें कि दरों की संख्या घटाने और दरों में कटौती की चर्चाएं 2022 में शुरू हुई थीं, जब जीएसटी व्यवस्था ने पांच वर्ष पूरे किए थे। दरों और स्लैब में कटौती को लागू करने में तीन वर्ष से अधिक का समय लग गया, और इस बीच आम चुनाव भी संपन्न हुए।

दोहरे प्रमाणन के जाल में उलझा इस्पात क्षेत्र

अजय श्रीवास्तव

गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) का लक्ष्य था उत्पाद गुणवत्ता का संरक्षण करना लेकिन अब भारतीय बाजार में वे प्रतिस्पर्धा के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। पहले कोई भी व्यक्ति आयात शुल्क चुकाकर या लाइसेंस हासिल करके वस्तुओं का आयात कर सकता था लेकिन अब भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) यह तय करता है कि कौन आयात कर सकता है और किस कारखाने से आयात कर सकता है। अब नियम रातोंरात बदल भी सकते हैं। इससे अनुपालन महंगा होता है, आपूर्तिकर्ताओं की तादाद कम होती है और एक ऐसी जोखिम वाली व्यवस्था बनती है जो पुराने लाइसेंसिंग राज से भी बुरी है। छोटे कारोबारी बड़ी कंपनियों के सामने हार मान लेते हैं क्योंकि वे बहुत प्रभावशाली होती हैं।

एक ताजा उदाहरण है इस्पात मंत्रालय का 13 जून का आदेश। इसके मुताबिक न केवल पूरी तरह तैयार या आधे तैयार स्टील उत्पादों बल्कि उन्हें बनाने में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल को भी बीआईएस से गुणवत्ता प्रमाणपत्र हासिल होना जरूरी है। यह नियम बमुश्किल एक दिन के नोटिस पर लागू कर दिया गया। इसकी वजह से तमाम ऑर्डर बंदरगाहों पर फंस कर रह गए, अनुबंध निरस्त किए गए और अदालती मामले शुरू हो गए। स्टील संबंधी आदेश इकलौता नहीं है बल्कि यह एक प्रवृत्ति ही बन गई है जहां क्यूसीओ का इस्तेमाल बाजार में बदलाव और चुनिंदा कारोबारियों का पक्ष लेने में किया जा रहा है। आइए पहले स्टील संबंधी आदेश को एक केस स्टडी के रूप में देखते हैं।

केस स्टडीः एक छोटी भारतीय कंपनी इंडोनेशिया की एक्स फैक्टरी से स्टील के उत्पाद आयात करती है। ऐसे उत्पाद भारत की विदेशी विनिर्माता प्रमाणन योजना (एफएमसीएस) के अधीन आते हैं जो बीआईएस को यह इजाजत देती है कि वह भारत को निर्यात करने वाली विदेशी कंपनियों की जांच और प्रमाणन कर सके। एफएमसीएस के अधीन, बीआईएस के ऑडिटर विदेशी इकाइयों का दौरा करते हैं ताकि उत्पादन प्रक्रिया का प्रमाणन कर सकें और यह तय कर सकें कि कच्चा माल भारतीय मानकों के अनुरूप है। एक बार संतुष्ट होने के बाद बीआईएस लाइसेंस जारी करता है ताकि फैक्टरी आईएसआई मार्क को अपना सके, लेकिन निगरानी प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है।

बहरहाल, 13 जून का आदेश हालात को पूरी तरह बदलने वाला है। अब कच्चे माल का हर आपूर्तिकर्ता भले ही वह किसी तीसरे देश में हो, उसे भी बीआईएस का प्रमाणन हासिल करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी विदेशी फैक्टरी को भी बीआईएस लाइसेंस हासिल करना होगा। बिना इसके एक्स नामक फैक्टरी भारत को निर्यात नहीं कर सकती भले ही उसके पास प्रमाणन हो अथवा नहीं।

प्रमाणन का बोझः यह नीति दोहरे प्रमाणन की आवश्यकता उत्पन्न करती है। पहला प्रमाणन, जो मायने रखता है, अंतिम रूप से तैयार उत्पाद के लिए है और वह एफएमसीएस के तहत पहले से लागू है। दूसरा, नया प्रमाणन कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के लिए है जो अक्सर तीसरे देश में होते हैं और भारतीय बाजार से काफी दूर होते हैं।

बीआईएस प्रमाणन हासिल करने में 6 से 18 महीने लगते हैं, इसमें मोटी फीस शामिल होती है और प्रदर्शन की गारंटी और अनुपालन का अंकेक्षण शामिल होता है। छोटी विदेशी मिलें जो किसी मध्यवर्ती निर्यातक के लिए मामूली चीजें बना रही होती हैं, उनके पास प्रमाणन के लिए समय और धन निवेश करने का कोई प्रोत्साहन नहीं होता है। इसका मतलब है, भारतीय खरीदारों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की संख्या को सीमित करना। भारत हर वर्ष जितना स्टील तैयार करता है उससे करीब 15 लाख टन अधिक इस्तेमाल करता है। देश का सबसे बड़ा इस्पात निर्माता भी जितना इस्पात बेचता है उसका 30 फीसदी से अधिक आयात करता है। आपूर्ति को सीमित करने और आयात को बीआईएस के नियंत्रण में डालने से स्टील आयात आदेश छोटे कारोबारियों के लिए कारोबार को लगभग असंभव कर देता है और कारोबार चुनिंदा बड़े कारोबारियों के हाथों में सिमट जाता है।

कानूनी पहलूः आदेश को पहले ही न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। 17 जुलाई को मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम स्थगन आदेश दे दिया क्योंकि यह आदेश बिना मशविरे के या बदलाव के लिए उपयुक्त समय दिए बिना जारी कर दिया गया था। इस्पात मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और कहा कि घरेलू उत्पादकों और आयातकों के बीच समता सुनिश्चित करने के लिए तथा कम गुणवत्ता वाले स्टील से बचाव के लिए यह उपाय आवश्यक था। 30 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश समाप्त कर दिया लेकिन मामले को उचित निर्णय के लिए वापस उच्च न्यायालय भेज दिया गया।

इसके बावजूद मंत्रालय के तर्कों में दम नहीं है। एफएमसीएस के मुताबिक पहले ही यह आवश्यक है कि बीआईएस प्रमाणित फैक्टरी में इस्तेमाल किया जाने वाला कच्चा माल भारतीय मानकों के अनुरूप हो। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के लिए अतिरिक्त लाइसेंसिंग कोई ठोस गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं करती। पहले से मौजूद सुरक्षा उपाय मसलन मिल टेस्ट प्रमाणपत्र, बंदरगाह स्तर पर पॉजिटिव मटीरियल आइडेंटिफिकेशन (पीएमआई) परीक्षण, और सीमा शुल्क निरीक्षण पहले ही खराब आयात को रोकने में सक्षम हैं।

डब्ल्यूटीओ के जोखिमः अमेरिका, यूरोपीय संघ या जापान, किसी बड़ी स्टील उत्पादक अर्थव्यवस्था को कच्चे माल के अलग प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है बशर्ते कि अंतिम उत्पाद राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता हो। इसके बजाय वे मिल टेस्ट प्रमाणपत्रों, तीसरे पक्ष के अधिमान्य परीक्षण और साझा मान्यता समझौतों पर भरोसा करते हैं।

भारत का दोहरा प्रमाणन मॉडल इन मानकों से काफी अलग है और इसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के तहत एक गैर-शुल्क बाधा के रूप में वर्गीकृत किए जाने का खतरा है। इससे भारत को व्यापार विवादों या प्रतिशोधात्मक उपायों का सामना करना पड़ सकता है। नेपाल पहले ही इस मॉडल के कारण क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न बाधाओं को लेकर चिंता व्यक्त कर चुका है।

इस आदेश को लागू करने का समय और चयनात्मक प्रकृति ने नियामक नियंत्रण की आशंका को जन्म दिया है। बताया जाता है कि एक प्रमुख स्टेनलेस स्टील निर्माता ने 13 जून से ठीक पहले अपने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए बीआईएस प्रमाणन प्राप्त कर लिया और आदेश जारी होने के तुरंत बाद कीमतें बढ़ा दीं। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को मिली छूट, जो उद्योग की लॉबिंग के बाद हासिल हुई, यह दर्शाती है कि सरकार इस नीति से होने वाले नुकसान को समझती है। फिर भी ऑटो पार्ट्स से लेकर निर्माण क्षेत्र तक कई अन्य उद्योग अब भी इस नियामक जकड़ में फंसे हुए हैं।

कमजोर ढंग से तैयार नीतिः ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को, जिनका भारत में कोई व्यावसायिक हित नहीं है, जबरन प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर करके सरकार ने अनावश्यक लागत जोड़ दी है और भारत की एक विश्वसनीय विनिर्माण साझेदार के रूप में छवि को खतरे में डाल दिया है। यदि सरकार को यह तरीका आवश्यक लगता है, तो यह कहां जाकर रुकेगा? क्या अब लौह अयस्क और कोयला खदानों को भी बीआईएस लाइसेंस लेना होगा?

आगे की राहः भारत को तत्काल उच्चस्तरीय समीक्षा और पारदर्शी नियमों की आवश्यकता है। 13 जून का आदेश तब तक स्थगित रहना चाहिए जब तक कि यह समीक्षा पूरी नहीं हो जाती है। सरकार को सभी प्रभावित पक्षों से बातचीत करने के बाद ही नीतिगत बदलाव करने चाहिए और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को स्टील उत्पाद श्रृंखला में किसी भी तरह की मिलीभगत के संकेतों की जांच करनी चाहिए।

अब जबकि भारत के लिए अमेरिकी बाजार लगभग बंद हैं तथा यूरोपीय संघ ज्यादा संरक्षणवादी हो चुका है तो भारत और अधिक अनिश्चितता नहीं झेल सकता है। क्यूसीओ के नियम अनुमान लगाने लायक, पारदर्शी और संतुलित होने चाहिए।

(लेखक जीटीआरआई के संस्थापक हैं)

आपका पक्ष

नेपाल में जेनजी आंदोलन और विश्व को सबक

नेपाल में जेनरेशन जी (जेनजी) के युवाओं ने दो दिन के अपने आंदोलन में सरकार को नेस्तनाबूद कर दिया। निवर्तमान प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। युवाओं के उग्र आंदोलन ने देश की कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले भी कर दिया। नेपाल का संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का आवास तथा अन्य सरकारी भवनों को युवाओं के गर्म खून ने फूंक डाला। नेपाल सरकार ने देश में आईटी ऐक्ट का हवाला देकर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया था जिसका खमियाजा उन्हें सत्ता गंवा कर भुगतना पड़ा। हालांकि यह भी खबर है कि नेपाल के जेनजी युवा नेताओं के बच्चों की विलासिता वाली जीवनशैली से नाराज होकर सोशल मीडिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हो रहे थे जिस पर सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाकर अंकुश लगाने की कोशिश की थी।

नेपाल में युवा आंदोलनकारियों ने मंगलवार को संसद, राष्ट्रपति भवन, उच्चतम न्यायालय और अन्य सरकारी भवनों में आग लगा दी

बहरहाल नेपाल में युवाओं का उत्पात पूरे विश्व के लिए एक सबक है। आज के जेनजी युवा सोशल मीडिया की ताकत को पहचान गए हैं तथा वह कुछ भी कर जाने को अंजाम दे सकते हैं भले ही उन्हें अपना घर, शहर और देश को ही क्यों न फूंकना पड़े। ऐसे बेलगाम युवाओं को काबू नहीं किया जा सकता है लेकिन उन्हें सही मार्ग दिखाया जा सकता है।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

हायर अधिनियम से अमेरिकी व्यापार ही सिमटेगा

इस समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार 'आईटी फर्में और जीसीसी परेशान' में अमेरिकी संसद में प्रस्तावित हाल्टिंग इंटरनैशनल रिलोकेशन ऑफ इंप्लायमेंट अधिनियम के आईटी फर्मों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर विपरीत प्रभावों की चर्चा की गई है। जिन अमेरिकी कंपनियों ने भारत में आईटी कंपनियों और जीसीसी को अपने प्रोजेक्ट आउटसोर्स किए हैं, उन्हीं कंपनियों के अधिकारी भारत को ही विपरीत प्रभावों से भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे भारतीय कंपनियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा लेकिन ऐसी अमेरिकी कंपनियों पर 25 फीसदी शुल्क के चलते वह या तो अपने प्रोजेक्ट बंद कर देगी या विश्व से अपना कारोबार समेट लेगी। अंततः नुकसान अमेरिका को ही होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप वह सब कदम उठा रहे हैं जो अमेरिका को वैश्विक व्यापार और राजनयिक संबंधों से अलग कर रहे हैं। संभवतः ट्रंप को यह डर सताने लगा है कि विश्व में अमेरिका का प्रभाव घट रहा है। अमेरिकी युवाओं में व्हाइट सुप्रीमेसी के भूत ने उनको भारतीय युवाओं जैसा कर्मठ और प्रगतिशील नहीं बनने दिया। आज भारत से अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कंपनियां बाहर हो जाएं तो लेश मात्र भी अंतर नहीं पड़ेगा बल्कि अब इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। भारत को अपनी आईटी कंपनियों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस के बाजार, जापान के बाजार खोजने होंगे। अमेरिका की टैरिफ और अन्य शुल्कों की डायनेमिक्स कोई दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ने वाली नहीं है, जब तक अमेरिका की आंख खुलेगी, तब तक देर हो चुकी होगी।

विनोद जौहरी, दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

फ्रांस में प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू की सरकार गिरने के बाद बुधवार को पेरिस और अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़कें अवरुद्ध कर दीं, आगजनी की और पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। गृह मंत्री ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के शुरुआती घंटों में लगभग 200 लोगों की गिरफ्तारी की घोषणा की। विरोध प्रदर्शन हालांकि ऑनलाइन शुरू हुआ था लेकिन बाद में लोग सड़कों पर आ गए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कल्पमेधा

सुदृढ़ मानसिकता वाले लोग सिद्धांतों या उद्देश्यों की चर्चा करते हैं, सामान्य मानसिकता वाले लोग घटनाओं की चर्चा करते हैं और कमजोर मानसिकता वाले लोग दूसरों की चर्चा करते हैं।
– सुकरात

पाबंदी की परतें

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है, जो हर नागरिक को बिना किसी दबाव और भेदभाव के अपनी राय एवं विचार व्यक्त करने की अनुमति देता है। इसमें बोलना, लिखना, कलाकारी और इंटरनेट का उपयोग करना जैसे विभिन्न रूप शामिल हैं। हालांकि, यह अधिकार असीमित नहीं है और दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करने, भेदभाव तथा हिंसा या नफरत को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियों की सूरत में यह कानूनी तौर पर बंदिश के दायरे में आ सकता है। नेपाल में जो जन आक्रोश फूटा है, वह सोशल मीडिया पर पाबंदी और उससे अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित होने से ही प्रेरित है। वहां सड़कों पर लोगों के गुस्से की आग इस कदर भड़की कि इसकी लपटें प्रधानमंत्री आवास तथा राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक जा पहुंची। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हिंसक झड़पों में कई लोगों की जान भी चली गई। सवाल है कि आखिर नेपाल में ऐसे हालात क्यों बनने दिए गए? समय रहते प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें विश्वास में लेने के प्रभावी प्रयास क्यों नहीं किए गए?

वैसे यह पहली बार नहीं है, जब किसी देश ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई हो। इससे पहले भी कई देश ऐसा कर चुके हैं, भले ही कारण अलग-अलग रहे हों। वर्ष 2009 में चीन के शिनजियांग प्रांत में हुए दंगों के बाद वहां की सरकार ने फेसबुक, एक्स और गूगल जैसे मंचों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसा इसलिए किया गया, ताकि देश में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सरकार विरोधी सामग्री के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। ईरान में भी वर्ष 2009 से सोशल मीडिया मंचों पर पाबंदी लगी है। इसी तरह तुर्किये ने भी वर्ष 2014 में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा के नाम पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि वर्ष 2016 में लोगों के विरोध के कारण यह पाबंदी हटानी पड़ी। मिस्र में वर्ष 2011 में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिसके बाद यहां सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहीं नहीं पाकिस्तान में भी इस तरह के आंशिक प्रयास होते रहे हैं।

इसमें दोराय नहीं कि सोशल मीडिया पर बिना किसी ठोस वजह से पूर्ण पाबंदी लगाने से अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित होती है। साथ ही आमजन के हितों पर भी गहरा असर पड़ता है। आज के दौर में सोशल मीडिया न केवल सूचना के प्रसार का एक बड़ा माध्यम बन गया है, बल्कि कुछ लोगों की आजीविका भी इस पर निर्भर करती है। मसलन, सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह के वीडियो डालने और उनसे होने वाली कमाई। बढ़ती बेरोजगारी की वजह से कई लोगों ने इसे अपना व्यवसाय बना लिया है। ऐसे में अगर सरकार अचानक सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दें, तो जन आक्रोश की लहर उठना स्वाभाविक है। यह बात भी सच है कि सोशल मीडिया पर अनुचित सामग्री का दायरा बढ़ रहा है, इसलिए इसे विनियमित किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। मगर, इस पहलू पर गौर करना भी जरूरी है कि कुछ लोगों की गलतियों का खमियाजा सभी को न भुगतना पड़े। नेपाल में भी संभवतः ऐसा ही हुआ है। जब युवाओं के विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया तो सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अगर समय रहते हालात को संभालने के प्रयास किए गए होते, तो सरकारी संपत्ति और जानी नुकसान से बचा जा सकता था।

साक्षरता की सीढ़ी

साक्षरता केवल किताबी शिक्षा हासिल करने तक सीमित नहीं होती। यह मनुष्य के भीतर जीवन मूल्यों की स्थापना के साथ-साथ उन्हें सजग और जागरूक भी बनाती है। इस लिहाज से देखें, तो शिक्षा का फलक बहुत बड़ा है। हिमाचल प्रदेश ने इस दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है और इसके पीछे उसकी लंबी यात्रा रही है। इस राज्य के पूर्ण साक्षर बनने की राह में कई चुनौतियां रहीं, लेकिन यह यात्रा निरंतर जारी रही। राज्य में बच्चों की संख्या की लिहाज से पर्याप्त विद्यालय खोले गए। शिक्षक-छात्र अनुपात को दुरुस्त किया गया। कई सुधारों के बाद अब इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आज हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर लगभग शून्य हो गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल में एक कार्यक्रम के दौरान हिमाचल को पूरी तरह साक्षर घोषित करते हुए कहा कि राज्य ने 99.3 फीसद साक्षरता दर हासिल कर ली है। यह राष्ट्रीय मानक 95 फीसद से अधिक है। निस्संदेह यह राज्य के लिए बड़ी कामयाबी है और यहां के नागरिकों के लिए गर्व का विषय है।

हिमाचल प्रदेश से पहले मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा भी पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा हासिल कर चुके हैं। केरल दो दशक पहले ही पूर्ण साक्षर राज्य बन गया था। अब तो उसे पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी घोषित कर दिया गया है। देश के कुछ अन्य राज्य भी पूर्ण साक्षरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हिमाचल की इस उपलब्धि को अब व्यापक दायरे में देखने का समय है। इसमें दोराय नहीं कि राज्य का यह कीर्तिमान सरकार के सतत प्रयासों का परिणाम है, लेकिन प्रदेश के उन जागरूक नागरिकों की भूमिका भी कम नहीं है, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने में जरा भी कोताही नहीं बरती। मगर इस चमकती तस्वीर के साथ बेरोजगारी की छाया भी नजर आती है। राज्य में साक्षरता बढ़ने के साथ सरकार को शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर भी सृजित करने होंगे। यानी साक्षरता में अव्वल आने के साथ राज्य की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है।

संघ के परिवर्तन पुरुष

अगर हम व्यापक संदर्भ में देखते हैं तो संघ की सौ साल की यात्रा में मोहन भागवत का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। चाहे वो गणवेश परिवर्तन हो, संघ शिक्षा वर्गों में बदलाव हो, ऐसे अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन उनके निर्देशन में संपन्न हुए।

नरेंद्र मोदी

आज 11 सितंबर है। यह दिन अलग-अलग स्मृतियों से जुड़ा है। एक स्मृति 1893 की है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व बंधुत्व का संदेश दिया और दूसरी स्मृति है 9/11 का आतंकी हमला, जब विश्व बंधुत्व को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। आज के दिन की एक और विशेष बात है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्मदिवस है, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलकर समाज को संगठित करने, समता-समरसता व बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में पूरा जीवन समर्पित किया है। संघ परिवार में जिन्हें परम पूजनीय सरसंघचालक के रूप में श्रद्धाभाव से संबोधित किया जाता है, ऐसे आदरणीय मोहन भागवत का आज जन्मदिन है।

यह एक सुखद संयोग है कि इसी साल संघ भी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। मैं मोहन भागवत को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें।

मेरा मोहन भागवत के परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। मुझे उनके पिता स्वर्गीय मधुकरराव भागवत के साथ निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। मैंने अपनी पुस्तक 'ज्योतिपुंज' में मधुकरराव के बारे में विस्तार से लिखा भी है। वकालत के साथ-साथ मधुकरराव जीवनभर राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित रहे। अपनी युवावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ कार्य की मजबूत नींव रखी। मधुकरराव का राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि वे अपने पुत्र मोहनराव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे। एक पारसमणि मधुकरराव ने मोहनराव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी।

मोहन भागवत का पूरा जीवन सतत प्रेरणा देने वाला रहा है। वे 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। सामान्य जीवन में प्रचारक शब्द सुनकर यह भ्रम हो जाता है कि कोई प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन जो संघ को जानते हैं, उन्हें पता है कि प्रचारक परंपरा संघ कार्य की विशेषता है। गत सौ वर्षों में देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक-युवतियों ने अपना घर-परिवार त्याग करके पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। भागवत भी उस महान परंपरा की मजबूत धुरी हैं। उन्होंने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। उस दौर में प्रचारक के रूप में भागवत ने आपातकाल-विरोधी आंदोलन को निरंतर मजबूती दी। उन्होंने कई वर्षों तक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों, विशेषकर विदर्भ में काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में मोहन भागवत के कार्यों को आज भी कई स्वयंसेवक स्नेह पूर्वक याद करते हैं। इसी कालखंड में उन्होंने बिहार के गांवों में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने के कार्य में समर्पित रहे।

वर्ष 2000 में मोहन भागवत सरकार्यवाह बने और यहां भी उन्होंने अपनी अनोखी कार्यशैली से हर कठिन परिस्थिति को सहजता और सटीकता से संभाला। 2009 में वे सरसंघचालक बने और आज भी अत्यंत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को हमेशा सर्वोपरि रखा। सरसंघचालक होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है। यह एक पवित्र विश्वास है, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी दूरदर्शी व्यक्तित्वों ने आगे बढ़ाया है और इस राष्ट्र के नैतिक और सांस्कृतिक पथ को दिशा दी है। असाधारण व्यक्तियों ने इस

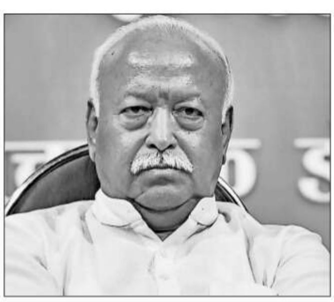

भूमिका को व्यक्तिगत त्याग, उद्देश्य की स्पष्टता और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण के साथ निभाया है। यह गर्व की बात है कि मोहन भागवत जी ने न केवल इस विशाल जिम्मेदारी के साथ पूर्ण न्याय किया है, बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति, बौद्धिक गहराई और सहृदय नेतृत्व भी जोड़ा है।

> **पिछले दिनों देश में जितने सफल जन-आंदोलन हुए, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोहन भागवत ने पूरे संघ परिवार को इन आंदोलनों में ऊर्जा भरने के लिए प्रेरित किया। मैं पर्यावरण से जुड़े प्रयासों और सतत जीवनशैली को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को जानता हूं। भागवत का जोर आत्मनिर्भर भारत पर भी है। कुछ ही दिनों में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सौ वर्ष का हो जाएगा। यह भी सुखद संयोग है कि विजयादशमी का पर्व, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और संघ का शताब्दी वर्ष एक ही दिन आ रहे हैं।**

भागवत का युवाओं से सहज जुड़ाव है और इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ कार्य के लिए प्रेरित किया है। वे लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं और संवाद करते रहते हैं। श्रेष्ठ कार्य पद्धति को अपनाने की इच्छा और बदलते समय के प्रति खुला मन रखना, ये भागवत की बहुत बड़ी विशेषता रही है। अगर हम व्यापक संदर्भ में देखते हैं, तो संघ की सौ साल की यात्रा में भागवत का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। चाहे वो गणवेश परिवर्तन हो, संघ शिक्षा वर्गों में बदलाव हो, ऐसे अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन उनके निर्देशन में संपन्न हुए। कोरोना काल में मोहन भागवत के प्रयास विशेष रूप से याद आते हैं। उस कठिन समय में उन्होंने स्वयंसेवकों को सुरक्षित रहते हुए समाजसेवा करने की दिशा दी और प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने पर बल दिया। उनके मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने जरूरतमंदों तक हरसंभव सहायता पहुंचाई, जगह-जगह चिकित्सा शिविर लगाए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों और वैश्विक विचारों को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्थाओं को विकसित किया। हमें कई स्वयंसेवकों को खोना भी पड़ा, लेकिन भागवत की प्रेरणा ऐसी थी कि अन्य स्वयंसेवकों की दृढ़ इच्छाशक्ति कमजोर नहीं पड़ी।

इस वर्ष की शुरुआत में मैंने नागपुर में उनके साथ माधव नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के दौरान कहा था कि संघ अक्षयवट की तरह है, जो राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है। इस अक्षयवट वृक्ष की जड़ें इसके मूल्यों की वजह से बहुत गहरी और मजबूत हैं। इन मूल्यों को आगे बढ़ाने में जिस समर्पण से मोहन भागवत जुटे हैं, वो हर किसी को प्रेरणा देता है। समाज कल्याण के लिए संघ की शक्ति के निरंतर उपयोग पर उनका विशेष बल रहा है। इसके लिए उन्होंने पंच परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें स्व बोध, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण के सूत्रों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। देश और समाज के लिए सोचने वाले हर भारतवासी को पंच परिवर्तन के इन सूत्रों से अवश्य प्रेरणा मिलेगी। संघ का हर कार्यकर्ता वैभव संपन्न भारत माता का सपना साकार होते देखना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए जिस स्पष्ट दृष्टि और ठोस कदम की जरूरत होती है, मोहन भागवत इन दोनों गुणों से परिपूर्ण हैं। उनके स्वभाव की एक और बड़ी विशेषता यह है कि वे मृदुभाषी हैं। उनमें सुनने की भी अद्भुत क्षमता है। यह विशेषता न केवल उनके दृष्टिकोण को गहराई देती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व एवं नेतृत्व में संवेदनशीलता और गरिमा भी लाती है।

मोहन भागवत हमेशा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के प्रबल पक्षधर रहे हैं। वैसे बहुत कम लोगों को ये पता है कि वे अपनी व्यस्तता के बीच संगीत और गायन में भी रुचि रखते है। वे विभिन्न भारतीय वाद्ययंत्रों में भी निपुण हैं। पठन-पाठन में उनकी रुचि, उनके अनेक भाषणों और संवादों में साफ दिखाई देती है। पिछले दिनों देश में जितने सफल जन-आंदोलन हुए, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोहन भागवत ने पूरे संघ परिवार को इन आंदोलनों में ऊर्जा भरने के लिए प्रेरित किया। मैं पर्यावरण से जुड़े प्रयासों और सतत जीवनशैली को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को जानता हूं। उनका जोर आत्मनिर्भर भारत पर भी है।

कुछ ही दिनों में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सौ वर्ष का हो जाएगा। यह भी सुखद संयोग है कि विजयादशमी का पर्व, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और संघ का शताब्दी वर्ष एक ही दिन आ रहे हैं। यह भारत और विश्वभर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघचालक हैं, जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। विचार के प्रति पूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन करते हुए उनके नेतृत्व में संघ कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है।

मैं मां भारती की सेवा में समर्पित मोहन भागवत के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की पुनः कामना करता हूं। उन्हें जन्मदिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं।

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं।)

जल्दबाजी के जोखिम

शिखर चंद जैन

दुनिया मेरे आगे

हम सब एक अजीब-सी हड़बड़ी में रहने लगे हैं। हमारे पास न ठीक से सोने का वक्त है न खाने का। किसी नजदीकी की बीमारी की खबर सुनकर भी हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि जाकर उसे हौसला दें, जरा सहानुभूति जता आएं या उसकी कुछ मदद कर दें। किसी की मृत्यु और अंतिम क्रिया जैसे जीवन के सबसे महत्त्वपूर्ण और अनुष्ठान पर भी अब औपचारिकता मात्र निभाने के लिए लोग जाते हैं। हड़बड़ी और व्यस्तता का आलम यह है कि हम न जाने का कोई ठोस और स्वीकार्य बहाना ढूंढ़ते हैं, ताकि कोई बुरा न मान जाए। किसी तरह चले जाएं तो इतनी भी सब्र नहीं रहती कि अंतिम क्रिया पूरी हो जाए, तब श्मशान से प्रस्थान किया जाए। दरअसल, हम निरंतर प्रतियोगिता प्रतिद्वंद्विता के मिजाज में रहने लगे हैं। बारहों महीने, आठों पहर हम शीर्ष पर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जीवन कोई दौड़ या प्रतियोगिता नहीं।

जीवन का आनंद जल्दीबाजी में शीर्ष तक पहुंचने में नहीं, बल्कि शीर्ष तक पहुंचने के सफर का खट्टा-मीठा अनुभव लेने में है। किसी ने खूब कहा है, उड़ने में बुराई नहीं है, लेकिन इतना भी न उड़ें कि जमीन दिखनी बंद हो जाए। जिंदगी के सफर को इसी मानसिकता के साथ तय करना चाहिए कि उम्मीद के काफिले पर सवार होकर हम चले भी जा रहे हैं तो क्या हुआ, अगर मंजिल ने कदम चूमने से इनकार कर दिया तो..! लेकिन इस बेहतरीन सफर की अच्छी यादें तो साथ ले जा रहे हैं।

> **जीवन के सफर को सुकून से तय करने के लिए पूर्णता और सौ फीसद सटीकता के भ्रम से भी उबरना पड़ेगा। संपूर्णता की अपेक्षा एक भ्रम है, जो किसी को हमेशा उलझाए रखता है और उसकी जीवन यात्रा को दूभर एवं बोझिल कर देता है। इसी आदत की वजह से लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं।**

इस सफर में हम कई बार लड़खड़ा भी सकते हैं, कई बार रुकेंगे और थकेंगे भी और अक्सर परेशान भी होंगे। मगर यही तो जिंदगी है। यों भी आसान चीजों में वह सुख कहां है, जो कठोर मेहनत से हासिल की हुई चीजों में है। इसीलिए मेहनत के फल को मीठा कहा गया है। यह याद रखना चाहिए कि हमारा शीर्ष कभी भी हमारे मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी जैसा नहीं हो सकता। उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार सफर तय करने देना चाहिए और हम अपनी जरूरत के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करें। फिर इन लक्ष्यों को हासिल करने का सफर तय करना चाहिए। यह ध्यान रहे कि हमारे लक्ष्य चाहे जितने भी बड़े क्यों न हों, उन्हें हासिल करने के दौरान कदम छोटे-छोटे होने चाहिए। हां, इस सफर में निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता का अर्थ यह कतई नहीं कि यात्रा अनवरत चलती ही रहे। ऊर्जा का पुनः संचय करने के लिए बीच-बीच में विश्राम भी लेना चाहिए और मन को प्रफुल्लित रखने के लिए उपाय भी करते रहने चाहिए। हमेशा स्वयं को निखारते रहना बेहद जरूरी है। यह निखार बाह्य सौंदर्य के साथ-साथ आंतरिक कौशल और कार्य में निपुणता के लिए भी आवश्यक है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को छोटे और आसान कार्यों में बांट कर लंबे समय तक उस पर काम करते हैं तो यही आदत हमें बड़ी सफलता दिला सकती है।

जब भी सफर थकाने लगे या उबाऊ लगने लगे, हमें अपनी ऊर्जा को जागृत करने की जरूरत है। उस डर और तकलीफ को पहचानना चाहिए जो हमें परेशान कर रही है। उससे लड़ना चाहिए। हम इसी वक्त अपनी असली ताकत पहचानेंगे। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं तो कोई बाहरी स्थिति हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। पुस्तक 'अवेकन द जायंट विदिन' में लिखा है कि आप विशाल शक्ति के मालिक हैं। उस शक्ति को जगाएं। यह कभी न भूलें कि जिंदगी के सफर में लोगों का साथ और रिश्ते बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। यह साथ हमें तभी मिलेगा, जब हम दूसरों की खुशी और सम्मान को प्राथमिकता देंगे। लोग तभी जुड़ेंगे, जब हम उनका सम्मान करेंगे। अच्छे यात्री यात्रा के दौरान हमेशा अपने सहयात्रियों की तरफ मदद के हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सफर के दौरान किन्हीं परिस्थितियों में उन्हें भी मदद की जरूरत पड़ सकती है।

जीवन के सफर में तीव्रता के बजाय कर्मशीलता और गहराई को महत्त्व देना ज्यादा जरूरी है। भगवदगीता का शाश्वत ज्ञान इस संबंध में एक व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है, जो प्रत्येक मनुष्य के श्रेष्ठ गुणों और उसकी कर्मशीलता को जागृत करने की प्रेरणा देता है। किसी के समक्ष हमें स्वयं को सिद्ध करने की जरूरत नहीं बस कार्य में एकाग्रता की जरूरत है। जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण हमें अपनी विफलताओं को सहज रूप में स्वीकार करने और उनसे सीखने की हिम्मत देता है। यह हिम्मत और प्रेरणा हमें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है।

जीवन के सफर को सुकून से तय करने के लिए पूर्णता और सौ फीसदी सटीकता के भ्रम से भी उबरना पड़ेगा। संपूर्णता की अपेक्षा एक भ्रम है, जो किसी को हमेशा उलझाए रखता है और उसकी यात्रा को दूभर और बोझिल कर देता है। इसी आदत की वजह से लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा समय श्रम और ऊर्जा लेने लगते हैं। इसी प्रकार आवेग में आकर निर्णय लेने की आदत हमें आगे चलकर पश्चताप करने के लिए मजबूर कर देती है। जल्दबाजी और उत्तेजना में लिए गए गलत निर्णय और अस्थिर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अक्सर बड़ी परेशानियां खड़ी कर देती हैं।

कुछ लोगों का सफर तो सिर्फ इसलिए कठिन हो जाता है कि वे सब कुछ खुद ही नियंत्रित करना चाहते हैं। यह आदत अक्सर दुखदायी होती है। हमें इस दुनिया में लगभग हर काम में दूसरों का सहयोग चाहिए होता है। इसलिए अपना एक सहयोग का तंत्र और सामाजिक संपर्क तैयार करके चलना चाहिए। इसके लिए हमें दूसरों का नहीं, अपना रवैया बदलने की आदत डालनी होगी। यह जरूर याद रखने की जरूरत है कि हम इस दुनिया में अगर दूसरे का दिल दुखाने के लिए नहीं आए हैं, तो इसके साथ ही हर किसी की अपेक्षाओं पर खरा उतरना भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है।

चौपाल

बेमौसम बारिश

कभी सूखा तो कभी बेमौसम बारिश देश की कृषि के लिए आफत बनती है। कुई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही, जबकि अब बरसात को अलविदा कहने का समय आ गया है। यह बारिश धान और अन्य मौसमी फसलों के लिए नुकसानदायक है। वहीं, यह हमें बीमारियों की तरफ भी धकेल रही है। सवाल यह है कि बेमौसम बारिश का आखिर क्या कारण है? क्या हमने आधुनिकता की अंधी दौड़ में खुद ही अपने हाथों प्रकृति के विरुद्ध जाकर बेमौसम बारिश को न्योता दे दिया है? कुदरत के आगे इंसान अभी तक बौना है। अगर इंसान ने कुदरत पर विजय सचमुच पा ली होती, तो प्रकृति का कहर हमें परेशान नहीं करता और न ही भारी तबाही का कारण बनता। इसलिए बेमौसम बारिश से फसलों को बर्बाद होने से बचाने और इसके दुष्परिणामों को रोकने के लिए हमें गंभीरता दिखानी होगी। देश की जीडीपी में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए कृषि विशेषज्ञों को चाहिए कि वे ऐसी तकनीक विकसित करें कि मौसम की बेरुखी से होने वाले फसलों के नुकसान से किसानों को बचाया जा सके।

– राजेश कुमार चौहान, जलंधर

शुचिता की चिंता

'सियासी शुचिता' (संपादकीय, 8 सितंबर) पढ़ा। 'एडीआर' की हालिया अध्ययन रपट में यह खुलासा बेहद चिंताजनक है कि देश के जनप्रतिनिधियों में से लगभग 47 फीसद नेता किसी न किसी अपराध में आरोपी हैं। यह रपट इस बात की परिचायक है कि इस समय चरित्र और शुचिता का कोई मूल्य नहीं बचा है। अपने नेताओं का चयन करते हुए शायद जनता चरित्र और ईमानदारी जैसी हमारी सबसे मूल्यवान निधि को कोई प्राथमिकता नहीं देती, अन्यथा ऐसे दागी जनप्रतिनिधियों का चयन संभव नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में उच्च शिक्षा, अच्छे संस्कार और सर्वोच्च स्तर के नैतिक मूल्य हमारी पहली पसंद होने चाहिए। लोकतंत्र में अपनी पसंद के जनप्रतिनिधि चुनते समय हम इन प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं। आज जिस स्तर के जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। यदि राजनीति में शुचिता लानी है, तो हमें चरित्रवान प्रत्याशियों को अपना प्रतिनिधि बनाना होगा।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

प्रेरणादायक जीत

भारत की पुरुष हाकी टीम ने राजगीर में आयोजित एशिया कप में दक्षिण कोरिया को हरा कर शानदार जीत हासिल की है। अपनी टीम के शानदार प्रदर्शन पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को मैच में 4-1 से पराजित किया है। दक्षिण कोरिया की टीम पांच बार की एशिया कप विजेता रही है, जिसे हरा कर भारत ने एशिया हाकी कप की ट्राफी जीती है। इसी के साथ उसने 2026 में होने वाले विश्व हाकी कप में पदार्पण किया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। हाकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और इस खेल में सफलता अर्जित करना बेहद रोमांचकारी और गौरवपूर्ण है। इस टूर्नामेंट में भारतीय हाकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही, जिन्होंने न केवल अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि वे टीम को पूरे हौसले के साथ खेलने के लिए प्रेरित करते रहे। देश की नई पीढ़ी को इस जीत से प्रेरणा लेनी चाहिए।

– वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

बढ़ते आभासी खतरे

सोशल मीडिया में अनुचित सामग्री और 'आनलाइन गेम्स' से फैल रही बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी का नेटवर्क मजबूत करना होगा। इस समय लोगों के साथ हो ररही बैंकिंग धोखाधड़ी को भी रोकने की जरूरत है, क्योंकि यह अब गंभीर समस्या का रूप ले चुकी है। लोग झांसे में आकर अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं। हालांकि जागरूकता के लिए बैंक विशेष कदम उठा रहे हैं, लेकिन नागरिकों को भी इस मामले में सचेत होना चाहिए। दूसरी ओर बच्चे भी आभासी खेल के दीवाने हो रहे हैं। इसका उन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही वे ठगे जा रहे हैं। सरकार को इस पर सख्त होने की जरूरत है, ताकि असामाजिक तत्वों पर रोक लगाई जा सके। समाज यदि जागरूक बनें, तो काफी हद तक आभासी जोखिम को रोका जा सकता है।

– शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 11 सितंबर 2025

शांति प्रयासों पर चोट

कतर की राजधानी दोहा में इस्राइल के हवाई हमलों ने गाजा में संघर्षविराम की उम्मीदों को धुंधला कर दिया है। ये हमले जितने अप्रत्याशित लगते हैं, उतने ही गैरजरूरी भी - खासकर जब शांति के लिए बातचीत चल रही हो। बड़ी बात कि इसके लिए अमेरिका को भी भरोसे में नहीं लिया गया था।

सकते में अमेरिका । इस्राइल की कार्रवाई ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को गहरे असमंजस में डाल दिया है। कतर और इस्राइल, दोनों ही वॉशिंगटन के करीबी सहयोगी हैं। हमास के साथ वार्ता में कतर मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। अब तक उसकी धरती पर सभी पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। जब इस्राइली एयर स्ट्राइक हुई, उस वक्त भी हमास के टॉप लीडर मीटिंग के लिए वहां जुटे थे।

कतर पर हमला

कतर बीच की कड़ी । कतर ने इस हमले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भले ही निशाना वह न हो, लेकिन इस्राइल का हमला सीधे तौर पर उसकी संप्रभुता और उसके अधिकार क्षेत्र के खिलाफ था। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कतर पहले की तरह हमास-इस्राइल वार्ता में रुचि दिखाता है? कतर की भूमिका इसलिए अहम हो जाती है, क्योंकि उस पर सभी पक्षों को भरोसा है। पूरे संघर्ष के दौरान वह हमास और इस्राइल के सीधे संपर्क में रहा है। उसके शांति प्रक्रिया से हटने पर बीच की कड़ी टूटने का डर है।

इस्राइल पर अविश्वास । गाजा में जंग शुरू हुए दो साल होने को हैं और इस बीच ऐसे कई मोड़ आए, जहां लगा कि संघर्ष फैल सकता है। इस्राइल ने पिछले साल सितंबर में लेबनान में हिज्बुल्लाह पर हमले किए थे। फिर इस साल जून में ईरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब इस ताजा हमले ने उसके प्रति अविश्वास को और बढ़ा दिया है। इसके बाद यह सवाल और तीखा हो जाएगा कि नेतन्याहू क्या वाकई में शांति चाहते हैं?

लोगों पर संकट । शांति प्रक्रिया को किसी भी तरह का झटका लगता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा गाजा के लोगों का, जो भयावह मानवीय त्रासदी से जूझ रहे हैं। कतर पर एयरस्ट्राइक से कुछ घंटों पहले ही इस्राइल ने गाजा को खाली करने की चेतावनी जारी की थी। इस्राइली सेना जमीनी स्तर पर बड़ा सैन्य अभियान चलाने की योजना बना रही है। हालांकि वैश्विक स्तर पर इसकी आलोचना हो रही है। UN ने चेताया है कि गाजा में पहले ही अकाल घोषित है, अब अगर वहां लड़ाई तेज होती है, तो आम लोग और भी गंभीर संकट में घिर जाएंगे।

साड्डी दिल्ली

कहां-कहां नेपाल

विवेक शुक्ला

फिरोजशाह रोड पर नेपाल एंबेसी हो, या यमुनापार के कड़कड़डूमा में पशुपतिनाथ मंदिर- नेपाल के ताजा घटनाक्रम का असर यहां के माहौल पर साफ-साफ महसूस किया जा सकता है। दोनों के गेट आजकल बंद ही रहते हैं। इनमें बहुत कम लोग आ जा रहे हैं। यहां का पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। वैसे, दिल्ली में कालकाजी के प्राचीन भैरव मंदिर में भी पशुपतिनाथ जैसे चार मुख वाले शिवलिंग की पूजा होती है, जिसे कुछ लोग पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में भी देखते हैं। अगर बात नेपाल एंबेसी की करें तो लगभग पांच साल पहले 14 जुलाई, 2020 को इसके बाहर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के एक विवादास्पद बयान पर विरोध जताने के लिए बड़ा प्रदर्शन हुआ था। ओली ने दावा किया था कि भगवान राम की अयोध्या नेपाल में है। इसी नेपाल एंबेसी से अफगानिस्तान और भूटान के साथ राजनयिक संबंधों को देखा जाता है। यहां पर राजधानी में रहने वाले नेपाली नागरिकों की आवाजाही लगी रहती है।

राजधानी-NCR में एक मोटे अनुमान के मुताबिक, करीब 5 लाख नेपाली नागरिक रहते हैं। आपको लगभग सभी मशहूर रेस्तरां में नेपाली शेफ मिलेंगे। नेपाली सिक्यॉरिटी के काम से भी जुड़े हैं। ये अधिकतर हिंदू और कुछ बौद्ध भी हैं। उरबा तमांग बीते करीब 15 सालों से साउथ दिल्ली की एक मशहूर सिक्यॉरिटी फर्म में नौकरी करते हैं। उन्हें एक शिकायत है। दिल्ली में बहुत सारे लोग नेपालियों को पूर्वोत्तर का मानते हैं। वैसे यहां बाकी नेपालियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच, नेपाल के कुछ प्रमुख नेताओं के दिल्ली से संबंध रहे। इस लिहाज से पहला नाम तो नेपाल के पांच बार प्रधानमंत्री रहे गिरिजा प्रसाद कोइराला का ही लिया जाएगा। वह किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़े, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) से मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने 1986 में JNU से पीएचडी की थी। इस बीच, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी नेपाली छात्र हर साल पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ साल पहले जब नेपाल में भूकंप के कारण भारी विनाश हुआ था, तब इन्होंने यहां राहत सामग्री एकत्र करके अपने देश में भेजी थी।

एकदा

अपने नाम की रट

अंग्रेजी साहित्य में Alfred Lord Tennyson (1809-1892) विक्टोरियन युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जब वह छोटे थे तो उन्हें घर में जल्दी सोने भेज दिया जाता। कमरे में अंधेरा, सन्नाटा और अकेलापन उन्हें डराने लगता। डर से उन्हें नींद नहीं आती। पिता नास्तिक थे। उन्हें कभी प्रार्थना करना या ईश्वर का नाम लेना सिखाया ही नहीं गया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक जगह लिखा है - एक दिन एक अनोखा उपाय सूझा। जब डर लगा तो अपनी आंखें बंद कर अपना ही नाम दोहराने लगा, 'टेनिसन! टेनिसन! टेनिसन...।' धीरे-धीरे यह मेरे लिए मंत्र-सा बन गया। अपने ही नाम की रट लगाता तो डर कम हो जाता और नींद भी आ जाती। समय बीतने पर उन्होंने महसूस किया कि यह अभ्यास केवल भय मिटाने का साधन नहीं है, उन्हें इससे शांति भी मिलती। जब भी जीवन में चिंता या तनाव आता, वह भीतर ही भीतर नाम दोहरा लेते और उनका मन शांत हो जाता। यह तो उन्हें बहुत बाद में पता चला कि इसे ही लोग ध्यान कहते हैं। बाद में उन्होंने लिखा, 'तुम भगवान का नाम या अपना ही नाम भी अगर दोहराओ, तो भी परिणाम वही होगा।' टेनिसन का अनुभव बताता है कि मनुष्य के भीतर ही एक तरह की शक्ति छिपी है, जो उसका मनोबल बढ़ाते रहती है। बस उसे पहचानने और साधने की जरूरत है। यही स्मरण आत्मशांति और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोल देता है।

Subrata Dhar

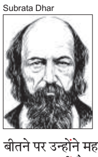

संकलन : **ललित गर्ग**

संघ की 100 साल की यात्रा में भागवतजी का कार्यकाल सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के प्रबल पक्षधर

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

आज 11 सितंबर है। यह दिन अलग-अलग स्मृतियों से जुड़ा है। एक स्मृति 1893 की है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्वबंधुत्व का संदेश दिया और दूसरी स्मृति है 9/11 का आतंकी हमला, जब विश्व बंधुत्व को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। आज के दिन की एक और विशेष बात है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्मदिवस है जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना जीवन समर्पित किया है। संघ परिवार में जिन्हें परम पूजनीय सरसंघचालक के रूप में श्रद्धाभाव से संबोधित किया जाता है, ऐसे आदरणीय मोहन भागवत जी का आज जन्मदिन है।

परिवार से गहरा संबंध । यह एक सुखद संयोग है कि इसी साल संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। मैं भागवत जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। मेरा उनके परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। मुझे उनके पिता, स्वर्गीय मधुकरराव भागवत जी के साथ निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। मैंने अपनी पुस्तक ज्योतिपुंज में मधुकरराव जी के बारे में विस्तार से लिखा भी है। वकालत के साथ-साथ मधुकरराव जी जीवनभर राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित रहे। अपनी युवावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ कार्य की मजबूत नींव रखी।

सत्तर के दशक में बने प्रचारक । मधुकरराव जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि अपने पुत्र मोहनराव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे। एक पारसमणि मधुकरराव ने मोहनराव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी। भागवत जी का पूरा जीवन सतत प्रेरणा देने वाला रहा है। वह 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। सामान्य जीवन में प्रचारक शब्द सुनकर भ्रम हो जाता है कि कोई प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन जो संघ को जानते हैं उनको पता है कि प्रचारक परंपरा संघ कार्य की विशेषता है। गत 100 वर्षों में देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक-युवतियों ने अपना घर-परिवार त्याग करके पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। भागवत जी भी उस महान परंपरा की मजबूत धुरी हैं।

समाज के लिए किया काम । भागवत जी ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उस दौर में प्रचारक के रूप में भागवत जी ने आपातकाल-विरोधी आंदोलन को निरंतर मजबूती दी। उन्होंने कई वर्षों तक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों, विशेषकर विदर्भ में काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में मोहन भागवत जी के कार्यों को आज भी कई स्वयंसेवक स्नेहपूर्वक याद करते हैं। इसी कालखंड में मोहन भागवत जी ने बिहार के गांवों में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने के कार्य में समर्पित रहे।

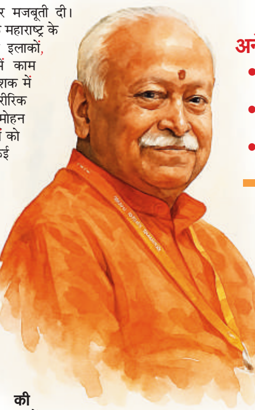

75वें जन्मदिन की अनेकानेक शुभकामनाएं

- आत्मनिर्भर भारत पर है संघ प्रमुख का जोर
- इमरजेंसी के दौरान प्रचारक बने भागवतजी
- युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं मोहनजी

राष्ट्र प्रथम की विचारधारा । वर्ष 2000 में वह सरकार्यवाह बने और यहां भी भागवत जी ने अपनी अनोखी कार्यशैली से हर कठिन परिस्थिति को सहजता और सटीकता से संभाला। 2009 में वह सरसंघचालक बने और आज भी अत्यंत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। भागवत जी ने राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को हमेशा सर्वोपरि रखा।

राष्ट्र को दिशा दी । सरसंघचालक होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है। यह एक पवित्र विश्वास है, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी दूरदर्शी व्यक्तित्वों ने आगे बढ़ाया है और इस राष्ट्र के नैतिक और सांस्कृतिक पथ को दिशा दी है। असाधारण व्यक्तियों ने इस भूमिका को व्यक्तिगत त्याग, उद्देश्य की स्पष्टता और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण के साथ निभाया है। यह गर्व की बात है कि भागवत जी ने न केवल इस विशाल जिम्मेदारी के साथ पूर्ण न्याय किया है, बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति, बौद्धिक गहराई और सहृदय नेतृत्व भी जोड़ा है।

युवाओं की प्रेरणा । भागवत जी का युवाओं से सहज जुड़ाव है और इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ कार्य के लिए प्रेरित किया है। वह लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं और संवाद करते रहते हैं। श्रेष्ठ कार्य पद्धति को अपनाने की इच्छा और बदलते समय के प्रति खुला मन रखना, ये मोहनजी की बहुत बड़ी विशेषता रही है। अगर हम व्यापक संदर्भ में देखते हैं तो संघ की 100 साल की यात्रा में भागवत जी का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। चाहे वह गणवेश परिवर्तन हो, संघ शिक्षा वर्गों में बदलाव हो, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके निर्देशन में संपन्न हुए।

टेक्नॉलजी का उपयोग । कोरोना काल में मोहन भागवत जी के प्रयास विशेष रूप से याद आते हैं। उस कठिन समय में उन्होंने स्वयंसेवकों को सुरक्षित रहते हुए समाजसेवा करने की दिशा दी और टेक्नॉलजी का उपयोग बढ़ाने पर बल दिया। उनके मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने जरूरतमंदों तक हरसंभव सहायता पहुंचाई, जगह-जगह मेडिकल कैंप लगाए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों और वैश्विक विचार को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्थाओं को विकसित किया। हमें कई स्वयंसेवकों को खोना भी पड़ा, लेकिन भागवत जी की प्रेरणा ऐसी थी कि अन्य स्वयंसेवकों की दृढ़ इच्छाशक्ति कमजोर नहीं पड़ी। इस वर्ष की शुरुआत में नागपुर में उनके साथ माधव नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के दौरान मैंने कहा था कि संघ अक्षयवट की तरह है, जो राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है। इस अक्षयवट वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं। इन मूल्यों को आगे बढ़ाने में जिस समर्पण से भागवत जी जुटे हुए हैं, वह हर किसी को प्रेरणा देता है।

पंच परिवर्तन का मार्ग । समाज कल्याण के लिए संघ की शक्ति के निरंतर उपयोग पर भागवत जी का विशेष बल रहा है। इसके लिए उन्होंने पंच परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें स्वबोध, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुम्ब प्रबोधन और पर्यावरण के सूत्रों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। देश और समाज के लिए सोचने वाले हर भारतवासी को पंच परिवर्तन के इन सूत्रों से अवश्य प्रेरणा मिलेगी। संघ का हर कार्यकर्ता वैभव संपन्न भारत माता का सपना साकार होते देखना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए जिस स्पष्ट विज़न और ठोस एक्शन की जरूरत होती है, मोहन जी इन दोनों गुणों से परिपूर्ण हैं। मोहन जी के स्वभाव की एक और बड़ी विशेषता है कि वह मृदुभाषी हैं। उनमें सुनने की भी अद्भुत क्षमता है। यह विशेषता न केवल उनके दृष्टिकोण को गहराई देती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व में संवेदनशीलता और गरिमा भी लाती है।

संगीत और गायन में रुचि । मोहन जी, हमेशा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के प्रबल पक्षधर रहे हैं। भारत की विविधता और भारत भूमि की शोभा बढ़ा रही अनेक संस्कृतियों और परंपराओं के उत्सव में भागवत जी पूरे उत्साह से शामिल होते हैं। वैसे बहुत कम लोगों को पता है कि भागवत जी व्यस्तता के बीच संगीत और गायन में भी रुचि रखते हैं। वह विभिन्न भारतीय वाद्ययंत्रों में भी निपुण हैं। पठन-पाठन में उनकी रुचि, उनके अनेक भाषणों और संवादों में साफ दिखाई देती है।

आत्मनिर्भर भारत पर जोर । पिछले दिनों देश में जितने सफल जन-आंदोलन हुए चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भागवत जी ने पूरे संघ परिवार को इन आंदोलनों में ऊर्जा भरने के लिए प्रेरित किया। मैं पर्यावरण से जुड़े प्रयासों और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को जानता हूं। मोहन जी का बहुत जोर आत्मनिर्भर भारत पर भी है। कुछ ही दिनों में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो जाएगा। यह भी सुखद संयोग है कि विजयादशमी का पर्व, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और संघ का शताब्दी वर्ष एक ही दिन आ रहे हैं।

ऐतिहासिक अवसर । यह भारत और विश्वभर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघचालक हैं, जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। एक युवा स्वयंसेवक से सरसंघचालक तक की उनकी यात्रा उनकी निष्ठा और वैचारिक दृढ़ता को दर्शाती है। विचार के प्रति पूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन करते हुए उनके नेतृत्व में संघ कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है। मैं मां भारती की सेवा में समर्पित भागवत जी के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। उन्हें जन्मदिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं।

ऐपल की नई पेशकश में है कितना दम

निमिष दुबे

आकृति राणा

अठारह साल पहले, Steve Jobs ने Macworld के दौरान पहली बार iPhone दिखाया था। और शायद इतिहास में किसी एक गैजेट ने उतना कोहराम नहीं मचाया, जितना उस पहले iPhone ने। हां, उसमें कई कमियां थीं। फिर भी वह अपनी किस्म का इकलौता फोन था। उसका काम करने का तरीका, उसका display और डिजाइन सबसे अलग थे। हां, उसका दाम उस समय भी ज्यादा ही था (तीस-पैंतीस हजार रुपये 2007 में काफी होते थे!), मगर वह एक अनोखा, जादुई फोन था।

एक नहीं, चार फोन । आज iPhone विश्व का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन ही नहीं, बल्कि भारत का भी 2025 का सबसे लोकप्रिय फोन है। मंगलवार को Apple ने इसका नवीनतम संस्करण - iPhone 17 series पेश किया, जिसमें एक नहीं चार iPhone हैं (iPhone 17, iPhone Air, iPhone17 Pro और iPhone 17 Pro Max)। इनमें विश्व का सबसे शानदार hardware है, चाहे वो processor, display, कैमरा या बैटरी हो। हां, कुछ कमियां अभी भी हैं (बैटरी अभी भी चींटी की गति से चार्ज होती है) लेकिन फिर भी यह लगभग हर मायने में फोनों का सम्राट कहे जाने लायक है।

खास नहीं, आम फोन । iPhone smartphones की दौड़ में सबसे आगे अवश्य निकल गया है, लेकिन इस चक्कर में पीछे छूट गया है उसका वह गुण जो उसे सबसे अलग रखता था। एक तरह से देखा जाए तो उसमें वह जादू न रहा जो स्टीव जॉब्स के समय में था। हमारे एक मित्र ने इस बात को सीधे-सीधे कहा, 'पहले आप iPhone इसलिए लेते थे क्योंकि आप सबसे अलग लगना चाहते थे, आज इसलिए लेते हैं क्योंकि आप सबकी तरह बनना चाहते हैं - आजकल iPhone खास नहीं, आम फोन है!'

कॉमन रूम

हार्डवेयर पर फोकस । पुराने और नए iPhone के बीच में ये अंतर iPhone 17 के लॉन्च के दौरान साफ नजर आ रहा था। जॉब्स जब iPhone दिखाते थे तो उनका जोर software और apps पर रहता था। वह दिखाना चाहते थे कि iPhone ऐसी चीजें कर सकता था और ऐसे apps चला सकता था जो दूसरे phones की काबिलियत से बाहर था। तब उच्च कोटि के apps और games (जैसे Flipboard और Infinity Blade) iPhone पर पहले देखे जाते थे और Android पर बाद में आते थे। लेकिन iPhone 17 में hardware कितना सटीक है, इस पर ध्यान दिया गया है।

सबसे बेहतर का दावा । नए iPhone के कैमरे कमाल के हैं और iPhone Air के पतलेपन की तो खास तारीफ की गई। जॉब्स के समय में iPhone 4 विश्व का सबसे पतला फोन बना था। फिर भी ज्यादा बात उसकी कार्यकुशलता और अनोखे design (वह पहला जाना माना फोन था जिसके side सीधे थे और जिसके सामने और पीछे शीशा था) की हुई थी, न कि उसके पतलेपन की! बात सीधी थी- iPhone उस समय अलग फोन होने का दावा करता था, अब वो सबसे बेहतर होना का दावा करता है।

कुक की सोच का आईना । यह बदलाव अच्छा है या बुरा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि iPhone विश्व का सबसे लोकप्रिय फोन है, लेकिन उसमें अब Tim Cook की सुनियंत्रित मेहनत और सोच झलकती है न कि स्टीव जॉब्स का जादू!

बापू को मिला मिथिला नरेश का साथ

तेजकर झा

दक्षिण अफ्रीका के नटाल में भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ महात्मा गांधी ने आवाज उठाई थी। अपने आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने को वह भारत भी आए थे। यह 1896 की बात है, जब कलकत्ता में गांधीजी की मुलाकात सुरेंद्र नाथ बैनर्जी से हुई। उन्होंने गांधीजी के प्रयासों की सराहना की, लेकिन यह भी कहा - 'मुझे डर है कि लोग शायद आपके इस कार्य में रुचि न दिखाएं। इसकी वजह यह है कि हमारे देश में ही दक्षिण अफ्रीका से कम समस्याएं नहीं।'

कलकत्ता की निराशा । कलकत्ता में एक भी गोष्ठी नहीं हो सकी। इस बीच दक्षिण अफ्रीका से एक जरूरी तार आया और गांधीजी को लौटना पड़ा। लेकिन, आगे चलकर उन्हें अपने आंदोलन में एक मजबूत साथ मिला - मिथिला नरेश सर लक्ष्मीश्वर सिंह का। वह खंडवला राजवंश के 20वें राजा थे। उनका शासन 1878 से 1898 तक रहा।

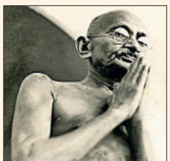

टाइम मशीन

कानून का विरोध । नटाल में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव से आहत लक्ष्मीश्वर सिंह ने इस मुद्दे को ब्रिटिश राज के सामने लाने का प्रयास किया। नटाल की प्रांतीय संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसका उद्देश्य भारतीयों के आवागमन को रोकना था। लक्ष्मीश्वर सिंह को इसकी जानकारी हुई, तो उन्होंने 'द टाइम्स ऑफ लंदन' के संपादक को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने सवाल उठाया कि नटाल में भेदभाव को नस्लीय न बताकर श्रमिकों से जुड़ा मामला कहा जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ब्रिटिश मजदूरों से भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए।

बापू का पत्र । लक्ष्मीश्वर सिंह के प्रयासों के बारे में जब गांधीजी को पता चला, तो वह बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने 10 जुलाई, 1897 को राजा लक्ष्मीश्वर को एक पत्र लिखा।

मदद की अपील । गांधीजी का संदेश था, '...हमारे पास गिनती के दिन शेष हैं। नटाल में भारतीयों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी किया जा रहा है और नटाल को भारतीयों की आवश्यकता भी है। नटाल सरकार हमे बंधुआ बना रही है, वह हमें स्वतंत्र नहीं देखना चाहती। क्या देश और भारतीय सरकार हमारी मदद करेगी? क्या प्रवासी भारतीयों को बंधुआ बनने से रोका जा सकता है? हमारा आपसे आग्रह है कि कृपया इस दिशा में अपने प्रयासों को और बढ़ाने की कृपा करें, आशा है हमें न्याय मिलेगा।'

महाराजा की पेशकश । इन पत्रों से इतना स्पष्ट होता है कि मिथिला नरेश उन कुछ सीमित व्यक्तियों में थे, जिनका प्रभाव साम्राज्य की सत्ता और आम जन पर एक समान था। गांधीजी के पत्र के जवाब में उन्होंने 12 अगस्त, 1897 को अपने कार्यालय को निर्देशित करते हुए लिखा, 'गांधी महोदय को उनके पत्र और दस्तावेज के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जाए। नटाल में प्रवासी भारतीयों के लिए क्या किया जाए, कौन-से कदम उठाए जाएं - इन विषय पर वह अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मैं सदा तत्पर हूं।'

(किताब 'राज दरभंगा : धर्म संरक्षण से लोक कल्याण तक' के अंश पर आधारित, पब्लिकेशन - ई समाद)

मैं ऊपर, आसमां नीचे

राहुल पाण्डेय

तेजी से बदल रहे आज के दौर में रोजगार हो, या रोजगार में तरक्की, इसकी योजना महज किस्मत पर नहीं छोड़ी जा सकती। तरक्की का यह सफर थोड़ा तेज और आसान हो जाता है, अगर आप प्रशिक्षकों की मदद लेते हैं। Intuit में प्रॉडक्ट डिवेलपमेंट की वाइस प्रेजिडेंट निधि गोपाल इसी पेशेवर योजना की एक मिसाल हैं। उन्होंने अपने सफर में अलग-अलग तकनीक और क्षेत्रों में काम किया। इन अनुभवों ने उनकी निर्णय लेने की क्षमताओं को पैना किया और उन्हें मजबूत फैसले लेने में सक्षम बनाया। शुरू में उन्होंने पाया कि कुछ तकनीकों पर उनकी पकड़ उतनी गहरी नहीं थी। तब उन्होंने उसमें वक्त लगाया और अपनी नींव को मजबूत किया। आज Intuit में वह अपनी टीम के साथ मिलकर AI पर काम कर रही हैं। इस बदलाव के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्ससस, ऑस्टिन से एक साल का AI और ML का पोस्टग्रैजुएट प्रोग्राम किया। बाकी महिलाओं को निधि से प्रेरणा मिल सकती है कि कैसे अलग-अलग क्षेत्रों में सीखना आपको ऐसी ऊर्जा से भरता है, जिससे करियर का सफर उतना टेढ़ा नहीं रह जाता। इसके लिए एक जुनून चाहिए होता है। इसी जुनून ने निधि को रसद, सप्लाई चेन, शिक्षा और तेल-गैस जैसे उद्योगों में काम करने का मौका दिलाया। निधि ने कई वर्षों तक जान-बूझकर बड़ी कंपनियों से निकलकर स्टार्टअप का रुख किया। वहां उन्होंने प्री-सेल्स, सेल्स, इंजीनियरिंग और लीडरशिप में अलग-अलग रोल अदा किए। इन अनुभवों ने न सिर्फ उनकी तकनीकी गहराई को बढ़ाया, बल्कि उन्हें एक सफल विशेषज्ञ भी बनाया। जाहिर है, करियर में तरक्की के लिहाज से अनुभव काफी ज्यादा मायने रखता है। जितना व्यापक अनुभव, उतनी ऊंची उड़ान।

निधि गोपाल

आधी दुनिया

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें www.speakingtree.nbt.in

शांति की तलाश में अशांति का सामान तो नहीं खरीद रहे

प्रेम रावत जी

इस संसार में आना-जाना उसी तरह चलता रहता है, जैसे समुद्र में लहरें और आसमान में बादल - जैसे सूरज हर सुबह निकलता है और हर शाम अस्त होता है। यही है हमारी जिंदगी। यह एक दिन का सूरज है - एक सवेरा, एक दोपहर, एक शाम। सूरज के निकलने से पहले अंधेरा था और ढलने के बाद फिर अंधेरा होगा। पर जो दिन हमें मिला, वह जीवन का है। उस दिन का उपयोग हम कैसे करते हैं, महत्वपूर्ण यही है।

'मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा।' आसपास काल मंडरा रहा है। वह मौके का इंतजार कर रहा है, पर उसकी परवाह ही नहीं, क्योंकि घमंड के नशे में कुछ पता ही नहीं चलता। घमंड सोचने पर मजबूर करता है, 'मैंने ये कर लिया, मैं ये हूं! मेरा ये है, मेरा वो है!' और हम भूल जाते हैं कि यहां क्यों आए? कबीरदास जी कहते हैं, 'तुम्हारा जन्म हुआ है, ताकि तुम उस चीज को पहचानो, उसको जानो और अपने जीवन को सफल बनाओ।' लोग लक्षणों पर ध्यान देते हैं, बीमारी पर नहीं। मेरा प्रयास बीमारी को खत्म करना है। जो लोग स्वयं से अनजान हैं, वे नहीं जानते कि वे कौन हैं? शांति दूर करने वाले लक्षण हैं - लालच, युद्ध, स्वार्थ, हिंसा और विश्वास की बढ़ती कमी। लेकिन हम शांति पाने के लिए बाहर भटकते हैं, पर यह तो हर इंसान के हृदय में निवास करती है। जब इस सांस का मूल्य समझ सकेंगे, तब पता चल जाएगा कि जीवन क्या है। जब आपके भीतर दीप जलता है, उम्मीद का सागर नजर आने लगता है। अगर अपने आप से सवाल पूछें कि मैं कुछ हूं या कुछ नहीं? तभी अपने अस्तित्व का पता चलता है। वह कौन-सी चीज है, जो हमें जीवित रखती है?

आखिरकार पता चलता है कि शांति पाने की जो अभिलाषा है, वही बार-बार हमें जीवित रखती है। इसीलिए कहा गया है कि मन के भीतर जब क्रांति की लहर है, तो शांति कैसे मिल सकती है। अपनी दिव्यता तलाशने का प्रयास होना चाहिए।

प्रस्तुति : आर.डी. अग्रवाल 'प्रेमी'

आर.एन.आई. नं. 510/57 © सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन: 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय: दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क: 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य: सोमवार से शनिवार: नेपाली 5 रु.; रविवार: नेपाली 6 रु. संपादक (दिल्ली मार्केट): आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

Machine Translated by Google

THE HINDU

आस्थावान व्यक्ति: नए उपराष्ट्रपति

राज्यसभा में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने में मददगार साबित हो सकते हैं । किशोरावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में

सी शामिल हुए 68 वर्षीय पी. राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा को संघ परिवार के एजेंडे से जोड़ने का एक और प्रयास है। श्री राधाकृष्णन 1974 तक तमिलनाडु जनसंघ की कार्यकारिणी के सदस्य थे—यह वह समय था जब तमिलनाडु में संघ परिवार की उपस्थिति नाममात्र की थी और उनका राजनीतिक जुड़ाव स्पष्ट रूप से विचारधारा से प्रेरित था, न कि करियरवाद से।

9 सितंबर, 2025 को, वे भारत के उपराष्ट्रपति बने, जो एक ओर उनकी वैचारिक निष्ठा का पुरस्कार था, तो दूसरी ओर आरएसएस में उनकी यात्रा में एक मील का पत्थर। उन्होंने 752 वैध मतों में से 452 मत प्राप्त किए और इंडिया ब्लॉक के न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराया। वे 1998 और 1999 में कोयंबटूर से दो बार लोकसभा के लिए चुने गए, जहाँ उन्हें अन्नाद्रमुक और फिर द्रमुक का समर्थन प्राप्त भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुना गया। उन्होंने संसदीय समितियों और शेयर बाजार घोटाले की जाँच करने वाली एक विशेष समिति में भी कार्य किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया।

2004 से 2007 तक, भाजपा के राज्य अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने 93 दिनों की "रथ यात्रा" की, जिसमें नदी जोड़ो की वकालत, अस्पृश्यता को समाप्त करना, आतंकवाद का मुकाबला करना और समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देना शामिल था।

झारखंड (2023) और महाराष्ट्र (2024) के राज्यपाल के रूप में, श्री राधाकृष्णन ने अपने प्रशासनिक अनुभव का विस्तार किया और अपने राजनीतिक कद को बढ़ाया, लेकिन उनकी नई भूमिका एक कठिन परीक्षा होगी। उपराष्ट्रपति के रूप में, वह राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करेंगे, जो उनके राजनीतिक कौशल की परीक्षा होगी। उन्होंने अतीत में संघवाद और केंद्र-राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के समर्थन में बात की है, लेकिन भाजपा और आरएसएस का सामान्य झुकाव सत्ता के केंद्रीकरण की ओर है। हाल के वर्षों में संसद की भूमिका कमजोर हुई है, जबकि कार्यपालिका ने अपनी शक्ति का अभूतपूर्व स्तर तक विस्तार किया है। राज्यसभा को विशेष रूप से विधेयकों को वित्त विधेयकों के रूप में मनमाने ढंग से वर्गीकृत करने से कमजोर किया गया है, जिन्हें इसके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यों की एक परिषद के रूप में राज्यसभा की अवधारणा हमेशा से सिद्धांत में अधिक व्यवहार में मौजूद थी, लेकिन इसका जानबूझकर क्षरण एक हालिया विकास है। हाल के वर्षों में सरकार और विपक्ष के बीच संबंध शत्रुतापूर्ण और विषाक्त हो गए हैं। संसदीय समितियाँ भी विचार-विमर्श के मंच की बजाय निरर्थक बयानबाज़ी का अखाड़ा बन गई हैं। श्री राधाकृष्णन के सामने एक चुनौती है। अपने कुशल व्यवहार से, वे सरकार और विपक्ष को बेहतर सहयोग और कम आक्रामक रुख अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

पीढ़ीगत क्रोध

दमन के बाद हिंसक शून्यवाद नेपाल में लोकतंत्र के लिए खतरा

टी मंगलवार को नेपाल में जो उथल-पुथल हुई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने संसद, सुप्रीम कोर्ट, राजनीतिक आवासों और मीडिया कार्यालयों को आग लगा दी और कैदियों को रिहा कर दिया, उसे पिछले दिन की कार्रवाई की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है जिसमें 19 युवा प्रदर्शनकारी मारे गए थे। प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे के बाद की ये कार्रवाइयां एक हिंसक शून्यवाद को उजागर करती हैं जो नेपाल की कड़ी मेहनत से हासिल की गई लोकतांत्रिक उपलब्धियों को खत्म करने की धमकी देती है। "जेन जेड विरोध प्रदर्शन" नेपाल की पुरानी राजनीतिक शिथिलता से हताशा के कारण पैदा हुए थे। 2005 के विजयी "जन आंदोलन II" के दो दशक से भी कम समय के बाद, निरंकुश राजशाही को उखाड़ फेंका गया और "नया नेपाल" का वादा किया गया, राजनीतिक प्रतिष्ठान ने केवल अस्थिरता और स्वार्थी शासन दिया है। 1990 के दशक से, नेपाल में 30 कार्यकालों में 13 सरकार प्रमुख बदल चुके हैं। मुख्यधारा की नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल और सीपीएन-माओवादी केंद्र के नेताओं ने चुनावी जनादेश की बजाय अनैतिक गठबंधनों को प्राथमिकता दी है। केपी ओली और शेर बहादुर देउबा जैसे नेताओं ने 2000 के दशक में जन आंदोलन II और संविधान सभा प्रक्रिया का समर्थन करने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई, जबकि माओवादी नेता पुष्प कमल दहल ने सत्ता में बने रहने को प्राथमिकता दी है। इसके परिणाम भयावह हैं: अर्थव्यवस्था धन प्रेषण पर निर्भर है, जिसके कारण युवाओं का भारी पलायन हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा "सबसे कम विकसित" कहे जाने वाले देश में विविधीकरण विफल हो रहा है।

देश की संभावनाओं को बर्बाद होते देख बड़ी हुई एक पूरी पीढ़ी के मोहभंग ने अब नई राजनीतिक ताकतों को जन्म दिया है। इनमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह जैसे निर्दलीय शामिल हैं, जो विकल्पों के लिए जनता की सच्ची भूख को दर्शाते हैं। हालाँकि, इन नई आवाज़ों द्वारा अपनाए गए कुछ रुख चिंता पैदा करते हैं। श्री.

शाह का कार्यवाहक सरकार के बजाय निर्वाचित संसद को भंग करके चुनाव कराने का आह्वान, या तो लोकतांत्रिक अपरिपक्वता या उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक, लोकतांत्रिक मानदंडों को त्यागने की इच्छा को दर्शाता है। बांग्लादेश की हालिया उथल-पुथल, जिसके कारण लोकतांत्रिक पतन हुआ, एक चेतावनी भरी कहानी पेश करती है। नेपाल को राज्य और नागरिक समाज संस्थाओं के विनाश को लोकतांत्रिक नवीनीकरण समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह संकट स्थिरता और दीर्घकालिक संवैधानिक सुधारों की माँग करता है जो संविधान सभा की प्रक्रिया से पहले किए गए वादों को पूरा करें, लेकिन संविधान लिखे जाने तक ये वादे कमज़ोर पड़ गए थे।

प्रत्यक्ष चुनावों वाली और निर्वाचित संसद के प्रति जवाबदेह राष्ट्रपति प्रणाली अस्थिरता के चक्र को तोड़ सकती है। लेकिन तत्काल शांति के बिना संवैधानिक सुधार का कोई मतलब नहीं है। नेपाली सेना को नागरिक लोकतांत्रिक कर्ताओं के लिए नियंत्रण फिर से स्थापित करने और सुधारों की रूपरेखा तैयार करने हेतु आगे आना होगा। विकल्प - हिंसक शून्यवाद को लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का जामा पहनाने की अनुमति देना - उन नींवों को नष्ट करने का जोखिम उठाता है जिन पर किसी भी "नए नेपाल" का निर्माण होना चाहिए।

कच्चातीवु, पाक जलडमरूमध्य विवादों पर आगे का रास्ता

निर्मला Chandrahasan

वकील है, श्रीलंका का सर्वोच्च न्यायालय

मैं भारत ने ऐतिहासिक रूप से पंचशील सिद्धांतों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, के माध्यम से क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति को आकार दिया है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सहयोग, और हाल ही में, अपनी "पड़ोसी प्रथम नीति" के साथ। इस रुख ने दक्षिण एशिया में शांति और परस्पर निर्भरता को बढ़ावा दिया है। हालाँकि, श्रीलंका के साथ उसके अनसुलझे मुद्दे, जैसे पाक जलडमरूमध्य में समुद्री संकट और कच्चातीवु द्वीप की संप्रभुता, चुनौतियाँ पेश करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान अप्रैल 2025 में कोलंबो में हुई बैठक में, दोनों सरकारों ने इन दीर्घकालिक चिंताओं पर पुनर्विचार किया। श्री मोदी ने शेरी मुद्दे पर एक "मानवीय दृष्टिकोण" पर ज़ोर दिया - जो आजीविका और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखे। यह दृष्टिकोण तभी सफल हो सकता है जब भारत और श्रीलंका सहयोग की भावना से पारिस्थितिक अनिवार्यताओं और ऐतिहासिक शिकायतों का समाधान करें।

आजीविका और संरक्षण में मतभेद तमिलनाडु तट और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मछुआरा समुदाय सदियों से पाक जलडमरूमध्य को साझा करते रहे हैं। लेकिन आज श्रीलंका में भारतीय जहाजों द्वारा मशीनीकृत तली में मछली पकड़ने के कारण विवाद और बढ़ गए हैं।

पानी.

संयुक्त राष्ट्र कानून सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र समुद्री स्वास्थ्य एजेंसी (UNCLOS) न केवल समुद्री संसाधनों के समतापूर्ण उपयोग पर बल्कि उनके संरक्षण पर भी ज़ोर देती है। इसी प्रकार, एफएओ की ज़िम्मेदार मत्स्य पालन आचार संहिता, 1995, बॉटम ट्रॉलिंग जैसी विनाशकारी प्रथाओं को अस्वीकार्य मानती है।

श्रीलंका ने 2017 में बॉटम ट्रॉलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन सैकड़ों भारतीय ट्रॉलर अभी भी इस प्रथा को जारी रखे हुए हैं, जिससे प्रवाल तल और झींगा आवासों को नुकसान पहुँच रहा है और मछलियों का भंडार घट रहा है। विडंबना यह है कि तमिलनाडु के छोटे कारीगर, जो पारंपरिक टिकाऊ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, भी इससे पीड़ित हैं: ट्रॉलर उद्योग ने उनके तटवर्ती संसाधनों को समाप्त कर दिया है, जिससे उन्हें विवादित जलक्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

इस प्रकार, यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि तमिल समुदायों के भीतर आजीविका का संघर्ष भी है - व्यवसायिक ट्रॉलर संचालकों और पारंपरिक शेरों के बीच, जो जीविका के लिए समुद्र पर निर्भर हैं।

एक स्थायी समाधान के लिए कारीगर शेरों और ट्रॉलर संचालकों की ज़रूरतों के बीच अंतर करना ज़रूरी है। ट्रॉलर संचालक सहानुभूति का दावा नहीं कर सकते क्योंकि उनका व्यावसायिक लाभ समुद्री स्थिरता और सामुदायिक कल्याण की कीमत पर है। छोटी नावों के कारीगर शेर "अनादि काल से" इन जलक्षेत्रों में डूबते रहे हैं और उनकी दुर्दशा मानवीय सहायता की माँग करती है।

इस पर बातचीत के माध्यम से काम किया जा सकता है भारतीय और श्रीलंकाई शेर संगठनों के बीच। श्रीलंकाई शेरों की सहमति से, वे कोटा या विनियमित कार्यक्रम तय कर सकते हैं।

तमिलनाडु के छोटे शेरों के लिए विशिष्ट दिनों या मौसमों पर सीमित शिंग अधिकार निर्धारित किए जाएंगे, जब तक कि भारत के स्टॉक ठीक नहीं हो जाते।

सामुदायिक संवेदनशीलता होनी चाहिए। श्री श्रीलंकाई तमिल सांसद और तमिल मीडिया, तमिलनाडु में श्रीलंका के लंबे गृहयुद्ध के दौरान उत्तरी शरणार्थियों द्वारा झेली गई कठिनाइयों को उजागर करके एक भूमिका निभा सकते हैं। इनमें से कई परिवारों को दशकों की आय का नुकसान तब हुआ जब सेना ने संघर्ष के दौरान समुद्र तक पहुँच प्रतिबंधित कर दी थी। उन्हें हमलावरों के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक नुकसान के सह-पीड़ितों के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए। ऐसे कदम सद्भावना को बढ़ावा देंगे। यह याद रखना ज़रूरी है कि श्रीलंकाई संघर्ष के दौरान, तमिलनाडु में तमिल शरणार्थियों का सहानुभूतिपूर्वक स्वागत किया गया, उन्हें शिविरों में ठहराया गया और सहायता प्रदान की गई। भाईचारे के इन बंधनों को बनाए रखना आवश्यक है।

भ्रांतियाँ दूर करना: सार्वजनिक बहस में अक्सर पाक जलडमरूमध्य में स्थित छोटे से निर्जन टापू कच्चाथीवु को शेरीज़ विवाद की जड़ बताया जाता है। यह भ्रामक है।

कच्चाथीवु का क्षेत्रफल आधे वर्ग मील से भी कम है, तथा सेंट जॉर्ज चर्च को छोड़कर यह बंजर है।
एंथनी, जहां 1974 की भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा संधि के तहत तमिलनाडु के शेरमेन वार्षिक उत्सव के लिए आते रहते हैं।

1974 के सीमा समझौते के तहत यह टापू श्रीलंकाई जलक्षेत्र में आ गया। यह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, सीमा संधियाँ पवित्र होती हैं (पैक्टा संट सर्वदा)। वैश्विक व्यवस्था को नुकसान पहुँचाए बिना इन्हें एकतरफ़ा तौर पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता - ठीक वैसे ही जैसे चीन द्वारा भारत के साथ अपनी निर्धारित सीमाओं पर विवाद अस्थिरता पैदा करता है।

"इंदिरा गांधी ने यह द्वीप सिरीमावो भंडारनायके को उपहार में दिया था" जैसे मिथकों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। वास्तव में, भारत ने निर्णय लेने से पहले संप्रभुता के ऐतिहासिक प्रमाणों का मूल्यांकन किया था। अभिलेखों से पता चलता है कि श्रीलंका का प्रशासनिक नियंत्रण पुर्तगाली और डच शासन काल से, और उससे भी पहले जन राज्य के तमिल राजाओं के समय से था।

निम्नलिखित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मिसालें मौजूद हैं। मिंक्वियर्स और एक्रेहोस मामले (फ्रांस बनाम यूनाइटेड किंगडम, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 1953) में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने डची ऑफ नॉर्मंडी के माध्यम से फ्रांस के ऐतिहासिक दावे के बावजूद, ब्रिटेन को संप्रभुता प्रदान की, क्योंकि उसने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था। इसी प्रकार, भारत ने स्वीकार किया कि श्रीलंका का दावा ज़्यादा मज़बूत था।

एक अन्य उदाहरण भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ का रण मध्यस्थता (1968) है।

इस प्रकार, कच्चातीवु को पुनः प्राप्त करना कोई प्रश्न नहीं है न्याय का नहीं, बल्कि राजनीतिक बयानबाज़ी का मामला है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक सुलझा हुआ मुद्दा बना हुआ है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि शिंग अधिकार एक अलग मामला है - यह द्वीप पर संप्रभुता से जुड़ा नहीं है।

पाक जलडमरूमध्य और आस-पास के जलक्षेत्रों को भारतीय और श्रीलंकाई कानून के तहत "ऐतिहासिक जलक्षेत्र" के रूप में मान्यता दी गई है - ऐसे क्षेत्र जहाँ संप्रभुता के अधिकार सामान्य प्रादेशिक समुद्रों की तुलना में और भी अधिक मजबूत हैं।

इस प्रकार, स्पष्ट सहमति के बिना कोई "निर्दोष मार्ग का अधिकार" या तीसरे राज्य का अधिकार नहीं है।
ऐतिहासिक अधिकारों की न्यायिक मान्यता मद्रास उच्च न्यायालय के अन्नाकुमारू पिल्लई बनाम मुथुपायल एवं अन्य (1904) मामले से शुरू होती है, जिसमें पारंपरिक मोती और शंख के आधार पर दावों को बरकरार रखा गया था। इसलिए, 1974 में भारत द्वारा समुद्री सीमा को स्वीकार करना मनमाना नहीं था, बल्कि कानूनी रूप से ऐतिहासिक मिसाल के अनुरूप था।

यूएनसीएलओएस (अनुच्छेद 123) अर्ध-संलग्न समुद्रों—जैसे पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी—में सहयोग को प्रोत्साहित करता है। यहाँ, संयुक्त संसाधन प्रबंधन न केवल आदर्श है, बल्कि अनिवार्य भी है।

बाल्टिक सागर मत्स्य पालन में मॉडल मौजूद हैं
सम्मेलन जहां लातविया, पोलैंड और यूरोपीय संघ ने संरक्षण के लिए कोटा साझा किया संसाधन।

भारत और श्रीलंका समान ढांचे को लागू कर सकते हैं, जैसे कि शिंग दिवसों और पकड़ के लिए समान कोटा, समुद्री जीव विज्ञानियों के लिए कच्चातीवु पर एक संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना, ताकि वे संसाधनों की निगरानी कर सकें और टिकाऊ तरीकों का सुझाव दे सकें, तथा भारत के 200 समुद्री मील के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में गहरे समुद्र में शिंग को बढ़ावा दे सकें, जिससे तट के निकटवर्ती जल पर दबाव कम हो और अवैध पारगमन में कमी आए।

अच्छे पड़ोस की नीति की ओर भारत का क्षेत्रीय नेतृत्व न केवल भौगोलिक, बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से भी आकार लेता है। श्रीलंका के साथ, ये संबंध विशेष रूप से गहरे हैं। इन्हें बनाए रखने के लिए, विवादों का समाधान लोकलुभावन बयानबाजी के बिना, बल्कि शांत सहयोग, कानूनी मान्यता और साझा आजीविका सुरक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए कई स्तरों की आवश्यकता है, जैसे सरकार-दर-सरकार वार्ता (विश्वास और संधि दायित्वों को बनाए रखना) और राज्य/प्रांतीय सहभागिता (तमिलनाडु और श्रीलंका की उत्तरी प्रांतीय परिषद और सामुदायिक संवाद को शामिल करना, लोगों के बीच सहानुभूति को प्रोत्साहित करना जो मीडिया की विकृतियों पर काबू पाती है)।

यदि समझदारी से निपटा जाए तो कच्चाथीवु और पाक जलडमरूमध्य मुद्दे संघर्ष के बजाय सहयोग के प्रतीक बन सकते हैं।

भारत और श्रीलंका न केवल समुद्री सीमाओं के साथ-साथ सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक संबंधों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। शेरीज़ मुद्दे के लिए दोनों समुदायों के साथ निष्पक्षता की आवश्यकता है, जिसमें कारीगरों की आजीविका और पारिस्थितिक स्थिरता को प्राथमिकता दी जाए। इस बीच, कच्चातीवु मुद्दा कानूनी रूप से सुलझा लिया गया है - अब इसे संसाधनों के प्रबंधन की वास्तविक समस्या पर हावी नहीं होना चाहिए। एक सहयोगात्मक शेरीज़ व्यवस्था अपनाकर, गहरे समुद्र के विकल्पों में निवेश करके और ऐतिहासिक कानूनी समझौतों का सम्मान करके, तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के शेर टकराव से सहयोग की ओर बढ़ सकते हैं। कूटनीति के लंबे चक्र में, छोटे विवादों को बड़े दृष्टिकोण पर हावी नहीं होना चाहिए: दक्षिण एशिया में शांति, समृद्धि और आपसी सम्मान।

यदि विवेक से काम लिया जाए तो कच्चातीवु और पाक जलडमरूमध्य मुद्दे संघर्ष के बजाय सहयोग के प्रतीक बन सकते हैं

एससीओ मार्ग पर एक संयुक्त और नई यात्रा

जू फेइहोंग

चीन का है भारत में राजदूत

एल पिछले सप्ताह, मुझे आपका स्वागत करने का सौभाग्य मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन में, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए चीन का दौरा करें और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और श्री मोदी के बीच बैठक में भाग लें। यह एकजुटता और मैत्री का शिखर सम्मेलन है। 24 वर्षों के विकास के बाद, एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बन गया है। एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन इस संगठन की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन रहा है।

श्री मोदी सहित 23 देशों के नेता या प्रतिनिधि तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख मित्रता को नवीनीकृत करने, सहयोग की संभावनाएं तलाशने, साझा विकास की तलाश करने तथा एससीओ को उच्च गुणवत्ता वाले विकास के एक नए चरण में आगे बढ़ाने के लिए एकत्र हुए।

एक उच्च-लाभदायक शिखर सम्मेलन । इसके सार्थक परिणाम सामने आए। तियानजिन घोषणापत्र में "चार सुरक्षा केंद्रों" की स्थापना की घोषणा की गई, जिनमें सुरक्षा चुनौतियों और खतरों का मुकाबला करने के लिए एससीओ सार्वभौमिक केंद्र और एससीओ मादक पदार्थ निरोधक केंद्र शामिल हैं, और एससीओ विकास बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया। एससीओ के सदस्य-देशों ने बयान जारी कर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के समर्थन में एक निष्पक्ष रुख और द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की उपलब्धियों की रक्षा के लिए एक न्यायसंगत आवाज़ व्यक्त की।

यह शिखर सम्मेलन विकास पर केंद्रित था। नेताओं ने अगले दशक के लिए एससीओ की विकास रणनीति को अपनाया।

इस पृष्ठभूमि में, श्री शी जिनपिंग ने घोषणा की कि चीन ऊर्जा, हरित उद्योग और डिजिटल अर्थव्यवस्था में चीन-एससीओ सहयोग के लिए तीन प्रमुख मंच स्थापित करेगा, और वैज्ञानिक एवं तकनीकी नवाचार, उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए तीन प्रमुख सहयोग केंद्र स्थापित करेगा। ये पहल सभी सदस्य देशों के लिए खुली हैं, जो संगठन को नए अवसर प्रदान करेंगी और क्षेत्र के सतत विकास को सशक्त करेंगी।

यह वैश्विक शासन व्यवस्था का नेतृत्व करने वाला एक शिखर सम्मेलन था। आज के दौर में शासन व्यवस्था की कमी के जवाब में,

विश्व में, श्री शी ने वैश्विक शासन पहल को आगे बढ़ाया, जिसमें संप्रभु समानता का पालन करने, अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन का पालन करने, बहुपक्षवाद का अभ्यास करने, लोगों-केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत करने और वास्तविक कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया गया, जो इस शिखर सम्मेलन का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया।

2017 में एससीओ में शामिल होने के बाद से भारत ने एससीओ के विकास को आगे बढ़ाने में श्री मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। चीन श्री मोदी की गहरी सराहना करता है।
मोदी और भारत चीन की एससीओ अध्यक्षता के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हैं। चीन, एससीओ के ढांचे के अंतर्गत सुरक्षा, वित्त पोषण, ऊर्जा, हरित उद्योग और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, ताकि दोनों देशों की जनता की बेहतर भलाई हो सके।

संबंधों की हीरक जयंती इस वर्ष चीन-भारत राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। तियानजिन में, श्री शी और श्री मोदी ने चीन-भारत संबंधों को और आगे बढ़ाने पर नई, महत्वपूर्ण और साझा समझ हासिल की। श्री शी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि चीन और भारत के लिए अच्छे पड़ोसी मित्र और साझेदार बनना सही विकल्प होना चाहिए जो एक-दूसरे की सफलता में मदद करें और ड्रैगन और हाथी को एक साथ नचाएँ। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत और चीन साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं।

उनकी आम सहमति उनकी असहमति से कहीं ज़्यादा है। भारत द्विपक्षीय संबंधों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखने और विकसित करने के लिए तैयार है।

हमें महत्वपूर्ण और सामान्य को बनाए रखना चाहिए
दोनों नेताओं के बीच हुई सहमति को मार्गदर्शन के रूप में लिया जाएगा तथा द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक व्यावहारिक प्रगति की ओर अग्रसर किया जाएगा।

सबसे पहले, हमें रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना होगा। आपसी विश्वास। हमें पिछले 75 वर्षों से गंभीरतापूर्वक सबक लेना चाहिए, सही रणनीतिक धारणा को मजबूत करना चाहिए, पड़ोसी प्रमुख देशों के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर रहने के सही तरीके तलाशने चाहिए, जिनकी विशेषताएँ आपसी सम्मान और विश्वास, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, साझा विकास की खोज और जीत-जीत सहयोग हों, और धीरे-धीरे विभिन्न दोनों सरकारों के बीच संवाद और आदान-प्रदान के लिए तंत्र।

दूसरा, हमें आदान-प्रदान और सहयोग को और बढ़ाना चाहिए। हमें विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो दोनों देशों का सबसे बड़ा साझा कारक है, और आपसी सहयोग और सफलता को बढ़ावा देना चाहिए, तथा व्यापार और निवेश प्रवाह को बेहतर बनाना चाहिए। चीनी पक्ष भारतीय पक्ष के साथ प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्रों में सहयोग को मज़बूत करने, और राजनीतिक दलों, थिंक टैंकों, मीडिया और युवाओं के बीच आदान-प्रदान और संचार को बढ़ावा देने के लिए तैयार है, ताकि हितों के अभिसरण का विस्तार हो और लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा मिले।

तीसरा, हमें अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मज़बूत करना चाहिए। हमें चीनी और भारतीय नेताओं की पुरानी पीढ़ी द्वारा शुरू किए गए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांतों का पालन करना जारी रखना चाहिए, एक-दूसरे के मूल हितों और प्रमुख चिंताओं का सच्चा सम्मान करना चाहिए, और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। हमें अतीत से बचे हुए सीमा प्रश्न को वर्तमान चीन-भारत संबंधों को परिभाषित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, न ही विशिष्ट मतभेदों को द्विपक्षीय सहयोग को प्रभावित करने देना चाहिए, ताकि चीन-भारत संबंधों का सुदृढ़ और स्थिर विकास सुनिश्चित हो सके।

आगे की राह: दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले प्रमुख विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्यों के रूप में, चीन और भारत विकास और पुनरोद्धार, विश्व शांति और स्थिरता बनाए रखने और वैश्विक शासन को बढ़ावा देने में समान रुचि रखते हैं। भारत और चीन अगले दो वर्षों में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेंगे। चीन एक-दूसरे की अध्यक्षता का समर्थन करने, ब्रिक्स सहयोग को गहरा और मजबूत करने, वैश्विक शासन पहल को संयुक्त रूप से लागू करने, धौंस और आधिपत्य का दृढ़ता से विरोध करने, अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय की रक्षा करने, और मानवता के साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण के लिए हाथ मिलाने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है।

चीन शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के ढांचे के तहत सहयोग बढ़ाने में भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है।

सहयोग संगठन (एससीओ)

द टटर्सटूदएडिटर

भारत, क्षेत्रीय अशांति : नेपाल में विरोध प्रदर्शन भड़क रहे हैं और पाकिस्तान व बांग्लादेश की सरकारें अस्थिरता से जूझ रही हैं, यह इस बात की याद दिलाता है कि लोकतंत्र कितना नाज़ुक हो सकता है (मुख्य पृष्ठ, 10 सितंबर)। भारत अपनी चुनौतियों के बावजूद, स्थिर संस्थाओं और मानवाधिकारों के मार्गदर्शन में मज़बूती से खड़ा है।

अपने लोगों की इच्छा। हम अक्सर इसे हल्के में न लें। लेकिन चारों ओर देखते हुए, हमें जो कुछ हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये पड़ोसी संकट हमें जुड़े रहने, जानकारी रखने और एकजुट रहने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा लोकतंत्र परिपूर्ण नहीं है, लेकिन यह हमारा है — और यह

काम कर रहे हैं। फिर भी, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पड़ोस की अस्थिरता पूरे देश में फैल सकती है

यदि हम सतर्क नहीं रहे तो हमारी अपनी सीमाएं खतरे में पड़ सकती हैं।

Ishika Rajpura,
Amritsar, Punjab

टेनिस में एक नया युग हाल ही में संपन्न हुआ यूएस ओपन विश्व टेनिस में न केवल कोर्ट पर बल्कि वैश्विक दर्शकों के दिलों में भी एक स्पष्ट पीढ़ीगत बदलाव का प्रमाण है। हालांकि, नोवाक जैसे दिग्गज जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर ने पुरुष टेनिस में एक साथ दबदबा बनाने वाले दो शीर्ष खिलाड़ियों के आगमन से बदलाव आया है। प्रतिभाशाली युवा - 'सिनकाराज़', जिनमें धैर्य, हिम्मत और शालीनता का संगम है। टेनिस सितारों की एक नई पीढ़ी के उभरने से इस अद्भुत खेल के प्रति उत्साह फिर से जाग उठा है।

R. Sivakumar,
चेन्नई

सुधार और स्पष्टीकरण

महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं, न कि 17वें, जैसा कि पहले पन्ने पर छपी एक रिपोर्ट, "राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए" (10 सितंबर, 2025) में बताया गया है। यह 17वाँ उपराष्ट्रपति चुनाव था क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी दोनों ही उपराष्ट्रपति के रूप में दो-दो कार्यकाल पूरा कर चुके थे।

पाठक संपादक की राय से टेलीफोन: +91-44-28576347/28576300; ई-मेल: readereditor@thehindu.co.in पर संपर्क किया जा सकता है।

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में डाक पता अवश्य होना चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

नेपाल में जेन जेड विद्रोह

''लेकिन होता भूडोल, बवंडर उठते हैं,
जनता जब कोपाकुल हो भृकुटि चढ़ाती है;
दो राह, समय के रथ का घर्घर-नाद सुनो,
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती,
सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है,
जनता की रोके राह, समय में ताव कहां?
वह जिधर चाहती, काल उधर ही मुड़ता है।''

नेपाल की जेन-जैड विद्रोह के बाद ओली सरकार का तख्ता पलटने पर रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां याद आती हैं। जब किसी भी देश की जनता आक्रोशित और आंदोलित हो जाए तो सब कुछ खाक हो जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देकर भागना पड़ा। क्रुद्ध लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री झाला नाथ खनाल की पत्नी को जिन्दा जला दिया। वित्त मंत्री और अन्य मंत्रियों को सड़कों पर पीटा। सत्ता का केन्द्र बिन्दु रहे सिंह दरबार, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और अन्य ऐतिहासिक इमारतें धू-धू कर जलीं। पहली नजर में युवाओं का विद्रोह सोशल मीडिया पर लगाई गई पाबंदियों के विरोध में नजर आया लेकिन बाद में यह विरोध हिंसक संघर्ष में तब्दील हो गया। हिंसा में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

अब सवाल यह है कि नेपाल आखिर क्यों उबला? पड़ोसी देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि घर में एक पीढ़ी विद्रोह कर दे जबकि हर महीने हजारों लोग नौकरी करने के लिए विदेश भाग रहे हैं। स्पष्ट है कि हिंसा और अशांति की जड़ें बहुत गहरी हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन हुए तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह नेपाल तक फैल जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना युवाओं के आक्रोश के लिए ट्रिगर साबित हुआ। केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने भी क्रूरता की पराकाष्ठा की, जब पुलिस फायरिंग से स्कूली बच्चों समेत 20 लोग मारे गए।

> **हिंसा के पीछे संस्थागत भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत और राजनीतिक असंतोष की बड़ी भूमिका है। पिछले 4 वर्षों में नेपाल में कई बड़े घोटाले सामने आए, जिसमें गिरि बंधु भूमि, स्वैप घोटाला जो 54,600 करोड़ का बताया जाता है। 13000 करोड़ का ओरिएंटल कॉरपोरेटिव घोटाला और लगभग 70 हजार करोड़ का कॉरपोरेटिव घोटाला शामिल है। इन बड़े घोटालों में आम जनता का विश्वास सरकार से पूरी तरह से उठ चुका है। नेपाल में 10.71 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। जबकि महंगाई आसमान को छू रही है। देश की कुल सम्पत्ति का 56 प्रतिशत हिस्सा केवल 20 प्रतिशत लोगों के पास है, जिनमें अधिकतर राजनीतिज्ञ शामिल हैं। अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है।**

जेन ज़ेड के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों को नेपाल में हाल ही में हुई घटनाओं की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। यह सिर्फ़ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का विरोध नहीं है। इंडोनेशिया और फिलीपींस की तरह, नेपाली सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने भी टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके सांसदों और राजनेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों की विलासितापूर्ण जीवनशैली और यात्राओं के लिए सार्वजनिक रूप से आलोचना की, जबकि देश का अधिकांश हिस्सा गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहा था। कई हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार घोटालों का प्रचार करते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल "नेपो बेबीज" की जीवनशैली को वित्तपोषित करने के लिए किया जा रहा है।

हिंसा के पीछे संस्थागत भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत और राजनीतिक असंतोष की बड़ी भूमिका है। पिछले 4 वर्षों में नेपाल में कई बड़े घोटाले सामने आए, जिसमें गिरि बंधु भूमि, स्वैप घोटाला जो 54,600 करोड़ का बताया जाता है। 13000 करोड़ का ओरिएंटल कॉरपोरेटिव घोटाला और लगभग 70 हजार करोड़ का कॉरपोरेटिव घोटाला शामिल है। इन बड़े घोटालों में आम जनता का विश्वास सरकार से पूरी तरह से उठ चुका है। नेपाल में 10.71 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। जबकि महंगाई आसमान को छू रही है। देश की कुल सम्पत्ति का 56 प्रतिशत हिस्सा केवल 20 प्रतिशत लोगों के पास है, जिनमें अधिकतर राजनीतिज्ञ शामिल हैं। अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है। राजनीतिक रूप से भी नेपाल की स्थिति जटिल है। जुलाई 2024 में ओली सरकार बनने के बाद उन्होंने देश को चीन के हाथ में गिरवी रख दिया है। भारत के साथ सीमा विवाद की वजह से आर्थिक दबाव बढ़ा, जिससे जनता में गहरी नाराजगी थी।

नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2008 में वहां 239 वर्षों से चल रहे राजशाही को खत्म कर दिया गया और लोकतंत्र की स्थापना की गई, लेकिन उसके बाद से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आ गई और अब तक कई बार सरकारें बदली जा चुकी हैं और 10 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना भले ही 2008 में हुई, लेकिन शुरूआत 1990 में बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था के साथ किया गया था, लेकिन उस वक्त राजा का प्रभाव बना हुआ था। 2001 में बड़ा परिवर्तन हुआ क्योंकि राजा बीरेंद्र और उनके परिवार की हत्या हुई और ज्ञानेंद्र राजा बने और सत्ता संभाली। 2005 में ज्ञानेंद्र ने बहुदलीय लोकतंत्र की सरकार को भंग किया और सत्ता पर पूर्ण रूप से कब्जा किया लेकिन 2006 से राजशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और 2008 में राजशाही को समाप्त कर लोकतंत्र स्थापित हुआ और नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया।

जिस तरह से सत्ता को म्यूजिकल चेयर बना दिया गया, मौजूदा विद्रोही भी उसी का परिणाम है। बीच-बीच में राजशाही की वापसी की मांग को लेकर भी उबाल आता रहा है। नेपाल की उथल-पुथल के बीच काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए उभर रहा है। बालेन्द्र शाह ने इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री भारत से ही हासिल की। रैपर और गीतकार के रूप में वे काफी लोकप्रिय हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि नेपाल कई वर्षों से चीन और अमेरिका का अखाड़ा बना हुआ है, इसलिए विद्रोह के पीछे विदेशी ताकतों की भूमिका को एक दम से नकारा नहीं जा सकता। बंगलादेश का घटनाक्रम हम देख चुके हैं। देखना है नेपाल में क्रांति के बाद शांति कैसे स्थापित होती है।

भंडार से जोड़ दिया जाए

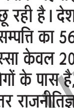

गीता पाढा

"परमार्थ को भी जब स्वार्थ से जोड़ दिया जाए,
आनंद को मौज-मस्ती के व्यवहार से जोड़ दिया जाए,,
स्त्रियों की आवाज को उनके बदकिरदार से जोड़ दिया जाए,
और पुरुषों की काबिलियत को उनकी
कमाई के आधार से जोड़ दिया जाए,,
शिक्षा के संस्थानों को व्यापार से जोड़ दिया जाए,
और भक्तों की आस्था को महंगे चढ़ावे के भंडार से जोड़ दिया जाए...।।"

राष्ट्र प्रथम की विचारधारा को समर्पित मोहन भागवत

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

संघ प्रमुख के 75वें जन्मदिवस पर विशेष

आज 11 सितंबर है। यह दिन अलग-अलग स्मृतियों से जुड़ा है। एक स्मृति 1893 की है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्वबंधुत्व का संदेश दिया और दूसरी स्मृति है 9/11 का आतंकी हमला, जब विश्व बंधुत्व को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। आज के दिन की एक और विशेष बात है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्मदिवस है जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। संघ परिवार में जिन्हें परम पूजनीय सरसंघचालक के रूप में श्रद्धाभाव से संबोधित किया जाता है, ऐसे आदरणीय मोहन भागवत जी का आज जन्मदिन है। यह एक सुखद संयोग है कि इसी साल संघ भी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। मैं भागवत जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें।

मेरा मोहन भागवत जी के परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। मुझे उनके पिता, स्वर्गीय मधुकरराव भागवत जी के साथ निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। मैंने अपनी पुस्तक ज्योतिपुंज में मधुकरराव जी के बारे में विस्तार से लिखा भी है। वकालत के साथ-साथ मधुकरराव जी जीवनभर राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित रहे। अपनी युवावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ कार्य की मजबूत नींव रखी।

मधुकरराव जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि अपने पुत्र मोहनराव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे। एक पारसमणि मधुकरराव ने मोहनराव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी।

भागवत जी का पूरा जीवन सतत प्रेरणा देने वाला रहा है। वे 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। सामान्य जीवन में प्रचारक शब्द सुनकर ये भ्रम हो जाता है कि कोई प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन जो संघ को जानते हैं उनको पता है कि प्रचारक परंपरा संघ कार्य की विशेषता है। गत 100 वर्षों में देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक-युवतियों ने अपना घर-परिवार त्याग करके पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। भागवत जी भी उस महान परंपरा की मजबूत धुरी हैं।

भागवत जी ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उस दौर में प्रचारक के रूप में भागवत जी ने आपातकाल-विरोधी आंदोलन को निरंतर मजबूती दी। उन्होंने कई वर्षों तक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों, विशेषकर विदर्भ में काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में मोहन भागवत जी के कार्यों को आज भी कई स्वयंसेवक स्नेहपूर्वक याद करते हैं। इसी कालखंड में मोहन भागवत जी ने बिहार के गांवों में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने के कार्य में समर्पित रहे। वर्ष 2000 में वे सरकार्यवाह बने और यहाँ भी भागवत जी ने अपनी अनोखी कार्यशैली से हर कठिन परिस्थिति को सहजता और सटीकता से संभाला।

2009 में वे सरसंघचालक बने और आज भी अत्यंत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। भागवत जी ने राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को हमेशा सर्वोपरि रखा। सरसंघचालक होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है। यह एक पवित्र विश्वास है, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी दूरदर्शी व्यक्तित्वों ने आगे बढ़ाया है और इस राष्ट्र के नैतिक और सांस्कृतिक पथ को दिशा दी है। असाधारण व्यक्तियों ने इस भूमिका को व्यक्तिगत त्याग, उद्देश्य की स्पष्टता और माँ भारती के प्रति अटूट समर्पण के साथ निभाया है। यह गर्व की बात है कि मोहन भागवत जी ने न केवल इस विशाल जिम्मेदारी के साथ पूर्ण न्याय किया है, बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति, बौद्धिक गहराई और सहृदय नेतृत्व भी जोड़ा है। भागवत जी का युवाओं से सहज जुड़ाव है और इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ कार्य के लिए प्रेरित किया है। वे लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं, और संवाद करते रहते हैं। श्रेष्ठ कार्य पद्धति को अपनाने की इच्छा और बदलते समय के प्रति खुला मन रखना, ये मोहनजी की बहुत बड़ी विशेषता रही है। अगर हम व्यापक संदर्भ में देखते हैं तो संघ की 100 साल की यात्रा में भागवत जी का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। चाहे वो गणवेश परिवर्तन हो, संघ शिक्षा वर्गों में बदलाव हो, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके निर्देशन में संपन्न हुए। कोरोना काल में मोहन भागवत जी के प्रयास विशेष रूप से याद आते हैं। उस कठिन समय में उन्होंने स्वयंसेवकों को सुरक्षित रहते हुए समाजसेवा करने की दिशा दी और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने पर बल दिया। उनके मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने जरूरतमंदों तक हरसंभव सहायता पहुंचाई, जगह-जगह मेडिकल कैंप लगाए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों और वैश्विक विचार को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्थाओं को विकसित किया। हमें कई स्वयंसेवकों को खोना भी पड़ा, लेकिन भागवत जी की प्रेरणा ऐसी थी कि अन्य स्वयंसेवकों की दृढ़ इच्छाशक्ति कमजोर नहीं पड़ी।

इस वर्ष की शुरुआत में, मैंने नागपुर में उनके साथ माधव नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के दौरान मैंने कहा था कि संघ अक्षयवट की तरह है, जो राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है। इस अक्षयवट वृक्ष की जड़ें इसके मूल्यों की वजह से बहुत गहरी और मजबूत हैं। इन मूल्यों को आगे बढ़ाने में जिस समर्पण से मोहन भागवत जी जुटे हुए हैं, वो हर किसी को प्रेरणा देता है। समाज कल्याण के लिए संघ की शक्ति के निरंतर उपयोग पर मोहन भागवत जी का विशेष बल रहा है। इसके लिए उन्होंने पंच परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें स्व बोध, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुम्ब प्रबोधन और पर्यावरण के सूत्रों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। देश और समाज के लिए सोचने वाले हर भारतवासी को पंच परिवर्तन के इन सूत्रों से अवश्य प्रेरणा मिलेगी। संघ का हर कार्यकर्ता वैभव संपन्न भारत माता का सपना साकार होते देखना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए जिस स्पष्ट विज़न और ठोस एक्शन की जरूरत होती है, मोहन जी इन दोनों गुणों से परिपूर्ण हैं। मोहन जी के स्वभाव की एक और बड़ी विशेषता ये है कि वो मृदुभाषी हैं। उनमें सुनने की भी अद्भुत क्षमता है। यह विशेषता न केवल उनके दृष्टिकोण को गहराई देती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व में संवेदनशीलता और गरिमा भी लाती है। मोहन जी, हमेशा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के प्रबल पक्षधर रहे हैं। भारत की विविधता और भारत भूमि की शोभा बढ़ा रही अनेक संस्कृतियों और परंपराओं के उत्सव में भागवत जी पूरे उत्साह से शामिल होते हैं। वैसे बहुत कम लोगों को ये पता है कि मोहन भागवत जी अपनी व्यस्तता के बीच संगीत और गायन में भी रुचि रखते हैं। वे विभिन्न भारतीय वाद्ययंत्रों में भी निपुण हैं। पठन-पाठन में उनकी रुचि, उनके अनेक भाषणों और संवादों में साफ दिखाई देती है। पिछले दिनों देश में जितने सफल जन-आंदोलन हुए चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोहन भागवत जी ने पूरे संघ परिवार को इन आंदोलनों में ऊर्जा भरने के लिए प्रेरित किया। मैं पर्यावरण से जुड़े प्रयासों और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को जानता हूं। मोहन जी का बहुत जोर आत्मनिर्भर भारत पर भी है। कुछ ही दिनों में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो जाएगा। यह भी सुखद संयोग है कि विजयादशमी का पर्व, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और संघ का शताब्दी वर्ष एक ही दिन आ रहे हैं। यह भारत और विश्वभर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघचालक हैं, जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। एक युवा स्वयंसेवक से लेकर सरसंघचालक तक की उनकी जीवन यात्रा उनकी निष्ठा और वैचारिक दृढ़ता को दर्शाती है। विचार के प्रति पूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन करते हुए उनके नेतृत्व में संघ कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है। मैं मां भारती की सेवा में समर्पित मोहन भागवत जी के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की पुन: कामना करता हूं। उन्हें जन्मदिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं।

ख़ाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक

मर्यादाएं
चन्द्रमोहन
संपादक : वीर प्रताप
chander_m@ hotmail.com
BLOG: chandermohan.net

घुटनेभर पानी में तस्वीर खिंचवाने के बाद केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब की स्थिति को जलप्रलय कहा है और साथ ही भरोसा भी दिलवाया कि केन्द्र की सरकार 'पंजाब के साथ मज़बूती से खड़ी है'। शिवराज सिंह चौहान की बात सही है। पंजाब की तबाही किसी प्रलय से कम नहीं है। ऐसी भयंकर बाढ़ इससे पहले 1988 में आई थी जब 500 लोग मारे गए थे पर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आज स्थिति 1988 से भी अधिक नाजुक और संकटपूर्ण है। उस वक्त 12 ज़िले प्रभावित हुए थे जबकि इस बार सभी 23 ज़िले बाढ़ की गिरफ्त में हैं। अनुमान है कि 4 लाख एकड़ खेत पानी से भर गए हैं। 2000 गांव पानी में डूब चुके हैं। 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं जो 1988 से लगभग 3 लाख ज़्यादा है। सीमा पर तैनात एक बीएसएफ़ अधिकारी ने बताया है कि "पानी की भारी मात्रा ने देहात की तस्वीर ही बदल दी है"।

सवाल है कि क्या कुछ बचाव हो सकता था? पहली बात तो है कि जितनी बारिश और जिस वेग के साथ हुई है वह पहले नहीं देखी गई। बीबीएमबी के चेयरमैन के अनुसार पौंग डैम में इतना पानी कभी नहीं आया। पंजाब के तीनों बड़े डैम, भाखड़ा,पौंग और रणजीत सागर लबालब भरे हुए हैं। इस बार डैमों में 20-25% पानी अधिक आया है। जब इतनी बारिश हो तो सरकार भी बेबस हो जाती है पर हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब तक इस बार जो तबाही हुई है वह केवल कुदरत की मार ही नहीं है। जैसे मैंने तीन सप्ताह पहले भी लिखा था, जो हुआ है वह इंसानी बेवक़ूफ़ी का भी परिणाम है पर अब पता चलता है कि यह मामला केवल बेवक़ूफ़ी का ही नहीं, यह सरकारी उदासीनता और लापरवाही का भी है। बार-बार होती तबाही के बावजूद सरकारें सोई रहती हैं और तब जागती हैं जब पानी सर तक पहुंच चुका होता है।

असंख्य सर्वेक्षण और अध्ययन बता चुके हैं कि तबाही के पीछे न केवल 'ह्यूमन फ़ैक्टर' है बल्कि 'गवर्नन्स फ़ैक्टर' भी है।

बारिश की पहली मार हिमाचल प्रदेश को झेलनी पड़ती है। इस बार जितनी तबाही हुई कि पहले नहीं हुई। 900 सड़कें ब्लॉक हैं। कुछ बह गईं तो कुछ को भूस्खलन ने रोक दिया है। बहुत पुल टूट चुके हैं। 1500 पॉवर ट्रांस्फार्मर बंद पड़े हैं। 400 पीने के पानी की स्कीमें काम नहीं कर रहीं। सरकार के अनुसार 4000 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है जो यह प्रदेश झेल ही नहीं सकता। 366 लोग मारे गए हैं। सड़कें तो लाइफ़ लाइन है। न टूरिस्ट आ रहा है और न ही सेब बाहर जा रहा है। पर क्या यह केवल कुदरत की मार ही थी या प्रदेश ने ही अपनी तबाही का इंतज़ाम कर लिया था? बाढ़ में पौंग डैम और चम्बा के पास बहकर आई लकड़ियों के वीडियो देखकर चिन्तित सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार और सम्बंधित संस्थाओं को नोटिस जारी किया है कि 'पेड़ों के अवैध कटान ने इस आपदा को आमंत्रित किया है'। हिमाचल प्रदेश का वन विभाग अवैध कटान से इंकार करता है पर यह तो खुला रहस्य है कि हमारे पहाड़ी प्रदेशों में ज़ोर-शोर से अवैध कटान होता है। वन कटाई बाढ़ और भूस्खलन को आमंत्रित करती है।

आशा है कि सुप्रीम कोर्ट मामलों को अंत तक लेकर जाएगा, क्योंकि हिमाचल सरकार में रोकने का दम नहीं है। मुख्यमंत्री ने कोई सीआईडी की जांच बैठा कर मामला दाखिल दफ्तर कर दिया है। तेज शहरीकरण हिमाचल के लिए ख़तरा बन रहा है। सरकार अवैध निर्माण के आगे हथियार फेंक कर बैठ गई, जिसका एक परिणाम हम मनाली में देख रहे हैं जहां ब्यास नदी बहुत बड़ा हिस्सा बहा कर ले गई है।

एक संसदीय कमेटी ने हाईवे निर्माण पर सवाल उठाए हैं कि ऊंची सड़कें पानी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट डाल रहें हैं। बेधड़क हाईवे निर्माण से पहाड़ खिसकने लगे हैं, जैसा मैंने पहले लेख में भी लिखा था, पर क्या हिमाचल की सरकार ने यह मामला एनएचएआई से उठाया है? जहां तक पंजाब का सवाल है, जो केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कही है उससे तो लगता है कि इतनी बड़ी तबाही का बड़ा कारण प्रशासनिक उदासीनता और निठुराई है। मंत्री का आरोप है कि दरिया के किनारे बने बांध अवैध खनन से कमजोर हो गए और पानी गांवों में घुस गया। उन्होंने बताया कि वाजपेयी और प्रकाश सिंह बादल की सरकारों के समय सतलुज, ब्यास, रावी और घग्गर के किनारों पर बने धुस्सी बांधों को मज़बूत और ऊंचा किया गया था, पर अब यह कमजोर पड़ गए हैं और पानी की मार नहीं सह सकें। पर अवैध खनन केवल बांधों पर ही नहीं हो रहा। नदी तट पर भी लगातार अवैध खनन चलता है जो नदी के तट को छिछला कर देता है और ऐसा सबकी आंखों के सामने हो रहा है पर कोई रोक नहीं है। बाढ़ का पानी तो पहाड़ों से आता है, जो सही बात पंजाब के मंत्री दोहरा रहे हैं, पर क्या हम इसे सम्भालने के लिए तैयार भी थे? हर दो तीन वर्ष के बाद पंजाब में बाढ़ आ रही है पर हम बेतैयार क्यों पाए जाते हैं? अवैध खनन और अव्यवस्थित निर्माण के कारण ड्रेनेज सिस्टम कमजोर पड़ गया जो जल प्रवाह को रोक नहीं सका। गुड़गांव और बैंगलुरू जैसे शहरों में भी निकासी के ऊपर निर्माण ने हमारे हाई-टैक शहरों को पानी में डूबो दिया था।

बहुत विशेषज्ञ कई सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि ड्रेन और नहरों की सफ़ाई न होने के कारण पानी की प्राकृतिक निकासी रुक जाती है। इसके अलावा धुस्सी बांधों की कमजोर हालत, हरी छत की कमी और नदी किनारे बिना सोचे-समझे निर्माण के कारण स्थिति और विकराल हो गई है। समय के साथ नदियों की पानी ले जाने की क्षमता कम हुई है। नदियों में गाद जम गई है। नदी और नालों की सफ़ाई और उन पर से अतिक्रमण को हटाने की तत्काल ज़रूरत है पर इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। बारिश कुछ रुकी है पर अभी त्रासदी का अंत नहीं हुआ। पंजाब में लाखों बेघर हैं। धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। पशु बह गए हैं। मकान गिर गए है।

बाढ़ अपने पीछे भारी विनाश छोड़ गई है। लोग अंधकारमय भविष्य की तरफ़ देख रहे हैं। पंजाब की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। बाज़ारों में रौनक़ नहीं है। एक बार पानी उतर गया तो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलना शुरू हो जाएंगी। बहुत लोग अभी से डायरिया, त्वचा की बीमारियों और उच्च टेंशन के कारण अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। पंजाब में ऐसी बाढ़ से देश की खाद्यान्न सुरक्षा खतरें में पड़ सकती है, क्योंकि अन्न भंडार में पंजाब सबसे अधिक योगदान डालता है। अभी से अनुमान है कि केन्द्रीय पूल में पंजाब का धान का टार्गेट 10 लाख टन कम होगा। खेत गाद से भरे हुए हैं अगली फसल उगाना भी मुश्किल होगा। पंजाब सरकार ने हिम्मत दिखाते हुए प्रभावित किसानों को राहत 6500 रुपए से बढ़ाकर 20000 रुपए प्रति एकड़ कर दी है पर पंजाब तो पहले ही क़र्ज़ मे डूबा हुआ है। केन्द्र सरकार की भूमिका भी बराबर महत्वपूर्ण रहेगी।

पंजाब की बहुत प्रशंसा की जाती है कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे अधिक क़ुर्बानी दी, देश का पेट भरा और सीमा की हिफ़ाज़त की। पर केवल प्रशंसा ही काफ़ी नहीं है। पंजाब को सम्भालना अब देश की भी ज़िम्मेवारी है। पंजाब को आपदा ग्रस्त प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए था पर नहीं किया गया। खुद केन्द्र सरकार भी दोष रहित नहीं है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जुलाई, अगस्त और यहां तक कि सितंबर में स्थिति ख़राब हो सकती है, अगर कोई प्रदेश सरकार लापरवाह है तो केन्द्र की ज़िम्मेवारी है कि चाबुक का इस्तेमाल करे। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के बीच ताल-मेल बैठाने की ज़िम्मेवारी भी केन्द्र सरकार की है। डैमों से अगर साथ-साथ पानी निकाला जाता तो एकदम पानी को निकालने और पंजाब को इस कदर डूबने से बचाया जा सकता था। डैमों का प्रबन्धन सख्ती से सही करने की ज़रूरत है। सिंचाई विभाग के पूर्व चीफ़ इंजीनियर अमरजीत सिंह दुल्लत ने कहा है कि मानसून सीजन में डैम में कम से कम 20-25 फुट जगह ख़ाली रखी जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं किया गया। कौन ज़िम्मेवार है?

प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब का हवाई दौरा करने के बाद उन्हें 1500 करोड़ रुपए और 1600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की है, पर जितनी बड़ी तबाही हुई है यह पर्याप्त नहीं है। पंजाब सरकार ने तो 20000 करोड़ रुपए मांगे थे। गुरुदासपुर के गांव ठेतारके के बख्शीश सिंह ने प्रधानमंत्री को बताया है कि उनके खेत में इतनी गाद जमा हो गई है कि अगले दो तीन साल वह कोई भी फसल उगाने की स्थिति में नही हैं।

उनका कहना था कि, "मेरे जैसे कई सौ किसान हैं जिनके खेतों में गाद जमा है। इनमें अधिकतर पहले ही क़र्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं। हम समझते हैं कि हमारा और हमारे परिवारों का भविष्य बर्बाद हो गया है"। जहां ऐसी निराशा हो वहां मज़बूती से हाथ थामने की ज़रूरत है। इस देश ने हर संकट के समय असाधारण संकल्प दिखाया है। पंजाब बाढ़ की इस महात्रासदी से निबटने के लिए वैसा संकल्प अभी नज़र नहीं आ रहा। आज तो पंजाब मिर्ज़ा ग़ालिब को दोहरा सकता है, हमने माना कि तग़ाफ़ुल (लापरवाही) न करोगे, लेकिन ख़ाक हो जाएंगे हम, तुम को खबर होने तक !

40 क्षेत्रीय दलों ने 2,532 करोड़ रुपये की आय घोषित की

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : देश में 40 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने वित्त वर्ष 2023-24 में 2,532.09 करोड़ रुपये की संयुक्त आय घोषित की, जिसमें से 70 प्रतिशत से अधिक धन चुनावी बॉण्ड के माध्यम से आया। 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) के विश्लेषण में यह बात सामने आई है। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले संगठन एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने सबसे अधिक 685.51 करोड़ रुपये की आय की सूचना दी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने 646.39 करोड़ रुपये, बीजू जनता दल (बीजद) ने 297.81 करोड़ रुपये, तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) ने 285.07 करोड़ रुपये और वाईएसआर कांग्रेस ने 191.04 करोड़ रुपये की आय की सूचना दी। रिपोर्ट के अनुसार इन शीर्ष पांच दलों ने 40 क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल आय का 83.17 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 40 क्षेत्रीय दलों की कुल आय 2,532.09 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2023-24 में 40 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कुल आय (1,796.02 करोड़ रुपये) का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान से आया। एडीआर ने कहा कि 20 क्षेत्रीय दलों की ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि के 313 दिन बाद भी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थीं। एडीआर के विश्लेषण के अनुसार 40 में से 20 दलों की ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि से 12 से 216 दिन की देरी के बाद निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हुईं। एडीआर ने कहा कि क्षेत्रीय दलों की कुल आय में वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 45.77 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई।

मंत्रियों की घोषित संपत्तियों में क्रिप्टो, पुराने वाहन, रिवॉल्वर, बंदूकें भी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए घोषित संपत्तियों में क्रिप्टोकरेंसी, दशकों पुराने वाहन, सोने के आभूषण, 'म्यूचुअल फंड' और कृषि भूमि शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार, कौशल विकास राज्य मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 31 मार्च, 2025 तक 21.31 लाख रुपये मूल्य के क्रिप्टो निवेश की सूचना दी। उनकी पत्नी चारु सिंह ने 22.41 लाख रुपये मूल्य की 'डिजिटल-एसेट होल्डिंग्स' का खुलासा किया। चौधरी एकमात्र मंत्री हैं जिन्होंने डिजिटल परिसंपत्तियों में क्रिप्टो को शामिल करते हुए घोषणा की है। जहां जमीन, शेयर या जमा राशि जैसे पारंपरिक निवेश कड़े नियमों के तहत संचालित होते हैं, वहीं भारत में क्रिप्टोकरेंसी अब भी नियामकीय अनिश्चितताओं से जूझ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निवेशकों को आभासी मुद्राओं के जोखिमों, जिनमें अस्थिरता और धोखाधड़ी शामिल हैं, के बारे में बार-बार चेतावनी दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने अपनी संपत्तियों में 37 साल पुराना स्कूटर और एक रिवॉल्वर शामिल होने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक दोपहिया वाहन के अलावा 27 लाख रुपये से अधिक के आभूषण और 19 लाख रुपये से अधिक के 'म्यूचुअल फंड' निवेश की भी घोषणा की है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

प्रवाह
77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

देशभक्ति दान की तरह है, जो घर से शुरू होती है।
-हेनरी जेम्स

पंजाब में 2023 में आई बाढ़ के बाद इसकी वजहों पर हुए अध्ययनों के बावजूद जिस तरह से यहां के सभी जिले बाढ़ के प्रकोप से जूझ रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व तैयारियों पर तमाम विमर्श के बाद भी हम इनसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं।

आफत का सैलाब

रावी, ब्यास व सतलुज जैसी बारहमासी नदियों के अलावा मौसमी नदी घग्गर और कई छोटी सहायक नदियां और उनमें प्रवाहित जलोढ़ मिट्टी जिस पंजाब को धरती के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक बनाती है, उसे इस उर्वरता की कीमत भी चुकानी पड़ रही है। दरअसल, पंजाब में बाढ़ जैसी स्थितियों के लिए हिमालयी राज्यों से आ रही नदियों और वहां हो रही भारी बारिश को दोषी माना जा रहा है। भारतीय पंजाब में अगस्त महीने में पिछले 26 वर्षों में सबसे अधिक बारिश हुई और सितंबर के पहले हफ्ते में भी सामान्य से 187 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे मौजूदा बाढ़ की स्थिति और भयावह हो गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, एक से सात सितंबर के बीच पंजाब में 66.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से लगभग तीन गुना ज्यादा है। इसकी गंभीरता का पता इस बात से चलता है कि पंजाब का कोई भी जिला बाढ़ के प्रकोप से बच नहीं सका है, और इससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के लिए करीब 1,600 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच कर बचाव कार्य कर रही हैं, लेकिन अभी कुल नुकसान का अंदाज लगाना मुश्किल है। अगर पंजाब इस वक्त हाल की सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है, तो इसकी वजहें सिर्फ प्राकृतिक नहीं हैं। समझना चाहिए कि पंजाब की स्थिति हिमाचल और जम्मू से अलग है। दोनों हिमालयी राज्यों में तबाही की वजह अचानक आई बाढ़ को समझा जा सकता है, लेकिन इन राज्यों की नदियों का उफान पंजाब तक पहुंचने में कुछ दिन का समय लगा, इसके बावजूद, इस समय का फायदा नहीं उठाया जा सका, जो वाकई हैरत की बात है। इसके अलावा एक अध्ययन के अनुसार, जुलाई से सितंबर के बीच भारी बारिश से पंजाब में बाढ़ जैसी स्थितियां हर वर्ष पैदा होती ही हैं। लेकिन, नदियों की उचित ढंग से सफाई न किए जाने पर उनमें गाद भर जाने से वे उथली हो जाती हैं और पानी किनारों को तोड़कर नजदीकी क्षेत्रों को डुबा देता है। इसके अतिरिक्त, बांधों से पानी छोड़ने की प्रक्रिया के प्रबंधन पर उठ रहे सवालों पर भी ध्यान देना चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए तो सरकारी एजेंसियां जुटी ही हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन को लेकर एक दूरगामी योजना के निर्माण की दिशा में तत्काल कदम उठाना भी जरूरी है।

परंपरा की मजबूत धुरी

भागवत जी की खासियत है कि उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। संघ की 100 साल की यात्रा में उनका कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा।

आज 11 सितंबर है। यह दिन अलग-अलग स्मृतियों से जुड़ा है। एक स्मृति 1893 की है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व बंधुत्व का संदेश दिया और दूसरी स्मृति है 9/11 का आतंकी हमला, जब विश्व बंधुत्व को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। आज के दिन की एक और विशेष बात है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्मदिवस है, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। संघ परिवार में जिन्हें परम पूजनीय सरसंघचालक के रूप में श्रद्धाभाव से संबोधित किया जाता है, ऐसे आदरणीय मोहन भागवत जी का आज जन्मदिन है।

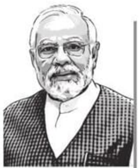

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

मेरा मोहन भागवत जी के परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। मुझे उनके पिता, स्वर्गीय मधुकरराव भागवत जी के साथ निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। मैंने अपनी पुस्तक *ज्योतिपुंज* में मधुकरराव जी के बारे में विस्तार से लिखा भी है। अपनी युवावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ कार्य की मजबूत नींव रखी। मधुकरराव जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि अपने पुत्र मोहनराव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे। एक पारसमणि मधुकरराव ने मोहनराव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी।

भागवत जी 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। जो संघ को जानते हैं, उन्हें पता है कि प्रचारक परंपरा संघ कार्य की विशेषता है। भागवत जी भी उस महान परंपरा की मजबूत धुरी हैं। भागवत जी ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उन्होंने कई वर्षों तक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों, विशेषकर विदर्भ में काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में उनके कार्यों को आज भी कई स्वयंसेवक स्नेहपूर्वक याद करते हैं। इसी कालखंड में मोहन भागवत जी ने बिहार के गांवों में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने के कार्य में समर्पित रहे।

वर्ष 2000 में वे सरकार्यवाह और 2009 में सरसंघचालक बने। उन्होंने राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को हमेशा सर्वोपरि रखा। सरसंघचालक होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है। यह एक पवित्र विश्वास है, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी दूरदर्शी व्यक्तित्वों ने आगे बढ़ाया है और इस राष्ट्र के नैतिक और सांस्कृतिक पथ को दिशा दी है। यह गर्व की बात है कि मोहन भागवत जी ने न केवल इस विशाल जिम्मेदारी के साथ पूर्ण न्याय किया है, बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति, बौद्धिक गहराई और सहृदय नेतृत्व भी जोड़ा है।

उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ कार्य के लिए प्रेरित किया है। श्रेष्ठ कार्य पद्धति अपनाने की इच्छा और बदलते समय के प्रति खुला मन रखना, मोहन जी की बहुत बड़ी विशेषता रही है। संघ की 100 साल की यात्रा में भागवत जी का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। चाहे गणवेश परिवर्तन हो या संघ शिक्षा वर्गों में बदलाव हो, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके निर्देशन में संपन्न हुए।

कोरोना काल में उन्होंने स्वयंसेवकों को सुरक्षित रहते हुए समाजसेवा करने की दिशा दी और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने पर बल दिया। हमें कई स्वयंसेवकों को खोना भी पड़ा, लेकिन भागवत जी की प्रेरणा ऐसी थी कि अन्य स्वयंसेवकों की दृढ़ इच्छाशक्ति कमजोर नहीं पड़ी।

इस वर्ष की शुरुआत में, मैंने नागपुर में उनके साथ माधव नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के दौरान कहा था कि संघ अक्षयवट की तरह है, जो राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है। इसकी जड़ें इसके मूल्यों की वजह से बहुत गहरी और मजबूत हैं। इन मूल्यों को आगे बढ़ाने में जिस समर्पण से मोहन भागवत जी जुटे हुए हैं, वह हर किसी को प्रेरणा देता है। समाज कल्याण के लिए संघ की शक्ति के निरंतर उपयोग पर उनका विशेष बल रहा है। इसके लिए उन्होंने पंच परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें स्व-बोध, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण के सूत्रों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। हर भारतवासी को पंच परिवर्तन के इन सूत्रों से अवश्य प्रेरणा मिलेगी।

संघ का हर कार्यकर्ता वैभव संपन्न भारत माता का सपना साकार होते देखना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए जिस स्पष्ट विजन और ठोस एक्शन की जरूरत होती है, मोहन जी इन दोनों गुणों से परिपूर्ण हैं। उनके स्वभाव की एक और बड़ी विशेषता है कि वे मृदुभाषी हैं। उनमें सुनने की भी अद्भुत क्षमता है। यह विशेषता न केवल उनके दृष्टिकोण को गहराई देती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व में संवेदनशीलता और गरिमा भी लाती है। मोहन जी हमेशा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के प्रबल पक्षधर रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि वे अपनी व्यस्तता के बीच संगीत और गायन में भी रुचि रखते हैं। वे विभिन्न भारतीय वाद्ययंत्रों में भी निपुण हैं। पठन-पाठन में उनकी रुचि, उनके अनेक भाषणों और संवादों में साफ दिखाई देती है। पिछले दिनों देश में जितने सफल जन-आंदोलन हुए, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोहन भागवत जी ने पूरे संघ परिवार को इन आंदोलनों में ऊर्जा भरने के लिए प्रेरित किया। मैं पर्यावरण से जुड़े प्रयासों और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को जानता हूं। मोहन जी का आत्मनिर्भर भारत पर भी बहुत जोर है।

कुछ ही दिनों में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो जाएगा। यह भी सुखद संयोग है कि विजयादशमी का पर्व, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और संघ का शताब्दी वर्ष एक ही दिन आ रहे हैं। यह भारत और विश्व भर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघचालक हैं, जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। एक युवा स्वयंसेवक से लेकर सरसंघचालक तक की उनकी जीवन यात्रा उनकी निष्ठा और वैचारिक दृढ़ता को दर्शाती है। मैं मां भारती की सेवा में समर्पित मोहन भागवत जी के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की पुनः कामना करता हूं। उन्हें जन्मदिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं!

edit@amarujala.com

जीवन धारा

एलिजाबेथ गिल्बर्ट

हिम्मत और जिज्ञासा एकसाथ मिलकर हमारे साधारण जीवन को असाधारण और जादुई बना सकती हैं, क्योंकि ये हमें चुनौतियों का सामना करने, नए रास्तों पर चलने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं।

रचनात्मक जीवन जीने का मार्ग है जिज्ञासा

ब्रह्मांड हम सभी के अंदर अनोखे रत्न छिपाता है और फिर पीछे हटकर देखता है कि क्या हम उन्हें ढूंढ पाते हैं। उन रत्नों को खोजने की कोशिश ही 'रचनात्मक जीवन' है। उस खोज को शुरू करने के लिए हिम्मत और जिज्ञासा चाहिए, जो एकसाथ मिलकर हमारे साधारण जीवन को असाधारण और जादुई बना सकती हैं, क्योंकि ये हमें चुनौतियों का सामना करने, नए रास्तों पर चलने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। उस खोज के अक्सर आश्चर्यजनक परिणाम होते हैं, जिन्हें मैं 'बड़ा जादू' कहती हूं। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है, जो सक्रिय रूप से अर्थ की तलाश करते हैं। आपको अपनी खुशियों को पाने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। और एक बार जब आप खुशी हासिल कर लें, तो उसे बनाए रखने में कभी ढील नहीं देनी चाहिए। आपको हमेशा उस खुशी की ओर बढ़ने के लिए कड़ा प्रयास करना होगा, ताकि आप उसमें डूबे रहें। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपका सहज संतोष खत्म हो जाएगा। संकट में प्रार्थना करना आसान है, लेकिन संकट के बीत जाने के बाद भी प्रार्थना करते रहना मायने रखता है, जो आपकी आत्मा को उसकी अच्छी उपलब्धियों को मजबूती से थामे रखने में मदद करती है। मुझे लगता है कि सबसे क्रांतिकारी काम यह है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। किसी के बचाने का, किसी की इजाजत का, दुनिया के निष्पक्ष होने का इंतजार नहीं करना और अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेना ही सबसे बड़ा बदलाव है। जिज्ञासा रचनात्मक जीवन जीने का मार्ग है। जिज्ञासा शुरुआत भी है और अंत भी। सबसे खास बात, जिज्ञासा सबके लिए उपलब्ध है। जुनून कभी-कभी बहुत दूर और मुश्किल लगता है। लेकिन जिज्ञासा नरम, शांत, स्वागत करने वाली और सबके लिए खुली है। जिज्ञासा का जोखिम जुनून से बहुत कम है। जिज्ञासा बस एक साधारण सवाल पूछती है, 'क्या कुछ है, जो तुम्हें रुचिकर लगता है? जिज्ञासा हमारी वह मित्र है, जो हमें स्वयं बनना सिखाती है। यह बहुत नरम, बहुत क्षमाशील और हमेशा साथ देने वाला दोस्त है। जुनून इतना स्थिर, इतना नरम, इतना क्षमाशील नहीं है और कभी-कभी उपलब्ध भी नहीं होता। जब हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, जो कहती है कि हमें हर वक्त जुनूनी होना चाहिए। अगर हमारे अंदर वह तीव्र इच्छाशक्ति नहीं है, तो हम निराशा महसूस कर सकते हैं। लेकिन जिज्ञासा हमेशा हमारे भीतर होती है। यह कम जोखिम वाला आगे बढ़ने और जीने का तरीका है। कामयाबी का रहस्य है कि हम खोजते रहें और हार न मानें, भले ही हमें पता चले कि कुछ वैसा नहीं है, जैसा हमने सोचा था। यही जिज्ञासा हमसे मांग करती है कि हम जागते रहें, सवाल पूछते रहें, पत्थर पलटते रहें, चाहे हम थक जाएं, डर जाएं, या सोचें कि हमने सब देख लिया। दुनिया इतनी बड़ी और खूबसूरत है कि इसे पूरी तरह कभी जाना नहीं जा सकता, और यही इसकी खूबी है।

अपनी जिम्मेदारी खुद लें

सूत्र

जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाबी के लिए जिज्ञासु होना जरूरी है। अपने भीतर के जानने की इच्छा को दिशा देनी होगी, तभी आप हर क्षेत्र में बेहतर हो पाएंगे। अपनी जिम्मेदारी खुद लेने से आपका जीवन निखर कर सुंदर हो जाएगा। दुनिया की विशालता को जानना मुश्किल है, और इसे जानने से ही जिंदगी खूबसूरत हो सकती है।

दूसरा पहलू

आखिर इंजीनियर पुलों पर पड़ने वाले भार की सीमा कैसे तय करते हैं और पानी के नीचे चीजें कैसे बनाते हैं?

पानी के नीचे पुल कैसे बनते हैं

जब मैं बच्चा था, मैंने एक कॉमिक (चित्रकथा) पढ़ी थी, जिसने मेरे सामने एक ज्वलंत प्रश्न खड़ा कर दिया था। पुलों पर पड़ने वाले भार की सीमा कैसे तय करते हैं? कॉमिक में केल्विन के पिता गलत जवाब देते हुए कहते हैं कि वे बड़े-बड़े ट्रक चलाते हैं, जब तक कि पुल टूट न जाए, फिर आखिरी ट्रक का वजन नापकर पुल बनाते हैं। अब मैं एक भू-तकनीकी इंजीनियर हूं और मुझे बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रश्नों के सही उत्तर मालूम हैं। लोग अक्सर केल्विन के पिता की तरह गलत दिशा में सोचते हैं। इंजीनियर एक अनुमानित भार वहन करने के लिए पुलों की डिजाइन बनाते हैं, न कि वजन सीमा का परीक्षण करते हैं। इसी तरह, लोग यह भी पूछते हैं कि इंजीनियर पानी के नीचे चीजें कैसे बनाते हैं? इंजीनियर आम तौर पर पानी के नीचे चीजें नहीं बनाते, बल्कि वे ऐसी चीजें बनाते हैं, जो बाद में पानी के नीचे चली जाती हैं। आप जो निर्माण कर रहे हैं और उसके चारों ओर चट्टान या मिट्टी है, तो उसे भूमिगत निर्माण माना जाता है, भले ही उसके ऊपर पानी की एक परत हो। जमीन के नीचे निर्माण में आम तौर पर शक्तिशाली सुरंग खोदने वाली मशीन का उपयोग होता है।

एरी पेरेज

पानी के अंदर निर्माण जटिल और चुनौतीपूर्ण है। बिल्डरों ने 'ब्रुकलिन ब्रिज' के खंभों का निर्माण कैसॉन का उपयोग करके किया था।

इन्सान, सामग्री और मशीनें पानी में ठीक से काम नहीं कर पातीं। लोगों को निरंतर वायु की जरूरत पड़ती है, पानी में कंक्रीट डालना मुश्किल है और कई सामग्रियां केवल सूखी जगह पर ही काम करती हैं।

यह मशीन मिट्टी या चट्टान को खोदकर सुरंग बनाती है। इंजीनियर इसका उपयोग चैनल टनल (एक रेलवे सुरंग) के जरिये करते हैं। हालांकि आधुनिक मशीनें काफी उन्नत हैं, फिर भी निर्माण की यह पद्धति करीब 200 साल पुरानी है। इन्सान, सामग्री और मशीनें पानी में ठीक से काम नहीं कर पातीं। लोगों को निरंतर वायु की जरूरत पड़ती है, पानी में कंक्रीट डालना मुश्किल है और कई सामग्रियां केवल सूखी जगह पर ही काम करती हैं। छोटे-मोटे काम, जैसे पहले से बनी सुरंग के हिस्सों को जोड़ना या जांच करना, पानी के नीचे हो सकता है। इसलिए निर्माण का अधिकांश कार्य बाहर ही होता है। एक बार ढांचा स्थापित हो जाने पर पानी के भीतर उसकी निरंतर निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। लोग आम तौर पर बाहर निर्माण करके ढांचे को पानी में ले जाते हैं। यदि पानी उथला है, तो श्रमिक धातु की दीवारें बनाकर सीधे सतह से निर्माण कर सकते हैं। आजकल, कॉफरडैम का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक अस्थायी, जलरोधी घेरा है, जिसके भीतर की जगह का पानी सुखाया जाता है। बिल्डरों ने 'ब्रुकलिन ब्रिज' के खंभों का निर्माण कैसॉन का उपयोग करके किया था। कैसॉन एक खाली ढांचा है जिसका उपयोग पानी के भीतर निर्माण कार्य करने के लिए किया जाता है। पानी के अंदर निर्माण के लिए इंजीनियरों ने कई तरीके विकसित किए हैं। अधिकांशतः वे पानी के अंदर निर्माण नहीं करते।

-द कन्वर्सेशन से

आंकड़े

भारत में खनन

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में खनन क्षेत्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें छत्तीसगढ़ सबसे आगे है।

छत्तीसगढ़	9.38%
ओडिशा	9.0%
झारखंड	5.32%
गुजरात	3.39%
मध्य प्रदेश	2.68%

आंकड़े प्रतिशत में हैं। | स्रोत : MoSPI

राजा ने क्रोध में साधु-संतों को देश से बाहर कर दिया। इसके एक-दो दिन बाद ही राज्य की व्यवस्था चरमरा गई और अंत में राजा क्षमा याचना करने लगा।

काया-माया झूठी है, सर्वत्र राम हैं

श्रीजीमहाराज के प्रमुख शिष्यों में एक श्रीरामदास जी थे। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की। इसके बाद श्रीरामदास जी गुरु की इच्छानुसार भगवान की कथा लोगों तक पहुंचाते थे। संतों से वैर रखने वाले कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने राज्य में भ्रम फैलाया कि यहां के संत धर्म की अवहेलना कर रहे हैं। वहां के राजा ने बिना विचार-विमर्श किए, क्रोध में आदेश दिया कि जो भी साधु-संत सनातन वर्णाश्रम धर्म की अवहेलना कर सभी वर्णों को हरि भक्ति का समान अधिकारी बताकर राम नाम जाप की ही प्रधानता से प्रचार कर मर्यादा को मिटा रहा है, उसे शीघ्र ही देश से बाहर कर दो।

सैनिकों ने सबको बाहर जाने को कहा। इस पर श्रीरामदास जी बोले, 'हम अनादि राम के साधु हैं। राजा की इच्छा है, तो हम देश छोड़ देंगे। देश किसका है? काया-माया झूठी है, सर्वत्र राम का ही राज्य है। जिस मुरारी की इच्छा को पुरारी महादेव मस्तक पर धारण करते हैं, वही हमारे साथ हैं। तुम अपनी सीमा रखो। ऐसा कहकर श्रीरामदास जी राज्य की सीमा से बाहर चले गए। संतों का अनादर व भगवान के नाम पर बिना सोचे-समझे निर्णय लेना राजा को महंगा पड़ा। एक-दो दिन में ही राज्य की व्यवस्था चरमरा गई। तब राजा घबराकर श्रीरामदास जी के पास जाकर क्षमा याचना करने लगा। श्रीरामदास जी बोले, 'भगवान से क्षमा मांगो।' इसके बाद राज्य व्यवस्था सही हो गई।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 11 सितंबर, 1950

नेपाल में सरकार के खिलाफ मुक्त आंदोलन चलेगा

नेपाल में "मुक्त आंदोलन" चलेगा

नेपाली कांग्रेस के नेता बीपी कोइराला ने कहा कि नेपाल में सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक मुक्ति आंदोलन शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम वर्तमान शासन प्रणाली के विरुद्ध हैं।

नेपाली आंदोलन के पीछे कौन

जितना स्वतःस्फूर्त यह आंदोलन दिख रहा है, क्या वाकई में ऐसा है या इसके पीछे विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं?

सुबीर भौमिक | मुद्दा

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जिस तरह से इस्तीफा देने के बाद नेपाली सेना के हेलिकॉप्टर में बैठकर भागे, उससे हमें पिछले साल पांच अगस्त को सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपने देश से भागने की याद आ गई। हसीना के मामले में, यह जल्द ही स्पष्ट हो गया था कि वह भारत जा रही हैं। लेकिन ओली को कौन आश्रय देता है, यह जानने के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन दोनों घटनाओं के बीच की भयावह समानताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पिछले साल बांग्लादेश में और अब नेपाल में, हसीना और ओली को सत्ता से हटाने वाले आंदोलन का नेतृत्व ज्ञात राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा नहीं किया गया था। बांग्लादेश में बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी ने छात्र आंदोलन को समर्थन दिया था, जो एक बड़े आंदोलन में बदल गया, लेकिन उसका प्रत्यक्ष नेतृत्व ऐसे युवा नेताओं द्वारा किया गया था, जिनका किसी भी राजनीतिक दल से सीधा संबंध नहीं था। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसी राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि एक गुमनाम गैर-सरकारी संगठन 'हामी नेपाल' ने किया था। पेशेवर इवेंट मैनेजर सुदन गुरुंग द्वारा 2015 में स्थापित, 'हामी नेपाल' आपदा राहत पर केंद्रित है। नेपाल के कई लोगों का कहना है कि उनके कार्यक्रमों को पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से दान में अच्छी-खासी धनराशि मिलती थी। जागरूकता शिविरों में उन युवा कार्यकर्ताओं की अच्छी-खासी भीड़ उमड़ी, जो नेपाल की राजनीतिक पार्टियों से निराश थे और सोशल मीडिया को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार से लड़ने की गुरुंग की प्रतिबद्धता में विश्वास रखते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी के दौरान, गुरुंग के सहयोगी, बांग्लादेश भेदभाव विरोधी छात्र मंच के 'समन्वयकों' की तरह, बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों को जुटाने के लिए संदेश भेज रहे थे, और जोर दे रहे थे कि वे स्कूल बैग के साथ स्कूल यूनिफॉर्म में आएं। संभवतः उनका विचार रहा होगा कि यदि आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो वर्दी में स्कूली बच्चे पुलिस को गोली चलाने जैसी कठोर कार्रवाई करने से रोक सकते हैं, लेकिन यदि पुलिस की गोलीबारी में कुछ स्कूली बच्चे मारे जाते, तो भावनात्मक प्रतिक्रिया आंदोलन को उस बिंदु तक पहुंचा देती, जहां से वापस लौटना असंभव होता।

बांग्लादेश और अब नेपाल, दोनों जगहों पर पुलिस ने शासन को बचाने के लिए सख्ती बरती और बड़ी संख्या में युवाओं की मौत ने आंदोलन को इतना उग्र बना दिया कि कोई रास्ता नहीं बचा। दोनों ही देशों में, आंदोलन और भी उग्र हो गया, जबकि सरकार ने आंदोलनकारियों की मुख्य मांगें मान ली थीं। बांग्लादेश और नेपाल, दोनों में आंदोलन अपेक्षाकृत अज्ञात संगठनों द्वारा चलाए गए, जिनकी गतिविधियां अक्सर खुफिया रडार से दूर रहती हैं। दोनों देशों में, आंदोलनकारियों ने लामबंदी के लिए नई पीढ़ी की तकनीकों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। भ्रष्टाचार और दमन के कारण राजनीतिक परिवेश में व्याप्त जनाक्रोश को कम करके नहीं आंका जा सकता और निश्चित रूप से 'हामी नेपाल' या बांग्लादेश छात्र मंच जैसे संगठन इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यह उम्मीद करना बहुत ज्यादा होगा कि वे अकेले नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। यहीं पर सत्ता परिवर्तन में रुचि रखने वाली महत्वपूर्ण शक्तियों के लिए काम करने वाली बाहरी एजेंसियों की भूमिका होती है। बांग्लादेश के सत्ता परिवर्तन में अमेरिका की डीप स्टेट की भूमिका जगजाहिर है। क्या नेपाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, यह जानने के लिए कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शीतयुद्ध के दौरान, अमेरिका ने नेपाल के मस्तंग क्षेत्र का इस्तेमाल तिब्बती गुरिल्लाओं को चीन से लड़ने के लिए हथियार और प्रशिक्षण देने के लिए किया था। अमेरिकी लेखक जॉन प्रैडोस ने अपनी पुस्तक *प्रेसिडेंट्स सीक्रेट आर्मी* में इस गुप्त अभियान का विस्तार से वर्णन किया है।

यह तब रुका, जब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1971 में चीन जाकर माओ से दोस्ती की। बाइडन प्रशासन द्वारा तिब्बती स्वतंत्रता की पुरजोर वकालत करते हुए तिब्बत अधिनियम पारित करने के बाद, अमेरिकी एजेंसियां तिब्बत में सशस्त्र छापामार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त ठिकानों की तलाश में हैं। चूंकि भारत चीन से अपने संबंधों को सामान्य कर रहा है और ऐसी योजनाओं को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए नेपाल में एक पश्चिम-समर्थक सरकार वाशिंगटन के लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकती है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

टैरिफ पर फिर उम्मीद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत से फिर व्यापार-वार्ता के लिए लालायित दिख रहे हैं, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने भी वार्ता-अनुकूल भावनाओं का इजहार कर अच्छे संकेत दिए हैं। दोनों देशों के बीच विधिवत वार्ताओं की शुरुआत तय दिख रही है। यह अच्छी बात है कि व्यापार-वार्ता को पटरी पर लाने के लिए नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच टेलीफोन लाइनें लगातार सक्रिय हैं। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के नेताओं ने अपने-अपने अधिकारियों को संदेश दिया है कि व्यापार-समझौते को जल्दी अंतिम रूप दें। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं।' ट्रंप को जवाब देने में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ज्यादा वक्त न लेते हुए विश्वास जताया कि द्विपक्षीय व्यापार-वार्ता भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। दोनों देशों की ओर से सर्वोच्च स्तर पर सकारात्मक संदेशों का आदान-प्रदान सराहनीय है और इससे समझौते की उम्मीदें बढ़ जाती हैं।

कुछ अमेरिकी अधिकारियों व आला नेताओं ने अपने तल्ख बयानों से भारत को न केवल नाराज किया है, मुश्किल स्थितियों में भी डाला है। ऐसे लोगों की चिंता बढ़ी है, जो वास्तव में, दोनों देशों के बीच स्वाभाविक संबंधों की उम्मीद रखते हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों में संशय की स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से रही है। वह कभी एक कदम आगे, तो दो कदम पीछे खींचते रहे हैं। वह एक ही सांस में भारत की तारीफ भी करते हैं और कटु वचन भी बोलते हैं। दूसरी ओर, भारतीय प्रधानमंत्री इस मोर्चे पर स्थिर हैं और उन्होंने दोहराया है कि हम दोनों देशों के लोगों के लिए उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। यह तथ्य है कि अगस्त के उत्तरार्द्ध में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को भारत आना था, पर वह यात्रा स्थगित हो गई थी। अब बताया जा रहा है कि भारतीय वार्ताकारों का एक दल अगले सप्ताह वाशिंगटन जा रहा है और वहां निर्णायक व्यापार-वार्ता की संभावना है।

भारत-अमेरिका के बीच सर्वोच्च स्तर पर सकारात्मक संदेशों का आदान-प्रदान सराहनीय है और इससे अच्छे द्विपक्षीय व्यापार समझौते की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

ट्रंप के टैरिफ वार से दुनिया तेजी से बदल रही है और ऐसे में, कुछ बातें बहुत स्पष्ट हैं। अगर ट्रंप भारत से दूरी बनाएंगे, तो जाहिर है, इसका सबसे ज्यादा असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल भारत को ही नुकसान होगा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी बहुत प्रभावित होगी। मिसाल के लिए, अमेरिका से एक प्रतिनिधिमंडल 17-18 सितंबर को भारत आ रहा है, जो लगभग तीन अरब डॉलर मूल्य के छह पनडुब्बी रोधी युद्धक विमानों के सौदे पर बात करेगा। इसके अलावा, भारत तेजस विमानों के लिए भी अमेरिका से इंजन खरीदना चाहता है। अमेरिका को निश्चित ही यह चिंता होगी कि अगर भारत से संबंध खराब हुए, तो भारत सामरिक खरीद से पीछे हट जाएगा। दूसरी चिंता क्वाड को लेकर है। अगर अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति क्वाड शिखर सम्मेलन के मंच पर भारत से बचेंगे, तो तय है, क्वाड अर्थहीन हो जाएगा। तीसरी चिंता, भारत ने अपना पक्ष दृढ़ता से रखा है, अतः अमेरिका अगर कुछ नरमी से बीच का रास्ता निकाले, तो उसकी अपनी चिंता भी दूर होगी। अमेरिका को समझना होगा कि भारत अपनी विशाल किसान व मजदूर आबादी के हित से समझौता नहीं कर सकता।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले | 11 सितंबर, 1950

शरारतपूर्ण प्रचार

जब से काश्मीर के बारे में डिक्सन के प्रयासों के असफल होने की घोषणा हुई है, तभी से पाकिस्तान में भारत के विरुद्ध भद्दे ढंग का जहरीला प्रचार शुरू हो गया है। पाकिस्तान से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर एक सरसरी निगाह डालने से यह तथ्य अपने-आप रोशन हो जाता है। पाकिस्तान के समाचार-पत्र डिक्सन की विफलता का सारा दोष भारत के माथे पर थोप रहे हैं। उनमें यह भी प्रकाशित किया जा रहा है कि कबायलियों में बड़ी बेचैनी फैल गई है और वे एक बार फिर जिहाद का नारा बुलन्द कर रहे हैं। वे काश्मीर के अपने सहधर्मियों को डोगरा शासन की चक्की में पिसते हुए नहीं देख सकते और वे उन्हें मुक्त करने के लिए तड़प रहे हैं। इस प्रचार को पाकिस्तान के शासकों का अप्रत्यक्ष समर्थन मिला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मन्त्री श्री जफरुल्ला ने लन्दन में अखबारों के प्रतिनिधियों के सामने काश्मीर की विस्फोटक स्थिति चित्रित करने के लिए कबायलियों की बेचैनी का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि कबायलियों में बेचैनी बढ़ रही है और स्थिति काबू से बाहर जा सकती है। पाकिस्तान तो कबायलियों को रोकने की अधिक से अधिक कोशिश ही कर सकता है। पाकिस्तानी समाचार पत्रों और पाकिस्तानी शासकों ने अपने प्रचार के लिए उपयुक्त अवसर चुना है; क्योंकि सर ओवन डिक्सन की रिपोर्ट पर सुरक्षा परिषद निकट भविष्य में विचार करने वाली है। काश्मीर की स्थिति को भयजनक और विस्फोटक बताकर सुरक्षा परिषद के सदस्यों को प्रभावित करने की चेष्टा की जा रही है।

कबायली काश्मीर पर अचानक चढ़ दौड़े थे। शुरू-शुरू में उन्होंने जो लूट-मार कर ली, वह कर ली। भारतीय सेना के काश्मीर में पहुंच जाने के बाद उन्हें आटे-दाल का भाव अच्छी तरह मालूम हो गया। अब काश्मीर भारत के संरक्षण में है। अगर कबायली लूट-मार के लोभ में अथवा धार्मिक उन्माद के वशीभूत होकर काश्मीर पर हमला करने की कोशिश करेंगे, तो उनके दांत खट्टे कर दिये जायेंगे। काश्मीर की प्रजा डोगरा वंश के महाराजा के शासन में अत्याचार की चक्की में पिस रही है, यह कहना जान-बूझकर दुनिया को धोखा देना है। महाराजा का शासन कभी का समाप्त हो चुका। आज शासन की वास्तविक बागडोर काश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला के हाथ में है।

मां भारती को समर्पित मोहन भागवत

यहां स्कैन करें

नरेंद्र मोदी | प्रधानमंत्री, भारत

सरसंघचालक मोहन भागवत का आज 75वां जन्मदिन है। यह एक सुखद संयोग है कि इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है।

आज 11 सितंबर है। यह दिन अलग-अलग स्मृतियों से जुड़ा है। एक स्मृति 1893 की है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व-बंधुत्व का संदेश दिया और दूसरी स्मृति है 9/11 का आतंकी हमला, जब विश्व-बंधुत्व को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। आज के दिन की एक और विशेष बात है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्मदिवस है, जिन्होंने *वसुधैव कुटुंबकम* के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है।

संघ परिवार में जिन्हें श्रद्धा भाव से परम पूजनीय सरसंघचालक संबोधित किया जाता है, ऐसे मोहन भागवत का आज जन्मदिन है। यह एक सुखद संयोग है कि इसी साल संघ भी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। मेरा मोहन भागवत के परिवार से गहरा संबंध रहा है। उनके पिता स्वर्गीय मधुकरराव भागवत के साथ निकटता से काम करने का मुझे सौभाग्य मिला था। मैंने अपनी पुस्तक *ज्योतिपुंज* में मधुकरराव के बारे में विस्तार से लिखा भी है। वकालत के साथ-साथ मधुकरराव जीवन भर राष्ट्र-निर्माण के कार्य में समर्पित रहे। अपनी युवावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ-कार्य की मजबूत नींव रखी। मधुकरराव का राष्ट्र-निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि वह अपने पुत्र मोहनराव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे। एक पारसमणि मधुकरराव ने मोहनराव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी।

मोहन भागवत का पूरा जीवन सतत प्रेरणा देने वाला रहा है। 1970 के दशक के मध्य में वह प्रचारक बने। सामान्य जीवन में प्रचारक शब्द सुनकर यह भ्रम हो जाता है कि कोई प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानते हैं, उनको पता है कि प्रचारक परंपरा संघ-कार्य की विशेषता है। विगत 100 वर्षों में देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक-युवतियों ने अपना घर-परिवार त्याग करके पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। भागवत भी उस महान परंपरा की मजबूत धुरी हैं।

भागवत ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उस दौर में प्रचारक के रूप में उन्होंने आपातकाल-विरोधी आंदोलन को निरंतर मजबूती दी। कई वर्षों तक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों, विशेषकर विदर्भ में उन्होंने काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में उनके कार्यों को आज भी कई स्वयंसेवक स्नेहपूर्वक याद करते हैं। इसी कालखंड में मोहन भागवत ने बिहार के गांवों में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने के कार्य में समर्पित रहे। वर्ष 2000 में वह सरकार्यवाह बने और यहां भी भागवत ने अपनी अनोखी कार्यशैली से हर कठिन परिस्थिति को सहजता और सटीकता से संभाला। साल 2009 में वह सरसंघचालक बने और आज भी अत्यंत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं।

सरसंघचालक होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है। यह एक पवित्र विश्वास है, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी दूरदर्शी व्यक्तित्वों ने आगे बढ़ाया है और इस राष्ट्र के नैतिक व सांस्कृतिक पथ को दिशा दी है। असाधारण व्यक्तियों ने इस भूमिका को व्यक्तिगत त्याग, उद्देश्य की स्पष्टता और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण के साथ निभाया है। यह गर्व की बात है कि मोहन भागवत ने न केवल इस विशाल जिम्मेदारी के साथ पूर्ण न्याय किया है, बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति, बौद्धिक गहराई और सहृदय नेतृत्व भी जोड़ा है।

भागवत का युवाओं से सहज जुड़ाव है और इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ-कार्य के लिए प्रेरित किया है। वह लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं और संवाद करते रहते हैं। श्रेष्ठ कार्य-पद्धति को अपनाने की इच्छा और बदलते समय के प्रति खुला मन रखना, यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता रही है। अगर हम व्यापक संदर्भ में देखें, तो संघ की 100 साल की यात्रा में भागवत का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। चाहे वह गणवेश परिवर्तन हो या संघ शिक्षा वर्गों में बदलाव- ऐसे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके निर्देशन में संपन्न हुए।

कोरोना काल में मोहन भागवत के प्रयास विशेष रूप से याद आते हैं। उस कठिन समय में उन्होंने स्वयंसेवकों को सुरक्षित रहते हुए समाजसेवा करने की दिशा दी और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने पर बल दिया। उनके मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने जरूरतमंदों तक हरसंभव सहायता पहुंचाई, जगह-जगह मेडिकल कैंप लगाए। हमें कई स्वयंसेवकों को खोना भी पड़ा, लेकिन भागवत की प्रेरणा ऐसी थी कि अन्य स्वयंसेवकों की दृढ़ इच्छाशक्ति कमजोर नहीं पड़ी।

मोहन भागवत के स्वभाव की एक और बड़ी विशेषता यह है कि वह मृदुभाषी हैं। उनमें सुनने की भी अद्भुत क्षमता है। यह विशेषता न केवल उनके दृष्टिकोण को गहराई देती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व में संवेदनशीलता व गरिमा भी लाती है। बहुत कम लोगों को यह पता है कि मोहन भागवत अपनी व्यस्तता के बीच संगीत और गायन में भी रुचि रखते हैं। वह विभिन्न भारतीय वाद्ययंत्रों में निपुण हैं। पठन-पाठन में उनकी रुचि, उनके अनेक भाषणों और संवादों में साफ दिखाई देती है। पिछले दिनों देश में जितने सफल जन-आंदोलन हुए, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोहन भागवत ने पूरे संघ परिवार को इन आंदोलनों में ऊर्जा भरने के लिए प्रेरित किया। पर्यावरण से जुड़े प्रयासों और सतत जीवनशैली को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को मैं जानता हूं। उनका जोर आत्मनिर्भर भारत पर भी है।

कुछ ही दिनों में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो जाएगा। यह सुखद संयोग है कि विजयादशमी का पर्व, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और संघ का शताब्दी वर्ष एक ही दिन आ रहे हैं।

यह भारत और विश्व भर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघचालक हैं, जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। विचार के प्रति पूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन करते हुए उनके नेतृत्व में संघ कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है।

मैं मां भारती की सेवा में समर्पित मोहन भागवत के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की पुनः कामना करता हूं। उन्हें जन्मदिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं!

उप-राष्ट्रपति चुनाव की जीत से भाजपा ने साधे कई निशाने

यहां स्कैन करें

नीरजा चौधरी | वरिष्ठ पत्रकार

उप-राष्ट्रपति चुनाव में सत्ता पक्ष की सफलता विपक्ष के लिए सबक हो सकती है। 'इंडिया' प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के 300 मतों के मुकाबले एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उम्मीद से कहीं अधिक 452 वोट मिले हैं। इसका मतलब है कि विपक्षी कुनबे में सेंध लगी है, जबकि आशंका सत्ता पक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग की थी। हालांकि, पहले के मुकाबले इस बार विरोधी दलों में एकजुटता अधिक दिखी है और उसमें टूट भी कम हुई है।

मुझे 1997 का उप-राष्ट्रपति चुनाव याद आ रहा है, जिसमें कृष्णकांत (441 मत) ने सुरजीत सिंह बरनाला (273 वोट) के खिलाफ जीत हासिल की थी। उसमें भी यह तय था कि कृष्णकांत के सिर जीत का ताज सजेगा, फिर भी सियासी फिजां में यह चर्चा तेजी थी कि 25-26 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। इस बार यह बहस कहीं अधिक मुखरता से हो रही है, क्योंकि विपक्षी उम्मीदवार की तयशुदा हार के बावजूद इस चुनाव के गहरे निहितार्थ थे। दरअसल, यह चुनाव एक ऐसी पृष्ठभूमि में हो रहा था, जिसमें सत्ता पक्ष सवालों की जद में था। जगदीप धनखड़ के अचानक उप-राष्ट्रपति पद छोड़ने से सरकार के साथ उनके तनाव की चर्चाएं तेज थीं, जबकि अमेरिकी टैरिफ के कारण प्रधानमंत्री निशाने पर थे। इतना ही नहीं, पहलगाम नरसंहार को तंत्र की नाकामी माना जा रहा था और एक महीने पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के करीबी संजीव बालियान के खिलाफ विपक्ष समर्थित राजीव प्रताप रूडी की जीत को सरकार के भीतर बढ़ते मतभेद का संकेत समझा गया था।

उप-राष्ट्रपति चुनाव ने विपक्ष पर दबाव बढ़ा दिया है। अब उसे खुद को कहीं अधिक गोलबंद करने के लिए मेहनत करनी होगी।

इसी सूरतेहाल में सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाया गया, जिसकी कुछ वजहें बिल्कुल साफ थीं। वह ओबीसी जाति से हैं, जिसकी राजनीति इन दिनों राहुल गांधी कर रहे हैं। वह तमिलनाडु से आते हैं, जहां भाजपा अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, ताकि अखिल भारतीय पार्टी के रूप में स्थापित हो सके। और सबसे बड़ी बात, वह संघ परिवार से जुड़े रहे हैं, जिससे यह संदेश देने की कोशिश हुई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनदेखी नहीं की जा रही। राधाकृष्णन को इन सबका फायदा तो मिला ही, व्यक्तिगत संबंध बनाने की उनकी योग्यता ने भी उन्हें वोट दिलाए। रही-सही कसर भाजपा की चुनावी रणनीति ने पूरी कर दी, जो हर मतदान में अपना पूरा दम-खम लगा देती है। इसके बरअक्स, विपक्षी दल उतने सक्रिय नहीं नजर आए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद मलेशिया में थे। बीआरएस, बीजद जैसे दलों ने तो मतदान से दूर रहना ही उचित समझा, जबकि ओडिशा में बीजद सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने ही पटखनी दी थी। यानी, विपक्षी पार्टियां कहीं अधिक प्रयास कर सकती थीं।

साफ है, पिछले छह महीनों से मुश्किलों से जूझ रहे प्रधानमंत्री इस चुनाव में मजबूती से उभरते दिख रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से दो-चार क्रॉस वोटिंग भी हो जाती, तो उन पर दबाव बढ़ जाता, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। यह बताता है कि बिगड़ती स्थिति को उन्होंने अपने नियंत्रण में कर लिया है। सवाल अब विपक्षी एकता पर उठेंगे। इस चुनाव में 15 वोट रद्द हुए हैं, जबकि 12 से 15 सांसदों के क्रॉस वोटिंग करने की बात कही जा रही है। यह संकेत है कि कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव पर भी इस नतीजे के असरंदाज होने के तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि, मैं इससे सहमत नहीं हूं। वहां का चुनाव जातिगत मसलों और स्थानीय मुद्दों के इर्द-गिर्द ही लड़ा जाएगा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का वहां काफी असर दिख रहा है। मगर सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) को अपने साथ लाने की सफल कोशिश की है, क्या ऐसा कोई प्रयास बिहार में संभव है? क्या यहां भी 'एमवाय+' की संकल्पना साकार हो सकती है?

इन सवालों के अभी ठीक-ठीक जवाब नहीं दिए जा सकते। मगर इतना तो स्पष्ट है कि इस उप-राष्ट्रपति चुनाव ने विपक्ष पर दबाव बढ़ा दिया है। अब उसे खुद को कहीं अधिक गोलबंद करने के लिए मेहनत करनी होगी। रही बात सत्ता पक्ष की, तो उसे इस नतीजे ने थोड़ी राहत जरूर दी है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

जब दिल में हो जगह

एक फकीर अपने छोटे से झोंपड़े में बीवी के साथ रहता था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। लगभग आधी रात को किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। फकीर ने बीवी से कहा, द्वार खोल दो, द्वार पर शायद कोई यात्री, कोई अपरिचित मित्र है। बीवी ने कहा, अपरिचित मित्र? हमारे तो जो परिचित हैं, वे भी मित्र नहीं होते। फकीर ने कहा, यह प्रेम का भाव है। तुम द्वार खोलो। पत्नी ने फिर टोका, हम दो के लिए ही जगह तंग है। तीसरा आदमी भीतर आएगा, तो हम क्या करेंगे?

फकीर ने कहा, पगली, यह किसी अमीर का महल नहीं कि छोटा पड़ जाए, गरीब का झोंपड़ा है। जब दिल में जगह हो, तो झोंपड़ा भी महल-सा मालूम होता है। तुम द्वार खोल दो! द्वार पर खड़े हुए आदमी को कैसे लौटाया जा सकता है? अभी तक जहां हम दोनों लेटे थे, तीनों बैठ लेंगे। बैठने के लिए काफी जगह है। पत्नी को दरवाजा खोलना पड़ा। एक मित्र आ गया, पानी से तरबतर। उसके कपड़े बदलवाए। फिर दरवाजा बंद करके तीनों बैठे-बैठे गपशप करने लगे। थोड़ी देर में दो और आदमियों ने दरवाजे पर दस्तक दी। फकीर ने द्वार से लगकर बैठे व्यक्ति से कहा- दरवाजा खोल दो, मालूम होता है कोई आया। उस आदमी ने कहा, अब जगह कहां है?

फकीर हंसने लगा। उसने कहा, बड़े पागल हो। मैंने तुम्हारे लिए जगह नहीं बनाई? प्रेम था, इसलिए जगह थी। प्रेम अब भी है, वह तुम पर ही खत्म नहीं हो गया। दरवाजा खोलो। अभी जहां हम दूर-दूर बैठे हैं, अब लगकर बैठ जाएंगे। पास-पास बैठने को काफी जगह है। दरवाजा खोलना पड़ा। दो और आदमी भीतर आ गए। वे पास-पास बैठकर गपशप करने लगे। रात कुछ आगे बढ़ी। एक गधे ने आकर सिर लगाया दरवाजे से। वह भी शरण चाहता था। फकीर ने दरवाजे से लगकर बैठे दोनों आदमियों से कहा- दरवाजा खोल दो। लगता है, कोई और मित्र आ गया।

तीनों ने एक स्वर में कहा, मित्र नहीं, गधा है। इसके लिए द्वार खोलने की क्या जरूरत है? फकीर ने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, अमीर के दरवाजे पर आदमी के साथ भी गधे जैसा व्यवहार किया जाता है। यह गरीब की झोंपड़ी है, हम गधे के साथ भी आदमी-सा व्यवहार करने के आदी हैं। दरवाजा खोल दो! वे सब कहने लगे, मगर जगह? फकीर ने कहा, जगह बहुत है; अभी तक हम बैठे थे, अब खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के लिए काफी जगह है। तुम लोग घबराओ मत, अगर जरूरत पड़ी, तो मैं बाहर होने को तैयार हूं। प्रेम इतना कर सकता है।

फकीर ने कहा, पगली, यह किसी अमीर का महल नहीं कि छोटा पड़ जाए, यह गरीब का झोंपड़ा है। जब दिल में जगह हो, तो झोंपड़ा भी महल होता है। तुम द्वार खोल दो!

एक प्रेमपूर्ण हृदय बनाने की जरूरत है। व्यक्तित्व में प्रेम की संभावना बढ़ती जानी चाहिए। वह इतनी बढ़ जानी चाहिए कि पौधों के प्रति, पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति, अपरिचितों के प्रति बढ़ता चला जाए।

ओशो

इमैनुएल मैक्रों | फ्रांसीसी राष्ट्रपति

कतर पर इजरायली हमला अस्वीकार्य है, चाहे वह किसी भी कारण से किया गया हो। हम कतर और उसके अमीर शेख तमीम अल थानी के साथ अपनी एकजुटता जताते हैं। किसी भी हालत में युद्ध पूरे क्षेत्र में नहीं फैलना चाहिए।

कतर पर इजरायली हमला अनुचित

अपनी तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका के कारण कतर को 'नया स्विट्जरलैंड' कहा जाता है। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड पारंपरिक तटस्थता और शांति के लिए ख्यात है। कतर को यह उपनाम उसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है, जो वैश्विक संघर्षों के युद्धविराम और कैदियों की अदला-बदली में उसकी अहम भूमिका में आसानी से देखा जा सकता है। मगर 9 सितंबर को इजरायल ने कतर को भी नहीं छोड़ा। उसने कतर की राजधानी दोहा पर मिसाइल हमले किए। हमले में कई लोगों की मौत और घायल होने की पुष्टि हुई है। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने इसे 'संप्रभुता का खुला उल्लंघन' व 'क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश' बताया है। कतर सरकार ने एक टीम गठित की है, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत सभी विकल्पों की समीक्षा करेगी।

दोहा पर इजरायली हमला किस कदर अनैतिक व अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, इसका सीधा प्रमाण तमाम बड़े देशों से आई प्रतिक्रिया से मिलता है। इजरायल के सबसे बड़े संरक्षक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमले के बाद कतर के अमीर से बात की। ट्रंप ने हमले की निंदा करते हुए दोहा के प्रति एकजुटता जताई और कतर से आग्रह किया कि वह गाजा में संघर्ष विराम कराने की अपनी भूमिका जारी रखे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से फोन पर बातचीत कर इजरायल के हमले की कड़ी निंदा की। वहीं, ईरान के राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए कतर की संप्रभुता के उल्लंघन को वैश्विक चिंता का विषय बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और कतर की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है।

यह हमला ऐसे समय में हुआ, जब एक ओर कतर और दूसरी ओर हमास गाजा में युद्धविराम कराने की कोशिश कर रहे थे। इजरायल अब तक इस क्षेत्र के कई देशों- जैसे ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन और अब कतर पर हमले कर चुका है। कल वह सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान तथा कुवैत पर भी हमला कर सकता है। इसलिए अब दुनिया के तमाम शांतिप्रिय मुल्कों को एक साथ मिलकर इजरायली अत्याचार के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। इसमें इस्लामी देशों को तो एकजुट होना लाजिमी है ही, तभी वे इजरायली आक्रामकता से बच पाएंगे, वरना इजरायल का मनसूबा साफ है कि गाजापट्टी के 20 लाख लोगों का सफाया कर उस पर कब्जा किया जाए।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

कतर में खलल

इसी तरह खत्म होंगे आतंकी संगठन

पश्चिम एशिया में स्थिति काफी समय से संकटपूर्ण बनी हुई है। इसके लिए हमास जैसे आतंकी संगठन पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। हमास तो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी है। पिछले 7 अक्तूबर को इसने अचानक इजरायल पर घातक हमला कर अनेक निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। लोकतांत्रिक और सभ्य देशों को चाहिए कि इसके खात्मे के लिए जो भी बन पड़े, वे जल्द करें।

इजरायल ने कतर पर जो हमला किया है, वह भी हमास को निशाना बनाकर ही किया है। हमले के वक्त हमास के वार्ताकार दोहा में थे। इनमें हमास के वे आतंकी सरगना भी शामिल थे, जो 7 अक्तूबर को इजरायल पर हमले के लिए जिम्मेदार थे। इसीलिए, इजरायल ने वहां हमला करके उन आतंकियों को ढेर करने का फैसला किया। ये लोग कथित तौर पर गाजा में युद्धविराम सुनिश्चित करने के लिए बातचीत कर रहे थे। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सूचना दे दी गई थी। इतना ही नहीं, इजरायल ने तो कतर तक को इस बारे में सावधान कर दिया था, ताकि वहां के नागरिकों को कोई क्षति न पहुंचे। हमास गाजा में रहने वालों की दुर्दशा का फायदा उठा रहा है, इसलिए उसका सफाया जरूरी है। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसकी ओर से नागरिकों का नुकसान कम करने के लिए कदम उठाए गए, जिनमें सटीक हथियारों का उपयोग और अतिरिक्त खुफिया जानकारी शामिल है। कहा जा रहा है कि इस हमले में कई हमास लड़ाके मारे गए हैं, जिनमें निर्वासित गाजा प्रमुख अल-हय्या सोन का बेटा भी शामिल है। ट्रंप ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि उनको हमले की जानकारी पहले से थी। जो भी हो, आतंकियों का सफाया करना विश्व शांति के लिए जरूरी है। आज ये आतंकी संगठन खुलेआम कहीं भी आतंक फैलाने और इंसानों की जान लेने में गुरेज नहीं करते। उनके हमलों में निरीह लोग, बच्चे, बूढ़े और बीमार तक मारे जा रहे हैं, बावजूद उनमें थोड़ी सी भी करुणा नहीं है। ऐसे ही आतंकियों के कारण भारत में भी बहुत बड़ा संकट बना हुआ है।

जहां तक हमास द्वारा शांति-वार्ता करने दोहा पहुंचने की बात है, तो यह केवल दिखावा था। दुनिया को यह भी मानना चाहिए कि इस तरह की वार्ताओं के जरिये हमास संकट के समय बचने का प्रयास करता है। वह इसे अपने छिपने के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करता है। जबकि, उसका मूल उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना ही होता है। इसलिए अगर इजरायल ने उसे निशाना बनाया है, तो कुछ गलत नहीं किया।

संतोष कुमार ठाकुर, समाजसेवी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 11 सितंबर, 2025

दैनिक जागरण

अपनी क्षमताओं का उपयोग न करना स्वयं के साथ अन्याय है

ट्रंप पर कितना भरोसा करें

भारत से संबंधों और टैरिफ के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यह पोस्ट उनके बदले हुए रवैये की पुष्टि करने वाली है कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं और मैं आने वाले समय में अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने यह भरोसा भी जताया कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उनकी इस सकारात्मक पोस्ट पर भारतीय प्रधानमंत्री ने भी इस आशय की पोस्ट की कि हमारी टीमें इस बातचीत को जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने भी राष्ट्रपति ट्रंप से वार्ता के लिए उत्सुकता जताई। अब प्रतीक्षा इस बात की है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जारी बातचीत कब पूरी करके किसी सफल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। संभवत ऐसा होने पर ही दोनों देशों के शासनाध्यक्षों के बीच वार्ता होगी। वैसे गतिरोध तोड़ने के लिए यह पहले भी हो सकती है, लेकिन जब तक टैरिफ का मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक बहुत अधिक उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। इसके बावजूद नहीं की जानी चाहिए कि ट्रंप ने हाल में यह दूसरी बार कहा है कि दोनों देशों के संबंधों के मामले में चिंता की कोई बात नहीं।

अमेरिकी राष्ट्रपति पर अधिक भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि गत दिवस ही उन्होंने यूरोपीय समुदाय से भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने को कहा, क्योंकि दोनों रूस से तेल खरीद रहे हैं। उन्होंने ऐसे भी संकेत दिए कि यदि यूरोपीय समुदाय के देश ऐसा करते हैं तो अमेरिका भी उनका अनुसरण कर सकता है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि व्यापार मामलों में उनके सलाहकार पीटर नवारो भारत के खिलाफ अपना दुष्प्रचार अभियान चलाए हुए हैं। यह ठीक है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को एक महान देश बता रहे हैं, लेकिन बहुत दिन नहीं हुए जब वे भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनमी बता रहे थे और एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद भारत पर तंज कस रहे थे। चूंकि यह स्पष्ट है कि ट्रंप पहले अनुचित बातें करके दबाव बनाते हैं और फिर बात बनती न देखकर अपना रवैया बदलते हैं, इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा और उन तैयारियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा, जिनके तहत अमेरिकी टैरिफ से मुकाबला करने की रणनीति बनाई जा रही है। इसी रणनीति के तहत स्वदेशी अपनाने के अभियान को गति देने के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी पहल की जा रही है। यह पहल जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप यह जता चुके हैं उन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है।

ई-रिक्शा पर लगाम

सुविधाएं चाहे जितनी हों परंतु नियमन नहीं होने से सड़कों पर ई-रिक्शा का परिचालन अराजक हो गया है। और यह समस्या आज किसी एक राज्य या एक शहर तक सीमित नहीं है। हर शहर इस समस्या से परेशान है। दरअसल ई-रिक्शा के निर्माण, प्रोत्साहन और संचालन में कई मंत्रालयों की भूमिका है। भारी उद्योग मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय कहीं न कहीं इससे जुड़े हैं। बीते एक दशक में ई-रिक्शा का अप्रत्याशित दबाव यातायात की सुगमता के लिए संकट है। उत्तर प्रदेश में भी ई-रिक्शा की निरंतर बढ़ती संख्या समस्या बढ़ा रही है। ऐसे में लखनऊ नगर निगम ने इस पर नियंत्रण, नियमन के लिए टेंपो-टैक्सी, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और ई-भार वाहन नियमावली एवं नियंत्रण उपविधि 2024 को मंजूरी दी है। उम्मीद की जा सकती है कि निगम की इस पहल से ई-रिक्शा का संचालन व्यवस्थित होगा। नई नियमावली में चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर, ई-रिक्शा का रूट निर्धारण तक शामिल है। लाइसेंस जारी किए जाएंगे और उल्लंघन पर वाहन जब्त करने का भी प्रविधान किया गया है। अच्छी बात यह है कि चालक के लिए आयु की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष करने से नाबालिगों के हाथों में ई-रिक्शा की हैंडल आने पर अंकुश होगा। घटिया गुणवत्ता वाले वाहनों पर लगाम और लेड-एसिड बैटरी वाले ई-रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से बंद करना आवश्यक है। अब चूंकि नगर निगम ई-रिक्शा चलाने के लिए शुल्क लेकर लाइसेंस भी जारी करेगा तो उम्मीद की जा सकती है कि गुणवत्ता की कठोर परख भी होगी। निश्चय ही प्रदेश के अन्य नगर निगमों में भी ऐसी पहल होनी चाहिए।

लखनऊ नगर निगम ने ई-रिक्शा चालकों के लिए नए सिरे से नियम तय किए हैं

जन आकांक्षाओं की उपेक्षा का असर

ऋषि गुप्ता

यह मान लेना सही नहीं होगा कि इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध ही नेपाल में आक्रोश का एकमात्र कारण बना। वहां लोग भ्रष्टाचार से भी त्रस्त हो गए थे

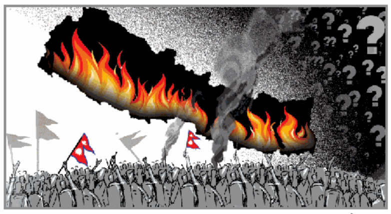

अवधेश राजपूत

नेपाल में युवाओं के आंदोलन ने देश में सरकार का तख्तापलट कर दिया। जेन जी कहे जाने वाले इन युवाओं के अभियान ने नेपाल सरकार द्वारा इंटरनेट मीडिया से जुड़े कुछ एप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के साथ जोर पकड़ा। सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों पर सख्ती के साथ युवाओं की मुहिम इतनी हिंसक हो गई कि प्रधानमंत्री सहित कई मंत्रियों के इस्तीफे से भी बात नहीं बनी और उन्हें जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। सवाल उठ रहा है कि क्या इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध को लेकर ओली सरकार का फैसला सही था? सरकार के नजरिये से देखें तो चूंकि इंटरनेट मीडिया कंपनियों ने देश के स्वायत्त ढांचे को नकारा, इसलिए देश के कानून और संप्रभुता को देखते हुए सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा। ऐसे में सवाल यह भी है कि नेपाल ने अब तक क्यों इन प्लेटफार्म को संचालित होने दिया और क्यों सरकारी दफ्तरों, विभागों, मंत्रालयों और मंत्रियों को इन इंटरनेट मीडिया अकाउंट बनाने और संचालित करने दिया गया? सीधा जवाब है कि सरकार की मंशा इंटरनेट मीडिया को नियंत्रण में रखने की थी, ताकि उस पर चल रहे आंदोलन को कमजोर किया जा सके।

ऐसी स्थितियां बनीं कैसे? इसके लिए पिछले महीने इंटरनेट मीडिया पर चली 'नेपो किड्स' यानी राजनीति और व्यापार में भाई-भतीजावाद के खिलाफ आंदोलन का जिक्र जरूरी है। नेपाल की जेन जी पीढ़ी ने एक खुला आंदोलन छेड़ रखा था, जिसमें राजनेताओं, पूर्व प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों के बच्चों की आलीशान जीवनशैली को निशाना बनाया जा रहा था। आमदनी से अधिक आय जैसे मुद्दों पर भी वे आक्रामक रहे। ऐसे में सरकार पर दबाव था कि वह इंटरनेट मीडिया को नियंत्रित करे। इसी दौरान इंटरनेट मीडिया कंपनियों ने पंजीकरण नहीं किया और उन पर प्रतिबंध लगाने का अवसर मिल गया। इस एकाएक कार्रवाई के चलते स्कूल-कालेज जाने वाली पीढ़ी आक्रोशित हो गई। एक ऐसे दौर में जब इंटरनेट मीडिया आम जरूरतों के साथ ही आमदनी का जरिये भी बन गया है तो युवाओं की ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी। एक विरोध-प्रदर्शन जो शांतिपूर्वक होना था वह इस कारण उग्र हो गया, क्योंकि सुरक्षा बलों ने उसे कुचलने के लिए पूरी ताकत लगाई और उसके बाद हिंसा की ऐसी आग लगी जो अभी तक शांत होती नहीं दिख रही।

यदि प्रधानमंत्री ओली ने बातचीत का रास्ता अपनाया होता तो मामला शांत हो सकता था। केपी ओली पर 'तानाशाह' तरीके से सरकार चलाने के आरोप लगते रहे थे, ऐसे में इंटरनेट का बंद किया जाना अभिव्यक्ति और विचारों की आजादी पर एक बड़ा प्रहार सा लगा। इस तरह दो दिनों से कम समय में नेपाल एक विचित्र स्थिति में पहुंच गया। फिलहाल सेना ने देश की सुरक्षा का जिम्मा लिया है, पर सरकार चलाने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। अनुमान है कि यहां भी बांग्लादेश की तर्ज पर एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और उसमें युवाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। ऐसी संभावित सरकार की कमान संभालने के लिए कुछ नामों की चर्चा भी चल रही है। नेपाल के राजनीतिक इतिहास में यह पहला अवसर है जब 14 से 25 आयुवर्ग वालों के नेतृत्व में ऐसा आंदोलन हुआ। नेपाल में आंदोलन वैसे तो सामान्य बात रही है। फिर चाहे 1990 का आंदोलन हो, जब राजनीतिक दलों ने राजशाही से उन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की हो या 2006 का जनांदोलन, जिसके चलते नेपाल में राजशाही हटी और पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना हुई।

इस सबके बीच यह मान लेना सही नहीं होगा कि इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध ही इस आक्रोश का एकमात्र कारण बना। वहां लोग भ्रष्टाचार से भी त्रस्त हो गए थे। नेपाल में सदियों पुरानी राजशाही व्यवस्था के खिलाफ चले दस वर्षों के लंबे आंदोलन के बाद 2006 में लोकतंत्र का बिगुल बजा और 2008 में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, लेकिन जिस भरोसे के साथ माओवादी सरकार को पूर्ण समर्थन मिला, वह उस पर खरी न उतर सकी। पहले प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड को साल भर के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद से नेपाल में एक दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री बन चुके हैं और कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। जिस तरह एमाले पार्टी के केपी शर्मा ओली, माओवादी नेता प्रचंड और नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा ने गठजोड़ के जरिये किसी भी स्थिति में सत्ता से चिपके रहने को तरजीह दी, उसने भी अस्थिरता बढ़ाई।

राजनीतिक अस्थिरता का नीतियों पर भी व्यापक असर पड़ा, जिससे विदेश नीति भी अछूती नहीं रही। देश में रोजगार के अवसरों की कमी से लेकर अच्छे शिक्षण संस्थानों का अभाव भी लोगों को अखर रहा था। ऊपर से उपलब्ध ढांचे का राजनीतिकरण, दुरुपयोग और भ्रष्टाचार देखकर उनका धैर्य जवाब देता गया। इसके चलते ही बेहतर अवसरों की तलाश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा देश छोड़कर पलायन कर गया। प्राकृतिक संपदा से संपन्न और पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला देश अपने समक्ष उपलब्ध अवसरों का लाभ नहीं उठा पाया। राजनीतिक दलों और सरकारों के विरुद्ध भावनाएं उबाल लेने लगीं और अब उसका ही प्रकटीकरण हो रहा है। जैसी तस्वीरें इस समय नेपाल से आ रही हैं, उन्हें देखकर यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि विरोध-प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व भी शामिल हो गए हैं। देश भर में आगजनी, सार्वजनिक-निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लूटपाट की खबरें आ रही हैं।

इस समय नेपाल एक दोराहे पर खड़ा है। एक राह नए लोकतांत्रिक ढांचे का अवसर तैयार करने वाली है और यदि इस अवसर को गंवाया जाता है तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जाएगी। यह घटनाक्रम अन्य देशों के लिए भी सबक है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरा उतरना और जनता के मुद्दों से जुड़े रहना कितना महत्वपूर्ण होता है। इनकी अनदेखी के परिणाम नेपाल से पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में भी देखने को मिल चुके हैं।

(लेखक एशिया सोसाइटी पालिसी इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में सहायक निदेशक हैं)
response@jagran.com

आर्थिक कायापलट करने वाली पहल

डा. सुरजीत सिंह

आज की दुनिया में माइक्रोचिप सिर्फ एक इलेक्ट्रानिक पुर्जा नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन है

अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ से उबरने का प्रयास करती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल डायमंड ने एक बड़ी उम्मीद जगाते हुए विदेशी निवेशकों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा है। हाल में आयोजित हुए सेमीकान इंडिया 2025 सम्मेलन में इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरी तरह स्वदेशी 32-बिट माइक्रो चिप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेंट की। इसे मात्र 30 महीनों में तैयार कर सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज की दुनिया में माइक्रोचिप सिर्फ एक इलेक्ट्रानिक पुर्जा नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। मोबाइल, लैपटाप, आटोमोबाइल, रक्षा उपकरण, मेडिकल मशीनें हर जगह चिप्स की आवश्यकता है। बिना इनके हमारे रोजमर्रा के गैजेट्स और मशीनें अधूरी हैं। स्मार्टफोन, लैपटाप, टीवी, स्मार्टवाच, इंटरनेट की गति आदि सभी सेमीकंडक्टर पर चलते हैं। आधुनिक गाड़ियां अब पूरी तरह इलेक्ट्रानिक सिस्टम पर आधारित हैं, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी मैनेजमेंट, सेंसर और नेविगेशन के लिए चिप बेहद जरूरी हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम आने वाली कई तरह की अत्याधुनिक मशीनों जैसे एमआरआइ, सीटी स्कैन आदि में भी चिप की जरूरत होती है। बड़े पावर प्लांट्स, 5जी नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड सर्विसेज सब सेमीकंडक्टर की बदौलत ही चलते हैं।

भारत प्रतिवर्ष 20 से 25 अरब डालर से ज्यादा के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रानिक चिप आयात करता है। आने वाले वर्षों में ये तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि नए मिशन के तहत भारत खुद अपने सेमीकंडक्टर बना सकता है। भारत का मकसद सिर्फ घरेलू जरूरतें ही पूरी करना नहीं है, बल्कि दुनिया के सेमीकंडक्टर बाजार में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बनाना भी है। 2023 में भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 38 अरब डालर था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 40 से 50 अरब डालर का हो गया। 2030 तक यह बाजार एक ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर से भी ज्यादा का हो जाएगा। यदि भारत इसमें से पांच से 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी भी हासिल करता है तो देश की जीडीपी

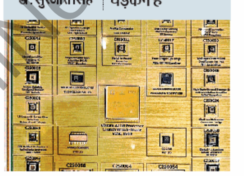

प्रगति को नए पंख लगाएगी स्वदेश निर्मित चिप। फाइल

दो से तीन प्रतिशत तक बढ़ सकती है। इससे भारत के पांच ट्रिलियन डालर इकोनमी बनने में तेजी आएगी। सेमीकंडक्टर के चार नए प्रोजेक्ट लांच हो चुके हैं, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सहयोग से छह प्रोजेक्ट लांच होने के क्रम में हैं। भारत आज ताइवान, कोरिया, अमेरिका, चीन आदि देशों की महारत को चुनौती देने के लिए तैयार है। वैश्विक स्तर पर ताइवान का योगदान 66 प्रतिशत, 17 प्रतिशत दक्षिण कोरिया एवं आठ प्रतिशत योगदान चीन का है।

माइक्रोचिप बनाने के लिए अत्याधुनिक प्लांट में हजारों इंजीनियर, तकनीशियन और आपरेटरों की आवश्यकता होती है। चिप निर्माण में सिलिकान वेफर, रसायन, विशेष गैसें और पैकेजिंग सामग्री का उपयोग होता है। इनकी आपूर्ति और प्रबंधन के लिए देशभर में छोटे-बड़े उद्योग और कंपनियां जुड़ेंगी, जिससे अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर करोड़ों की संख्या में उत्पन्न होंगे। भारत पहले से ही आइटी और चिप डिजाइन में दुनिया का एक मजबूत केंद्र है। चिप डिजाइन, टेस्टिंग और साफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लाखों उच्च कौशल वाले रोजगार उपलब्ध होंगे। माइक्रोचिप उद्योग से जुड़े परिवहन, गोदाम, सुरक्षा, सफाई और तकनीकी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बाजार पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए विशेष कोर्स, प्रशिक्षण केंद्र और अनुसंधान संस्थान विकसित किए जाएं, जिसके माध्यम से न केवल प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार होगा, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में भी शिक्षक, शोधकर्ता और ट्रेनर के रूप में बड़ी संख्या में नई नौकरियां निकलेंगी।

सेमीकंडक्टर उद्योग में भारी मात्रा में पानी और बिजली की भी खपत होती है। भारत को इस उद्योग के विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन पर भी ध्यान देना होगा। इसके लिए ग्रीन एनर्जी, रीसाइक्लिंग और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्राथमिकता देनी होगी। भारत को विशेष औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण करना होगा। चिप निर्माण एक अत्यंत तकनीकी प्रक्रिया है, जिसके लिए प्रशिक्षित इंजीनियर और टेक्नीशियन चाहिए। इसके लिए भारत को इंजीनियरिंग कालेजों, आइटीआइ और विश्वविद्यालयों में सेमीकंडक्टर से जुड़े विशेष कोर्स शुरू करने होंगे। विदेशी विशेषज्ञों से प्रशिक्षण और सहयोग भी जरूरी होगा, ताकि मानव संसाधन वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार हो सके।

सेमीकंडक्टर उद्योग में प्रतिस्पर्धा का आधार अनुसंधान है। भारत को अपने आइआइटी, एनआइटी और निजी विश्वविद्यालयों को चिप डिजाइन और अनुसंधान से जोड़ना होगा। सरकार को नई तकनीकों पर काम करने वाले स्टार्टअप्स और रिसर्च सेंटर को आर्थिक सहायता और टैक्स में छूट प्रदान करनी होगी। भारत आज जिस गति से तकनीकी प्रगति की ओर बढ़ रहा है, उसमें माइक्रोचिप उद्योग को सबसे बड़ा गेमचेंजर माना जा रहा है। इससे न सिर्फ चिप का आयात कम होगा, बल्कि कीमत कम होने से स्वदेशी एवं विदेशी बाजार में बढ़त हासिल करने में भी हम आगे होंगे। इससे 2047 तक देश को विकसित बनाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

वर्तमान का आनंद

जीवन की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम हमेशा बेहतर कल का इंतजार करते रहते हैं। 'सही समय' की प्रतीक्षा में हम अपना बहुत सारा समय व्यर्थ कर देते हैं। हमें लगता है कि कभी ऐसा समय आएगा, जब सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और सब कुछ सरल एवं सहज हो जाएगा, जबकि चुनौतियों का दूसरा नाम ही जीवन है। कालखंड के प्रत्येक हिस्से में अपनी अलग चुनौतियां, उलझनें और अनिश्चितताएं रहती हैं। यदि हम सुख और संतोष को भविष्य के किसी कालखंड पर टाल देंगे तो यह प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होगी। वास्तविकता यही है कि जीवन जटिल है और उसकी जटिलता एकाएक नहीं सुलझने वाली। हमें छोटी-छोटी बातों और उपलब्धियों पर प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये बड़ी खुशियों की निमित्त बनती हैं।

जीवन की वास्तविकता यही है कि जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, वही जीवन को सार्थक बना पाता है। सुख का रहस्य समस्याओं के समाप्त होने में नहीं, बल्कि उनके बीच संतुलन और मुस्कान खोजने में छिपा है। कठिनाइयों का बोझ जितना हम पर हावी होता है, उतना ही हमारा वर्तमान छिनता चला जाता है। स्मरण रहे कि समय सबसे मूल्यवान पूंजी है। यह न रुकेगा न लौटेगा। यदि हम खुशी और संतोष को टालते रहे तो जीवन हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। प्रतीक्षा करते बस समय निकलता जाएगा और हम पछतावा करते रह जाएंगे।

यह जरूरी है कि जीवन के हर पल को अवसर मानें। गलतियों से सीखें, रिश्तों की गर्माहट को महसूस करें और अपनी अपूर्णताओं के बीच भी पूर्णता की दिशा में प्रयास करते हुए मुस्कुराना सीखें। जीवन की जटिलताओं को गले लगाकर ही हम उसके रस को चख सकते हैं। वास्तविक परिपक्वता यही है कि हम यह समझ लें कि प्रसन्नता कोई गंतव्य नहीं, अपितु निरंतर चलने वाली यात्रा है।

अमन सिंह गौर

संवेदनहीनता उजागर करती आपदाएं

डा. वेदप्रकाश

बाढ़, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए किए जाएं पर्याप्त उपाय

विगत लंबे समय से देश के विभिन्न प्रदेशों में भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन से आपदाएं जारी हैं। क्या ये आपदाएं शासन-प्रशासन और कुछ लोगों की संवेदनहीनता को उजागर नहीं करतीं? नदी, नाले, पेड़-पौधे, जंगल और पर्वत पर्यावरणीय संरचना के अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग हैं। कहीं विकास के नाम पर तो कहीं लालच की प्रवृत्ति के चलते इस पर्यावरणीय संरचना को बिगाड़ा जा रहा है। पहाड़ों से अनुचित छेड़छाड़, नदी, पर्वत और धरती से अवैध खनन, अतिक्रमण और पेड़ों की अवैध कटाई जारी है। नदी-नालों के बहाव क्षेत्र में अवैध बस्तियां बसाई जा रही हैं। राजनीति और भ्रष्टाचार अवैध तंत्र को पोषित कर रहे हैं। अवैध के विरुद्ध कानून और कार्रवाई हाशिए पर है।

विगत कुछ दिनों में ही पर्वतीय राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर से बाढ़ एवं आपदा के कारण लगभग 28 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। इन प्रदेशों से कई गांवों का नामोनिशान मिट गया तो हजारों गांव प्रभावित भी हुए हैं और कई सौ लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त पंजाब के तमाम जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। खेती के साथ-साथ लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। राजस्थान में भी बाढ़ और भारी बारिश से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों मकान गिर चुके हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े बताते हैं कि बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं विगत वर्षों की तुलना में इस बार लगभग दो गुनी हो चुकी हैं। उत्तराखंड के धराली-भराली से शुरू हुआ प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला हिमाचल, जम्मू-कश्मीर से होते हुए राजस्थान, पंजाब और दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली में कुछ दिन पहले यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विगत कई दशकों से नदी और नालों से गाद नहीं निकाली गई है। ड्रेनेज प्लान भी पुराने ही चल रहे हैं। यमुना का जलग्रहण क्षेत्र अतिक्रमण की चपेट में है। क्या यह शासन-प्रशासन की संवेदनहीनता का द्योतक नहीं है?

विभिन्न पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में नदियों से अवैध खनन जारी है। यह भी विडंबना ही है कि केवल मानसून अथवा किसी आपदा के समय ही अवैध खनन, अतिक्रमण और प्रकृति से छेड़छाड़ की बातों पर चर्चा होती है, उसके बाद फिर ढाक के तीन पात हैं। लगातार बढ़ती आपदाओं को ध्यान में रखते हुए आज यह आवश्यक है कि पर्वतीय राज्यों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करते हुए सतत और व्यापक नीतियां बनें। समूचे देश में नदियों का बाढ़ क्षेत्र और नालों का प्रभाव क्षेत्र परिभाषित हो। उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण और अतिक्रमण प्रतिबंधित और दंडनीय किया जाए। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में त्वरित सूचना एवं पूर्व अनुमान तकनीक विकसित की जाएं, ताकि जान-माल का कम से कम नुकसान हो।

(लेखक किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विवि में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)

आक्रोश की आग में धधकता नेपाल

'संकट में नेपाल' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी में पड़ोसी देश नेपाल में ओली सरकार की मनमानी नीतियों के विरुद्ध भड़के युवा आक्रोश को केपी शर्मा ओली की अदूरदर्शिता माना गया है। नेपाली सरकार द्वारा कुछ इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को प्रतिबंधित कर देने के फलस्वरूप भड़का युवा आंदोलन देखते ही देखते हिंसक हो गया। अचानक भड़की नेपाल की इस आग के पीछे की वास्तविकता अभी तक अबूझ है। यदि बात केवल इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के प्रतिबंध तक ही सीमित होती तो नेपाली सरकार द्वारा इस पर लगे प्रतिबंध को हटा लेने की घोषणा के साथ ही आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। हालांकि आंदोलन थमने के बजाय उग्र होता चला गया और सब कुछ तहस-नहस करते हुए ओली सरकार के इस्तीफा देने पर भी रुका नहीं। हालांकि अब नेपाली सेना ने कमान संभाल ली है और अराजकता की आग में धधकते नेपाल को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल नेपाल का भविष्य अंधेरे में है और आगामी नेतृत्व के संबंध में अटकलें ही चल रही है। श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल इन तीनों पड़ोसी देशों में जिस एक ही पैटर्न से लोकतांत्रिक सरकारों का तख्तापलट हुआ है, वह भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि यहां भी एक तबका ऐसा है जो ऐसी अराजकता में विश्वास रखता है और गाहे-बगाहे उसका प्रदर्शन भी करता रहता है। हालांकि भारत के मजबूत लोकतंत्र और सक्षम नेतृत्व के कारण इन देशघातियों के नापाक मंसूबे पूरे नहीं हो पाते। भारत विरोधियों के मंसूबे सफल भी नहीं होने चाहिए। राष्ट्र विरोधी शक्तियों के पराभव के लिए 'राष्ट्र सर्वोपरि' के भाव को जीवंत रखने की जरूरत है। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों का शुभचिंतक रहा है। नेपाल के संकट से भी वह चिंतित है और यथाशीघ्र शांति की कामना कर रहा है।

डा. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़ (उप्र)

मेलबाक्स

विकास की ओर अग्रसर बिहार

बिहार के पिछड़ेपन के गुनहगार नामक संपादकीय आलेख में सुरेंद्र किशोर द्वारा बिहार के पिछड़ेपन पर अपनी राय व्यक्त करते हुए नीतीश सरकार के सुशासन के लगभग 20 वर्ष और लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के लगभग 15 वर्षों के शासनकाल पर विचार व्यक्त करते हुए कांग्रेस जैसी पूर्व में रही सत्तारूढ़ सरकारों के शासनकाल पर प्रकाश डाला गया है। हालांकि यदि किसी भी राज्य के पिछड़ेपन को आंका जाए तो वहां रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय उसका सबसे बड़ा पैमाना कहा जा सकता है। साल 2024-2025 की यदि हम बात करें तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से भी काफी कम आंकी गई है। मतलब साफ है कि अभी भी बिहार की स्थिति कुछ क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क आदि आधारभूत क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा ज्यादा चिंताजनक तो नहीं, लेकिन मिश्रित रूप से पिछड़ी हुई बनी है। यदि बिहारवासियों के सामने ऐसी स्थिति नहीं बनी होती तो ये लोग गरीबी, भुखमरी के दंश को झेलते हुए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में पलायन क्यों करते? हालांकि हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि बिहार में सबसे ज्यादा शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ही रही है। साल 1990 तक कांग्रेस किसी न किसी रूप में सत्ता में बनी रही। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार होने के बावजूद बिहार में जो प्रगति अथवा विकास की गति देखी जानी चाहिए थी, वह पूर्ण रूप से नजर नहीं आई। साल 2005 से नीतीश कुमार का जलवा बिहार की जनता में कायम है। अनेक क्षेत्रों में उन्होंने बिहार की स्थिति में सुधारों का प्रयास किया है। शायद इन्हीं प्रयासों के कारण लोग उन्हें सुशासन बाबू की संज्ञा देने लगे हैं। राजनीतिक अथवा अवसरवादी दृष्टिकोण से यदि बिहार अभी भी अपने पिछड़ेपन को दूर नहीं कर सकता है तो फिर यह कहा जा सकता है कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण कोई और नहीं, बल्कि बिहार पर राज करने वाले राजनीतिक दल ही हैं जो हमेशा से अपनी निजी महत्वाकांक्षा के आगे बिहार के विकास का गला घोटते आए हैं।

पवन कुमार मुरली, गुरुग्राम

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

अपनी क्षमताओं का उपयोग न करना स्वयं के साथ अन्याय है

ट्रंप पर कितना भरोसा करें

भारत से संबंधों और टैरिफ के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यह पोस्ट उनके बदले हुए रवैये की पुष्टि करने वाली है कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं और मैं आने वाले समय में अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने यह भरोसा भी जताया कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उनकी इस सकारात्मक पोस्ट पर भारतीय प्रधानमंत्री ने भी इस आशय की पोस्ट की कि हमारी टीमें इस बातचीत को जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने भी राष्ट्रपति ट्रंप से वार्ता के लिए उत्सुकता जताई। अब प्रतीक्षा इस बात की है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जारी बातचीत कब पूरी करके किसी सफल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। संभवत ऐसा होने पर ही दोनों देशों के शासनाध्यक्षों के बीच वार्ता होगी। वैसे गतिरोध तोड़ने के लिए यह पहले भी हो सकती है, लेकिन जब तक टैरिफ का मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक बहुत अधिक उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। इसके बावजूद नहीं की जानी चाहिए कि ट्रंप ने हाल में यह दूसरी बार कहा है कि दोनों देशों के संबंधों के मामले में चिंता की कोई बात नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति पर अधिक भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि गत दिवस ही उन्होंने यूरोपीय समुदाय से भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने को कहा, क्योंकि दोनों रूस से तेल खरीद रहे हैं। उन्होंने ऐसे भी संकेत दिए कि यदि यूरोपीय समुदाय के देश ऐसा करते हैं तो अमेरिका भी उनका अनुसरण कर सकता है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि व्यापार मामलों में उनके सलाहकार पीटर नवारो भारत के खिलाफ अपना दुष्प्रचार अभियान चलाए हुए हैं। यह ठीक है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को एक महान देश बता रहे हैं, लेकिन बहुत दिन नहीं हुए जब वे भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनमी बता रहे थे और एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद भारत पर तंज कस रहे थे। चूंकि यह स्पष्ट है कि ट्रंप पहले अनुचित बातें करके दबाव बनाते हैं और फिर बात बनती न देखकर अपना रवैया बदलते हैं, इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा और उन तैयारियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा, जिनके तहत अमेरिकी टैरिफ से मुकाबला करने की रणनीति बनाई जा रही है। इसी रणनीति के तहत स्वदेशी अपनाने के अभियान को गति देने के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी पहल की जा रही है। यह पहल जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप यह जता चुके हैं उन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है।

विकास को रफ्तार

बिहार का राजकोषीय घाटा 6.2 से गिरकर 2.9 प्रतिशत होना यह बताता है कि राज्य विकास के रास्ते में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम से प्रगति दिख रही है। तभी तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य की विकास दर 8.64 प्रतिशत तक पहुंचने के साथ इस एक वर्ष में अर्थव्यवस्था 4.89 से बढ़कर 5.31 लाख करोड़ रुपये की हो गई है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इन आंकड़ों के साथ अगले कुछ वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ रुपये होने की जो बात कही है, वह भी दूर नहीं। इसके कई कारण हैं। सरकार ने राज्य में औद्योगिक माहौल का विकास किया है। उद्योग लगाने के लिए जमीन के साथ छूट व अन्य सुविधाओं की घोषणा की है। इस कारण कई औद्योगिक घराने निवेश के लिए पहुंच रहे हैं। सिर्फ उद्योग ही नहीं खेती, निर्माण और परिवहन के अलावा पर्यटन को भी बढ़ावा देने पर काम हुआ है। बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। साथ ही स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम हुआ है। इससे इन उत्पादों को बाजार मिल रहा है। मखाना को ही लें तो जीआइ टैग मिलने के बाद इसकी मांग व कीमत बढ़ी है। इससे किसानों के साथ व्यापारियों को लाभ हो रहा। हालांकि, विकास में बाधक भ्रष्टाचार व अपराध जैसी चुनौतियों के विरुद्ध और सख्ती की जरूरत है।

हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम से राज्य विकास की राह पर है और राजकोषीय घाटा कम हुआ।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या नेपाल का घटनाक्रम भारत के लिए चिंता का विषय है?

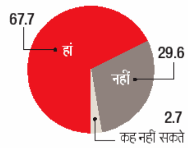

आज का सवाल

क्या उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम विपक्षी एकता के लिए झटका है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

जन आकांक्षाओं की उपेक्षा का असर

ऋषि गुप्ता

यह मान लेना सही नहीं होगा कि इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध ही नेपाल में आक्रोश का एकमात्र कारण बना। वहां लोग भ्रष्टाचार से भी त्रस्त हो गए थे

नेपाल में युवाओं के आंदोलन ने देश में सरकार का तख्तापलट कर दिया। जेन जी कहे जाने वाले इन युवाओं के अभियान ने नेपाल सरकार द्वारा इंटरनेट मीडिया से जुड़े कुछ एप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के साथ जोर पकड़ा। सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों पर सख्ती के साथ युवाओं की मुहिम इतनी हिंसक हो गई कि प्रधानमंत्री सहित कई मंत्रियों के इस्तीफे से भी बात नहीं बनी और उन्हें जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। सवाल उठ रहा है कि क्या इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध को लेकर ओली सरकार का फैसला सही था? सरकार के नजरिये से देखें तो चूंकि इंटरनेट मीडिया कंपनियों ने देश के स्वायत्त ढांचे को नकारा, इसलिए देश के कानून और संप्रभुता को देखते हुए सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा। ऐसे में सवाल यह भी है कि नेपाल ने अब तक क्यों इन प्लेटफार्म को संचालित होने दिया और क्यों सरकारी दफ्तरों, विभागों, मंत्रालयों और मंत्रियों को इन इंटरनेट मीडिया अकाउंट बनाने और संचालित करने दिया गया? सीधा जवाब है कि सरकार की मंशा इंटरनेट मीडिया को नियंत्रण में रखने की थी, ताकि उस पर चल रहे आंदोलन को कमजोर किया जा सके।

ऐसी स्थितियां बनीं कैसे? इसके लिए पिछले महीने इंटरनेट मीडिया पर चली 'नेपो किड्स' यानी राजनीति और व्यापार में भाई-भतीजावाद के खिलाफ आंदोलन का जिक्र जरूरी है। नेपाल की जेन जी पीढ़ी ने एक खुला आंदोलन छेड़ रखा था, जिसमें राजनेताओं, पूर्व प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों के बच्चों की आलीशान जीवनशैली को निशाना बनाया जा रहा था। आमदनी से अधिक आय जैसे मुद्दों पर भी वे आक्रामक रहे। ऐसे में सरकार पर दबाव था कि वह इंटरनेट मीडिया को नियंत्रित करे। इसी दौरान इंटरनेट मीडिया कंपनियों ने पंजीकरण नहीं किया और उन पर प्रतिबंध लगाने का अवसर मिल गया। इस एकाएक कार्रवाई के चलते स्कूल-कालेज जाने वाली पीढ़ी आक्रोशित हो गई। एक ऐसे दौर में जब इंटरनेट मीडिया आम जरूरतों के साथ ही आमदनी का जरिये भी बन गया है तो युवाओं की ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी। एक विरोध-प्रदर्शन जो शांतिपूर्वक होना था वह इस कारण उग्र हो गया, क्योंकि सुरक्षा बलों ने उसे कुचलने के लिए पूरी ताकत लगाई और उसके बाद हिंसा की ऐसी आग लगी जो अभी तक शांत होती नहीं दिख रही।

यदि प्रधानमंत्री ओली ने बातचीत का रास्ता अपनाया होता तो मामला शांत हो सकता था। केपी ओली पर 'तानाशाह' तरीके से सरकार चलाने के आरोप लगते रहे थे, ऐसे में इंटरनेट का बंद किया जाना अभिव्यक्ति और विचारों की आजादी पर एक बड़ा प्रहार सा लगा। इस तरह दो दिनों से कम समय में नेपाल एक विचित्र स्थिति में पहुंच गया। फिलहाल सेना ने देश की सुरक्षा का जिम्मा लिया है, पर सरकार चलाने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। अनुमान है कि यहां भी बांग्लादेश की तर्ज पर एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और उसमें युवाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। ऐसी संभावित सरकार की कमान संभालने के लिए कुछ नामों की चर्चा भी चल रही है। नेपाल के राजनीतिक इतिहास में यह पहला अवसर है जब 14 से 25 आयुवर्ग वालों के नेतृत्व में ऐसा आंदोलन हुआ। नेपाल में आंदोलन वैसे तो सामान्य बात रही है। फिर चाहे 1990 का आंदोलन हो, जब राजनीतिक दलों ने राजशाही से उन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की हो या 2006 का जनांदोलन, जिसके चलते नेपाल में राजशाही हटी और पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना हुई।

अवधेश राजपूत

इस सबके बीच यह मान लेना सही नहीं होगा कि इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध ही इस आक्रोश का एकमात्र कारण बना। वहां लोग भ्रष्टाचार से भी त्रस्त हो गए थे। नेपाल में सदियों पुरानी राजशाही व्यवस्था के खिलाफ चले दस वर्षों के लंबे आंदोलन के बाद 2006 में लोकतंत्र का बिगुल बजा और 2008 में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, लेकिन जिस भरोसे के साथ माओवादी सरकार को पूर्ण समर्थन मिला, वह उस पर खरी न उतर सकी। पहले प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड को साल भर के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा था। तब से लेकर आज तक नेपाल में एक दर्जन से भी अधिक प्रधानमंत्री बन चुके हैं और कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। साथ ही जिस तरह से एमाले पार्टी के केपी शर्मा ओली, माओवादी नेता प्रचंड और नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा ने गठजोड़ के जरिये किसी भी स्थिति में सत्ता से चिपके रहने को तरजीह दी, उसने भी राजनीतिक अस्थिरता बढ़ाई।

राजनीतिक अस्थिरता का नीतियों पर भी व्यापक असर पड़ा, जिससे विदेश नीति भी अछूती नहीं रही। किसी सरकार ने 'इंडिया-कार्ड' का इस्तेमाल किया तो दूसरे ने 'चाइना-कार्ड' का। देश में रोजगार के अवसरों की कमी से लेकर अच्छे शिक्षण संस्थानों का अभाव भी लोगों को अखर रहा था। ऊपर से उपलब्ध ढांचे का राजनीतिकरण, दुरुपयोग और भ्रष्टाचार देखकर उनका धैर्य जवाब देता गया। इसके चलते ही बेहतर अवसरों की तलाश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा देश छोड़कर पलायन कर गया। प्राकृतिक संपदा से संपन्न और पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला देश अपने समक्ष उपलब्ध अवसरों का लाभ नहीं उठा पाया। राजनीतिक दलों और सरकारों के विरुद्ध भावनाएं उबाल लेने लगीं और अब उसका ही प्रकटीकरण हो रहा है। जैसी तस्वीरें इस समय नेपाल से आ रही हैं, उन्हें देखकर यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि विरोध-प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व भी शामिल हो गए हैं। देश भर में आगजनी, सार्वजनिक-निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लूटपाट की खबरें आ रही हैं।

इस समय नेपाल एक दोराहे पर खड़ा है। एक राह नए लोकतांत्रिक ढांचे का अवसर तैयार करने वाली है और यदि इस अवसर को गंवाया जाता है तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जाएगी। यह घटनाक्रम अन्य देशों के लिए भी सबक है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरा उतरना और जनता के मुद्दों से जुड़े रहना कितना महत्वपूर्ण होता है। इनकी अनदेखी के परिणाम नेपाल से पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में भी देखने को मिल चुके हैं।

(लेखक एशिया सोसाइटी पालिसी इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में सहायक निदेशक हैं)

response@jagran.com

आर्थिक कायापलट करने वाली पहल

डा. सुरजीत सिंह

आज की दुनिया में माइक्रोचिप सिर्फ एक इलेक्ट्रानिक पुर्जा नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन है

अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ से उबरने का प्रयास करती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल डायमंड ने एक बड़ी उम्मीद जगाते हुए विदेशी निवेशकों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा है। हाल में आयोजित हुए सेमीकान इंडिया 2025 सम्मेलन में इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरी तरह स्वदेशी 32-बिट माइक्रो चिप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेंट की। इसे मात्र 30 महीनों में तैयार कर सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज की दुनिया में माइक्रोचिप सिर्फ एक इलेक्ट्रानिक पुर्जा नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। मोबाइल, लैपटाप, आटोमोबाइल, रक्षा उपकरण, मेडिकल मशीनें हर जगह चिप्स की आवश्यकता है। बिना इनके हमारे रोजमर्रा के गैजेट्स और मशीनें अधूरी हैं। स्मार्टफोन, लैपटाप, टीवी, स्मार्टवाच, इंटरनेट की गति आदि सभी सेमीकंडक्टर पर चलते हैं। आधुनिक गाड़ियां अब पूरी तरह इलेक्ट्रानिक सिस्टम पर आधारित हैं, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी मैनेजमेंट, सेंसर और नेविगेशन के लिए चिप बेहद जरूरी हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम आने वाली कई तरह की अत्याधुनिक मशीनों जैसे एमआरआइ, सीटी स्कैन आदि में भी चिप की जरूरत होती है। बड़े पावर प्लांट्स, 5जी नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड सर्विसेज सब सेमीकंडक्टर की बदौलत ही चलते हैं।

भारत प्रतिवर्ष 20 से 25 अरब डालर से ज्यादा के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रानिक चिप आयात करता है। आने वाले वर्षों में ये तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि नए मिशन के तहत भारत खुद अपने सेमीकंडक्टर बना सकता है। भारत का मकसद सिर्फ घरेलू जरूरतें ही पूरी करना नहीं है, बल्कि दुनिया के सेमीकंडक्टर बाजार में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बनाना भी है। 2023 में भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 38 अरब डालर था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 40 से 50 अरब डालर का हो गया। 2030 तक यह बाजार एक ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर से भी ज्यादा का हो जाएगा। यदि भारत इसमें से पांच से 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी भी हासिल करता है तो देश की जीडीपी दो से तीन प्रतिशत तक बढ़ सकती है। इससे भारत के पांच ट्रिलियन डालर इकोनमी बनने में तेजी आएगी। सेमीकंडक्टर के चार नए प्रोजेक्ट लांच हो चुके हैं, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सहयोग से छह प्रोजेक्ट लांच होने के क्रम में हैं। भारत आज ताइवान, कोरिया, अमेरिका, चीन आदि देशों की महारत को चुनौती देने के लिए तैयार है। वैश्विक स्तर पर ताइवान का योगदान 66 प्रतिशत, 17 प्रतिशत दक्षिण कोरिया एवं आठ प्रतिशत योगदान चीन का है।

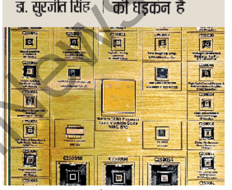

प्रगति को नए पंख लगाएगी स्वदेश निर्मित चिप ● फाइल

माइक्रोचिप बनाने के लिए अत्याधुनिक प्लांट में हजारों इंजीनियर, तकनीशियन और आपरेटरों की आवश्यकता होती है। चिप निर्माण में सिलिकान वेफर, रसायन, विशेष गैसें और पैकेजिंग सामग्री का उपयोग होता है। इनकी आपूर्ति और प्रबंधन के लिए देशभर में छोटे-बड़े उद्योग और कंपनियां जुड़ेंगी, जिससे अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर करोड़ों की संख्या में उत्पन्न होंगे। भारत पहले से ही आइटी और चिप डिजाइन में दुनिया का एक मजबूत केंद्र है। चिप डिजाइन, टेस्टिंग और साफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लाखों उच्च कौशल वाले रोजगार उपलब्ध होंगे। माइक्रोचिप उद्योग से जुड़े परिवहन, गोदाम, सुरक्षा, सफाई और तकनीकी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बाजार पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए विशेष कोर्स, प्रशिक्षण केंद्र और अनुसंधान संस्थान विकसित किए जाएं, जिसके माध्यम से न केवल प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार होगा, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में भी शिक्षक, शोधकर्ता और ट्रेनर के रूप में बड़ी संख्या में नई नौकरियां निकलेंगी।

सेमीकंडक्टर उद्योग में भारी मात्रा में पानी और बिजली की भी खपत होती है। भारत को इस उद्योग के विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन पर भी ध्यान देना होगा। इसके लिए ग्रीन एनर्जी, रीसाइक्लिंग और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्राथमिकता देनी होगी। भारत को विशेष औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण करना होगा। चिप निर्माण एक अत्यंत तकनीकी प्रक्रिया है, जिसके लिए प्रशिक्षित इंजीनियर और टेक्नीशियन चाहिए। इसके लिए भारत को इंजीनियरिंग कालेजों, आइटीआइ और विश्वविद्यालयों में सेमीकंडक्टर से जुड़े विशेष कोर्स शुरू करने होंगे। विदेशी विशेषज्ञों से प्रशिक्षण और सहयोग भी जरूरी होगा, ताकि मानव संसाधन वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार हो सके।

सेमीकंडक्टर उद्योग में प्रतिस्पर्धा का आधार अनुसंधान है। भारत को अपने आइआइटी, एनआइटी और निजी विश्वविद्यालयों को चिप डिजाइन और अनुसंधान से जोड़ना होगा। सरकार को नई तकनीकों पर काम करने वाले स्टार्टअप्स और रिसर्च सेंटर को आर्थिक सहायता और टैक्स में छूट प्रदान करनी होगी। भारत आज जिस गति से तकनीकी प्रगति की ओर बढ़ रहा है, उसमें माइक्रोचिप उद्योग को सबसे बड़ा गेमचेंजर माना जा रहा है। इससे न सिर्फ चिप का आयात कम होगा, बल्कि कीमत कम होने से स्वदेशी एवं विदेशी बाजार में बढ़त हासिल करने में भी हम आगे होंगे। इससे 2047 तक देश को विकसित बनाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

वर्तमान का आनंद

जीवन की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम हमेशा बेहतर कल का इंतजार करते रहते हैं। 'सही समय' की प्रतीक्षा में हम अपना बहुत सारा समय व्यर्थ कर देते हैं। हमें लगता है कि कभी ऐसा समय आएगा, जब सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और सब कुछ सरल एवं सहज हो जाएगा, जबकि चुनौतियों का दूसरा नाम ही जीवन है। कालखंड के प्रत्येक हिस्से में अपनी अलग चुनौतियां, उलझनें और अनिश्चितताएं रहती हैं। यदि हम सुख और संतोष को भविष्य के किसी कालखंड पर टाल देंगे तो यह प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होगी। वास्तविकता यही है कि जीवन जटिल है और उसकी जटिलता एकाएक नहीं सुलझने वाली। हमें छोटी-छोटी बातों और उपलब्धियों पर प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये बड़ी खुशियों की निमित्त बनती हैं।

जीवन की वास्तविकता यही है कि जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, वही जीवन को सार्थक बना पाता है। सुख का रहस्य समस्याओं के समाप्त होने में नहीं, बल्कि उनके बीच संतुलन और मुस्कान खोजने में छिपा है। कठिनाइयों का बोझ जितना हम पर हावी होता है, उतना ही हमारा वर्तमान छिनता चला जाता है। स्मरण रहे कि समय सबसे मूल्यवान पूंजी है। यह न रुकेगा न लौटेगा। यदि हम खुशी और संतोष को टालते रहे तो जीवन हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। प्रतीक्षा करते बस समय निकलता जाएगा और हम पछतावा करते रह जाएंगे।

यह बहुत आवश्यक है कि हम जीवन के प्रत्येक पल को एक अवसर मानें। अपनी गलतियों से सीखें, रिश्तों की गर्माहट को महसूस करें और अपनी अपूर्णताओं के बीच भी पूर्णता की दिशा में प्रयास करते हुए मुस्कुराना सीखें। जीवन की जटिलताओं को गले लगाकर ही हम उसके रस को चख सकते हैं। वास्तविक परिपक्वता यही है कि हम यह समझ लें प्रसन्नता कोई गंतव्य नहीं, अपितु निरंतर चलने वाली एक यात्रा है।।

अमन सिंह गौर

पाठकनामा

pathaknama@pat .jagran.com

आक्रोश की आग में धधकता नेपाल

'संकट में नेपाल' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी में पड़ोसी देश नेपाल में ओली सरकार की मनमानी नीतियों के विरुद्ध भड़के युवा आक्रोश को केपी शर्मा ओली की अदूरदर्शिता माना गया है। नेपाली सरकार द्वारा कुछ इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को प्रतिबंधित कर देने के फलस्वरूप भड़का युवा आंदोलन देखते ही देखते हिंसक हो गया। अचानक भड़की नेपाल की इस आग के पीछे की वास्तविकता अभी तक अबूझ है। यदि बात केवल इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के प्रतिबंध तक ही सीमित होती तो नेपाली सरकार द्वारा इस पर लगे प्रतिबंध को हटा लेने की घोषणा के साथ ही आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। हालांकि आंदोलन थमने के बजाय उग्र होता चला गया और सब कुछ तहस-नहस करते हुए ओली सरकार के इस्तीफा देने पर भी रुका नहीं। हालांकि अब नेपाली सेना ने कमान संभाल ली है और अराजकता की आग में धधकते नेपाल को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल नेपाल का भविष्य अंधेरे में है और आगामी नेतृत्व के संबंध में अटकलें ही चल रही है। श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल इन तीनों पड़ोसी देशों में जिस एक ही पैटर्न से लोकतांत्रिक सरकारों का तख्तापलट हुआ है, वह भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि यहां भी एक तबका ऐसा है जो ऐसी अराजकता में विश्वास रखता है और गाहे-बगाहे उसका प्रदर्शन भी करता रहता है। हालांकि भारत के मजबूत लोकतंत्र और सक्षम नेतृत्व के कारण इन देशघातियों के नापाक मंसूबे पूरे नहीं हो पाते। भारत विरोधियों के मंसूबे सफल भी नहीं होने चाहिए। राष्ट्र विरोधी शक्तियों के पराभव के लिए 'राष्ट्र सर्वोपरि' के भाव को जीवंत रखने की जरूरत है। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों का शुभचिंतक रहा है। नेपाल के संकट से भी वह चिंतित है और यथाशीघ्र शांति की कामना कर रहा है।

डा. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़ (उप्र)

अराजक तत्वों ने स्थिति बिगाड़ी

अभी अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में युवाओं के विरोध से हुए तख्तापलट की तपिश ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि हिमालयन देश नेपाल की संसद से लेकर सड़क तक पर हिंसा, हंगामा, लूट, हत्या, आगजनी और जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। यह न केवल शर्मनाक है, अपितु नेपाली लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी भी है। प्रदर्शनकारियों ने एक-एक करके पूरे नेपाल को दावानल में झोंक दिया है। संसद, राष्ट्रपति भवन, कोषागार, बैंक और सरकारी मीडिया हाऊस को जला डाला। भ्रष्टाचार, महंगाई, भाई-भतीजावाद से आमजन त्रस्त हो चुके थे। हालांकि सरकार द्वारा इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध से जेनेरेशन जेड (जेन-जी) के भड़कने को तात्कालिक कारण बताया गया है। इसमें कुछ अराजक तत्व भी शामिल हो गए, इसी कारण पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाने जैसी बर्बर घटनाएं हुईं। वहां वित्त मंत्री को भी सरेराह पीटा गया और प्रधानमंत्री ओली को देश से भागना पड़ा। नेपाल में घोर अराजकता फैल गई है।

डा. हर्षवर्द्धन कुमार, पटना

राजशाही की ओर लौटता नेपाल

नेपाल में राजशाही समर्थकों का प्रभाव बढ़ा है। बालेंद्र शाह और सुदन गुरुंग जैसे नेताओं के समर्थन से आंदोलन उग्र हुआ है। अब यह माना जा रहा है कि नेपाल में राजशाही की वापसी हो सकती है। नेपाल सरकार की विदाई के बाद नेपाल की युवा शक्ति इसका जश्न मना रही है। आठ-नौ सितंबर को नेपाल में जो कुछ हुआ, उसकी बुनियाद मार्च 2025 में रखी गई थी। नौ मार्च को काठमांडू में राजशाही शासन के समर्थन में आंदोलन हुआ था, हजारों लोग इसमें शामिल हुए. इस आंदोलन को नेपाल का हैक्टिविज्म कहा गया, यानी सत्ता और सत्ता के केंद्रों को जनता के नियंत्रण में लेने के लिए सिस्टम को हैक करने वाला आंदोलन। आंदोलन को काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का समर्थन था। बालेंद्र शाह मैथिली मूल के मधेशी समुदाय से आते हैं। वह राजशाही और हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। सुदन गुरुंग ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। ये आंदोलन कुछ ऐसा था, जैसा कि नवंबर 2011 में अमेरिका में 'आक्यूपाई वाल स्ट्रीट' आंदोलन चला था। अमेरिका में सामाजिक असमानता और पूंजीवाद के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता जुटे थे और नेपाल में नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता ने आंदोलन शुरू किया। अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से संविधान और राजा ज्ञानेंद्र मिलकर नेपाल पर राज करेंगे।

विवेक रंजन, जहिंगरा, मोतिहारी

पोस्ट

नेपाल में सड़कों पर दिख रही अराजकता एक बड़ी चिंता का कारण है, लेकिन यहां कुछ लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि भारत में ऐसा कब होगा? सत्ता परिवर्तन का मार्ग असल में लोकतांत्रिक होना चाहिए। यही कारण है कि आजादी के बाद से हमारे यहां स्थिरता रही है, जबकि पड़ोसी देशों में उथलपुथल होती रही है।

मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल। अगर भारत इस प्रकार की प्रतिकूल स्थितियों से सुरक्षित रह पाया है तो उसमें हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती की बेहद अहम भूमिका रही। ऐसे में हमें और सतर्क रहना होगा कि ये संस्थान किसी भी तरह से कमजोर न पड़ें।

तवलीन सिंह@tavleen_singh

बैलेट पेपर से मतदान होने में बड़े नुकसान हैं। जैसे कि इसमें वोट निरस्त होने का डर रहता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में पंद्रह वोट निरस्त हो गए। जब सांसद ही ठीक से वोट नहीं डाल सकते तो आम लोगों का तो भगवान ही मालिक है।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जनपथ

इंटरनेट है बन गया खतरनाक हथियार,
बिना तोप-तलवार यह करता गहरी मार।
करता गहरी मार पलट सकता है सत्ता,
इसके बिन तो आज न हिलता कोई पत्ता।
बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी इससे होते सेट,
बिदके पूरा देश न पाए जो इंटरनेट!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 151

****

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, गुरुवार 11 सितम्बर 2025
संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

संविधान की ताकत का नया अहसास

नेपाल में सोमवार से शुरु हुए युवाओं के आंदोलन से सत्ता तो उखड़ ही गई है, समूची व्यवस्था भी तहस-नहस हो चुकी है। सेना ने कमान संभाल कर कर्फ्यू लगाया है, काठमांडू की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा कायम हुआ है, लेकिन इस सन्नाटे के उस पार क्या होगा, यह केवल उन्हीं लोगों को पता होगा, जिनकी शह पर पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है। फिलहाल प्रधानमंत्री और कम से कम 10 मंत्रियों के इस्तीफे तो हो ही चुके हैं, कुछ गिने-चुने प्रतिनिधि बचे हैं, जिन पर इस्तीफे का दबाव है। सरकार के अलावा मीडिया, कारोबार इन सब पर भी आंदोलनकारियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। मंगलवार को संसद भवन, राष्ट्रपति का घर, प्रधानमंत्री का घर समेत कई सरकारी संस्थानों पर आंदोलनकारियों ने आग लगा दी। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को भीड़ ने पीटा, पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी। इसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की मौत हो गई। नेपाल के सबसे बड़े मीडिया संस्थान कांतिपुर के दफ्तर को जलाया, हिल्टन होटल को जला दिया, जेल तोड़ी, जिसमें कई कैदी भाग गए। कई दुकानों में तोड़-फोड़ की और फ्रिज, एसी जैसे कीमती सामानों की लूट हुई। इतने उपद्रव के बाद सेना ने अपने हाथ में कमान ली है, तो फिलहाल तोड़-फोड़, लूटमार रुकी है। लेकिन आंदोलन अब भी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि प्रदर्शनकारी संविधान बदलने और नयी सरकार के गठन की मांग कर रहे हैं।

नेपाल बिल्कुल पड़ोस में है, तो वहां के हालात देश पर असर डालेंगे, ऐसी आशंका बनी हुई है। सोशल मीडिया पर हमेशा की तरह किसी भी घटना पर त्वरित फैसले सुनाने वाले अंदाज में लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। अपने-अपने राजनैतिक रुझान के मुताबिक कोई चेतावनी दे रहा है कि सरकार समझ जाए कि आम आदमी का गुस्सा जब फूटता है, तो कैसे उसके सब्र का बांध टूटता है, कोई सरकार की तारीफ कर रहा है कि हमारे पड़ोसी देशों में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे यहां हालात संभले हुए हैं। बात सही है कि भारत में हज़ार तरह की तकलीफें और सौ तरह की नाराजगियों के बावजूद ऐसी अराजकता के हालात नहीं बने हैं। लेकिन 2011-12 के दौर को याद करें, जब तत्कालीन सरकार के खिलाफ ऐसी ही नाराजगी की चिंगारी को भड़काने की पूरी कोशिशें हुई थीं। इंडिया अंगेस्ट करप्शन के बैनर तले लोकपाल की मांग पर जो अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ था, वह देश को अराजकता की तरफ ही उकसा रहा था। कभी रामदेव, कभी रविशंकर, कभी जग्गी वासुदेव जैसे आध्यात्म का कारोबार करने वाले लोग इस आंदोलन में अपने पूरक अध्याय जोड़ रहे थे। राष्ट्रपति भवन के सामने प्रदर्शन, इंडिया गेट पर प्रदर्शन, रामलीला मैदान में जलसे की तरह चलाया जा रहा आंदोलन सब सरकार को उकसा रहे थे कि वह कोई सख्त कार्रवाई करे और फिर सारी व्यवस्था को हाथ में लेने का मौका आंदोलनकारियों को मिले। लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने संयम दिखाया। बार-बार अनशन पर बैठे लोगों के बीच आकर वार्ताओं के दौर चलाए, ताकि जनता को समझ आ सके, कि जो भी फैसला होगा संविधान के दायरे में रहकर होगा। जो बात संविधान सम्मत नहीं होगी, उसे नहीं माना जाएगा, फिर चाहे सत्ता ही क्यों न चली जाए।

ऐसा ही हुआ भी। अन्ना हजारे के आंदोलन को मीडिया ने भरपूर कवरेज दिया, क्योंकि उसे भी सत्ता में परिवर्तन चाहिए था। किरण बेदी जैसे पूर्व पुलिस अधिकारी हाथ में तिरंगा लेकर अन्ना हजारे के मंच से ऐसे लहराते थे, मानो तिरंगे पर निर्वाचित सरकार का कोई हक है ही नहीं। बहरहाल, आंदोलन खत्म हुआ, इंडिया अंगेस्ट करप्शन कहां गया पता नहीं, लोकपाल का कानून बना, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, अन्ना हजारे अपने गांव पहुंच गए और अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ गए। किरण बेदी की राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं भी पूरी हुईं, कुमार विश्वास अब सेलिब्रिटी कवि, कथावाचक और राजनैतिक विश्लेषक बन चुके हैं, उनकी बेटी की तीज हो तो पूर्व केन्द्रीय मंत्री पधारती हैं। कहने का आशय यह कि हरेक को अपने-अपने हिस्से का लाभ मिल गया। भाजपा को तो खैर पूरी की पूरी सत्ता ही मिल गई। इस तरह अन्ना आंदोलन की कीमत यूपीए सरकार ने अपनी सत्ता खोकर चुका दी। जिन लोगों को सत्ता मिली है, उनका संविधान में अब कितना यकीन है या नहीं है, यह अलग सवाल है। लेकिन उस समय देश में जिस किस्म की अराजकता फैलाकर सत्तापलट की कोशिशें हुई थीं, कम से कम उनसे देश बच गया, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस थी।

अब केंद्र में भाजपा है, तो फिर से सरकार से नाराजगी के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहां भी संविधान ही देश को बचाते हुए दिख रहा है। इस बात पर अब भारत के मुख्य न्यायाधीश की मुहर भी लगी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति देने की शक्ति से संबंधित 14 प्रश्नों पर सुनवाई कर रही है। इसी दौरान मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने पड़ोसी मुल्कों के हालात का जिक्र किया और कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए कि हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। नेपाल में भी हम यही देख रहे हैं। चीफ जस्टिस गवई की इस टिप्पणी पर पांच जजों की संविधान पीठ के एक जज जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा- हां, बांग्लादेश में भी। माननीय न्यायाधीशों की इस टिप्पणी से देश को बनाने और संवारने में संविधान की भूमिका एक बार फिर रेखांकित हुई है। विचारणीय पहलू यह है कि इसी संविधान को बदलने की बात बार-बार सरकार और भाजपा की तरफ से आती है। हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में 130वें संविधान संशोधन विधेयक की वकालत करते हुए केरल में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि संविधान बदलना चाहिए। यानी 240 पर आकर भी भाजपा के इरादे नहीं बदले हैं। लेकिन कम से कम नेपाल के हालात देखकर ही हम सबक ले लें।

राहुल गांधी के नाम खुला खत

दुनियादारी

■ सर्वमित्रा सुरजन

प्रिय राहुल जी,
यह देखकर अच्छा लगा कि आप एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच गए हैं। सांसद यदि अपने निर्वाचन क्षेत्र में जितना अधिक वक्त बिताएंगे, उतने करीब से लोगों की समस्याओं और उम्मीदों को समझ पाएंगे। आप पांचवीं बार सांसद बने हैं, इसलिए बेहतर समझते हैं कि किसी उम्मीदवार को जब लाखों लोग वोट देकर संसद तक पहुंचाते हैं, तो वो महज वोट नहीं होते, उन लाखों लोगों के लिए बेहतर भविष्य की बंद पोटली होती है, जिसे खोलना या बंद रखना सांसद पर निर्भर करता है। और राहुल आप इस बार केवल सांसद नहीं हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आपने इस बार की लोकसभा में खुलकर कहा है कि विपक्ष जनता की आवाज़ उठाएगा। कहने की जरूरत नहीं कि इस काम को आप बखूबी कर रहे हैं। संसद में आपके तमाम भाषण जनआकांक्षाओं का ही दर्पण दिखा रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले आपने दो बार में पूरा भारत नाप लिया। उसके अलावा भी आपकी यात्राएं चलती रहती हैं। अभी बिहार में आपकी वोटर अधिकार यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इन यात्राओं में अलग-अलग तबकों के लोगों से आपकी अलग मुलाकात कराई जाती है। उनसे बातचीत के वीडियो आप के यू ट्यूब चैनल पर आते हैं। आठ-दस लोग बैठे हैं, आपको कभी राहुल, कभी भैया, कभी सर का संबोधन देकर खुलकर बात कर रहे हैं। बता रहे हैं कि मौजूदा राजनीति में कौन सी कमियां उन्हें खटक रही हैं, सरकार की नीतियां किस तरह उद्योगपतियों का पोषण कर रही हैं और गरीबों के हक मार रही हैं। वीडियो बनाने के बाद आपके साथ फोटो खिंचवाई जाती है, जिसे लोग अपने-अपने सोशल मीडिया एकाऊंट पर पोस्ट कर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी से वे कितना नजदीक हैं। अभी 7 सितंबर को ही भारत जोड़ो यात्रा की तीसरी सालगिरह पर कई लोगों ने आपके साथ चलते हुए बात करने की अपनी-अपनी तस्वीरें लगवाईं, कुछ लाइक्स और कमेंट हासिल किए। इन सबसे अपनी जान-पहचान के लोगों में तो उनका ओहदा या रुतबा थोड़ा और बढ़ गया, लेकिन बदले में कांग्रेस को क्या हासिल हुआ, क्या इसका विश्लेषण आपकी टीम ने कभी किया है। दर्जनों वीडियो राहुल गांधी यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं, मगर इनसे क्या कांग्रेस के सत्ता में आने के मौके मजबूत हुए हैं, इसकी पड़ताल भी होनी चाहिए।

आप खुद इस बात पर विचार करिए कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने में आपकी विराट भूमिका राहुल गांधी द यूट्यूबर की भूमिका में पेश करने वाले लोग क्या एक अलग किस्म का खेल कर रहे हैं। बेशक जनप्रतिनिधि को जनता के असली हाल मालूम होना चाहिए। लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जिन लोगों के साथ आपकी चर्चाएं करवाई जाती हैं, वे सारी बातें सच ही कहते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये बातें स्क्रिप्टेड हों और आपके सामने इसे अलग तरह से पेश किया जा रहा हो। और मान लें, जो कुछ बातें आप के सामने आती हैं, वे सच हों, तब भी केवल शिकायत सुनने या करने से हासिल क्या होगा। बदलाव तो तभी होगा, जब कांग्रेस या आज का इंडिया गठबंधन सत्ता में आए। इसके लिए आपकी टीम क्या काम कर रही है, ये भी आप ही को देखना होगा।

वोट चोरी का मसला हो, चुनाव में धांधली या किसी अन्य किस्म की अनियमितता, राहुल आप अक्सर ये कहते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि राहुल आप या आपके साथी सत्ता में कब और कैसे आएंगे। इसके लिए कौन सी तैयारी आप कर रहे हैं। तेलंगाना में आपकी जीत हुई, क्योंकि वहां रेवंत रेड्डी ने जमीनी स्तर पर काम किया। कर्नाटक में भी डी के शिवकुमार और सिद्धारमैया की मजबूत पकड़ के कारण ऐसा संभव हुआ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी हुई है, लेकिन वहां के अंतर्विरोध किसी से छिपे नहीं हैं। राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गोवा, सब कांग्रेस ने अपनी कमजोरियों से गंवाए। फिर भी अब तक घर के भेदियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया।

आप खुद इस बात पर विचार करिए कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने में आपकी विराट भूमिका राहुल गांधी द यूट्यूबर की भूमिका में पेश करने वाले लोग क्या एक अलग किस्म का खेल कर रहे हैं। बेशक जनप्रतिनिधि को जनता के असली हाल मालूम होना चाहिए। लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जिन लोगों के साथ आपकी चर्चाएं करवाई जाती हैं, वे सारी बातें सच ही कहते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये बातें स्क्रिप्टेड हों और आपके सामने इसे अलग तरह से पेश किया जा रहा हो।

अभी मंगलवार 9 सितंबर को सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उप-राष्ट्रपति चुन लिए गए। इसके साथ ही अब देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री समेत कई अहम पदों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े लोग काबिज हो चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संघ से निर्देशित संगठन राष्ट्रसेविका समिति से जुड़ी रही हैं। नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ओम बिड़ला, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेन्द्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर केबिनेट के सारे सदस्य संघ की पृष्ठभूमि से हैं। विष्णुदेव साय, मोहन चरण मांझी, भजन लाल शर्मा, पुष्कर धामी ये सारे मुख्यमंत्री संघ से जुड़े रहे हैं। राज्यपालों में भी ओम माथुर, राजेन्द्र अर्लेकर, शिवप्रताप शुक्ल इनका जुड़ाव संघ से रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह शताब्दी वर्ष है, एक वफादार संघ कार्यकर्ता होने के नाते नरेन्द्र मोदी इससे बेहतर तोहफा और क्या दे सकते थे। बस अब यही कसर बाकी रह गई है कि संविधान खत्म हो और भारत पूरी तरह हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जिस संगठन ने खुद को कभी राजनैतिक संगठन न कहकर हमेशा सांस्कृतिक संगठन कहा, उसके हाथ में देश की पूरी कमान हो, शासन-प्रशासन पर उसी का पूरा नियंत्रण हो, ऐसी मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। हिटलरकालीन जर्मनी में भी सत्ता और प्रशासन पर नाजीवादी लोग बिठा दिए गए थे, लेकिन हिटलर ने कभी अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को नहीं छिपाया, न ही फासिस्ट ताकतों ने खुद को जर्मनी की सियासत से अलग किया।

राहुल कृपया ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह उपलब्धि भले ही नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में हासिल हुई हो, लेकिन इसका सारा श्रेय अकेले श्री मोदी को नहीं दिया जा सकता। इसके लिए संघ के लोगों ने बीते सौ सालों से अथक परिश्रम तो किया ही, उनके परिश्रम को वांछित फल कांग्रेस समेत कई अन्य दलों के कारण मिला। आम आदमी पार्टी के तो कहने ही क्या, जिस अन्ना आंदोलन से यह पार्टी निकली और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, वह पूरा आंदोलन तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ही देन है। अब इसमें हैरानी भी नहीं होती कि यह आंदोलन यूपीए सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ और संघ के षड्यंत्र को समझते हुए भी इसे खाद-पानी देकर बढ़ाया गया।

दिवंगत डा. मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ थे, लेकिन सियासी दांव-पेंच उनकी विशेषज्ञता से परे थी। आपकी मां सोनिया गांधी इन चालों को बखूबी समझती हैं, क्योंकि पहले इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी की सोहबत में और उसके बाद खुद राजनीति में सक्रिय होने के बाद उन्होंने पहचानना सीख लिया कि कौन खुलकर संघ से जुड़ा है, किसने मुखौटा लगाकर संघ का साथ दिया है। लेकिन वे भी इन मुखौटों के पीछे के असली चेहरों को सामने नहीं ला पाईं। पर राहुल अभी समझ नहीं आ रहा है कि आपने ऐसे चेहरों को कितना पहचाना है। नेहरूजी की तरह आपने भी आरएसएस के लिए जरा सी मुरव्वत कभी नहीं दिखाई। शायद इसलिए भाजपा के लिए आप सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं। आप चाहे जितनी शालीनता, सौम्यता, नैतिकता के साथ राजनीति करें, भाजपा किसी भी हद तक गिरेगी, यह मानकर चलिए।

आपकी विदेश यात्राओं से लेकर हरेक बात पर जो खुफिया निगाहें पीछा करती रहती हैं, उन्हें अब हल्के में आपको नहीं लेना चाहिए। अभी रायबरेली के दौरे पर आपका काफिला रोकने की कोशिश हुई। श्री मोदी की स्वर्गीय मां के अपमान पर आपका विरोध हो रहा है। आप भी यह जानते हैं कि आपके विरोध और छवि खराब करने के लिए कोई न कोई बहाना तो भाजपा के पास हमेशा तैयार रहेगा। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा, इस पर भी विचार करना होगा। भाजपा का एक वार हो फिर कांग्रेस की तरफ से चंद लोग ट्वीट कर पलटवार करें, या बदले में मोदी-शाह पर सवाल उठाएं, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। असली बदलाव सत्ता हासिल करने से ही होगा। जिसमें फिलहाल आपकी मेहनत सौ प्रतिशत से ज्यादा है, लेकिन उस पर बार-बार पानी फेरा जा रहा है।

आपने आम अवाम की तकलीफों को सुना और समझा है। धान रोपकर, जूते सिलकर, सिर पर बोझा ढोकर देख भी लिया। लेकिन ये सब करके भी आप उनके हालात नहीं बदल सकते। जिस मेहनतकश के दर्द को आपने महसूस किया है, उसे दूर करने का एकमात्र उपाय ये है कि आप सत्ता में आएं और उनके लिए बेहतर नीतियां बनाएं। इसके लिए आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें करनी चाहिए। मीडिया मालिकों की सच्चाई आप जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस नेताओं के साथ उन पत्रकारों की सांठ-गांठ बनी हुई है, जिनके कारण यूपीए सत्ता से हटी, ऐसे लोगों की पड़ताल कीजिए। हो सके तो वैकल्पिक मीडिया तैयार करने का काम करें। यह ठीक है कि चंद उद्योगपतियों से सरकार को लाभ मिल रहा है, लेकिन इस वजह से सारे उद्योगपतियों से आप दूरी नहीं बना सकते। सत्ता की राजनीति का तकाजा है कि उसे कारोबारियों को अपने साथ रखना होता है। ये काम गांधीजी ने भी किया और नेहरूजी ने भी। आप इस बारे में अपनी झिझक छोड़ेंगे और उद्योगपतियों से भी चर्चाएं करेंगे तो उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे।

अंत में फिर से यही कहूंगी कि आप को सत्ता का मोह नहीं है, यह सब जानते हैं। लेकिन जिन करोड़ों लोगों में आपने बेहतर कल की उम्मीद जगाई है, जिन लोगों ने भाजपा को 240 पर ही रोक दिया क्योंकि उन्हें संविधान बचाना है, उन सबकी आस आप पर ही टिकी है, जिसे पूरा करने के लिए इंडिया गठबंधन का सत्ता में आना जरूरी है। अगला कोई वीडियो बनाने या किसी समूह से बात करने में बस इस बात को ध्यान में रखिएगा।

ब्रिक्स वर्चुअल बैठक और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित न करना अशुभ संकेत

■ नित्य चक्रवर्ती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 सितंबर को जारी एससीओ घोषणापत्र और इस साल 6 जुलाई के ब्रिक्स वक्तव्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत-अमेरिका संबंधों में पारस्परिकता बहाल करने का कोई संकेत दे रहे हैं? यह सवाल बेहद प्रासंगिक है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर को आयोजित वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल न होने और इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी शामिल न होने का फ़ैसला किया।

ट्रंप के टैरिफ़ युद्ध और प्रभावित देशों, ख़ासकर वैश्विक दक्षिण के देशों द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा एकतरफ़ा टैरिफ़ लगाए जाने के ख़िलाफ़ साझा रुख़ अपनाने के मौजूदा संदर्भ में ये दोनों घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। ब्रिक्स के दो प्रमुख सदस्य - भारत और ब्राज़ील, अमेरिका को अपने-अपने निर्यात पर 50 प्रतिशत की दर से ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। 2025 के लिए ब्रिक्स के अध्यक्ष ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स घोषणापत्र के अनुवर्ती के रूप में 8 सितंबर को यह बैठक बुलाई थी, जिस पर भारतीय प्रधानमंत्री और अन्य सभी ब्रिक्स सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे।

इस वर्चुअल बैठक में भारत और इथियोपिया को छोड़कर सभी राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। चीन के राष्ट्रपति शीजिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कार्ययोजना सुझाने में अहम भूमिका निभाई। भारत का प्रतिनिधित्व हमारे विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने किया, जिन पर अन्य राष्ट्राध्यक्षों के भाग लेने के दौरान किसी ने ध्यान नहीं दिया। डॉ. जयशंकर ने हमेशा की तरह वैश्विक चुनौतियों पर एक अकादमिक व्याख्यान दिया, जिसमें अमेरिकी निर्णय के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता पर शायद ही कोई बात की गई। उन्होंने केवल व्यापार उपायों को गैर-व्यापार बाधाओं से जोड़ने पर चिंता व्यक्त की। इस व्याख्यान में अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया कदमों पर प्रहार किया गया, लेकिन यह वैश्विक व्यापार मुद्दों पर व्याख्यान के शब्दाडंबर में डूब गया, और तत्काल उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं किया गया।

जयशंकर ने कहा, 'व्यापार पैटर्न और बाज़ार पहुंच आज वैश्विक आर्थिक विमर्श में प्रमुख मुद्दे हैं। दुनिया को टिकाऊ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बढ़ती बाधाएं और लेन-देन को जटिल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा।' यह सामान्य वैश्विक व्यापार परिदृश्य के लिए एक अच्छा संबोधन है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यों के परिणामस्वरूप 2025 की वर्तमान स्थिति सामान्य नहीं है। इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए? डॉ. जयशंकर के भाषण में तात्कालिक मुद्दों से निपटने के लिए कोई ठोस सुझाव नहीं दिया गया।

बल्कि उन्होंने ब्रिक्स के भीतर की समस्या पर बात की। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रवाह की समीक्षा करके एक मिसाल कायम कर सकता है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि हमारे कुछ सबसे बड़े घाटे ब्रिक्स भागीदारों के साथ हैं और हम शीघ्र समाधान के लिए दबाव बना रहे हैं। इस समय इस वर्चुअल ब्रिक्स बैठक में इस मुद्दे को टाला जा सकता था। यह बैठक टैरिफ पर अमेरिकी उपायों का सामना करने और राजनीतिक मुद्दों को व्यापार मामलों से जोड़ने के लिए तत्काल रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई थी। भाषण में भारत का मुख्य ध्यान इसी पर होना चाहिए था, जो नहीं था।

चीनी राष्ट्रपति ने अमेरिकी कार्रवाई को टैरिफ युद्ध करार दिया, जबकि ब्राज़ील के राष्ट्रपति और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति दोनों ने टैरिफ ब्लैकमेल से निपटने के लिए संयुक्त कार्रवाई का सुझाव दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने भी ट्रम्प का नाम लिए बिना कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। वर्चुअल बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति पर अन्य ब्रिक्स सदस्यों, विशेष रूप से ब्राज़ील ने ध्यान दिया क्योंकि राष्ट्रपति लूला अगले साल नरेंद्र मोदी को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपेंगे और भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नरेंद्र मोदी के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल न होने से ब्रिक्स सदस्यों के बीच कुछ आशंकाएं पैदा हो गई हैं क्योंकि उन्होंने 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में पिछले एससीओ शिखर सम्मेलन और 6 और 7 जुलाई को रियो डीजनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया था।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबंध में, संयुक्त राष्ट्र सत्र 23 सितंबर से शुरू होगा और 30 सितंबर तक चलेगा। भारतीय प्रधानमंत्री को 26 सितंबर को संबोधित करने का समय दिया गया था। उसी दिन, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को महासभा को संबोधित करने के लिए समय दिया गया है। ऐसे नाजुक दौर में, संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष देश और दुनिया के सामने मौजूद प्रमुख मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सभा को संबोधित करेंगे। यह पूरी तरह तय है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार डॉ. मुहम्मद यूनुस भी इसमें शामिल होंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबंध में, संयुक्त राष्ट्र सत्र 23 सितंबर से शुरू होगा और 30 सितंबर तक चलेगा। भारतीय प्रधानमंत्री को 26 सितंबर को संबोधित करने का समय दिया गया था। उसी दिन, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को महासभा को संबोधित करने के लिए समय दिया गया है। ऐसे नाजुक दौर में, संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष देश और दुनिया के सामने मौजूद प्रमुख मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए करते हैं।

पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही प्रमुख मुद्दों पर अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। पाकिस्तान भारत के साथ मुद्दों का ज़िक्र ज़रूर करेगा। डॉ. जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन उन्हें सत्र के अंत में बोलने का मौका मिलेगा और कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार, दोनों ही नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति का पूरा फायदा उठाकर भारत के बारे में अपना एकतरफा बयान देंगे। इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होते, तो 26 सितंबर को सभा को संबोधित करने वाले वे पहले व्यक्ति होते। मूल सभा कार्यक्रम के अनुसार, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अन्य सभी राष्ट्राध्यक्षों को उनके बाद स्थान दिया गया है।

लेकिन नरेंद्र मोदी के इस बेहद महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में शामिल न होने के असली कारण क्या हैं? एक कारण यह हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने से बचना चाहें, जो पहले दिन से ही सत्र में मौजूद रहेंगे। अगर अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों पर विश्वास किया जाए, तो प्रधानमंत्री ट्रंप के फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। यह कूटनीति चलाने का कोई तरीका नहीं है। अगर ट्रंप बात करना चाहते हैं, तो आप उनसे बात करें और भारत की स्थिति स्पष्ट रूप से बताएं। लुका-छिपी की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत एक विशाल देश है, जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और साथ ही यह पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। प्रधानमंत्री में ट्रंप को यह बताने का साहस होना चाहिए कि भारत अपनी नीतियों के बारे में क्या सोचता है। बैठकें होती हैं और असहमति में समाप्त हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों और दुश्मनों, दोनों के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए। शायद नरेंद्र मोदी इस पुरानी कहावत को भूल गए हैं।

ललित सुरजन की कलम से

अन्ना, बाबा, भाजपा और सरकार

'यह निर्विवाद सत्य है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार विकराल रूप से व्याप्त है। इस पर विजय पाने के लिए सुतार्किक एवं समयबद्ध योजना बनाने की आवश्यकता है, जबकि अभी जैसी हायतौबा मचाई जा रही है उसमें भ्रष्टाचार को महज एक भावनात्मक मुद्दे के रूप में उभारा जा रहा है। जो इसे उछाल रहे हैं, वे स्वयं भी शायद नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार दूर हो। हम अपने पाठकों को एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं कि देश में इस मसले पर पहले भी दो बड़े भावनात्मक आन्दोलन हुए हैं। पहला- 1973-74 में गुजरात के 'नवनिर्माण आंदोलन' के रूप में जिसकी परिणिति जयप्रकाश नारायण की 'संपूर्ण क्रांति' में हुई और दूसरा- बोफोर्स के खिलाफ विश्वनाथ प्रताप सिंह का जनमोर्चा जिसका प्रसाद उन्हें प्रधानमंत्री पद के रूप में मिला।'

'उपरोक्त दोनों आन्दोलनों के बारे में देखना कठिन नहीं है कि भ्रष्टाचार को भावनात्मक मुद्दे के रूप में खूब उछाला गया, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। भ्रष्टाचार नहीं मिटना था सो नहीं मिटा, क्योंकि आन्दोलन करने वालों के इरादे ही नेक नहीं थे। उनका मकसद येन-केन-प्रकारेण राजनैतिक सत्ता हासिल करने का था, जिसके लिए जनता को प्यादों की तरह इस्तेमाल किया गया।'

(9 जून 2011 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2012/04/10_23.html

पावन प्रसंग

मन की शांति

मन की शांति का सबसे बड़ा उपाय मन की त्यागमूलक वृत्ति को उजागर करना है। सबसे पहले मन को त्याग भाव में रखा जाए, उसे बाह्यजगत् से पड़ने वाली अड़चन से बचा, एकटक अंतर्हृदय में केंद्रित रखा जाए। मन की अभिलाषा होती है बाहर घूमने जाऊँ, अत: उसे बांधकर जिम्मेदारीपूर्वक अपने वश में किया जाए। इसके बाद मन को दिशाहीन न होने देने के लिए, उसे सदा सार्थक एवं उपयोगी कार्य में लगाया जाए। इस प्रकार हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारा मन निरंतर उद्वेगरहित होकर शांति की दिशा में बढ़ चलता है।

मन है एक विशाल सरोवर, जिसका स्त्रोत है मनुष्य की वृत्तियां। यदि वृत्तियों को रोककर उन्हें किसी आदर्श की दिशा में लगाया जाए, उनसे लाभलेकर मन की गति एवं स्वरूप को निर्धारित किया जाए तो देखते-ही-देखते संकल्पपूर्वक मन को नियंत्रित करना एवं आत्मिक शांति को प्राप्त करना सहज हो जाता है। मन अशांत है तो इसका एक ही कारण है, मन का अज्ञान और उसका किसी प्रकार अपनी शक्ति के स्त्रोत से वंचित हो जाना।

मन की अंतरंग वृत्ति को जिस दिन मनुष्य समझना सीख जाएगा, उस दिन उसे अपने प्रत्येक प्रयोजन में सफलता प्राप्त होगी एवं वह निस्पृह हुआ अपने केंद्रीय लक्ष्य की दिशा में बढ़ चलेगा। प्रकाश का सूर्य ही उसकी शांति, सद्गति एवं प्रेरणा का कारण है और यह प्रकाश और कुछ नहीं, मन का आत्मा से सम्मिलन है।

इसके उपरांत उसे सत्य से विमुख होने का कोई कारण नहीं रह जाता एवं वह विचारदर्शी बन, समग्रता में सत्य का बोध प्राप्त करता है तथा उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई अपनी भीतरी दिव्यता को उजागर करने में नहीं होती तथा वह निस्पृह एकाकी हो, अपने को हर दृष्टि से उन्नत एवं समर्थ बनाता जाता है।

मन की तरंग को अपने वश में कर लेना ही शांति का उपाय है तथा जिस मन में अपने निग्रह की क्षमता आ गई है, वह फिर दु:ख-द्वंद्वों में पड़ कर अपनी क्षमताओं से विमुख नहीं होता है। मन पर पड़ने वाले कुप्रभावों को जिस दिन हम सद्विचारों से समाप्त करना सीख जाएंगे तथा सुविचार अंतरात्मा की गहन प्रेरणा से क्रियाशील होंगे, तभी हमें ।वास्तविकता का पथ एवं सत्य-विषय के शोध का ।पथ दिखाई पड़ेगा।

जब मन किसी विषयवस्तु से जा टकराता है, तब वह अपने मूल प्रयोजन को ही भुला बैठता है। है एवं उसे अंतर्मन की गहराई से आ रही सत्य की आवाज र सुनाई नहीं देती एवं तब वह एक उपकरण न रहकर केंद्रीय उपादान बन बैठता है। यही मन की दुर्बलता एवं उसे किसी भी सत्संकल्प में न लगा पाने का कारण है। जब मन अपने सभी दोषों को त्याग देता है तो उसे वास्तव में सत्य-विषय के अनुसंधान का अवसर प्राप्त होता है एवं तब वह शांति के केंद्र, आत्मा की अमिट प्यास की ओर झुक पड़ता है।

-अखण्ड ज्योति

आपके पत्र

नेपाल के हालात और भारत में राधाकृष्णन की जीत के मायने!

ऐसा लग रहा है 9 सितम्बर 2025 का दिन नेपाल में लोकतांत्रिक शासन के ख़ात्मा का दिन साबित हुआ है। यदि युवा आंदोलन कारियों की नज़र से इस दिन का मूल्यांकन किया जाए तो इसकी वजह मंहगाई और भ्रष्टाचार को बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि लोकतंत्र की छत्रछाया में ये नेता अधिनायकवाद की ओर बढ़ चले थे। जबकि जनता ने सामंतवादी सरकार के लिए जिम्मेदार राजतंत्र को उखाड़ फेंका था। हालांकि नेपाल को राजतंत्र की ओर पुन: धकेलने की कोशिश में कई हिंदुवादी संगठन लगे हुए थे जिनके तार बताया जा रहा है कि भारत की हिंदुत्ववाली ताकतों से जुड़े थे। यह इसलिए भी सच लगने लगा था क्योंकि जब नेपाल जैसा एकलौता हिंदुराष्ट्र ,लोकतांत्रिक देश बना तब सबसे ज्यादा चोटिल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाली शक्तियां ही हुई थीं।

लेकिन उनके इस गुपचुप आंदोलन की जो सफलता दिख रही है उसे धार दिया एक युवा ने जिसका नाम सुडान गुरुंग या सुदन गुरुंग! 24 वर्षीय सुदन गौरांग जिसे नेपाल का ''Gen Z क्रांतिकारी'' कहा जा रहा है! यह ना ही कोई राजनीति को एकमात्र सत्ता से सरकार को हटाना ही हो गया था। जिसमें वे सफ़ल भी रहे। जिससे हिंदुत्व वादियों की पौ-बारह हो गई है। आश्चर्यजनक इसलिए और भी है कि लोकतांत्रिक देश में सरकार को सम्मान जनक तरीके से चुने हुए सांसद हटा सकते थे। अब देखना यह है कि इन उपद्रवकारी ताकतों को एकजुट करने वालों की असलियत सामने आती है या नहीं क्योंकि वे अपने मकसद में सफल हो गए हैं।

दूर दृष्टि डालें तो भारत को छोड़कर सारे हमारे तमाम पड़ोसी देशों में जन आक्रोश लगभग इन्हीं कारणों से उपजा है वहां सत्ता परिवर्तन इसी तरह की अराजकता के माध्यम से हुआ है। श्रीलंका, बांग्लादेश ने यह हिंसक राह दिखाई है। नेपाल इस तरह का तीसरा देश है। इंडोनेशिया और पाकिस्तान में भी अंदर अंदर ज्वार उठता दिखाई दे रहा है।

इन घटनाओं को देखते हुए भारत को सावधान रहने की ज़रूरत है। यहां युवा उत्तेजित ज़रुर है किंतु वे संवैधानिक रास्ते से बदलाव के पक्षधर हैं। मगर यदि लोकतांत्रिक चुनावों में वोट चोरी का अध्याय बंद नहीं होता है तो भारत में ऐसे अराजक तत्वों को रोका जाना मुश्किल होगा।

बहरहाल लोकतंत्र का नेपाल में खात्मा होना चिंता का विषय है। इसी दिन भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी था। जीत तो सत्तारूढ़ पार्टी की तय थी किन्तु इंडिया गठबंधन ने जिस एका का परिचय दिया तथा निर्दलीय साथ में आए। वह इस बात का द्योतक है कि सत्तारूढ़ पार्टी की ज़मीन दरकी हुई है। इसे इस तरह समझा जा सकता है उप राष्ट्रपति चुनाव सन् 2022में एनडीए को 528 और इंडिया गठबन्धन को 182 वोट मिले थे। 2025 के चुनाव में अब एनडीए को 452 और इंडिया गठबन्धन को इस वर्ष 300 वोट मिले हैं यदि 15 रिजेक्ट वोट मिल जाती तो स्थिति और मज़बूत होती। लेकिन दो सालों में आया यह परिवर्तन मायनेखेज है और सत्तारूढ़ दल की हार को दर्शाता है। चूंकि यह चुनाव सांसदों के आंकड़े पर निर्भर था इसलिए जीत होनी ही थी। किंतु विपक्ष की बढ़त सरकार के लिए भी खतरे का इशारा कर रही है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में जनता कैसा जनादेश देती है वह महत्वपूर्ण होगा।

कुल मिलाकर दोनों देशों में लोकतंत्र को किनारे कर हिंदुराष्ट्र की ओर धकेलने की कवायद जारी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में मिले मतों से विपक्ष की हैसियत में इज़ाफ़ा हुआ है उससे लगता है आने वाले समय में भारत प्रजातंत्र की रक्षा में समर्थ होगा।

नेपाल के लोगों को भी इस बदलाव को गंभीरता से लेना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा कर ही जन जन की रक्षा संभव होती है। **-सुसंस्कृति परिहार**

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

चिंतन

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद रक्षा क्षेत्र का सिरमौर बनता भारत

वो भी समय था, जब भारत अपनी रक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से रूस व अन्य देशों पर निर्भर था। यहां तक कि गोला बारूद तक के लिए विदेशी रक्षा उपकरण निर्माताओं की तरफ झोली फैलानी पड़ती थी। इतना ही नहीं, भारी भरकम रकम देने के बाद भी रक्षा उपकरण देने में भी लगातार देरी सहन करनी पड़ती थी। अब हालात बदलने लगे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम सौ फीसदी आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन हालात वो भी नहीं रहे, जो दो दशक पहले तक थे। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति जैसे बड़े रणनीतिक फैसलों के कारण घरेलू रक्षा उत्पादनों को बहुत हद तक प्रोत्साहन मिला है। रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी भी अपेक्षाकृत बढ़ी है और सार्वजनिक उपक्रमों की उत्पादन क्षमता में खासा सुधार आया है। इसमें एमएसएमई ने भी योगदान दिया। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि इस कारण 2013-14 में जहां 686 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 23,622 करोड़ रुपये हो चुका है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में रक्षा निर्यात में भी 12 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। साफ नजर आता है कि देश रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में तेज से उभर रहा है। इसी कारण वैश्विक मंचों पर भी भारत की छवि मजबूत होती जा रही है। हाल में लोवी इंस्टीट्यूट पावर इंडेक्स की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि रक्षा क्षेत्र में भारत दुनिया के सिरमौर देशों की कतार में खड़ा होने की तैयारी में है। देश आधुनिक हथियारों और तकनीक के मामले में तेजी से तरक्की कर रहा है, इस तथ्य की पुष्टि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हुई, जब ब्रह्मोस मिसाइलों और ड्रोन रोधी स्वदेशी प्रणाली आकाशतीर ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अब तक हमें आमतौर पर यही लगता था कि ऑपरेशन सिंदूर ने सैन्य क्षेत्र में भारत की नई और उभरती ताकत से पूरी दुनिया का परिचय करवाया है। जिस तरह से सिर्फ चार दिनों के भीतर भारतीय सशस्त्र सेना ने पाकिस्तान का गेम ओवर किया, उससे खुद को सुपर पावर कहने वाले देश भी हक्के-बक्के रह गए। लेकिन, अब ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ हमारी सैन्य ताकत को ही बयां नहीं किया, रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी भारत के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। भारत आज अमेरिका, रूस, फ्रांस समेत 100 से ज्यादा देशों को सैन्य हथियार और रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। भारत के जिन हथियारों की अंतरराष्ट्रीय सैन्य बाजार में ज्यादा डिमांड है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने रूस के साथ मिलकर बनाया है। फिलीपींस इसका पहले से खरीदार था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में शानदार प्रदर्शन की वजह से करीब 15 देश इसे खरीदने के लिए लालायित हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भारत के रक्षा उपकरण न केवल सटीक हैं बल्कि गुणवत्ता पर भी खरे उतरते हैं। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो खलता है। इस प्रगति के बावजूद रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता को घटाना अभी भी चुनौती बना हुआ है। इन प्रयासों को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में मेहनत करनी होगी और निवेश भी बढ़ाना होगा। छोटे और मध्यम उद्यमों को रक्षा उत्पादन में और अवसर देने होंगे। साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार की प्रतिस्पर्धा का भी ध्यान रखना होगा। यह तभी संभव है जब हम रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे और सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर साझेदारी, नए बाजारों की खोज और रक्षा स्टार्टअपों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना होगा।

जन्म दिवस पर विशेष

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

समता व बंधुत्व को समर्पित जीवन

संघ का हर कार्यकर्ता वैभव संपन्न भारत माता का सपना साकार होते देखना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए जिस स्पष्ट विज़न और ठोस एक्शन की जरूरत होती है, डॉ. मोहन भागवत इन दोनों गुणों से परिपूर्ण हैं। उनके स्वभाव की एक और बड़ी विशेषता ये है कि वे मृदुभाषी हैं। उनमें सुनने की भी अद्भुत क्षमता है। यह विशेषता न केवल उनके दृष्टिकोण को गहराई देती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व में संवेदनशीलता और गरिमा भी लाती है। डॉ. भागवत हमेशा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के प्रबल पक्षधर रहे हैं। वैसे बहुत कम लोगों को ये पता है कि डॉ.भागवत अपनी व्यस्तता के बीच संगीत और गायन में भी रुचि रखते हैं। वे विभिन्न भारतीय वाद्ययंत्रों में भी निपुण हैं।

आज 11 सितंबर है। यह दिन अलग-अलग स्मृतियों से जुड़ा है। एक स्मृति 1893 की है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व बंधुत्व का संदेश दिया और दूसरी स्मृति है 9/11 का आतंकी हमला, जब विश्व बंधुत्व को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। आज के दिन की एक और विशेष बात है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्म दिवस है जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। संघ परिवार में जिन्हें परम पूजनीय सरसंघचालक के रूप में श्रद्धाभाव से संबोधित किया जाता है, ऐसे डॉ. मोहन भागवत का आज जन्मदिन है। यह एक सुखद संयोग है कि इसी साल संघ भी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। मैं डॉ. भागवत को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें।

मेरा डॉ. मोहन भागवत के परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। मुझे उनके पिता, स्वर्गीय मधुकर राव भागवत के साथ निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। मैंने अपनी पुस्तक 'ज्योति पुंज' में मधुकर राव के बारे में विस्तार से लिखा भी है। वकालत के साथ-साथ मधुकर राव जीवनभर राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित रहे। अपनी युवावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ कार्य की मजबूत नींव रखी। मधुकर राव का राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि अपने पुत्र मोहन राव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे। एक पारसमणि मधुकर राव ने मोहन राव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी।

डॉ. भागवत का पूरा जीवन सतत प्रेरणा देने वाला रहा है। वे 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। गत 100 वर्षों में देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक-युवतियों ने अपना घर-परिवार त्याग करके पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। डॉ.भागवत ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उस दौर में प्रचारक के रूप में भागवत ने आपातकाल-विरोधी आंदोलन को निरंतर मजबूती दी। उन्होंने कई वर्षों तक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों, विशेषकर विदर्भ में काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में डॉ. मोहन भागवत के कार्यों को आज भी कई स्वयंसेवक स्नेह पूर्वक याद करते हैं। इसी कालखंड में डॉ.भागवत ने बिहार के गांवों में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने के कार्य में समर्पित रहे।

सरसंघचालक होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है। यह एक पवित्र विश्वास है, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी दूरदर्शी व्यक्तित्वों ने आगे बढ़ाया है और इस राष्ट्र के नैतिक और सांस्कृतिक पथ को दिशा दी है। असाधारण व्यक्तियों ने इस भूमिका को व्यक्तिगत त्याग, उद्देश्य की स्पष्टता और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण के साथ निभाया है। यह गर्व की बात है कि डॉ. मोहन

भागवत ने न केवल इस विशाल जिम्मेदारी के साथ पूर्ण न्याय किया है, बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति, बौद्धिक गहराई और सहृदय नेतृत्व भी जोड़ा है। डॉ. भागवत का युवाओं से सहज जुड़ाव है और इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ कार्य के लिए प्रेरित किया है। वे लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं, और संवाद करते रहते हैं।

श्रेष्ठ कार्य पद्धति को अपनाने की इच्छा और बदलते समय के प्रति खुला मन रखना, ये डॉ.मोहन की बहुत बड़ी विशेषता रही है। अगर हम व्यापक संदर्भ में देखते हैं तो संघ की 100 साल की यात्रा में डॉ.भागवत का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। चाहे वो गणवेश परिवर्तन हो, संघ शिक्षा वर्गों में बदलाव हो, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके निर्देशन में संपन्न हुए।

कोरोना काल में डॉ. मोहन भागवत के प्रयास विशेष रूप से याद आते हैं। उस कठिन समय में उन्होंने स्वयंसेवकों को सुरक्षित रहते हुए समाजसेवा करने की दिशा दी और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने पर बल दिया। उनके मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने जरूरतमंदों तक हरसंभव सहायता पहुंचाई, जगह-जगह मेडिकल कैंप लगाए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों और वैश्विक विचार को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्थाओं को विकसित किया। हमें कई स्वयंसेवकों को खोना भी पड़ा, लेकिन डॉ.भागवत की प्रेरणा ऐसी थी कि अन्य स्वयंसेवकों की दृढ़ इच्छाशक्ति कमजोर नहीं पड़ी।

इस वर्ष की शुरुआत में, मैंने नागपुर में उनके साथ माधव नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के दौरान कहा था कि संघ अक्षयवट की तरह है, जो राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है। इस अक्षयवट वृक्ष की जड़ें इसके मूल्यों की वजह से बहुत गहरी और मजबूत हैं। समाज कल्याण के लिए संघ की शक्ति के निरंतर उपयोग पर डॉ. मोहन भागवत का विशेष बल रहा है। इसके लिए उन्होंने पंच परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें स्व-बोध, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण के सूत्रों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। देश और समाज के लिए सोचने वाले हर भारतवासी को पंच परिवर्तन के इन सूत्रों से अवश्य प्रेरणा मिलेगी। पिछले दिनों देश में जितने सफल जन-आंदोलन हुए चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डॉ. मोहन भागवत ने पूरे संघ परिवार को इन आंदोलनों में ऊर्जा भरने के लिए प्रेरित किया। मैं पर्यावरण से जुड़े प्रयासों और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को जानता हूं।

डॉ. भागवत का बहुत जोर आत्मनिर्भर भारत पर भी है। कुछ ही दिनों में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो जाएगा। यह भी सुखद संयोग है कि विजयादशमी का पर्व, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और संघ का शताब्दी वर्ष एक ही दिन आ रहे हैं। यह भारत और विश्वभर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास डॉ. मोहन भागवत जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघचालक हैं, जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। एक युवा स्वयंसेवक से लेकर सरसंघचालक तक की उनकी जीवन यात्रा उनकी निष्ठा और वैचारिक दृढ़ता को दर्शाती है। विचार के प्रति पूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन करते हुए उनके नेतृत्व में संघ कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है। मैं मां भारती की सेवा में समर्पित डॉ. मोहन भागवत के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की पुनः कामना करता हूं। उन्हें जन्मदिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं।

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

दिवस विशेष

डॉ. योगिता राघव

विवेकानंद के शिकागो भाषण को अपने जीवन में उतारें

शिकागो में 11 सितम्बर 1893 के ऐतिहासिक दिन विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपने अविस्मरणीय, अविश्वसनीय, अद्वितीय व ऐतिहासिक भाषण से न केवल भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर स्थापित किया, बल्कि पूरी दुनिया को सहिष्णुता, सार्वभौमिकता और मानवता का अमूल्य संदेश दिया और भारत के युवाओं में एक नई चेतना और आत्मविश्वास का संचार भी किया। "मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों" कहकर जैसे ही उन्होंने अपना संबोधन प्रारंभ किया, सभागार गगनभेदी तालियों से गूंज उठा। यह भाषण केवल शब्दों का संगम नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता, भाईचारे और विश्व बंधुत्व का उद्घोष था। आज, 132 वर्ष बाद भी यह उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायी है। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कहा कि भारत केवल सहिष्णुता का ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करने का देश है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत ने सदैव सताए गए और शरणार्थी समुदायों, चाहे वे यहूदी हों या पारसी, को खुले हृदय से अपनाया है। यह विचार आज की दुनिया के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जहां कट्टरता और संकीर्णता के बीच शांति और सद्भाव का मार्ग खोजा जा रहा है। विवेकानंद ने अपने भाषण में कट्टरता और हठधर्मिता को मानव समाज का सबसे बड़ा शत्रु बताया। उन्होंने कहा कि इनसे धरती बार-बार खून से लाल हुई है और सभ्यताएं मिट गई हैं। अब समय आ गया है जब मानवता को ऐसे दानवों से मुक्त होकर भाईचारे और एकता की ओर बढ़ना होगा। विश्व धर्म सम्मेलन दुनिया को यदि कुछ दिखा सकता है तो वह होगा, धर्मों की पवित्रता, शुद्धता और पुण्यता, क्योंकि धर्मों से ही इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। यदि धार्मिक एकता के समय भी कोई यह सोचता है कि उसी के धर्म का विस्तार हो और दूसरे धर्मों का विनाश हो तो ऐसे लोगों के लिए मुझे दिल से लज्जा महसूस होती है। स्वामी विवेकानंद

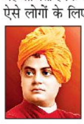

केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, बल्कि युवाओं के मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने भारत के युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। उनका प्रसिद्ध मंत्रः "उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।" आज भी हर युवा के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। उनका विश्वास था कि आत्मविश्वास और साहस के बल पर युवा न केवल अपना भविष्य गढ़ सकते हैं, बल्कि राष्ट्र को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। विवेकानंद का संदेश केवल धार्मिक एकता का आह्वान नहीं था, बल्कि यह युवाओं के लिए भी दिशा-निर्देश था। उन्होंने युवाओं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनने तथा जाति-धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। वह चाहते थे कि युवा भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ आएं। आज का युवा डिजिटल युग में अवसरों के साथ-साथ बेरोजगारी, तनाव और पहचान के संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में विवेकानंद का शिकागो भाषण युवाओं को आत्मबल देता है और याद दिलाता है कि वे उस महान संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं, जिसने दुनिया को शांति, सहिष्णुता और मानवता का पाठ पढ़ाया है। उनके विचारों का अनुसरण करके, युवा न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों को आज भी कई संगठन ज़मीनी स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) जैसे छात्र संगठन विवेकानंद के इन्हीं विचारों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। एबीवीपी का मूल मंत्र, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, सीधे विवेकानंद के उस दर्शन से जुड़ा है जिसमें उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा उपकरण माना था। एबीवीपी युवाओं को समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण की दिशा में प्रेरित कर रहा है। स्वामी विवेकानंद ने जो विचार दिए, एबीवीपी उन्हें एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रही है। विवेकानंद ने युवाओं को जो सपना दिखाया था, एबीवीपी के कार्यकर्ता उसे साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि शाश्वत संदेश है जो हर पीढ़ी के भारतीय युवाओं को प्रेरित करता रहेगा। आज उनके शिकागो भाषण की वर्षगांठ पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि उनके विचारों को केवल पढ़ा ही न जाए, बल्कि जीवन में उतारा भी जाए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

(लेखिका अभाविप गुरुग्राम की महानगर अध्यक्ष हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मृत्यु के उपरांत ही समाप्त होती है यात्रा

संकलित
दर्शन

शरीर में समाहित ऊर्जापुंज को आत्मा कहा गया है। यह आत्मा अनंत ऊर्जा अर्थात परमात्मा का एक अति सूक्ष्म अंशमात्र है। भौतिक जगत में रहते हुए यह भौतिक शरीर एक यात्री के सदृश होता है। शरीर के जन्म के साथ ही यात्रा प्रारंभ होती है एवं मृत्यु के उपरांत समाप्त हो जाती है। अर्थात भौतिक शरीर के लिए जीवन एक यात्रा के समतुल्य है। जन्म के साथ ही ऊर्जापुंज अर्थात आत्मा भौतिक शरीर से संयुक्त होकर उसकी यात्रा में सहयात्री की भूमिका का निर्वहन करने लगता है एवं मरणोपरांत स्वयं को यात्रा से अलग कर लेता है। यह कहा जा सकता है कि भौतिक शरीर की यात्रा का आदि और अंत स्पष्टतः ज्ञात होता है, परंतु ऊर्जापुंज जिसे आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है, अपनी यात्रा के आदि और अंत से सर्वथा अपरिचित होता है। आत्मा की यात्रा कब और क्यों प्रारंभ हुई तथा कब और क्यों पूर्ण होगी? इन प्रश्नों का हल आज भी एक चुनौती के रूप में खड़ा है। ऊर्जापुंज अगणित भौतिक शरीरों की भौतिक यात्रा में सहयात्री की भूमिका को निभाता हुआ अपनी अनंत दिव्ययात्रा को जारी रखता है। अर्थात आत्मा की इस अलौकिक यात्रा में अनंत लौकिक यात्राएं शामिल होती हैं। इस अलौकिक यात्रा के संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह यात्रा अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर ही पूर्ण होगी, किंतु अनंत को परिभाषित करना भी असंभव है। अनंत को अज्ञात का पर्याय माना जा सकता है। प्रश्न यह उठता है कि इस अनंत गति को अनवरत जारी रखने के लिए आवश्यक बल किस स्रोत से प्राप्त होता है?

विचार अच्छे नहीं तो नीयत साफ नहीं

संकलित
प्रेरणा

महाभारत में द्युत क्रीड़ा में युधिष्ठिर दुर्योधन और शकुनि से सब कुछ हार गए थे। उस समय ये तय हुआ था कि जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लेंगे, तब उन्हें उनका हारा हुआ राज्य लौटा दिया जाएगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया था। शर्त के मुताबिक, दुर्योधन को पांडवों का राज्य लौटाना था। इसके लिए श्रीकृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों ने वनवास पूरा कर लिया है, अब उन्हें उनका राज्य लौटा दो। श्रीकृष्ण की बात सुनने के बाद दुर्योधन ने पांडवों को राज्य लौटाने से मना कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि वो पांडवों को एक गांव भी नहीं देगा। दुर्योधन की जिद के आगे धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य भी कुछ बोल नहीं सके। इसके बाद श्रीकृष्ण दरबार से जाने लगे तो दुर्योधन ने उनसे कहा कि आप हमारे अतिथि हैं, आप बिना भोजन किए न लौटें। श्रीकृष्ण ने कहा कि मैं किसी के यहां खाना खाते समय दो बातें ध्यान रखता हूं। पहली, मुझे बहुत भूख लगी हो। दूसरी, सामने वाला मुझे बहुत प्रेम से खिला रहा हो। अभी ये दोनों ही बातें नहीं हैं, न तो मुझे भूख है और न ही तुम मुझे प्रेम से निमंत्रण दे रहे हो। जैसा तुम्हारा स्वभाव है, इसमें भी कोई षड़यंत्र हो सकता है। इतना कहकर श्रीकृष्ण वहां से चले गए और बाद में भगवान ने विदुर के यहां भोजन किया था।

अंतर्मन

आज की पाती

राहुल कांग्रेस का खोया गौरव लौटाने को बेताब

राहुल कांग्रेस के खोए गौरव को लौटाने बेताब राहुल ने उत्तरप्रदेश में पहला रोड शो अपने बहन प्रियंका गांधी के साथ मिलकर तैयार की गई पटकथा से भटके बिना की हो। लोगो से हाथ मिलाना और जातिविहीन समाज सरीखे उदार मुद्दे उठाना राहुल का क्रम बन चुका है। लेकिन उनको पता लग पाता है तब तक वे कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते है, जो मुद्दा बन जाता है। हालांकि, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने के लिए राहुल को बडी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह आसान भी नही है। राहुल ब्रांड बिहार की धूल घुसरित गलियों में उतार दिया गया। दरअसल, गांधी परिवार होने के बावजूद कांग्रेस को उनसे उम्मीदे बेहिसाब है। *-कांतिलाल मांडोत, सूरत*

करंट अफेयर

ब्रिटेन में सिख विरासत के संरक्षण का आह्वान

पूर्व राज्यसभा सदस्य सरदार तरलोचन सिंह ने ब्रिटिश सिख सांसदों और उनके साथियों से महाराजा रणजीत सिंह के बिखरे हुए खजानों पर प्रामाणिक शोध कराने का आह्वान किया है ताकि उन्हें उचित रूप से सूचीबद्ध किया जा सके और भावी पीढ़ियों के लिए एक संग्रहालय में संरक्षित किया जा सके। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष सोमवार शाम लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स परिसर में ब्रिटिश सिख एसोसिएशन द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सिंह (92) ने उन खबरों की ओर इशारा किया जिनमें औपनिवेशिक काल की एक फाइल का खुलासा हुआ था जिसमें भारत में

सिख साम्राज्य के 19वीं सदी के शासक के कई खजानों का दस्तावेजीकरण किया गया था। सिंह ने कहा, 'महाराजा रणजीत सिंह के तोशाखाने (खजाने) से खजानों की एक सूची जारी की जानी चाहिए ताकि हमारे बच्चे हमारी सिख विरासत पर गर्व कर सकें।' उन्होंने कहा, 'ऐतिहासिक अभिलेखों में उल्लेख है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का पवित्र पंख, जो उनकी पगड़ी को सुशोभित करता था, तोशाखाने में रखा जाता था और महाराजा रणजीत सिंह उसे प्रतिदिन छूते थे।'

ऑफ बीट

दांतों की दैनिक सफाई में छिपा प्लास्टिक संकट

दांतों की नियमित सफाई, फ्लॉसिंग और छह महीने में एक बार दंत चिकित्सक से दांतों की जांच कराना। ये सभी दांतों की सफाई के लिए जरूरी कदम माने जाते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये दैनिक आदतें

अनजाने में पृथ्वी पर माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं। शोध से पता चला है कि टूथपेस्ट, फ्लॉस, टूथब्रश और दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री के माध्यम से हर दिन माइक्रोप्लास्टिक के अरबों कण जल प्रणाली में पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि प्लास्टिक माइक्रोबीड पर कई देशों में प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन आज भी कई टूथपेस्ट में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद होते हैं। वहीं, अधिकांश डेंटल फ्लॉस नायलॉन या टेफ्लॉन जैसे गैर-जैव अपघटनीय पदार्थों से बने होते हैं, जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। टूथब्रश दैनिक जीवन का उपयोगी हिस्सा है। लेकिन ये टूथब्रश भी इस संकट में योगदान दे रहे हैं। सामान्य उपयोग के दौरान उनके नायलॉन ब्रिसल के छोटे-छोटे कण टूटकर पानी के माध्यम से जल प्रणाली में प्रवेश कर जाते हैं। ये कण मलजल में प्रवेश करते हैं, उपचार प्रणालियों से गुजरते हैं और अंततः समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें प्लवक, शंख, मछली खा जाते हैं और अंततः यह मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं।

X ट्रेंड f

रेल सेवाओं का विस्तार

आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन के अनुरूप हम देशभर में रेल सेवाओं के विस्तार के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसी दिशा में भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। इससे यहां के लोगों का जीवन आसान होगा।
- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रकृति का विकास

हम बीटीआर में न केवल बुनियादी ढाँचे के विकास और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस खूबसूरत क्षेत्र में प्रकृति का विकास हो। सरकार ने प्राकृतिक परिवेश की रक्षा और पशु-पक्षियों की आबादी को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
- हिमंत बिस्वा सरमा, सीएम, असम

युवक को न्याय मिले

निर्मम भाजपा सरकार से हताश होकर एक युवा ने आत्मदाह के द्वारा सरकार को जगाने के लिए जो कोशिश की है वो बेहद दर्दनाक है। भाजपा सरकार घायल युवक को अच्छे से अच्छा इलाज-उपचार सुनिश्चित करे और युवक को न्याय प्रदान करे।
- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

काठमांडू में फंसे यात्री

यह बेहद चिंताजनक है कि नेपाल में बिगड़े हालातों के बीच, बड़ी संख्या में राजस्थान के यात्री काठमांडू में फंसे हुए हैं। प्रदेश सरकार को वहां फंसे यात्रियों को सुरक्षित राजस्थान लाने का इंतजाम करना चाहिए।
-अशोक गहलोत, पूर्व सीएम, राजस्थान

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 फोनः 9253681019-20
ई-मेल : **haribhoomi@gmail.com**
वेब-साइट : www.haribhoomi.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

11 hindi nd-06_page 02.qxd 9/10/2025 7:09 PM Page 1

पायनियर
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 11 सितंबर 2025

टैरिफ का दौर

स्वदेशी पर जोर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ ने भारत को काफी प्रभावित किया है। इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे बाह्य और आंतरिक, दोनों नीतियों में बदलाव जरूरी हो गया है। स्वदेशी लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी के दर्शन का आधार रहा है। उन्होंने 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' नारों के जरिए स्वदेशी का जोरदार समर्थन किया है।

आज, स्वदेशी का मुद्दा व्यावहारिक व्यावहारिकता पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों से अपने आह्वान में एक बार फिर स्वदेशी की भावना का आह्वान किया है और उनसे ₹स्वदेशी₹ को एक जनांदोलन बनाने का आह्वान किया है। आगामी त्योहारों को ₹स्वदेशी मेलों₹ के साथ मनाने का मोदी का प्रयास सांस्कृतिक होने के साथ-साथ आर्थिक भी है। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या स्वदेशी का ऐसा पुनरुत्थान ट्रंप के टैरिफ का प्रतिकार कर सकता है। मोदी राष्ट्रीय भावना का लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे समय में जब वैश्विक रुझान प्रतिकूल प्रतीत हो रहे हैं, भारतीय निर्मित वस्तुओं को चुनने का उनका आह्वान पहले जैसा प्रतिध्वनित हो भी सकता है और नहीं भी।

चाहे हम इसे पसंद करें या न करें, आज दुनिया एक छोटी सी जगह है, और उपभोक्ताओं की पसंद किसी क्षेत्र या देश तक सीमित नहीं है; वे वैचारिक नहीं, बल्कि भोगवादी हैं। इक्कीसवीं सदी की अर्थव्यवस्था देशभक्तिपूर्ण खरीदारी से आसानी से प्रभावित नहीं होती। अगर यह कारगर भी हो, तो भी यह टैरिफ की भरपाई में मामूली भूमिका ही निभाएगा। भारतीय निर्यातकों को अभी भी कड़ी

प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, और इसका दबाव नौकरियों और आय पर दिखाई देगा। निर्वाचन क्षेत्रों में स्वदेशी मेले स्थानीय कारीगरों की उपस्थिति बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे राष्ट्रीय निर्यात रणनीति का विकल्प नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री का विनिर्माण और आत्मनिर्भरता पर जोर उचित है, लेकिन इसके साथ ही, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

भारत को व्यापारिक झटकों का सामना करने के लिए उत्पादकता में सुधार करना होगा, लालफीताशाही को कम करना होगा और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन में निवेश करना होगा। हाल ही में घोषित जीएसटी सुधार सही दिशा में एक कदम हैं। अगर इन्हें गंभीरता से लागू किया जाए, तो ये वास्तव में व्यावसायिक संचालन को आसान बना सकते हैं। स्वदेशी संरक्षणवाद या पुरानी यादों का बहाना नहीं बन सकता। इसे प्रतिस्पर्धात्मकता के रूप में पुनर्व्याख्यायित किया जाना चाहिए। टैरिफ के खिलाफ भारत के लिए सबसे अच्छा दांव दोतरफा है। पहला, व्यापारिक साझेदारों में विविधता लाना और मजबूत स्थिति में रहते हुए बातचीत करना। दूसरा, वास्तविक घरेलू क्षमता को बढ़ावा देना ताकि भारतीय सामान केवल देशभक्ति के कर्तव्य के कारण न चुने जाएँ, बल्कि इसलिए चुने जाएं क्योंकि वे अच्छी गुणवत्ता के हैं।

दीर्घकालिक लक्ष्य 'मेड इन इंडिया' को गुणवत्ता, विश्वसनीयता और नवाचार का पर्याय बनाना होना चाहिए। स्वदेशी की राजनीति त्योहारों के मौसम में भावनाओं को उभार सकती है, लेकिन स्वदेशी का अर्थशास्त्र प्रतिस्पर्धात्मकता पर आधारित होना चाहिए। मोदी का भारत को यह याद दिलाना सही है कि आत्मनिर्भरता अब एक नारा नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि यह केवल एक भावनात्मक अपील न रहे, बल्कि एक संरचनात्मक परिवर्तन का रूप ले। तभी भारत घरेलू स्तर पर लचीलेपन के साथ विदेशी टैरिफ का सामना कर पाएगा।

संपत्ति के लेन-देन में अघोषित पैसा

बेहिसाबी नकदी, खासकर संपत्ति के लेन-देन में, लंबे समय से भारत की राजकोषीय पारदर्शिता और आर्थिक प्रशासन के लिए एक चुनौती रही है। विभिन्न प्रावधानों के बावजूद, एक के बाद एक सरकारें संपत्ति के कम मूल्यांकन, स्टांप शुल्क की चोरी और काले धन के प्रचलन को रोकने के लिए संघर्ष करती रही हैं।

सुभाष चंद्र अग्रवाल
लेखक, सूचनाधिकार परामर्शदाता हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269व के तहत एक प्रावधान हुआ करता था जो सरकार को खरीदार द्वारा आयकर रिटर्न में घोषित बिक्री मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक पर संपत्ति खरीदने का विकल्प देता था। हालांकि, सरकार के सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण, 01.07.2002 से इस प्रावधान को अधिनियम से हटा दिया गया। पहला, सरकार को उन संपत्तियों को खरीदने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती थी जिन्हें आयकर विभाग रिटर्न में कम मूल्यांकित मानता था। दूसरा, इस प्रावधान के कारण अक्सर जानबूझकर संपत्तियों का अधिग्रहण होता था जिससे अंततः नुकसान होता था, क्योंकि सरकार बाद की नीलामी में खरीद मूल्य भी नहीं वसूल पाती थी।

वर्तमान में, आयकर विभाग के पास एकमात्र प्रावधान खरीद मूल्य और सर्किल रेट के बीच के अंतर को अघोषित स्रोतों से आय के रूप में मानने का है। हालांकि, यह प्रावधान अपने आप में समस्याग्रस्त है। कुछ क्षेत्रों, जैसे नई दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, में सर्किल रेट वास्तविक बाजार दर से अधिक है। इससे संपत्ति के लेन-देन में अजीबोगरीब स्थितियां पैदा होती हैं, क्योंकि स्टाम्प शुल्क वास्तविक खरीद मूल्य से अधिक मूल्य पर चुकाना पड़ता है। इसके विपरीत, अधिकांश मामलों में, संपत्ति के लेन-देन में बेहिसाब नकदी प्रमुख रूप से शामिल होती है।

संपत्ति के लेन-देन में बेहिसाब नकदी की भागीदारी को कई सुधारों के माध्यम से कम किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। सबसे पहले, संपत्ति के लेन-देन पर स्टाम्प शुल्क की दर को पूरे देश में समान रूप से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना चाहिए, जिसमें नगरपालिका शुल्क भी शामिल हैं। यदि संपत्ति पूरी तरह से महिला के नाम पर खरीदी जाती है, तो 1 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, और यदि संपत्ति पुरुषों और महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से खरीदी जाती है, तो छूट को आनुपातिक रूप से कम किया जाना चाहिए। दूसरा, एक स्थायी स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना शुरू की जानी चाहिए, जिसके तहत व्यक्ति अधिकतम कर स्लैब के तहत स्वेच्छा से अपने आयकर रिटर्न में नकदी सहित बेहिसाब आय की घोषणा कर सकते हैं।

इस स्लैब को वर्तमान प्रभावी दर लगभग 43 प्रतिशत (अधिभार और उपकर के कारण) के बजाय, राजा चेल्लिया समिति द्वारा मूल रूप से अनुशंसित 30 प्रतिशत पर बहाल किया जाना चाहिए। यदि कोई संपत्ति विक्रेता किसी विशेष वर्ष में बेहिसाब नकदी घोषित करता है, तो आयकर विभाग उस खरीदार के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेगा जिसने ऐसी बेहिसाब नकदी प्रदान की होगी।

ऐसी योजना में घोषित धनराशि का 20 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बॉन्ड में अनिवार्य दीर्घकालिक निवेश का प्रावधान भी शामिल होना चाहिए, जिस पर आरबीआई बॉन्ड के बराबर वार्षिक ब्याज दर (वर्तमान में लगभग 8 प्रतिशत प्रति वर्ष) हो। उदाहरण के लिए, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को ऐसी निधियों के प्रबंधन का दायित्व सौंपा जा सकता है, और इसके संचालन का विस्तार करके प्रत्येक जिले में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। ये इकाइयाँ मध्याह्न भोजन योजना और रेलवे खानपान में उपयोग के लिए पके हुए उत्पाद बना सकती हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक दोनों लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना के दोहरे प्रावधानों - कुल लाभ पर 12.5 प्रतिशत या दस करोड़ रुपये तक के पुनर्निवेशित शेष पर 20 प्रतिशत - को शेयरों से होने वाले लाभ की तरह एक समान 10 प्रतिशत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यह बदलाव करदाताओं को संपत्ति के लेन-देन पारदर्शी तरीके से करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे बेहिसाबी नकदी पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा, आयकर विभाग को एक विशेष वेबसाइट विकसित करनी चाहिए, जिस पर संपत्ति विक्रेताओं को बिक्री के लिए इच्छित संपत्तियों का पूरा विवरण देना होगा।

अपेक्षित या बातचीत के बाद तय किया गया विक्रय मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। कोई भी संभावित क्रेता जो निर्धारित अवधि (उदाहरण के लिए, 30 दिन) के भीतर घोषित मूल्य से अधिक कीमत पर संपत्ति खरीदना चाहता है, उसे 10 प्रतिशत बयाना राशि जमा करके ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए। यदि कई बोलीदाता आगे आते हैं, तो सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को खरीद का अधिकार प्राप्त होगा, बशर्ते कि शेष राशि का भुगतान अंतिम निर्णय के दस कार्यदिवसों के भीतर कर दिया जाए। यदि सबसे ऊँची बोली लगाने वाला भुगतान करने में विफल रहता है, तो बयाना राशि जब्त कर ली जानी चाहिए, और अगली सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को अवसर दिया जाना चाहिए। यदि कोई ऊंची बोली लगाने वाला सामने नहीं आता है, तो विक्रेता मूल रूप से बातचीत के बाद तय किए गए सौदे को आगे बढ़ा सकता है। इस प्रस्तावित वेबसाइट को राज्यवार, ज़िलावार और क्षेत्रवार पदानुक्रमिक रूप से संरचित किया जाना चाहिए, और संपत्ति दलालों के बीच इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

यदि सावधानीपूर्वक कार्यान्वित किया जाए, तो यह प्रावधान संपत्ति के लेन-देन में बेहिसाबी धन की भूमिका को काफी हद तक कम कर देगा। इससे वास्तविक विक्रेताओं को भी लाभ होगा क्योंकि इससे उन्हें अपनी संपत्तियों का उचित बाजार मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बजाय इसके कि वे बिचौलियों और दलालों के हाथों में पड़ जाएं, जो अक्सर मुनाफे का बड़ा हिस्सा हड़प लेते हैं।

इसी पोर्टल में बैंकों द्वारा ऋण वसूली के लिए नीलाम की गई संपत्तियों के लिए भी एक अनुभाग शामिल होना चाहिए, जिससे वित्तीय संस्थानों और निवेशकों, दोनों के लिए एक समेकित, पारदर्शी बाजार के रूप में कार्य किया जा सके। सामूहिक रूप से, ये उपाय संपत्ति के लेन-देन में पारदर्शिता लाएँगे, बेहिसाबी नकदी की भूमिका को काफी कम करेंगे और साथ ही आवास क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। परिणामस्वरूप, संपत्ति से संबंधित कराधान के माध्यम से सरकार के लिए अधिक राजस्व सृजन होगा। अंत में, भारत को स्वीडन जैसे देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन और उन्हें अपनाना चाहिए, जो अपनी नकदी रहित अर्थव्यवस्था और क्रेडिट कार्ड के व्यापक उपयोग के लिए जाने जाते हैं।

भारत में, क्रेडिट कार्ड का उपयोग सीमित है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि व्यापारी अक्सर कार्ड से भुगतान करने पर, खासकर कम मार्जिन वाले व्यवसायों में, 2 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लेते हैं। यह अधिभार इसलिए है क्योंकि बैंक वर्तमान में कार्ड लेनदेन पर लगभग 2 प्रतिशत शुल्क लगाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए, सरकार को क्रेडिट कार्ड भुगतान पर बैंक शुल्क को 0.5 प्रतिशत तक सीमित करना चाहिए, जिसका खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।

इस तरह के उपाय से क्रेडिट कार्ड का उपयोग काफी बढ़ जाएगा, जिससे बैंकों को अधिक लेनदेन की मात्रा के माध्यम से लाभ होगा, जबकि सरकार को बेहतर कर अनुपालन के कारण राजस्व में वृद्धि होगी। बेहिसाबी नकदी का एक अन्य प्रमुख स्रोत माल और सेवा कर (जीएसटी) संरचना का दुरुपयोग है। अप्रयुक्त जीएसटी चालान कभी-कभी नकदी के बदले में ₹बेचे₹ जाते हैं, जिसमें खरीदार और विक्रेता झूठे इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों के लाभों को साझा करते हैं। इस प्रथा ने 8 नवंबर, 2016 को विमुद्रीकरण के बाद भी नकदी परिसंचरण में काफी योगदान दिया है।

इसे संबोधित करने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) केवल व्यापार योग्य वस्तुओं के लिए ही दी जानी चाहिए, न कि उन वस्तुओं के लिए जिन्हें खर्च के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या जिनके लिए मूल्यह्रास का दावा किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य सुधारात्मक कदम भी उठाए जाने चाहिए

खादीः विकसित भारत की स्वदेशी पहचान

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दक्षिण अफ्रीका से लौटकर बापू ने चरखे के माध्यम से स्वदेशी से स्वावलंबन का बिगुल फूका था। आज वहीं चरखा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सकल्प से स्वदेशी क्रांति का आधार बन गया है।

मनोज कुमार
लेखक, खादी व ग्रामाद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं।

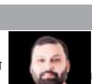

पूरी दुनिया इन दिनों टैरिफ वॉर के चक्रव्यूह में उलझी है। हर देश अपने-अपने हितों को साधने के लिए आयात-निर्यात पर शुल्क की दीवारें खड़ी कर रहा है। वैश्विक कूटनीति के इस दौर में आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने नए तनाव पैदा किए हैं और वैश्विक व्यापार का संतुलन डगमगा रहा है। प्रत्येक देश इस चक्रव्यूह को भेदने के रास्ते खोज रहा है। लेकिन इससे निकलने के लिए भारत के पास पूर्व में आजमाया हुआ एक शाश्वत समाधान है- स्वदेशी।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दक्षिण अफ्रीका से लौटकर बापू ने चरखे के माध्यम से स्वदेशी से स्वावलंबन का बिगुल फूका था। आज वहीं चरखा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सकल्प से स्वदेशी क्रांति का आधार बन गया है। हाल ही में गुजरात की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था-गुजरात की ये धरती दो मोहन की है- एक सुदर्शन चक्रधारी द्वारकाधीश श्रीकृष्ण और दूसरे चरखाधारी मोहन, साबरमती के संत पूज्य बापू। इन दोनों के मार्गदर्शन पर भारत निरंतर सशक्त हो रहा है। सच्चे अर्थों में मैं कहू तो खादी के माध्यम से स्वदेशी क्रांति का ये मोदी युग है। आज जब गांवों में चरखे-करघे की घरघराहट गूंजती है, तो उसमें केवल सूत नहीं, बल्कि विकसित भारत की आत्मा का तान-बाना बुनता है। जिस चरखे को महात्मा गांधी ने आजादी का अस्त्र बनाया था, उसी चरखे को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत का आधार बना दिया है। खादी अब केवल वस्त्र नहीं, बल्कि स्वदेशी क्रांति की ध्वजवाहक बन चुकी है। स्वदेशी क्रांति के अगुवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विभिन्न मंचों से लगातार देशवासियों से खादी और स्वदेशी उत्पाद अपनाने का आह्वान करते रहे हैं।

31 अगस्त 2025 को अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में त्योहारों की रौनक होगी। इन त्योहारों में स्वदेशी को कभी न भूलें-उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामानों से हो, रोशनी वही जो भारत में बनी झालरों से हो। जीवन की हर जरूरत में स्वदेशी हो और गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इसी तरह से उन्होंने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से संबोधन के दौरान सभी दुकानदारों व व्यापारियों से अपील की कि वे अपनी दुकानों पर बोर्ड लगाएं जिसमें लिखा हो, यहां स्वदेशी माल बिकता है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, जब भी हमने संकल्प लिया है, तब-तब उसे सिद्ध कर दिखाया है। खादी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। खादी विलुप्त होने के कगार पर थी, कोई पूछने वाला नहीं था। जब मुझे सेवा का अवसर मिला, मैंने देश से आह्वान किया और लोगों ने संकल्प लिया। नतीजा यह हुआ कि एक दशक में खादी की बिक्री लगभग सात गुना बढ़ी है। देशवासियों ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ खादी को अपनाया है। भारत में यह समय तीज और त्योहारों का है। प्रधानमत्री की अपील है कि यह त्योहारों का मौसम केवल संस्कृति का उत्सव न होकर आत्मनिर्भरता का उत्सव भी बने। उनका मंत्र साफ है- हम जो भी खरीदेंगे, वह मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा और जो भी बेचेंगे वो भी स्वदेशी होगा। आइए हम सभी आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने जैसे संदेशों के साथ अमृतकाल का विकसित और समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लें। ध्यान रहे कि. विकसित भारत की नौव हमें, अपनी-अपनी इकाई से ही रखनी होगी।

हम 144 करोड़ भारतवासी संकल्प लें कि हम स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदेंगे और बेचेंगे, जो एक स्वावलंबी, समृद्धिशाली राष्ट्र बनाने में सहायक होगा। बीते 11 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ऐतिहासिक उपलब्धिया हासिल की है। कारोबार पहली बार पौने दो लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है। खादी की बिक्री में सात गुना तक की वृद्धि हुई है। आज देशभर में लगभग 2 करोड़ लोग खादी और ग्रामोद्योग से जुड़कर रोजगार पा रहे हैं। यह केवल आंकड़े नहीं, बल्कि स्वदेशी क्रांति का जीवंत प्रमाण है। मोदी के नेतृत्व में खादी और ग्रामोद्योग न केवल वोकल फॉर लोकल का अगुवा है, बल्कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की जीवंत मिसाल भी बन चुका है।

प्रधानमंत्री ने मन की बात से लेकर संसद और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक हर जगह खादी का गौरवगान किया है। उन्होंने कहा है- जब आप खादी खरीदते हैं, तो यह सिर्फ वस्त्र नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को संबल देने वाला कदम होता है। यही खादी आज विकसित भारत 2047 प्रतिशत अभियान का आधार बन गई है।

राष्ट्र प्रथम की नीति और वंचितों के हितों की भावना से प्रेरित हमारे प्रधानसेवक सदैव लघु उद्यमियों, पशुपालकों, किसानों और श्रमजीवी भाइयों-बहनों की चिता करते रहे हैं। अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री दुनिया के ऐसे विलक्षण नेता हैं, जो अपने छोटे कारोबारियों और हस्तशिल्पियों के उत्पादों को स्वयं प्रोत्साहित और प्रचारित करते हैं। इतना सशक्त और स्पष्ट संदेश केवल वही दे सकते हैं कि देश के उत्पादन में देशवासियों का पसीना झलके। यही भावना वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के संकल्प की जीवंत बनाती है। आज हम सबका एक ही मंत्र होना चाहिए- एक ही संकल्प, स्वदेशी विकल्प हर त्यौहार, सिर्फ स्वदेशी उपहार मेरा मानना है अभी भारत के धैर्य की परीक्षा का समय है। लेकिन समय बदलते समय नहीं लगता। चरखे का पहिया निरंतर गति से घूम रहा है।

भारतीय जनमानस का खून-पसीना पूरे उत्साह और सामर्थ्य से अर्थव्यवस्था को सींच रहा है। यही सामर्थ्य विकसित भारत की गाड़ी को उस मंजिल तक पहुंचाएगा, जहां विश्व की महाशक्तियां भी भारत की विराट शक्ति को स्वीकारने पर विवश होंगी। आज नहीं तो कल, भारत को विश्व गुरु के रूप में मान्यता मिलकर रहेगी। यह मान्यता हमारे लोकतंत्र की जीवत ऊर्जा और सास्कृतिक सामर्थ्य का प्रमाण बनेगी। यहीं हमारे स्वदेशी तंत्र का आधार बनेगी। दबाव चाहे जितना भी आए, हम उसे सहते हुए और अधिक सुदृढ होते जाएंगे। यही प्रधानमंत्री जी का संदेश है और यही खादी शक्ति से स्वदेशी क्रांति का मंत्र भी।

आप की बात

क्यों जला नेपाल ?

देश और दुनिया में सत्ता के प्रति राजनेताओं की बढ़ती लालसा को देखकर राष्ट्रकवि दिनकर ने बहुत सालों पहले अपने प्रसिद्ध काव्य रश्मिरथी में लिखी पंक्तियां जब नाश मनुष्य पर छाता हे पहले विवेक मर जाता है आज भी प्रासंगिक होकर वर्तमान में दुनिया के देशों के राजनीतिक हालात पर सौ फीसदी सच भी बैठती हे ! हाल ही में हुए नेपाल में युवाओं के उग्र आन्दोलन में केपी ओली सरकार का पतन जिस तरह से युवा आक्रोश की वजह से हुआ हे उसे देखकर आज यदि दिनकर होते इस प्रकार अपना दर्द कविता के माध्यम से व्यक्त करते हे कि जब सत्ता में बेठे लोगों का भ्रष्टाचार चरम पर छाता हे तब देश की युवा शक्ति जागृत होकर सरकारों की होली खुद अपने हाथो से जलाता है। बेकौल नेपाल में जो कुछ भी हुआ वह देखने में सुनने में अच्छा नही लगता हे और ऐसा किसी भी देश में होना भी नही चाहिए लेकिन ऐसा दुनिया में पहली बार नही हुआ हे ! अक्सर सता में बेठे लोग जब तानाशाह बन जाते हे तो जनता द्वारा उनका हश्र ऐसा हो जाता कि जान बचना मुश्किल हो जाती हे ! हमारे देश के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अफगानिस्तान श्रीलंका में भ्रष्टाचार की वजहसे जनता द्वारा सत्ताओ को सिहासन से उखड फेकते ने देखा! समूची दुनिया में भ्रष्टाचार एक बड़ी विकराल समस्या बनती जा रही है !

– **अरविंद रावल**, झाबुआ, मप्र

उपराष्ट्रपति की भूमिका

उपराष्ट्रपति केवल देश के संवैधानिक ढाँचे का ही हिस्सा नहीं होते, बल्कि वे भारतीय संसदीय व्यवस्था की सुचारु कार्यप्रणाली में भी केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और इस नाते उच्च सदन की मयार्दा, गरिमा और अनुशासन बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। सदन की कार्यवाही को संतुलित और निष्पक्ष रूप से चलाना, विभिन्न दलों के सांसदों को राष्ट्रहित के मुद्दों पर एकजुट करना और बहस को सार्थक दिशा देना उपराष्ट्रपति का मुख्य कर्तव्य होता है। अक्सर राज्यसभा में तीखी बहसें और राजनीतिक मतभेद देखने को मिलते हैं, लेकिन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका यह सुनिश्चित करने की होती है कि संसद की कार्यवाही विवाद और शोरगुल के बीच भी उत्पादक बनी रहे। कई बार देखा गया है कि उपराष्ट्रपति ने अपने अनुभव और संतुलन से प्रश्नकाल की उपयोगिता को बढ़ाया और महत्वपूर्ण विधायी चचाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इसके अतिरिक्त, जब किसी सांसद के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन का नोटिस दिया जाता है, तो उसे स्वीकार करना या खारिज करना पूरी तरह सभापति यानी उपराष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। यदि वे इसे गंभीर मानते हैं, तो मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है। इसके अलावा, समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है।

– **विभुक्ति बुपक्या**, उज्जैन

भारत के साथ चीन

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के डबल टैरिफ शुल्क से बचने के लिए आज भारत सरकार ने अमेरिका से अपने व्यापारिक आर्थिक सम्बंध कम करते हुए अब जब एशिया में चायना की और अपने व्यापारिक दोस्ती के अपने हाथ बढ़ाए हैं तो उसे चायना ने भी हाथों-हाथ लिया है। चायना ने अपनी और से दोस्ताना व्यवहार करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत के खिलाफ थोपें पचास प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ को आज न केवल अनुचित बल्कि अतार्किक भी बताया है। चीन के भारत में राजदूत शु फेहोग ने चीन भारत के बीच एतिहासिक सम्बंधों और साझा सहयोग पर जोर देते हुए कहा है कि भारत पर डबल टैरिफ शुल्क को लगा कर अमेरिका इसे एक व्यापारिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।अतः हमें भी किसी भी प्रकार के टैरिफ और व्यापारिक युद्धों का दृढ़ता से विरोध करना चाहिए।आज चीन एवं भारत के बीच नजदीकी आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध है, अतः हमें चीन भारत मित्रता और सहयोग को आज एक व्यापक सक्रिय सहयोग देने की आवश्यकता है।हम अमेरिकी टैरिफ शुल्क को भारत के खिलाफ लगाए जाने का विरोध करते हैं। अतः हम आज चीन! के इस व्यापक समर्थन की दिल खोल कर प्रशंसा करते हैं।

– **मनमोहन राजावत राज**, शाजापुर

भय पैदा करते फर्जी मेल

तकनीक का विस्तार चिंता और तनाव का कारण भी बना है ।शरारती तत्व इन सेवाओं का दुरुपयोग कर सरकार के साथ ही जनता को भी पसोपस में डाल रहे हैं ।हाल के दिनों में लगातार शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य केंद्रों, विमान सेवाओं, मंदिरों, रेलों आदि को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल मिल रहे हैं। सौभाग्य से सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के कारण कोई गंभीर घटना नहीं घटी है लेकिन इन संदेशों ने आम जनता के मन में भय और असुरक्षा की भावना जरूर बढ़ा दी है। इस तरह के मेल न केवल मानसिक आतंक फैलाते हैं बल्कि बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान भी पहुंचाते हैं। सुरक्षा जांच, यातायात अवरोध और सेवाओं में व्यवधान से समय व संसाधनों की बबार्दी होती है। ऐसे कृत्य सामाजिक शांति और व्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रहार करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि साइबर सेल और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर ऐसे फर्जी मेल करने वालों को शीघ्रता से चिन्हित कर कठोर दंड दें। साथ ही आमजन को भी जागरूक किया जाए। कड़े कानून, तकनीकी निगरानी और सख्त कार्रवाई ही ऐसे शरारती तत्वों पर अंकुश लगा सकती है ताकि समाज भयमुक्त वातावरण में अपना दैनिक जीवन जी सके।

– **अमृतलाल मारू 'रवि'**, इन्दौर मप्र